

जयप्रकाश की विचारधारा

सम्पादक
श्री रामवृक्ष वेनीपुरी



जयप्रकाश की विचारधारा

दो शब्द -

जब मेरी लिखी जयप्रकाशजी को जीवनी प्रकाशित हुई, तभी से मित्रों का आग्रह आने लगा कि उनके विचारों और सिद्धान्तों पर भी एक पुस्तक प्रकाशित होनी चाहिये ।

सबसे जबरदस्त आग्रह था बनारस-राज्य के उस जमादार का जिसने अपने खून से एक खत लिखकर कहा था—

आपकी इस जीवनी ने तो मुझे पागल बना दिया । गरीबों के जिस नेता की मुझे तलाश थी, वह मुझे मिल गया । लेकिन, मैं उसे सिर्फ देखकर सन्तुष्ट नहीं हो सकता । मैं तो उसके विचारों पर चलना चाहता हूँ । क्या कोई ऐसी किताब नहीं लिखियेगा कि मैं अपने नेता के विचारों से पूरी तरह वाकिफ हो सकूँ ? आपको मेरी कसम—मेरे खून की कसम । इसीलिए अपने खून से ही यह खत लिख रहा हूँ आपको ।

मैंने तभी से इस किताब की ओर ध्यान दिया । चीजें जहाँ-तहाँ बिखरी पड़ी थीं । कितनी चीजें मूलतः अँगरेजी में थीं । सबका सग्रह करने में ढेर हुई और काफी देर हो गई ।

खैर, अब यह लोगो के सामने हाजिर है । मैंने कोशिश की है कि इसमें जयप्रकाशजी के विचारों का पूर्णतः संकलन हो जाय । उनके सभी प्रमुख लेखों, पुस्तकाओं का ही सग्रह इसमें नहीं है; उनके कितने ही व्याख्यानों को भी दे दिया है, जिनके नोट मैंने हो लिये थे । फिर जयप्रकाश-जीजेल में जो छिटफुट नोट लिखते रहे, उनमें से भी बहुत चीजों को दे दिया है । कई चीजें तो ऐसी हैं, जो पहले-पहल यहीं छप रही हैं ।

राष्ट्र-कवि श्री मैथिलीशरण गुप्त ने लिखा था—“सचमुच आपका जय-

प्रकाशजी से मस्तिष्क का ही नहीं, हृदय का सम्बन्ध है ।” लेकिन इस पुस्तक का सकलन सिर्फ हार्दिक प्रेम से ही प्रेरित होकर नहीं हुआ है ।

देश में जो असन्तोष है, बेकली है, उसमें देश की जनता, देश के नौजवान जयप्रकाश की ओर ही ध्यान लगाये बैठे हैं । ऐसी हालत में यह आवश्यक था कि उनके विचारों को एकसाथ संग्रह करके उनके सामने रख दिया जाय, जिसमें वे समझें कि जयप्रकाश क्या चाहते हैं और उन्हें कहाँ ले जाना चाहते हैं ।

अवभक्ति हमेशा ही बुरी है, किन्तु किसी नये सदेश के मसीहा के प्रति अवभक्ति तो उसके साथ विश्वासघात और अपने साथ धोखा है ।

विजयादशमी
१९४८

श्री रामवृक्ष बेनीपुरी

विषय-सूची

प्रथम खण्ड

समाजवाद क्यों और कैसे ?

१	समाजवाद . सामाजिक संगठन की एक पद्धति	३
२	समाजवाद की रूपरेखा	२१
३	समाजवाद—किस रास्ते ?	३३
४	मार्क्सवाद . अनुभव से छनकर	४८
५	समाजवाद और भारतीय संस्कृति	६१
६	समाजवादी एकता	६८
७	सोशलिस्ट पार्टी : सिद्धान्तलोकन	८४
८	समाजवादी कार्यक्रम	१०८

द्वितीय खण्ड

क्रांति की लपटों में

१	आजादी के सैनिकों के नाम—पहला पत्र	१३५
२	आजादी के सैनिकों के नाम—दूसरा पत्र	१४६
३	आजादी के सैनिकों के नाम—तीसरा पत्र	१७९
४	अमेरिका के अफसरों और सिपाहियों के नाम	२०२
५	अपने विद्यार्थियों से	२१३

तीसरा खण्ड

सीखचों के अन्दर से

१	देवली के मशहूर खत	२२३
२	क्या युद्ध अविभाज्य है ?	२३६
३	लाहौर किले की शत्रुणायें	२५३
४	कुछ फुटकर चीजे	२७०

(ख)

चतुर्थ खण्ड

आजादी के बाद

१	जन-राज्य या हिन्दू-राज्य	२८३
२	वापू की हत्या : जिम्मेवार कौन ?	२९७
३	कांग्रेस मर गई	३११
४	तब हमारा देश स्वर्ग होगा	३१७

२८५

२९५

३१

३१५

समर्पण

भारतीय समाजवाद के आचार्य और नेता
श्री जयप्रकाश नारायणजी को—

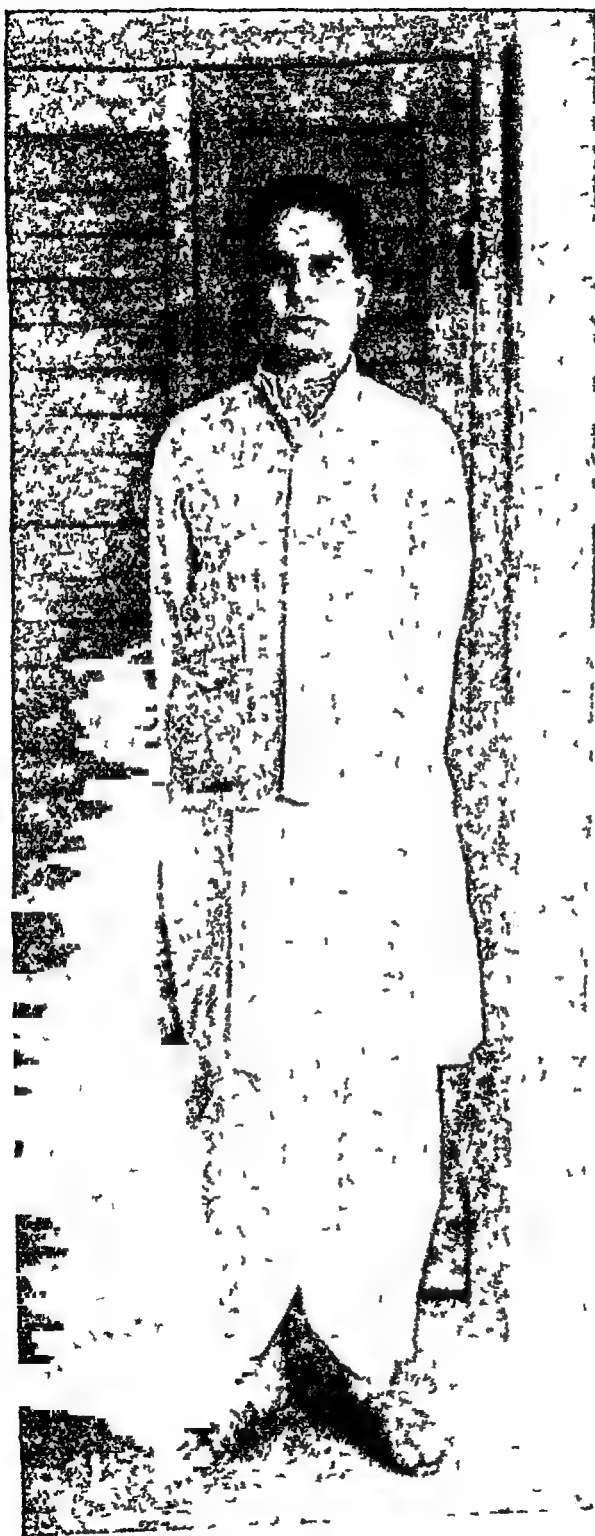
प्यारे साथी,

आज ही आपकी वर्षगांठ है—४६ वीं वर्षगांठ ! वर्षगांठ के अवसर पर
कौन-सा उपहार लालें आपके लिए ? बस लीजिये यही—त्वदीय वस्तु गोविन्द
तुभ्यमेव समर्पयत् ?

विजयदशमी }
१९४८ }

श्री रामवृक्ष वेनीपुरी





साथी जयप्रकाश

जयप्रकाश की विचारधारा

प्रथम खंड

समाजवाद—क्यों और कैसे ?

समाजवाद : सामाजिक संगठन की एक पद्धति

समाजवाद के बारे में हमेशा याद रखना यह है कि यह समाज को नये सिरे से बसाने की एक प्रणाली है। समाजवाद व्यक्तिगत आचार की नियमावली का नाम नहीं है। यह वह चीज नहीं है जिसे हम या आप इक्के-दुक्के प्रयोग में ला सकें। यह कुछ गरम दिमागों की पैदावार भी नहीं है। जब हम कहते हैं कि हिन्दुस्तान में समाजवाद की स्थापना होनी चाहिए, तो उसका मतलब यह होता है कि देश के पूरे आर्थिक और सामाजिक जीवन का, उसके खेतों, कारखानों, विद्यालयों और मनोरंजनगृहों का नये सिरे से संगठन होना चाहिए। इसमें सन्देह नहीं कि किसी एक गाँव या किसी एक कारखाने का संचालन भी समाजवादी तरीके पर किया जा सकता है। लेकिन, उसे समाजवाद नहीं कहा जा सकता। छोटे बच्चे भी मुँह से पानी का फुहरा देकर उसपर सूरज के सातों रंगों की लीला पैदा कर सकते हैं, लेकिन आसमान में जो इन्द्रधनुष उगता है उसकी सतरंगी छटा ही न्यायी होती है।

इससे स्वभावतः ही यह नतीजा निकलता है कि जो लोग समाजवाद के आधार पर समाज का नवनिर्माण करना चाहते हैं उनके हाथों में अधिकार होना चाहिए और उस अधिकार के पीछे काफी ताकत होनी चाहिए। बिना इस अधिकार और ताकत के आदर्शवादियों की कोई भी जमात समाजवाद नहीं कायम कर सकती।

किन्तु यहाँ हमें समझ लेना है कि इस अधिकार या शक्ति का क्या अर्थ है? आज की दुनिया को देखिये तो आप पायेंगे कि जिस साधन से कोई गिरोह, कोई पार्टी या कोई आदमी अपनी योजना, अपनी स्कीम समाज या

जयप्रकाश की विचारधारा

राष्ट्र पर लादता है, उस साधन का नाम है राज्य । जब राज्य आपके हाथ में हो तो आप कानून बनाकर या प्रचार और शिक्षा के जोर पर अपनी इच्छा या योजना समाज पर लाद सकते हैं । आज के विज्ञान ने प्रचार और शिक्षा की ताकत बहुत ही बढ़ा दी है । इसके बावजूद किसी ने विरोध किया तो राज्य के दमनात्मक पहलुओं—पुलिस और फौज का उपयोग कर आप उस विरोध को चकनाचूर कर दे सकते हैं । सरकार के हर कानून के पीछे सरकार की सम्मानने-बुझानेवाली या डराने-धमकाने वाली ताकत छिपी रहती है ।

आज के ससार में कोई भी पार्टी समाजवाद कायम नहीं कर सकती जिसके हाथ में राज्य की मशीन न हो । राज्य की यह मशीन जनता ने आपको चुनाव में विजयी बनाकर दी हो या हथियारबन्द दस्ते संगठित कर, छापा मार कर वह हासिल की गई हो—हमारी इस समय की बहस से उसका कोई सरोकार नहीं है ।

जिस पार्टी के हाथ में राज्य-सत्ता होगी, वह समाजवाद की स्थापना करने की आशा कर सकती है, दर्शाए कि उसके हाथ में दो चीजों में से एक हो । पहली चीज, इतनी ताकत कि वह विरोधों को कुदल दे सके या दूसरी चीज, जनता की इतनी मदद कि विरोधी सर ही न उठा पायें । इन दोनों चीजों का मतलब भी अन्त में एक ही होता है । समाजवादी सरकार के हाथ में जो ताकत होती है वह भी तो जनता की मदद से ही प्राप्त होती है । उसके विरोध में जो ताकत खड़ी होती है, वे धनवालों की ताकत होती हैं और स्वभावतः वे जनता की मदद से वंचित होती हैं ।

मैंने कहा कि जिस पार्टी के हाथ में राज्य-सत्ता हो, हुक्मत की ताकत हो, वह चाहे तो इस पृथ्वी पर ही समाजवादी स्वर्ग का निर्माण कर सकती है । सोचना यह है कि इस नव-निर्माण की शुरुआत कैसे की जाय ? क्या सबसे पहले यह काम किया जाय कि जितने शोषक हो, मोटी-मोटी तोड़वाले

पूँजीपति हों उन्हें, इकट्ठा कर गोली से उड़ा दिया जाय । मान लीजिये, हिन्दुस्तान में समाजवाद कायम हुआ और प० जवाहरलाल उसके सभापति या प्रधान मंत्री हुए, तो क्या उनका पहला काम यह होगा कि युक्त प्रान्त के जितने तालुकेदार हैं, उन्हें एक पक्ति में खड़ा करें और तोप से उड़ा दें ? या जितने राजा-महाराजा या सेठ-साहूकार हैं, सबके खजाने या तिजोरियाँ जब्त कर लें और उन्हें लोगों में बराबर-बराबर बाँट दें ? क्या वह टाटा के लोहे के कारखाने को उसमें काम करनेवाले मजदूरों के हाथ में सौंप दें और उन्हें कह दें कि अब यह चीज तुम्हारी है, तुम अब भला-बुरा जैसा चाहो इसका इस्तेमाल करो ? क्या वह देश में जितनी जमीन है सबको बराबर-बराबर टुकड़ों में बाँट दें और देश में जितने लोग हैं, उन्हें एक-एक चप्पा दे दें ? क्या ऐसा करना समाजवाद कहलायेगा ?

नहीं, समाजवाद इतनी भोड़ी, भद्दी और बेहूदी चीज का नाम नहीं । वह एक वैज्ञानिक, सभ्य और सुसंगत प्रणाली का नाम है ।

तो, जवाहरलाल को ऐसी हालत में क्या करना होगा ?

हम इसका जवाब तुरत पा जायें, यदि हम जिस समाज में रह रहे हैं, उसके स्वरूप को अच्छी तरह समझ लें ।

असमता: समाज की केन्द्रीय समस्या

अपने समाज को देखने से सबसे पहले जो दर्दनाक और अजीब बात सामने आती है, वह है असमता की, नाबराबरी की । पद में, संस्कृति में, सुअवसर में—सब जगह असमता का बोलबाला है । जिन्दगी के लिए जितनी भी अच्छी चीजें हैं उनका बँटवारा बराबरी के आधार पर न होकर ऐसे ऊल्लू-जल्लू ढग से हुआ है कि देखने से ही चित्त दर्दग्रस्त हो जाता है । गरीबी, भूख, गंदगी, बीमारी, अज्ञान—ज्यादा आदमियों के भाग्य में मानो

जयप्रकाश की विचारधारा

ये ही लिखे हैं और एक मुट्ठी लोग सारे आराम, सुख-चैन, दिलासिता, संस्कृति, पद और शक्ति का उपभोग कर रहे हैं। अपने देश में हम यही देखते हैं और संसार में भी यही बात है। अपने देश में तो इनका और भी विवृत रूप है। अपने अभागे देश की ताह दौलत और गरीबी, अत्याचार और पतन का बेतुकापन भला और दूसरी जगह कहीं देखने को मिलेगा ?

यह असमता दर कैसे की जाय, यही हमारे समाज की आज प्रमुख समस्या है। असमता की इस अवस्था पर प्रत्येक युग के महान पुरुषों का, ऋषियों और महात्माओं का ध्यान गया है और उन्होंने उसके हल के तरह-तरह के उपाय बताये हैं—दान, उदारता, काल्पनिक लोक—जहाँ सब बराबर हों—भाग्यवानों से प्रार्थना की कि वे अभागों पर दया करें, धन की निन्दा, दद्रिता का यशगान, आवश्यकताओं को कम करने का उपदेश—ये चीजें ही साधारणतः असमता के अभिशाप को दूर करने के साधन के रूप में पेश किये गये हैं। अपने युग के महात्माओं द्वारा भी हमें ऐसा ही सन्देश मिल रहा है।

किन्तु, समाजवादी इस असमता को दूर करने के लिए कुछ दूसरा ही उपाय पेश करता है। एक डाक्टर जिस ताह रोग के प्रति रुख रखता है, वही रुख समाजवादी का इस समस्या के प्रति है। वह यह नहीं मानता कि दुनिया में असमता बनी ही रहेगी और उसका काम सिर्फ उसमें कुछ कमी करना या उसे वर्दीत के लायक बनाना है। वह तो इस समस्या की जड़ तक पहुँचने की कोशिश करता है, फिर इस कोशिश में लगता है कि समाज में असमता रहे ही नहीं।

असमता का कारण—क्या यह जन्मजात है ?

यह असमता कैसे आई, क्यों आई, इसकी जड़ कहीं है ? समाजवादी

समाजवाद—क्यों और कैसे?

ज्यों ही उन बातों की छानबीन शुरू करता है, सबसे पहले उसके सामने जीव-विज्ञान खड़ा हो जाता है। जीव-विज्ञान के नाम पर कहा जाता है कि सभी मनुष्य एकसाँ नहीं पैदा होते, जैसा कि जनतंत्रवादी दुहराते फिरते हैं। वल्कि वे जन्म से ही नाबराबर पैदा होते हैं। आदमी की योग्यता जन्म से ही गुण और परिमाण, दोनों में ही भिन्न-भिन्न होती है। देखने से भी ऐसा ही मालूम पड़ता है और मानव समाज की बुद्धि में समानता की खोज करनेवाले नये मनोवैज्ञानिक भी इस बात को नहीं काटते।

लेकिन हमें देखना तो यह है कि यह जन्मजात असमता सामाजिक असमता को कहाँ तक प्रभावित करती है? समाजवादी इसको कबूल करता है कि संसार के अन्य पदार्थों और जीवों की तरह आदमी में भी भिन्नता है। समाज के एक छोर पर एक मुट्ठी प्रतिभाशील व्यक्तियों का गिरोह है, तो दूसरे छोर पर उसी तरह एक छोटा-सा गिरोह बेवकूफों और कमबलों का है और बीच में एक बहुत बड़ा बहुमत उन लोगों का है जो योग्यताओं में प्रायः एक-साँ हैं।

इन जन्मजात विभिन्नताओं का असर हम समाज पर भी पड़ा हुआ देखते हैं। पढ़ने-लिखने में, कला और विज्ञान की निपुणता प्राप्त करने में हम असमता के उदाहरण प्रायः ही पाते हैं। फिर धन में, शक्ति में, पद में, सुअवसर में भी असमता का बोल-बाला है। लेकिन समाजवादी कभी इस बात पर विरोध की आवाज बुलन्द नहीं करता कि समाज में टैगोर ऐसे कलाकार और रमण ऐसे वैज्ञानिक क्यों पैदा होते हैं? टैगोर और रमण ऐसे महापुरुषों को समाज में पाकर समाजवादी को आनन्द ही होता है। किन्तु, उसे खेद इस बात का है कि हजारों टैगोर और रमण आत्मविकास का सुअवसर न पाने के कारण अज्ञात हो चिता पर चढ़ जाते हैं। किसी समाजवादी ने असमता के दोष बताते हुए कभी यह नहीं कहा कि क्यों प्रकृति कुछ ही

जयप्रकाश की विचारधारा

व्यक्तियों को कविता और विज्ञान का वरदान देती है। समाजवादी का विरोध तो है दूसरी कौटि की असमता से यानी धन, पद आदि की असमता से। आज की दुनिया में जहाँ धन ही सारी सामाजिक शक्तियों का केन्द्र बन गया है, उस धन का असम बँटवारा ही पूरी सामाजिक समस्या का मूल है।

धन का यह असम वितरण, नाबराबर बँटवारा क्यों हुआ और क्यों होता है ? यहाँ फिर जीव-विज्ञान की दुहाई दी जाती है। कहा जाता है कि कुछ लोग होशियार के रूप में ही पैदा होते हैं, वे अच्छी तरह काम-काज का अंजाम देते हैं और दूसरों के बनिस्बत धनी बन जाते हैं। कुछ देर के लिए इसे भी मान लीजिये। लेकिन जो लोग बपौती में धन पाते हैं उनके बारे में क्या कहियेगा ? बपौती में धन पाने के लिए किसी जन्मगत योग्यता की आवश्यकता तो है नहीं। लखपति का बेटा वज्रमूर्ख हो क्यों न हो, वह अपने बाप की लाखों रुपये की सम्पत्ति का उसी तरह मालिक हो जायगा जैसे कि वह स्वयं प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। यह साफ है कि बपौती में धन पाना इसलिए संभव है कि समाज में उसके लिए एक रिवाज बन गया है और कानून उस रिवाज पर मुहर लगा चुका है। उस रिवाज, उस कानून को बदल दीजिये तो देखियेगा कि आज जो हजारों व्यक्ति लखपति छैले बनकर घूमते नजर आते हैं, कल से वे दर-दर भीख माँगते फिरें।

अब हम उन लोगों को लें, जिन्होंने खुद धन कमाया है। जबतक उनके पास विशेष योग्यता नहीं थी, तब तक भला लखपति कैसे बन गये ?

निस्सन्देह ही एक सफल व्यापारी बनने के लिए एक खास टंग की योग्यता चाहिए। लेकिन क्या यह अजीब बात मालूम नहीं होती है कि भगवान ने धन पैदा करने की ताकत सिर्फ एक ही टंग की योग्यता पर लाद दी हो और दूसरे लोगों की तकदीर में यह लिख दिया हो कि तुम धनी लोगों की मर्जी पर ही जीओ ? एक बहुत बड़ा गणितशास्त्री हो, अपने समय

समानवाद—क्यों और कैसे ?

का यह सबसे बड़ा अनुसंधानकर्ता हो, इन अनुसंधानों के चलते उसे अमरत्व भी प्राप्त हो जाय, किन्तु इनके चलते वह धनी भी बन जायगा, यह निश्चित नहीं। क्या उस गणितशास्त्री की प्रतिभा का मूल्य उन मामूली साहूकारों के बराबर भी नहीं है जो व्यापार के कुछ बंधे नियम पर चलते और हजारों-लाखों पर हाथ फेरते हैं ? यों ही, चतुर से चतुर वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला से कोई पैसा नहीं बना सकता जब तक वह छुद व्यापारी न बने। मालूम ऐसा होता है कि व्यापारियों की प्रयोगशाला में ही धन पैदा करने की सारी ताकत केन्द्रित है।

चलिये, अब हम व्यापारियों की इस प्रयोगशाला को देखें और खोज करें कि धन किस तरह पैदा और इकट्ठा किया जाता है।

धन का उत्पादन और संग्रह

हमारी इस दुनिया में एक तरफ आदमी है और दूसरी तरफ प्रकृति। सारी सम्पत्ति प्रकृति के गर्भ में है। मनुष्य कोई सम्पत्ति तभी प्राप्त कर सकता है जब प्रकृति पर वह काम करे। इस तरह हम देखते हैं कि सभी सम्पत्तियों का मूल-स्रोत प्रकृति है या मनुष्य की मेहनत जिसके द्वारा वह प्रकृति से मनमानी चीजें वसूल करता है। प्रकृति और मनुष्य की मेहनत—यही वह आधार-शिला है जिसपर सारा अर्थ-शास्त्र खड़ा है।

धन एकत्र कैसे होता है ? यह साफ है कि अगर आदमी प्रकृति से उतनी ही चीज ले पाये जितनी का उपभोग कर सके, तो फिर धन एकत्र कहाँ से हो ? आदमी प्रकृति से कितना ले सकता है यह निर्भर करता है उसकी पैदा करने की ताकत पर। यानी, उसके औजार किस ढंग के हैं और उसके काम का तरीका क्या है ? इसलिए धन तभी एकत्र हो सकता है जब आदमी की पैदा करने की ताकत इतनी बढ़ गई हो कि वह अपनी जीविका से भी ज्यादा पैदा कर सके। धन के इकट्ठा होने का यह मौलिक आधार है।

जयप्रकाश की विचारधारा

शिकार, मछली मारने, खेती करने की कला जब इतनी उन्नति कर गई कि आदमी अपनी जीविका से ज्यादा प्राप्त करने लगा, तभी धन का एकत्र होना संभव हुआ ।

अब जिस समाज में पैदा करने की कला जीविका के मापदंड से आगे बढ़ गई हो, वहाँ उसका हर सदस्य कुछ न कुछ धन इकट्ठा कर ही लेगा । शर्त सिर्फ यह है कि वह अपने लिए काम करने को आजाद हो, उसके पास अपने औजार हो, प्रकृति तक उसकी स्वतन्त्र पहुँच हो और अपनी कमाई वह अपने ही पास रख सके । उस समय धन एकत्र करने की दर इस बात पर निर्भर करेगी कि उस समय समाज में एक आदमी ज्यादा से ज्यादा कितना पैदा करता और कम से कम कितना खर्च करता है । ऐसा हो सकता है कि कोई परिवार जितना पैदा करे उसे सारा-का-सारा उपभोग कर ले । ऐसी हालत में वैसे परिवारों के पास धन का सग्रह नहीं हो पायेगा । लेकिन वह परिवार भूखों भी नहीं मरेगा क्योंकि हमने यह मान लिया है कि उस समाज में पैदावार जीविका के मापदंड को न सिर्फ छू सकी है, बल्कि वह आगे भी बढ़ गई है ।

इस समाज में कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनमें असाधारण प्रतिभा हो । स्वभावतः वे लोग दूसरों की अपेक्षा ज्यादा पैदा कर सकेंगे और यदि वे मितव्ययी हैं तो ज्यादा बचा भी सकते हैं । दूसरी तरफ कम प्रतिभा वाले लोग होंगे जो बहुत ही थोड़ा या कुछ भी नहीं बचा सकेंगे । लेकिन हर हालत में ऐसे समाज में हर तन्दुरुस्त आदमी कुछ धन इकट्ठा करने का कम-से-कम अपनी परवरिश करने के लायक तो होगा ही, वशतः कि जैसा हम पहले कह चुके हैं, वह अपने लिए काम करने को आजाद हो, उसके पास अपने औजार हो, प्रकृति तक उसकी मुली पहुँच हो और अपनी पैदावार का वह आप ही मालिक हो ।

अब हम इस कात्पनिक समाज से अपने समाज की ओर आते हैं। हम यह देखते हैं कि उत्पादन के साधन—चाहे खेती-गृहस्थी में लीजिये या उद्योग-धंधों में—इस तरह से तरक्की कर गये हैं कि अब कोई भी आदमी बहुत आसानी से अपनी जीविका की अपेक्षा ज्यादा पैदा कर सकता है। हिन्दुस्तान का किसान स्वभावतः ही पुराणपथी समझा जाता है और उसके खेती के औजार और तरीके बहुत पुराने और बहुत अशो में रही हैं। तो भी वह अपनी जीविका से ज्यादा ही पैदा कर सकता है। फिर यह क्या बात है कि हमारे लाखों-करोड़ों आदमी दिन में एक बार भी भर पेट भोजन नहीं पाते ? साथ ही साथ हम यह भी देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत ऐसे भी लोग हैं जो अपनी जरूरतें ही अच्छी तरह पूरी नहीं कर लेते, बल्कि ऊँचे दर्जे की आराम-चैन की जिन्दगी गुजारते हैं। एक तरफ यह भुखमरी और दूसरी ओर यह आराम-चैन—यह किस तरह संभव हो सका है ?

पहले हम गरीबों के ही सवाल को लें। अपने वर्तमान समाज की विकसित उत्पादनशक्ति को देखते हुए यह संभव है कि हिन्दुस्तान का हर आदमी अपनी परिवारिक भोजन में कर ले। यही नहीं, हर आदमी के पास कुछ धन जमा भी रह सकता है। लेकिन हम ऐसा नहीं देख रहे हैं, बल्कि सच बात तो यह है कि हिन्दुस्तान के हर लोग अच्छी तरह खा-पी भी नहीं सकते। ऐसा क्यों हो रहा है ? क्योंकि ऐसा होने के लिए जो शर्तें हमने ऊपर बतायी हैं, वे सब लुप्त हो चुकी हैं। लोगों की खुली पैठ प्रकृति तक नहीं रह गई है। बहुत अशो में उनके औजार अपने नहीं हैं। वे सिर्फ अपने लिए काम नहीं करते और न अपने द्वारा पैदा की हुई चीज को अपने ही लिए रख पाते हैं। ऐसी बात क्यों हो गई है, यह बहुत ही पुराना किस्सा है। लेकिन यह बात सच है, इसे एक अंघा भी देख सकता है।

तो हमारी जनता की जो गरीबी है उसका कारण यह है कि पैदावार

जयप्रकाश की विचारधारा

के साधन यानी औजार, सामान, जमीन आदि पर उसका अपना अधिकार नहीं है। इन चीजों के लिए उसे दाम चुकाने पड़ते हैं और जितना ही अधिक उसे देना पड़ता है, पैदावार का उतना ही कम हिस्सा उसे मिल पाता है और उतनी ही ज्यादा उसकी गरीबी बढ़ती जाती है। बहुत लोग तो ऐसे हैं कि जिनके पास उन चीजों के दाम चुकाने के लिए कुछ भी नहीं होता। इसलिए उनके लिए अपनी मेहनत बेचने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं रह जाता है। अगर हर आदमी के पास पैदावार के साधन होते, तो फिर गरीबी का कहीं नाम-निशान नहीं होता। हाँ, यदि आबादी इतनी अधिक बढ़ गई होती कि पैदावार के साधनों की वर्तमान उत्पादन-शक्ति जनता की जरूरतों को पूरी करने में अक्षम होती, तो बात दूसरी है। किन्तु, यह निश्चय रूप से कहा जा सकता है कि यद्यपि हिन्दुस्तान की आबादी इतनी अधिक बढ़ गई है, तो भी ऐसी हालत नहीं हो पाई है।

अब हम धनी लोगो की बात लें। कुछ आदमियों ने गरीबों की अपेक्षा लाखों करोड़ों गुणा धन इकट्ठा कर रखा है, यह कैसे संभव हो सका? कोई भी व्यक्ति कितना भी चतुर क्यों न हो, पैदावार की किसी भी मंजिल में एक तरह के उत्पादन के साधन द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से हजारों गुणा ज्यादा पैदा कर नहीं सकता। यह साफ बात है कि धनी लोगों का जो असख्य धन है, वह उनका अपना कमाया हुआ नहीं है। एक ही समाज में रहनेवाले आदमी की उत्पादन-शक्ति में इतनी असमता हो नहीं सकती। हम पहले कह चुके हैं कि धन पैदा करने का एक ही साधन है, वह है प्रकृति पर आदमी द्वारा परिश्रम किया जाना और धन का संग्रह तभी हो सकता है जब आदमी अपनी जीविका से अधिक पैदा करे। आदमी कितना पैदा कर सकेगा, इसकी सीमा निर्धारित है। समाज में पैदावार की कला जिस हद तक विकसित होगी उसी पैमाने पर आदमी पैदा भी कर सकेगा। यह बात यूरो-

समाजवाद—क्यों और कैसे ?

पीय समाज पर भी लागू है यद्यपि वहाँ की पैदावार बहुत कुछ कल-पुर्जों पर ही निर्भर करती है। वहाँ हम पाते हैं कि पैदावार के साधन—खास कर औद्योगिक पैदावारों के साधन, अपने देश की अपेक्षा इतने विकसित हो चुके हैं कि अब कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता। किन्तु, इससे मेरी दलील में कोई खलल नहीं आता। अगर उन कल पुर्जों पर सम्मिलित रूप से काम करनेवाले लोग अपने हिस्से सही-सही पा सकें, तो भी हालत वही होगी जिसकी कल्पना हमने पहले की थी। यानी समाज के हर व्यक्ति के पास खाने-पीने के बाद भी काफी धन इकट्ठा हो जा सकता है और न तो कहीं गरीबी का नाम होगा और न आज की तरह कुछ लोगों के हाथ में अधिकांश धन का सग्रह ही हो सकेगा।

फिर हमारे आज के समाज में जो लखपति-करोड़पति बन गये हैं, वह कैसे ? ऐसा कहा जा सकता है कि मेहनती लोगों ने बड़ी धीरता से लगातार मेहनत करके इतने धन का सग्रह किया है। इसका जवाब तुरत दिया जा सकता है कि परिश्रम और मितव्ययिता खानदानी चीज नहीं रही है, और न इनके द्वारा इतने धन एकत्र ही किये जा सकते हैं। आज हम जिन्हें लखपति-करोड़पति पाते हैं, खास कर व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में, उनके बाप-दादे क्या थे हमें मालूम है। धन एकत्र होने का रहस्य धनियों के खानदान और प्रतिभा के अन्दर नहीं छिपा है। उसके रहस्य को हमें कुछ दूसरी ही जगह ढूँढ़ना पड़ेगा।

धन और शोषण

धन किस तरह से इकट्ठा होता है, इसके विश्लेषण से इस रहस्य का पता लगा जाता है। कल्पना कीजिये कि जिस समाज में उत्पादन जीविका के दर्जे से ऊपर जा चुका है यानी आदमी उतना पदा कर लेता है जिसमें खाने-पीने

जयप्रकाश की विचारधारा

से भी बहुत कुछ बच जाय और उस समाज में एक ऐसा आदमी है जो दस आदमियों को काम पर लगाता और उन्हें सिर्फ उतना देता है जितने की जरूरत उन्हें खाने-पीने या जीने के लिए है और बाकी को अपनी भोली में रख लेता है। ऐसी हालत में यह स्पष्ट है कि वह आदमी उस समाज के साधारण आदमियों की अपेक्षा, जो सिर्फ अपने ही उत्पादन करते हैं, दस गुणा अधिक धन इकट्ठा कर सकता है और कुछ ही दिनों में वह बहुत धनवान हो ही जायगा। जितने ही ज्यादा आदमियों को वह मजदूरी पर रखेगा, उतने ही ज्यादा उसके धन की वृद्धि होगी।

फिर कल्पना कीजिये कि उसी समाज में एक ऐसा आदमी भी है जिसने प्रकृति पर, मान लीजिये जमीन पर, एकाधिकार कायम कर लिया हो। उस एकाधिकार के बल पर वह जमीन पर तब तक किसी को काम करने नहीं देगा जबतक पैदावार का एक हिस्सा देने का शर्तनामा नहीं कर दिया जाता है। यह एकाधिकारवाला व्यक्ति भी दूसरे आदमियों की अपेक्षा ज्यादा धनी हो जायगा और उसका धन उसी अनुपात में बढ़ता जायगा जिस अनुपात में वह जमीन का मालिक है और उसके जोतनेवाले से मालगुजारी वसूल कर पाता है। दूसरे प्राकृतिक साधनों पर भी यही बात लागू है।

अब हमें धन की असमता के रहस्य का पता लग गया और हम यह भी जान गये कि शोषण का यथार्थ अर्थ क्या है ?

अब यहाँ यह सवाल पूछा जा सकता है कि कोई आदमी दूसरे के लिए काम ही क्यों करे और इस तरह क्यों अपनी कमाई का एक हिस्सा जान-बूझ कर दूसरे को दे दे—जब कि वह अपने लिए भी काम कर सकता और अपनी सारी कमाई को खुद भोग सकता है ? इस सवाल के जवाब के लिए हमे मानव जाति के पूरे सामाजिक और राजनीतिक इतिहास का पर्यवेक्षण करना पड़ेगा। संक्षेप में इसका जवाब यह है कि कोई आदमी भी ऐसा करना नहीं

समाजवादः—क्यों और कैसे ?

चाहता और मानव इतिहास में किसी आदमी ने ऐसा नहीं किया है जब तक वह ऐसा करने को बाध्य नहीं कर दिया गया हो ।

सभी मानवीय समाजों में जबतक जमीन की हृदयन्दी नहीं हुई थी और लोग जंगल को साफ करने और उसपर खेती करने में स्वतंत्र थे, तब तक कोई भी आदमी दूसरे के लिए काम नहीं करता था । सबसे पहले कुछ लोगों ने प्रकृति के वरदानों पर एकाधिकार स्थापित किया । यह एकाधिकार जोर-जबर्दस्ती से, नगी शक्ति के आधार पर, कायम किया गया । चारों तरफ आदमी के ऐसे गिरोह खड़े होने लगे जिन्होंने प्रकृति पर, मुख्यतः जमीन पर अपना एकाधिकार स्थापित किया और दूसरों को दास, अर्द्धदास या स्वतंत्र करदाता बनने को बाध्य किया ।

यही बात उद्योग-धंधों में भी हुई । जब तक उद्योग-धंधे उस सतह पर थे जब कि स्वतंत्र व्यक्तिगत उत्पादन संभव था, तबतक औद्योगिक, शोषण और फलतः औद्योगिक आय में बहुत कम विभेद था । लेकिन, ज्यों-ज्यों उत्पादन बढ़ता गया और शहर बसते गये, कारीगरों और गुलामों को एक साथ मिलकर अपने स्वामियों के लिए काम करने को लाचार होना पड़ा । इस तरह औद्योगिक आय में असमता का बोलबाला हुआ । औद्योगिक पूँजीपतियों की अत्यधिक वृद्धि तब से शुरू हुई जब भाग के बल पर उद्योग-धंधे चलाये जाने लगे । इसे ही औद्योगिक क्रांति कहा जाता है । औद्योगिक क्रांति के चलते मजदूरों का ज्यादा-से-ज्यादा शोषण सम्भव हुआ ।

ऐसा कहा जाता है कि हमारे समाज में ऐसे भी आदमी हैं जो न तो मजदूरों से काम लेते हैं और न मालगुजारी वसूल करते हैं, न दूसरे किसी तरह का कर लेते हैं, किन्तु, तो भी वे काफी धनी हैं और कभी-कभी तो पूँजीपतियों और जमींदारों से भी 'ज्यादा' धनी होते हैं । जैसे—कुछ लोग व्यापारी हैं, कुछ लोग फाटकेबाज हैं, कुछ लोग महाजन हैं । वे लोग न

जयप्रकाश की विचारधारा

तो खुद धन पैदा करते हैं और न धन पैदा करने में लगे हुए लोगों की मेहनत का ही शोषण करते हैं। लेकिन अगर हम गौर करके देखें तो यह स्पष्ट हो जायगा कि उनके धन का तुरत का जरिया चाहे जो कुछ हो, लेकिन वह आता है समाज द्वारा पैदा किये हुए सम्पूर्ण धन में से ही कट-छट कर।

हम पहले देख चुके हैं कि धन मेहनत से ही पैदा होता है। और उसमें से एक हिस्सा धन पैदा करने वाले मेहनतकश के पास जाता और बाकी उन शोषक वर्गों के पहुंचता है जो उस मेहनतकश को मजदूरी पर काम कराते हैं। ये शोषकवर्ग मेहनत करने वालों द्वारा पैदा की हुई चीजों का स्वयं उपभोग नहीं कर सकते। इसलिए उन्हें बैंक डालना, उनके बड़े दूसरी चीजों का खरीदना जरूरी होता है। व्यापारियों और फाटके बाजों की पैदाइश यहीं से शुरू होती है। तैयार माल का बेचना और कच्चा माल का खरीदना पूजीपतियों के लिए लाजिमी होता है। क्योंकि इसके बिना चीजों के पैदावार का सिलसिला जारी नहीं रखा जा सकता। इसलिए, मजदूरों से शोषण किये गये धन का एक हिस्सा वे खरीदार और विक्रेता की हैसियत से व्यापारियों और फाटकेबाजों को दे देते हैं। सूदखोर महाजनों की भी यही बात है। कहा जाता है कि वे रुपया देते और सूद लेते हैं। किन्तु, यह सूद आता कहाँ से है? सूद भी उत्पादन के रिलेसले में ही पैदा होता है और मजदूरों को देकर बचे हुए कोष से चुकता किया जाता है। चाहे मुनाफा कहिये या सूद, कमीशन कहिये या दलाली—ये सब के सब एक ही कोप से आते हैं और वह कोष मेहनतकश द्वारा पैदा किया जाता है और पैदावार के साधनों पर एकाधिकार रखने वाले लोग शोषण द्वारा उसे मेहनतकश से उचंग कर एकत्र करते हैं। रुपया से रुपया नहीं पैदा हो सकता। न कोई भी धार्मिक या व्यापारिक उलटफेर उसे पैदा कर सकता है। पूजीवादी व्यापार का सारा खेल इस बात में है कि उसके भिन्न-भिन्न बांग ज्यादा-से-ज्यादा

समाजवाद—क्यों और कैसे ?

शोषण करें और इस शोषण का केन्द्रीय लक्ष्य है वेचारे मेहनतकश की कमाई पूँजीवादी प्रतियोगिता या व्यापार के वारीक रहस्य यही है। विश्वविद्यालयों में धन के सग्रह के बारे में जो कुछ पढाया जाता है वह सब भ्रमजाल है—भूलभुलैया है।

हम इसे दुहरा ले। क्योंकि दुहराने में फायदा ही है। धन उन्हीं के पास एकत्र होता है, जिनका उत्पादन के साधन पर कब्जा होता है और उसके चलते जो दूसरों की मेहनत का शोषण करते हैं। इस शोषण द्वारा संचित-कोष से ही दूसरे-दूसरे गिरोह भी अपना हिरसा लेते हैं। यह सोचना वित्कुल गलत है कि ये बीचवाले लोग किसी रूप में भी धन पैदा करते हैं। उनका धन कमाने का मानी सिर्फ यह है कि शोषण द्वारा एकत्र धन में से कितना अधिक वह अपनी ओर खींच सकते हैं। प्रोफेसर, वकील, डाक्टर वगैरह सबके संव उसी एक ही कोष से अपनी भोली भरते हैं। हाँ, कभी-कभी वे असल धन पैदा करनेवाले अर्थात् मजदूरों और किसानों की खाली भोली से भी कुछ न-कुछ माड ही लाते हैं।

सक्षेप में—धन की असमता का मुख्य कारण यह है कि प्रकृति के वरदानों पर, जिनसे धन पैदा होता है और उत्पादन के साधनों पर, जिनके द्वारा धन पैदा होता है कुछ लोगों का व्यक्तिगत कब्जा हो गया है जो उनका उपयोग अपने लाभ के लिए करते हैं। यही से आर्थिक-शोषण शुरू होता है। यानी मेहनतकश के पास से पूरी पैदावार छीन ली जाती है, सिर्फ उसके जिन्दा रहनेभर का सामान उसके लिए दे दिया जाता है। यह कभी तो सीधे-सीधे होता है, कभी तिरछे-तिरछे। सीधा आर्थिक शोषण वह है जब पूँजी-पति मजदूरों से अपने कारखानों में काम लेता है। और अप्रत्यक्ष शोषण वह है जब जमीन या दूसरे प्राकृतिक साधनों का मालगुजारी या दूसरे ढंग के करो पर लगाता है।

जयप्रकाश की विचारधारा

पैदावार के ये साधन जोर जबर्दस्ती से ही व्यक्तिगत हाथों में गये। जो लोग इस तरह जोर जबर्दस्ती कर सकते थे, उनके हाथों में युगों तक धन बढ़ता रहा। इसके बाद ही कुछ आविष्कार हुए जिनके चलते ससार ने औद्योगिक-क्रांति देखी। यही से शोषण का वह भीषण युग प्रारम्भ होता है जिसमें लाखों-करोड़ों आदमियों को एक मुट्ठी लोग कारखानों में जोतते और करोड़पति, अरबपति बनते जाते हैं।

समाज में जो आज असमता है उसका कारण क्या है अब हम जान गये। तब हमारे लिए यह जानना कठिन नहीं रह गया कि इस असमता को दूर करने का समाजवादी तरीका क्या हो सकता है ?

असमता कैसे दूर हो ?

समाज को आज की असमता के दूर करने के सिद्धान्ततः दो ही उपाय हैं यदि वे व्यवहार में आ सकें तो फिर हम उनके आधार पर एक न्यायपूर्ण सुखी समाज का निर्माण कर सकते हैं। पहला उपाय है कि हम समाज का इस तरह पुनर्निर्माण करें कि हर आदमी अपने ही लिए काम कर सके—वह किसी तरह की मालगुजारी या कर दिये बगैर अपने खेत पर खेती कर सके या अपने कारखाने में अपने औजारों से काम करे। किसी आदमी के पास उत्पादन के साधन इतने अधिक न हों कि वह उनका उपयोग अपने ही हाथों से न कर सके।

लेकिन ज्यों ही हम अपने समाज में इस तरह का परिवर्तन करने लगेंगे, एक कुहराम मच जायगा। इस तरह का परिवर्तन समाज की प्रारम्भिक अवस्था में ही संभव था। ऐसे समाज में रेल और तार के लिए कोई गुंजायश नहीं। वैज्ञानिक दृष्टि से तो यह समाज बहुत ही कमजोर होगा और आज का कोई भी पच्चीसी राष्ट्र जब चाहे उसे निगल सकेगा। ऐसे समाज के लोगों का

समाजवाद—क्यों और कैसे ?

रहन-सहन भी बहुत नीचे दर्जे का होगा । क्योंकि हर आदमी पर आमदनी बहुत ही कम पड़ेगी । इसलिए यदि इस तरह के परिवर्तन वर्तमान बुराइयों से बचने के लिए संभव भी हो, तो भी अनेक कारणों से हमें उससे बाज ही आना है ।

यह उपाय काम में लाया नहीं जा सकता । इस उपाय को काम में लाने के लिए एक निर्मम तानाशाही चाहिये । क्योंकि जिनके पास धन है वे ऐसे समाज में रहने को न तैयार होंगे, न उसके लिए अपना धन छोड़ना चाहेंगे । किन्तु ऐसी तानाशाही के लिए भी उस समाज में कोई आधार न होगा । इसलिए हमें दूसरे उपाय की ओर जाना पड़ेगा ।

असमता दूर करने का समाजवादी उपाय

असमता दूर करने का जो दूसरा तरीका है उसे हम आप समाजवादी तरीका कह सकते हैं । धन का संग्रह कैसे होता है, यह हम जान चुके हैं । इसलिये समाजवादी कहता है कि उत्पादन के सभी साधनों पर से व्यक्तिगत अधिकार को खतम कर दीजिये और उसके बदले समूचे समाज का अधिकार उसपर स्थापित कीजिये ।

उत्पादन के साधनों पर ज्यों ही हम व्यक्तिगत अधिकार नष्ट कर देंगे और उन्हें पूरे समाज की सम्पत्ति मान लेंगे, त्योंही आर्थिक-शोषण की जड़ कट जायगी । आर्थिक-शोषण जब समाप्त हुआ तो फिर आर्थिक असमता रह नहीं जायगी । और, ज्योंही आर्थिक असमता दूर हुई, हमारे समाज का एक मौलिक अभिशाप दूर हो गया । मेहनतकश के शोषण से ही व्यक्तिगत हाथों में धन का संग्रह होता है । उत्पादन के साधन पर जब सामाजिक अधिकार कायम हो गया तो फिर दूसरे के लिए मजदूरी या भाड़े पर काम करने का सवाल ही कहीं उठेगा ? सब लोग अपने लिए काम करेंगे, व्यक्तिगत रूप में नहीं, सामूहिक रूप से । जो कुछ उत्पादन

जयप्रकाश की विचारधारा

होगा वह नफे के लिए नहीं, बल्कि सार्वजनिक उपभोग के लिए। सामाजिक अधिकार का मानी यह है कि सब धन पर सबका अधिकार है और सबको उसके उपभोग की गारंटी है। जो कुछ पैदा होगा, उसका बँटवारा पहले काम के रूप और परिमाण के अनुसार होगा। किन्तु धीरे-धीरे सबसे योग्यता के अनुसार काम लेने और आवश्यकता के अनुसार देने की व्यवस्था स्थापित की जायगी। पैदावार का बँटवारा करते समय उसका कुछ अंश राज्य और रक्षा के लिए, स्कूल और अस्पताल के लिए, आर्थिक विकास के लिए और दूसरे सार्वजनिक कार्यों के लिए रख लिया जायगा।

आज हम समझ चुके होंगे कि समाजवाद का मौलिक सिद्धान्त क्या है ? उत्पादन के सभी साधनों पर समाज भर का अधिकार हो—समाजवाद की मूल भित्ति यही है। समाजवादी ढंग पर समाज का पुनर्निर्माण तबतक संभव नहीं है, जबतक उत्पादन के साधनों पर से व्यक्तिगत अधिकार उठा नहीं दिया जाता।

यदि कोई नया राज्य समाजवाद के आधार पर समाज का संगठन करना चाहे, तो संभव है कि तुरंत वह इसे काम में लाने में समर्थ न हो सके। लेकिन यदि उसे सफल होना है तो उत्पादन के उन सभी बड़े साधनों पर सामाजिक अधिकार स्थापित करना ही पड़ेगा जो देश के आर्थिक जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव रखते और उसकी कुंजी अपने हाथ में रखते हैं।

विकसित समाज में उत्पादन के साधनों के साथ ही विनिमय और वितरण के साधन भी उन्नति करते जाते हैं—जैसे बैंक, रेल-टार, व्यापारिक संस्थानें आदि। उन पर भी सामाजिक अधिकार स्थापित करना होगा।

अब हम यह बता सकते हैं कि राजसत्ता हाथ में आने पर समाजवाद को स्थापना के लिए जवाहर लाल जी को क्या क्या करना चाहिये !

समाजवाद की रूपरेखा

आज के किसी भी समझदार व्यक्ति को यह मानने में आपत्ति न होगी कि समाज के विकास की अगली मंजिल समाजवाद है। किन्तु समाजवाद क्या है, इस प्रश्न पर लोग इसी तरह एक राय नहीं रखते। समाजवादी विचारको और कार्यकर्ताओं द्वारा समय-समय पर समाजवाद और समाजवादी समाज के विभिन्न चित्र उपस्थित किये जाते रहे हैं। यदि हम समाजवाद की मुख्य विचारधाराओं में से एक अर्थात् मार्क्सवाद को ले लें, तो मतभेद का क्षेत्र निश्चय ही बहुत सीमित रह जाता है। पूरी तरह समाप्त वह फिर भी नहीं होता। मार्क्स में ही आस्था रखकर चलनेवाले ऐसे समाजवादी आंदोलन मिलेंगे जो एक दूसरे से गहरा मतभेद ही नहीं रखते, आपस में झगड़ते और लड़ते भी रहते हैं। उदाहरण के लिए स्टालिनवादी और ट्राट्स्कीवादी दोनों ही मार्क्स के झण्डे के नीचे चलने का दम भरते हैं, पर उनका मतभेद इतना गहरा है कि वे एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। इनमें से कौन-सी मार्क्सवादी विचारधारा के लोग समाजवाद का सही चित्र उपस्थित करते हैं? जो इन दोनों लड़नेवाले खेमों में से किसी एक के साथ नहीं हैं वे यही उत्तर देंगे कि दोनों में से कोई भी सही तस्वीर नहीं पेश करता।

हमारे अपने देश में कम्युनिस्ट और रायवादी दोनों ही मार्क्स की कसमें खाते हैं, किन्तु मार्क्स की दुहाई देते हुए वे जिस प्रकार की नीति बरतते हैं उससे पाठक परिचित ही हैं। इन लोगों के लिये मार्क्सवाद का अर्थ मैक्सवेल के एजेंट बनकर काम करना और भारतीय क्रांतिकारियों की

जयप्रकाश की विचारधारा

खुफियागिरी करना भी रहा है। दोनों ही मार्क्सवादी होने का दावा करते हैं, पर दोनों एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। इनके अलावा भी मार्क्स की पताका को उड़ानेवाले छोटे-छोटे कई समूह इस देश में हैं, जिनमें इस विषय पर सहमति नहीं है कि मार्क्सवाद क्या है। मार्क्सवाद के सम्बन्ध में प्रचलित भ्रम और प्रतिस्पर्धी दावों को देखते हुए, मेरी राय में भारत के समाजवादी आंदोलन को, मार्क्सवादी विचारधारा, मार्क्स की मृत्यु के पश्चात् के ससार के इतिहास तथा अपने देश की अवस्था एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए समाजवाद की अपनी रूपरेखा तैयार करनी चाहिये। मार्क्सवाद समाज के परिवर्तनों की व्याख्या करनेवाला समाजविज्ञान एवं समाज के परिवर्तन की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ऐसी अवस्था में मार्क्सवादी विचारधारा में कट्टरपन के लिये अथवा 'बाबा वाक्यं प्रमाणम्' की मनोवृत्ति के लिए स्थान नहीं हो सकता। जो लोग एक ओर मार्क्सवाद को विज्ञान कहकर पुकारते हैं और दूसरी ओर उसमें कट्टरपन का समावेश करते हैं, वे उसके प्रति बड़ा अन्याय करते हैं। विज्ञान में अन्तिम सत्य जैसी वस्तु नहीं होती। विज्ञान की प्रगति मनुष्य के ज्ञान-भण्डार से मिथ्या ज्ञान को उत्तरोत्तर दूर करने से होती है। यदि मार्क्सवाद विज्ञान है तो मार्क्स अन्तिम सत्यों का प्रतिपादन नहीं कर सकते थे। वे अपने पूर्ववर्ती विचारकों की अपेक्षा अन्तिम सत्यों के अधिक निकट थे, यही कहा जा सकता है। आज जब कि मार्क्स के जमाने की अपेक्षा ज्ञान का भण्डार कहीं अधिक विस्तृत हो गया है और पूँजीवादी समाज के सम्बन्ध में हमारा अनुभव और पर्यवेक्षण भी कहीं अधिक है, हम ऐसी स्थिति में हैं कि मार्क्स की अपेक्षा निकटतर सत्य के दर्शन कर सकें।

दो मंजिलें

समाजवादी समाज के निर्माण की दो मंजिलें हैं—पहली संक्रमण-काल की मंजिल अर्थात् पूँजीवाद से समाजवाद की ओर जाने की मंजिल और

समाजवाद — क्यों और कैसे ?

दूसरी वह मजिल जब कि समाजवाद की स्थापना हो चुकी रहती है । यह स्पष्ट है कि सन्नमण कालीन समाज का रूप वर्तमान अवस्था तथा अन्तिम लक्ष्यो को ध्यान में रखकर ही निर्धारित किया जायगा । यहाँ मैं केवल समाजवाद के अन्तिम लक्ष्यो पर ही विचार करूँगा । समाजवाद का लक्ष्य है मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण का अन्त ; सभी के लिए आत्मविकास के समान अवसर का प्रबन्ध ; समाज के भौतिक एवं नैतिक साधनों का पूरा विकास तथा वर्ग विशेष के मुनाफे को नहीं बल्कि पूरे समाज की आवश्यकता एवं इच्छा को ध्यान में रखते हुए उनका उपयोग ; राष्ट्रीय सम्पत्ति तथा सामाजिक, शिक्षा-सम्बन्धी तथा दूसरे प्रकार की सेवाओं का उन सबके बीच न्यायपूर्ण बँटवारा जो अपने परिश्रम द्वारा समाज की सेवा करते हैं । समाज के सघटन की जिस प्रणाली से ये उद्देश्य सिद्ध होते हैं उसी को हम समाजवाद कहेंगे ।

मेरी राय में इन उद्देश्यों की सिद्धि तभी हो सकती है जब कि प्रचलित समाज में आसूल परिवर्तन किये जायें और भावी समाज का आर्थिक एवं राजनीतिक निर्माण नीचे बताये गये आधार पर किया जाय ।

सबसे पहले तो पूर्ण राजनीतिक स्वाधीनता की आवश्यकता है । दूसरे शब्दों में भारत का स्वतंत्र राष्ट्र बन जाना आवश्यक है । ब्रिटिश शासन के कायम रहते हुए समाजवाद की स्थापना नहीं हो सकती, इसे दुहराने की जरूरत नहीं है ।

दूसरी आवश्यकता आजकल के उस सुविधाप्राप्त वर्ग को हटाने की है जिसके हाथ में आज के समाज में आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति केन्द्रीभूत है और जो अपनी शक्ति के कारण इस अधिकार को परम्परागत रूप में बनाये रखने का प्रयत्न करता है । दूसरे शब्दों में, देशी नरेशों, जमींदारों और पूँजी-पतियों को अपने आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभुत्व को छोड़ने के लिए विवश करना होगा ।

जयप्रकाश की विचारधारा

ब्रिटिश सत्ता के देश से हटने के बाद देशी नरेशों की सत्ता, जमींदारी तथा पूँजीवादो पद्धति का अन्त करना अपेक्षाकृत सरल कार्य होगा। यदि भारतीय जनता ब्रिटिश राज का अन्त करने में समर्थ हुई तो सामन्तवाद और पूँजीवाद का अन्त करने से उसे कोई शक्ति रोक न सकेगी। उसके मार्ग में बाधक शक्ति केवल एक ही हो सकती है—जनता की अपनी राजनीतिक चेतना के विकास की अवस्था।

देशी नरेशों की सत्ता की समाप्ति से कोई ऐसी समस्या नहीं उत्पन्न होती जिसका हल समाजवाद को ढूँढना हो। उसका प्रबन्ध तो पूँजीवाद ने ही पहले से कर रखा है। देशी नरेशों को उनकी गदियों से हटाकर साधारण नागरिकों की स्थिति में लाना होगा। उनकी रियासतें भौगोलिक सीमा, आर्थिक साधन तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध को ध्यान में रखकर वैज्ञानिक ढंग से निर्धारित प्रदेशों का अंग बन जायँगी।

जमींदारी प्रथा का अन्त भी प्रचलित भूमि व्यवस्था के पुनः सघटन की दिशा में पहला ही कदम है। यह प्रश्न अवश्य सिद्धांत और व्यवहार सम्बन्धी अनेक जटिलताओं से भरा हुआ है। केवल यह कह देने से कि समाजवादी भारत में जमींदार न होंगे, हम यह नहीं बतलाते कि हम देश में किस प्रकार की कृषि का विकास करना चाहते हैं। समाजवादी कृषि का जो चित्र मेरे सामने है, उसकी व्याख्या मैं इस लेख में आगे करूँगा।

पूँजीवाद का विनाश निस्सन्देह समाजवाद की दिशा में बहुत बड़ा कदम है, किन्तु केवल पूँजीवाद का अन्त हो जाने से समाजवाद की स्थापना नहीं हो जाती। यह तो केवल निषेधात्मक अंग हुआ, जिसके साथ विधेयात्मक अंग को जोड़ना है।

खेती का सवाल

समाजवाद की आर्थिक रूपरेखा पर विचार करते हुए पहले हम खेती के

समाजवाद—क्यों और कैसे ?

सवाल को लें। हमारे देश की भूमि-व्यवस्था अवर्णनीय रूप से जटिल है। किन्तु सभी प्रचलित भूमि-व्यवस्थाओं में एक बात समान रूप से पाई जाती है। वह यह है कि सभी व्यवस्थाओं में मुट्ठी भर जमीन के मालिक कहे जानेवालों अथवा महजनों के लाभ के लिए खेत को जोतनेवाले सच्चे किसान का शोषण किया जाता है। इन सभी व्यवस्थाओं को खत्म करके इनके स्थान पर एक नयी भूमि-व्यवस्था कायम करनी होगी। समाजवादी कृषि की स्थापना के सिलसिले में हमें सहयोग तथा सामूहिक कृषि की दो मंजिलों से गुजरना होगा।

जमींदारी प्रथा की समाप्ति के पश्चात् ज्यादा बड़ी जोतों को छोटी जोतों में तोड़ने और बिल्कुल छोटी जोतों को इतनी बड़ी बनाने के उद्देश्य से कि उनपर खेती करना आर्थिक दृष्टि से अलाभकर न हो, जमीन का फिर से बँट-वारा करना जरूरी होगा। एक निश्चित नाप से बड़े रकबे की जमीन कोई किसान नहीं रख सकेगा। उदाहरण के लिए ३० एकड़ वह ज्यादा से ज्यादा जमीन होगी जो किसी किसान के पास रह सकती है। इसी प्रकार ५ एकड़ जमीन का वह छोटे-से-छोटा टुकड़ा हो सकता है जिससे कम किसी किसान-परिवार के पास न होना चाहिये। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जमीन न दी जायगी जो गांव का रहनेवाला न हो और खुद खेती न करता हो।

गांव में की जमीन का मालिक कानून की नजर में, अलग-अलग व्यक्ति न होकर, सम्ूचा गांव ही होगा और अलग-अलग व्यक्तियों के साथ खेत का बन्दोबस्त करना, राज्य के द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार, ग्राम-पंचायतों का कार्य होगा। इस प्रकार बन्दोबस्त की गई जमीन पर किसानों का एक प्रकार का मालिकाना हक होगा। किसानों का उनकी जमीनों पर मौजूदा मालिकाना हक माना जायगा—उन जमीनों को छोड़कर जिनके बहुत बड़ी या बहुत छोटी होने के कारण घोर विषमता को दूर करने की दृष्टि से

जयप्रकाश की विचारधारा

फिर से बँटवारा करना और उनके रकबों में तबदीली करना जरूरी हो जायगा। किन्तु किसानों का यह मालिकाना हक इसी बात तक महदूद रहेगा कि किसान अपनी जोत रकबे के हिसाब से गाँव की जमीन की उपज में से अपना हिस्सा पा सकें। किसी किसान को यह अधिकार न होगा कि ग्राम-पंचायत के अलावा दूसरे किसी के हाथ जमीन की बिक्री कर सके। खेती अथवा खेती से सम्बद्ध दूसरे काम किसान व्यक्तिगत रूप से अलग-अलग न करेंगे। प्रत्येक ग्राम-पंचायत अन्य कार्यों के साथ किसानों की सहयोग-समिति का कार्य भी करेगी। खरीदने, बेचने और उधार लेने आदि के सभी काम सहयोग समिति के द्वारा ही होंगे। खेत पर काम करनेवाले सभी व्यक्तियों को राज्य की ओर से मजदूरी के बारे में बनाये गये कानूनों के मुताबिक नकद या अनाज के रूप में मजदूरी दी जायगी और उपज में से लागत को निकाल कर जितनी पैदावार बच रहेगी, वह जोत के रकबे के मुताबिक किसानों में बाँट दी जायगी।

यह समाजवादी कृषि की पहली मंजिल, सहयोगी कृषि की मंजिल है। अगली मंजिल सामूहिक कृषि की मंजिल होगी जिसमें खेती की जमीन में किसानों की व्यक्तिगत मिल्कियत नहीं रह जाती। (रूस में सामूहिक कृषि में लगे हुए प्रत्येक किसान तरकारी उगाने, चिड़िया पालने या इसी तरह के दूसरे कामों के लिए तीन एकड़ तक जमीन निजी तौर पर रख सकता है) और समूचे गाँव की जमीन का इन्तजाम गाँव की सामूहिक कृषि-समिति द्वारा होता है। रूस में सामूहिक कृषि की स्थापना लोगों को काफी कष्ट देकर और डिकटेटरी तरीके पर हुई थी। कुछ लोगों का अनुमान है कि सामूहिक खेती को सफल बनाने के लिए सोवियत रूस में दो करोड़ व्यक्तियों को जान से हाथ धोना पड़ा। मैं नहीं चाहता कि इतने बड़े पैमाने पर किसानों को यातना दी जाय और न समाजवादी मिद्धान्त ही इसकी अनुमति देता है।

समाजवाद—क्यों और कैसे ?-

जमींदारी के खातेमें, जमीन के फिर से बँटवारे और बड़ी जमीनों को छोटी जोतों में बाँटने में खेती में लगी हुई जनता के १५ से लेकर २० फीसदी जनता पर राज्य का दबाव पड़ेगा, पर सामूहिक खेती के लिए ६० से ७० फीसदी जनता को दबाना पड़ सकता है। जनता के नाम पर दोलने और काम करनेवाली किसी भी सस्था के लिए इतना बड़ा दमन किसी भी तरह जायज नहीं हो सकता। ८० प्रतिशत के लाभ के लिए २० प्रतिशत के साथ जबरदस्ती की जा सकती है, पर ७० फीसदी किसानों के साथ 'उन्हीं की भलाई के लिए' जबरदस्ती नहीं की जा सकती। सहयोगी कृषि के लिए ही बहुतों पर दबाव डालने की जरूरत पड़ेगी ; किन्तु दबाव डालने, राजी करने तथा कुछ आर्थिक सुविधाएँ देने की नीतियों के बुद्धिमत्तापूर्ण सम्मिश्रण से सहयोगी कृषि में सफलता मिल सकती है। किन्तु सामूहिक खेती के लिए बड़े पैमाने पर लोगों की इच्छा के विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ेगी। ऐसा करना समाजवाद के ही सिद्धान्तों के विरुद्ध होगा, क्योंकि समाजवाद शोषित जनता की इच्छा को लेकर चलता है। ऐसी दशा में सामूहिक कृषि की प्रगति धीमी होगी, और प्रचार तथा प्रदर्शन के द्वारा जनता में जिस गति के साथ उसके लिए क्षेत्र तैयार होगा, उसी गति के साथ वह आगे बढ़ सकेगी। किन्तु कृषि सम्बन्धी जो नयी वस्तियाँ बसाई जायँ उनमें आरम्भ से ही सामूहिक खेती अपनायी जा सकती है।

उद्योग-धन्धे

आज की व्यक्तिगत खेती को सामूहिक खेती का रूप देने पर खेती के धन्धे में लगे हुए बहुत से लोग बेकार हो जायँगे। इसके अतिरिक्त ग्रामीण जनता को उद्योग-धन्धों में जगह देनी पड़ेगी, खासकर खेती के सहायक उद्योग-धन्धों में। अब हम समाजवादी उद्योग-प्रणाली पर विचार करेंगे। समाजवादी भारत में बड़े और छोटे पैमाने पर चलनेवाले दो प्रकार के उद्योग-

जयप्रकाश की विचारधारा

धन्धे होंगे। सभी बड़े पैमानेवाले उद्योग-धन्धों का स्वामित्व तथा प्रबन्ध संघ की सरकार अथवा प्रान्तीय सरकारों का होगा। मजदूर संघों के प्रतिनिधियों का नीचे से लेकर ऊपर तक कारखानों के प्रबन्ध में उचित भाग होगा।

छोटे पैमाने पर चलनेवाले सभी उद्योग धन्धे, मेरी राय में, सहकारी उत्पादक समितियों द्वारा चलाये जाने चाहिये। धन्धे का स्वामित्व और प्रबन्ध इन्हीं समितियों के हाथ में होगा। इन समितियों के संचालन-सम्बन्धी नियम बनाने के अतिरिक्त राज्य उनके कार्य में कोई हस्तक्षेप न करेगा। राज्य द्वारा संचालित तथा उत्पादक समितियों द्वारा संचालित उद्योग-धन्धों के अतिरिक्त शहर की म्यूनिसिपैलिटियों द्वारा संचालित उद्योग-धन्धे भी होंगे। म्यूनिसिपैलिटियाँ यदि बड़े धन्धों को नहीं, तो मध्यम प्रकार के और छोटे पैमानेवाले उद्योग-धन्धों का संचालन कर ही सकती हैं। समाज द्वारा संचालित इन उद्योग धन्धों के प्रबन्ध में स्वभावतः मजदूरों का उचित भाग होगा। सहयोग समितियाँ तथा समाज द्वारा संचालित उद्योग-धन्धों की बात में दो दृष्टियों से कहता हूँ। एक तो बेकार जनता को, जिसकी तादाद खेती और बड़े उद्योग-धन्धों के क्षेत्रों में क्रान्ति होने के कारण और भी बढ़ जायगी, राज्य की ओर से आनेवाले कुछ दिनों तक काम न दिया जा सकेगा; दूसरे, मैं यह भी नहीं चाहता कि उद्योग तथा व्यवसाय के क्षेत्र में राज्य एकाधिकार प्राप्त कर ले। जैसा कि हम रूस में पाते हैं, समाजवाद के अन्तर्गत खतरा यह है कि कहीं राज्य धीरे-धीरे समाप्त हो जाने के बदले नागरिकों के समस्त जीवन को अपने चंगुल में जकड़ रखनेवाली अन्यायी शक्ति का स्थान न ले ले। इस प्रकार के एकाधिकार के फलस्वरूप एक दल के उस प्रकार के सर्वग्रासी अधिनायकत्व की स्थापना होती है जिसे हम रूस में देख सकते हैं। उद्योग-धन्धों का प्रबन्ध और स्वामित्व राज्य की नौकरशाही के हाथों में ही केन्द्रीभूत

समाजवाद—क्यों और कैसे ?

न करके और ग्रामों को लोकतांत्रिक जन-राज्य का रूप देकर हम ऊपर बताये गये खतरे को बहुत हद तक दूर कर देते हैं ।

व्यापार के क्षेत्र में मेरे दिमाग में जो तस्वीर है वह यह है—विदेशी व्यापार पूरी तरह राज्य के हाथ में होगा । देश का आन्तरिक व्यापार राज्य, स्थानीय मण्डलों (पंचायतों तथा म्यूनिसिपैलिटियों) और सहयोग समितियों में बँटा हुआ होगा । बैंक का सारा कारोबार राज्य के हाथों में होगा ।

इस प्रकार मेरे समाजवाद की यह आर्थिक रूपरेखा हुई—

- (१) ग्राम-पंचायतों द्वारा संचालित सहयोगी कृषि ।
- (२) नई बस्तियों में सामूहिक खेती ।
- (३) राज्य के स्वामित्व तथा प्रबन्ध में बड़े पैमाने के उद्योग-धन्धे ।
- (४) समाज के स्वामित्व और प्रबन्ध में चलनेवाले (पंचायतों द्वारा संचालित) व्यवसाय ।

(५) सहयोगी उत्पादक समितियों द्वारा संचालित छोटे पैमानेवाले व्यवसाय ।

मेरे दिमाग में समाजवाद का जो चित्र है, अब मैं उसके राजनीतिक अंग की ओर आता हूँ ।

लोकतन्त्र

समाजवादी भारत में राज्य पूर्णतः लोकतांत्रिक होगा । बिना लोकतन्त्र के समाजवाद का अस्तित्व सम्भव नहीं । आजकल भ्रमवश बहुत से लोग यह सोचते हैं कि समाजवादी राज्य में श्रमिक वर्ग का अधिनायक तन्त्र होना आवश्यक है । यह धारणा मार्क्स की शिक्षा के विरुद्ध है । श्रमिक वर्ग के अधिनायक तन्त्र का स्थान केवल पूँजीवाद से समाजवाद के सक्रमण-काल में ही हो सकता है । इस सक्रमण-काल में भी अधिनायक तन्त्र की स्थापना प्रत्येक अवस्था में अनिवार्य नहीं है । मार्क्स ने इंग्लैण्ड जैसे पूँजीवादी राज्य के सम्बन्ध में, जहाँ राजनीतिक लोकतन्त्र का बोलबाला था और जहाँ

जयप्रकाश की विचारधारा

कोई बड़ी स्थायी सेना नहीं थी, कल्पना की थी कि वहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली के द्वारा ही समाजवाद की स्थापना हो सकती है। किन्तु ऐसे विरल उदाहरणों को छोड़कर आम तौर पर मार्क्सवादी विचारधारा में संक्रमण-काल में अधिनायक तन्त्र की स्थापना आवश्यक मानी गई है। किन्तु मार्क्सवाद का यह एक मूलभूत सिद्धान्त है कि संक्रमण-काल का अन्त होते ही अधिनायक तन्त्र का भी अन्त हो जाय। जब पुराने शासकवर्गों का अन्त हो जाय और समाज केवल श्रमिकों का समाज रह जाय, उस अवस्था में भी अधिनायक तन्त्र के बने रहने की कल्पना करना मूर्खता होगी क्योंकि श्रमिक वर्ग का यह अधिनायक तन्त्र अपने लिए नहीं हो सकता।

वर्तमान समाज से समाजवाद की ओर संक्रमण भारतवर्ष में लोकतन्त्रात्मक रूप धारण करे अथवा अधिनायकतन्त्रात्मक ? मेरा निजी विचार है कि वह लोकतन्त्रात्मक रूप ग्रहण करेगा—किन्तु यह स्मरण रखने की बात है कि मार्क्सवादी सिद्धान्त के अनुसार श्रमिक वर्ग के अधिनायक तन्त्र का अर्थ उस की कम्युनिस्ट पार्टी की भाँति दल-विशेष का अधिनायकत्व नहीं है। श्रमिक वर्ग का अधिनायकतन्त्र पूरे श्रमिक वर्ग का अधिनायकत्व है, भारतवर्ष अथवा जारशाही के बाद के उस जैसे औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए देशों में इस अधिनायक तन्त्र का अर्थ केवल मजदूरों का नहीं बल्कि मजदूरों, किसानों तथा मध्यम श्रेणी के शोषित वर्गों का सम्मिलित अधिनायकत्व होगा। इन वर्गों के एक या एक से अधिक दल हो सकते हैं। इन दलों को इस बात की स्वतन्त्रता होनी चाहिए कि वे सम्मिलित रूप से अधिनायक तन्त्र में भाग लें या इस अधिनायक तन्त्र के अन्तर्गत रहते हुए स्वाधीनतापूर्वक कार्य कर सकें। श्रमिक वर्ग के अधिनायक तन्त्र का यह अर्थ कभी-भी नहीं था कि मजदूर वर्ग या दूसरे श्रमिक वर्गों का दमन

समाजवाद—क्यों और कैसे ?

किया जायगा ; उसका अर्थ केवल शोषक वर्गों का और उनकी राजनीतिक तथा आर्थिक सस्थाओं का दमन ही है ।

समाजवाद के अन्तर्गत लोकतन्त्र के प्रश्न पर कुछ विस्तार के साथ विचार करने की आवश्यकता है । सर्व प्रथम समाजवाद के अन्तर्गत लोकतन्त्र का अर्थ यह है कि किसी दल-विशेष का शासन न हो, मजदूरों की एक से अधिक राजनीतिक पार्टियाँ हो सकती हैं, मजदूरों और किसानों के सहकारी संघों आदि की अपनी विभिन्न पार्टियाँ हो सकती हैं जो स्वाधीनतापूर्वक कार्य कर सकती हैं । समाजवाद के अन्तर्गत लोकतन्त्र का अर्थ यह होना चाहिए कि विचार प्रकट करने और राजनीतिक सस्थाओं की स्थापना करने की पूर्ण स्वाधीनता है । मजदूर संघों, सहकारी समितियों और इस प्रकार की दूसरी सस्थाओं को अपने समाचारपत्र प्रकाशित करने, अपनी रेडियो-व्यवस्था रखने और अपना विद्यालय चलाने की स्वाधीनता होनी चाहिए ।

समाजवाद के अन्तर्गत लोकतन्त्र का दूसरा अर्थ यह है कि मजदूर-संघ राज्य के अग और उसके अनुचर न होकर राज्य का समर्थन करनेवाली स्वाधीन सस्थाएँ हों और वे सरकार के दिन-प्रतिदिन के कार्यों पर नियन्त्रण रख सकें । इस में मजदूर संघों को कतई आजादी नहीं है और उन्हें इस सिद्धांत के आधार पर राज्य का अनुचर बनाया गया है जब कि राज्य मजदूरों का राज्य हो जाता है तो मजदूरों की सभी सस्थाएँ भी राज्य का अनुचर बन जाती हैं । इस में राज्य और शासन को एक समझ लिया गया है । कोई खास राज्य मजदूरों का राज्य हो सकता है । किन्तु समय विशेष की सरकार जानकर या अज्ञान में मजदूरों के हितों के विरुद्ध भी कार्य कर सकती है । इस बात को ध्यान में रखते हुए मजदूर वर्ग की स्वतन्त्र सस्थाएँ भी होनी चाहिए—और समाजवादी समाज में मजदूरसंघों का महत्व सिर्फ सरकार से ही घटकर होगा—जो इस स्थिति में हों कि सत्ताहृद सरकार पर नियन्त्रण

जयप्रकाश की विचारधारा

रख सकें, उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक सकें और जरूरत पड़ने पर उसे बदल सकें ।

इस प्रकार मेरी दृष्टि में समाजवादी भारत का जो रूप है वह आर्थिक एवं राजनीतिक दोनों ही दृष्टियों से पूर्णतः लोकसत्तात्मक होगा । इस लोकतन्त्र में मनुष्य न तो पूँजीवाद का गुलाम होगा न राज्य का, मनुष्य स्वतन्त्र होगा । वह समाज की सेवा करेगा और समाज उसे बदले में जीविका के साधन प्रदान करेगा । किन्तु एक सीमा के भीतर वह अपना धन्य और समाज में अपना पद स्वयं चुनने के लिए स्वतन्त्र होगा । वह अपने विचारों को व्यक्त करने में स्वतन्त्र होगा और उसे अपने नैतिक विकास का पूरा अवसर प्रदान किया जायगा ।

एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य के बीच शारीरिक और मानसिक विकास के अन्तर को छोड़कर और कोई अन्तर न होगा, क्योंकि आमदनी में अधिक अन्तर न होगा ।

समाजवाद—किस रास्ते ?

भारतीय समाजवाद की रूपरेखा क्या होगी, इस सम्बन्ध में मैं लिख चुका हूँ। अब प्रश्न उठता है कि भारत में समाजवाद की स्थापना किस प्रकार होगी।

यह साफ है कि समाजवादी भारत आप ही आप इतिहास के गर्भ से निकल कर नहीं आ कूड़ेगा। आज के भारत और समाजवादी भारत के बीच सन्नान्ति का एक समय होगा। यह समय लम्बा होगा या छोटा यह भीतरी और बाहरी परिस्थितियों एवं समाजवादी नीति की बुद्धिमानी या बेवकूफी पर निर्भर करता है। लेकिन सन्नान्ति काल से हमें गुजरना ही होगा, यह निश्चित है।

इसके पहले मैंने लिखा है—‘यह स्पष्ट है कि सन्नान्ति काल का रूप वर्तमान परिस्थितियों और अन्तिम उद्देश्यों पर यानी समाजवाद की उस रूपरेखा पर निर्भर करेगा जो हमारा लक्ष्य है।’ उस लक्ष्य की रूपरेखा हमने तय कर ली है। पहले उस रूपरेखा को निश्चित कर लेना आवश्यक था क्योंकि हमें कहाँ जाना है यह जान कर ही हम अपनी राह चुन सकते हैं।

खैर, अब हमने अपनी मजिल जान ली और यह भी जान लिया कि हमें कहाँ से शुरू करना है, यानी हमने देश की परिस्थिति भी समझ ली। अब देखना यह है कि वह कौन-सा रास्ता है जो हमें यहाँ से उस आखिरी मजिल तक पहुँचा सकता है। क्या बहुत से रास्ते हैं, जिनमें से किसी एक को हम अपनी मर्जी से चुन ले सकते हैं ? मेरा विश्वास है, सही रास्ता सिर्फ एक ही है। उसके अतिरिक्त दूसरे रास्ते हमें मजिल से दूर कर देंगे ; हमारे लक्ष्य से भटका देंगे। इसलिए हमें समाजवाद तक पहुँचने का रास्ता चुनने में चौकस रहना है।

शान्ति का रास्ता

इस रास्ते के चुनाव में समाजवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स से हमें क्या मदद मिल सकती है, यह देख लें। मजदूरों की पहली अन्तर्राष्ट्रीय मजलिस जब १८७२ में हेग में बैठी तो कार्यपद्धति पर बोलते हुए उन्होंने यों कहा था—
“अपनी नयी सस्था की स्थापना के लिए मजदूरों को एक दिन राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करना ही पड़ेगा। हम जोर देकर नहीं कह सकते कि इस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए एक ही रास्ता होगा। रास्ते के चुनाव के पहले हमें भिन्न देशों की संस्थाओं, प्रणालियों और परम्पराओं पर ध्यान देना होगा। इसमें शक नहीं कि इंग्लैण्ड और अमेरिका ऐसे देश हैं—जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, उन देशों में आपके देश हालैण्ड को भी शामिल किया जा सकता है—जहाँ यह राज-सत्ता शांतिपूर्ण तरीकों से भी प्राप्त की जा सकती है। लेकिन सभी देशों की स्थिति ऐसी नहीं है।” यों मार्क्स ने समाजवाद स्थापित करने के लिए साफ-साफ दो रास्ते बताये हैं। एक है शांति का रास्ता और दूसरा हिंसा का रास्ता। इन दोनों रास्तों में से किसको अपनाया जाय, यह हर देश की परिस्थिति पर निर्भर करता है। इस में प्रजातन्त्र नहीं था,

इस लिए लेनिन ने हिंसात्मक क्रांति के रास्ते को चुना; यद्यपि आज इसपर सन्देह किया जा सकता है कि विधान-परिषद् में अपना बहुमत नहीं देखकर उसे भग कर देने का उनका कार्य कहाँ तक न्यायोचित था। इंग्लैंड में प्रजातन्त्र है और मार्क्स के जमाने की अपेक्षा उसका रूप अधिक विकसित हो चला है। फलतः हम देखते हैं कि वहाँ का मजदूर-दल प्रजातांत्रिक पद्धति से ही सरकार की बीगडोर अपने हाथ में ले चुका है और अपनी समाजवादी योजनाओं को काम में ला रहा है।

भारत में न तो प्रजातन्त्र है और न भारतीय समाज का आधार ही प्रजातन्त्र पर है। भारत में प्रजातन्त्र नहीं है, क्योंकि इस पर अंग्रेजों का राज है, जिस राज का आधार जनता की इच्छा नहीं बल्कि तलवार की ताकत है। यों ही भारत का समाज राजाओं, नवाबों, जमींदारों, कुलीन लोगों, छोटी जाति के लोगों और अन्ततः अंग्रेजों में बँटा हुआ है। ये विभाजन बिल्कुल अप्रजातान्त्रिक है। इसमें प्रजातन्त्र की कहीं भावना भी नहीं है।

पिछले कितने वर्षों से भारत एक स्वतंत्र प्रजातन्त्र की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहा है। इस संघर्ष का हथियार हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस है, यह सब कोई जानते हैं। कांग्रेस के प्रयत्नों से देश आज सफलता के नजदीक पहुँच चुका है, किन्तु अब भी हमें काफी जोर लगाना है। हमें समाजवाद तक किस रास्ते पहुँच सकेंगे, यह बहुत कुछ हमारे इन प्रयत्नों के नतीजों पर निर्भर करता है। अभी यह साफ नहीं हुआ है कि नतीजा क्या होने जा रहा है। फिर हम इस प्रक्रिया के सिर्फ देश के मात्र नहीं हैं बल्कि हमारा उसमें सक्रिय सहयोग है और उसे नतीजों की प्रभावित करने के लिए हमें कुछ नहीं उठा रखा है।

आज की स्थिति में समाजवाद तक पहुँचने के संक्रांति-काल के दो विभाग हैं, यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है। पहला विभाग भारत में एक स्वतंत्र

अजयप्रकाश की विचारधारा

• प्रजातन्त्र की स्थापना तक का है और दूसरा जब हम उस प्रजातन्त्र को समाजवादी प्रजातन्त्र में रूपान्तरित करेंगे, तबके लिए है।

पहले मैं दूसरे ही विभाग को लेता हूँ। मान लीजिये कि भारत में हमने एक पूर्ण प्रजातन्त्र राज्य कायम कर लिया। ऐसे प्रजातन्त्र में यदि हम ऐतिहासिक समताओं पर ध्यान दें और मार्क्स और लेनिन के बताये सिद्धान्तों को मानें, तो निस्सन्देह ही पूँजीवादी वर्ग सबसे ऊपर होगा। ऐसी हालत में श्रमिक वर्ग और शहर एवं देहात के गरीब किस तरह पूँजीपतियों को उस सर्वोच्च स्थान से पदच्युत करके समाजवाद की स्थापना कर सकेंगे? वे प्रजातांत्रिक पद्धति से काम लेंगे या हिंसात्मक क्रांति करेंगे?

जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो प्रजातांत्रिक पद्धति को ही पसन्द करूँगा। याद रखिये, मैंने समाजवाद की रूपरेखा तैयार करते हुए भारत के समाजवाद को प्रजातांत्रिक समाजवाद का रूप दिया था। मार्क्सवाद का यह स्वयंसिद्ध सिद्धान्त है कि समाजवाद प्रजातन्त्र के बिना जीवित रह नहीं सकता। चीन के कम्युनिस्ट नेता माव-से-तुंग का यह कहना कि समाजवाद की स्थापना प्रजातन्त्र के द्वारा ही हो सकती है, गलत है। हिंसात्मक क्रांति और अधिनायकतन्त्र द्वारा भी समाजवादी प्रजातन्त्र के लक्ष्य तक पहुँचा जा सकता है। लेकिन जिस एक ही देश में इसकी परीक्षा की गई है, वहाँ हम कुछ दूसरा नजारा देखते हैं। रूस में आज जो राज्य है, वह एक पूरा नौकर-शाही राज्य है। वहाँ प्रजातन्त्र बिल्कुल नहीं है। मैं इतिहास में सबक लेने का हामी हूँ। अगर भारत के समाजवादी आन्दोलन को प्रजातन्त्रात्मक पद्धति के इस्तेमाल की आजादी न हो, तो फिर पूँजीवादी शासन को नाश करने का सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता है और वह रास्ता है हिंसात्मक क्रांति और अधिनायकतन्त्र का। लेकिन मैं अभी इस धारणा पर चल रहा हूँ कि भारत में पूर्ण प्रजातन्त्रात्मक राज्य की स्थापना हो सकती है। हमने देखा है कि १८७२

समाजवाद—किस रास्ते ?

ई० मे ही, जब कि राजनीतिक प्रजातंत्र अपने पूरे विकास पर नहीं पहुँच पाया था, मार्क्स ने समाजवाद तक पहुँचने के लिए शांतिमय सम्राटिकाल की भी कल्पना की थी। तबसे जो सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, यदि हम उन्हें ध्यान में रखें, जैसा कि मार्क्सवादी होने के कारण हमारे लिए यह कर्तव्य हो जाता है, तो हमें मार्क्स के विचारों को दृढ़तापूर्वक स्वीकार करना चाहिये। मार्क्स के जमाने की अपेक्षा आज राजनीतिक प्रजातंत्र ज्यादा प्रजातन्त्रात्मक हो चुका है और पूँजीवाद की आर्थिक, राजनैतिक और सैद्धान्तिक शक्तियाँ यूरोपीय देशों में विलकुल खोखली हो चुकी हैं और इंग्लैण्ड में तो उनकी और भी बुरी हालत है। दूसरे, ससार के सभी बड़े-बड़े हिस्सों में समाजवाद और मजदूरवर्ग की ताकत उन्नति की ओर है और बहुत से देशों में प्रजातन्त्रात्मक समाजवादी पार्टियाँ राज्यसिंहासन पर आरुढ़ हैं। यहाँ तक कि प्रजातंत्र पर विश्वास न रखते हुए भी कम्युनिस्ट पार्टियाँ प्रजातन्त्रात्मक साधनों का प्रयोग कर रही हैं, कम से कम शब्दों के द्वारा ही सही, अधिनायकतंत्र को बुरा बता रही हैं। फ्रांस की कम्युनिस्ट पार्टी अपने देश की सबसे बड़ी पार्टी होने पर भी वहाँ की विधान-परिषद् में शामिल हुई और प्रजातन्त्रात्मक विधान को काम में लाने में हिस्सा बँटा रही है। हमारे देश में जैसा हमने मान लिया है, यदि पूँजीवादी वर्ग प्रजातन्त्रात्मक राज की गद्दी पर बैठ रहा हो, तो भी उसमें वह ताकत न होगी, जो इंग्लैण्ड या अमेरिका के पूँजीपति-वर्गों में है। यहाँ का पूँजीवाद बहुत ही कमजोर होगा। उसमें इतनी ताकत नहीं होगी कि वह पूँजीवाद के ढाँचे में देश की आर्थिक समस्याओं को हल कर सके। इस स्थिति से समाजवाद के लिए काम करनेवाली शक्तियों को बल मिलेगा। एक और भी पहलू है जो इस देश में काम करेगा। यों तो हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन में भिन्न-भिन्न वर्गों के लोग शामिल हैं, किन्तु वह प्रमुखतः किसानों और शहरी

संयमकाय की विचारधारा

बाबूदल का प्रतिनिधित्व करता है। यदि हम सिर्फ नेतृत्व पर ही ध्यान न दें तो मेरे इस कथन की सच्चाई स्पष्ट हो जायगी। जब मैंने यह मान लिया था कि पूँजीपति वर्ग के हाथ में राजसत्ता आ गई तो उसके साथ ही मैंने यह भी मान लिया था कि राजसत्ता उसने राष्ट्रीयता की तरंगों पर खेल कर ही हासिल की है। इसके अतिरिक्त, भले ही यह सम्भव हो या न हो, ऐसा नेतृत्व राष्ट्रीय ताकतों का उपयोग करते समय आपसे आप ऐसी जिम्मेदारियों के भेरे में फँस जायगा, जिसका निर्वाह वह अपने स्वार्थों के साथ वफादार रह कर नहीं कर सकता। नतीजा यह होगा कि जनता का भ्रम दूर होता जायगा और समाजवाद की शक्तियों को अधिक से अधिक बल मिलता जायगा। पूँजीवाद जब सत्तार में एक वर्धमान शक्ति था तब वह राष्ट्रीय नेतृत्व के योग्य अपने को मुश्किल से बना सका था। आज का पूँजीवाद तो हास की ओर बढ़ रहा है। भला किस तरह वह उस काम को सम्पन्न कर सकेगा ?

इन बातों से मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि यदि हिन्दुस्तान में पूर्ण प्रजातन्त्र की स्थापना हो जाती है तो हमें शान्तिमय प्रजातन्त्रात्मक पद्धतियों से ही समाजवाद तक पहुँचना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि हिन्दुस्तान की समाजवादी पार्टी को—सोशलिस्ट पार्टी का विकास उस ओर हो रहा है—चुनाव में शामिल होकर, वोटों से जीत कर राजसत्ता और व्यवस्थापिका सभाओं पर कब्जा करना चाहिए और कानून बनाकर पूँजीवाद के नाश और समाजवाद की सृष्टि का प्रयत्न करना चाहिए।

दूसरा रास्ता

एव हम हिन्दुस्तान में पूर्ण प्रजातन्त्र स्थापित करने के प्रयत्न को लें। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, कांग्रेस के नेतृत्व में पिछले वर्षों प्रजातन्त्र की स्थापना के लिए जो हमने लड़ाइयाँ लड़ीं, वे अब सफलता के निकट पहुँच

चुकी हैं। किन्तु साम्राज्यवादी शक्ति मुस्लिम लोग और देशी राजे अपने इन दो बाजुओं के सहारे मजबूती से हमारा रास्ता रोके खड़ी हैं। ऐसी हत्की-फुत्की बातें कि अंग्रेज सही माने में हिन्दुस्तान छोड़ने का तय कर चुके हैं, बिल्कुल लगी हैं और जनता को ठगने के लिए की जाती हैं। क्योंकि जनता को यह डर है कि हम उसके रास्ते के कांटे चुनने के बदले कहीं ऐसे समझौते में न फँस जायें जो उसकी आजादी और प्रजातन्त्र को ही खतरे में डाल दे। कांग्रेस ने इंग्लैंड द्वारा भेजे गये उसके मन्त्रिमण्डल के शिष्ट मण्डल का प्रस्ताव स्वीकार कर के विदेशी सत्ता और सम्प्रदायवाद तथा देशी सामंतशाही से ऐसा समझौता कर लिया है जिसका असर दूर तक जा सकता है। जिस भारतीय प्रजातन्त्र का आधार समझौता होगा, उसे पूर्ण प्रजातन्त्र नहीं कह सकते, जिसकी कल्पना मैंने ऊपर की है, और जिस प्रजातन्त्र में शांतिमय तरीके से भी समाजवाद तक पहुँचना मैंने सम्भव मान लिया है।

अंग्रेजी राज में प्रजातन्त्र नहीं है, देशी रियासतों में प्रजातन्त्र नहीं है, सम्प्रदायवाद में प्रजातन्त्र नहीं है। ये तीनों प्रजातन्त्रविरोधी शक्तियाँ हमारे सामने खड़ी हैं। तीनों के मिलने से उनकी सम्मिलित ताकत कहीं बढ़ गई है। हम इन प्रतिक्रियावादी ताकतों पर किस तरह विजय प्राप्त कर सकते हैं ? उनसे दबकर उन्हें सहूलियतें दे देकर हम उन्हें काबू में कर नहीं सकते। हमारे राष्ट्रीय नेताओं का यह विश्वास है कि इन शक्तियों से समझौते करके इतनी बड़ी राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर ली जा सकती है कि हम बाद में प्रजातन्त्र के दुश्मनों का नाश कर सकेंगे। लेकिन यह भुला दिया जाता है कि इस तरह से जो राजनीतिक सत्ता प्राप्त की जायगी उसकी बागडोर सिर्फ राष्ट्रीयता और प्रजातन्त्र के ही हाथों में नहीं रहेगी, बल्कि प्रतिक्रियावादी ताकतों का भी उसमें हिस्सा होगा। राजसत्ता में हिस्सेदार होकर ये शक्तियाँ मजबूत ही होगी, कमजोर नहीं। हाल का इतिहास हमें बताता है कि सम्प्रदायवाद के

जयप्रकाश की विचारधारा

साथ जैसे-जैसे हमने रियायतें कीं, त्यों-त्यों वह मजबूत ही होता गया और आज वह भयानक राक्षस के रूप में खड़ा है। भविष्य में जो सहूलियतें दी जायेंगी, उनका नतीजा इसके उल्टा होगा, इसकी कोई दलील हमारे पास नहीं। बल्कि खतरा यह है कि अपने राष्ट्रीय जीवन के मौलिक सिद्धांतों के साथ समझौता करके हम एक ऐसे बीमार और रोगी भारत का जन्म देंगे जिसके लिए जिन्दगी और उसके लुटफ हराम ही साबित होंगे। वैसी हालत में एक बहुत बड़ी क्रांति ही उसे फिर से तन्दुरुस्त जिन्दगी दे सकेगी।

तो प्रतिक्रियावादी ताकतों और प्रजातन्त्र के दुश्मनों को हराने का कौन-सा रास्ता है? रास्ता सिर्फ एक है। हम 'भारत छोड़ो' की मांग को फिर से ऊपर लावें और विदेशी हुकूमत के साथ आखिरी लड़ाई लड़ने को जनता का आह्वान करें और उसका सघटन करें। यह विदेशी हुकूमत ही हमारा पहला और प्रमुख दुश्मन है, और यही हमारे देश की प्रतिक्रियावादी ताकतों को उभाड़ती और सहायता देती है। इसलिए पहले हम इस हुकूमत का ही नाश करें। यह बहुत मुमकिन है कि अपने अस्तित्व पर खतरा आया हुआ देखकर यह हुकूमत अपने दोस्तों को अपने साथ जुटाये। लेकिन हमें इस खतरे का सामना करना ही है। आज भी जब हम समझौते और सहूलियतों की बातें कर रहे हैं तो वही चाल चली जा रही है और आजादी और प्रजातन्त्र की ताकतों को कुचलने और गला घोटने की कोशिशें हो रही हैं। हमें यह मानना चाहिये कि उसकी चालें कुछ अंशों में सफल हो रही हैं और आजादी और प्रजातन्त्र खतरे में पड़ते जा रहे हैं। मेरा यह पक्का यकीन है कि जब हम अंगरेजी हुकूमत से सीधी लड़ाई छेड़ देंगे तब उसकी ऐसी हरकतें उस पैमाने पर कामयाब नहीं हो सकेंगी जैसे आज हो रही हैं। मुमकिन तो यह है कि वे बिल्कुल ही नाकामयाब साबित हों।

मेरा विश्वास है कि क्रांति की आग में ही साम्राज्यवाद अपने दोनों

सहायका—साम्प्रदायवाद और सामन्तवाद के साथ जल जायगा, दूसरा कोई चारा नहीं है ।

मैं यह साफ देख रहा हूँ कि समाजवाद तक पहुँचने के पहले एक बड़ी क्रान्ति का होना लाजिमी है । साथ ही मैं यह भी देख रहा हूँ कि उस क्रान्ति के सफल होने के लिये सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य ही नहीं, बल्कि सामाजिक उद्देश्य भी हमारे सामने रहना चाहिये । यह एक प्रकट सत्य है कि क्रान्ति के सफल होने के लिये उसके झण्डे पर सिर्फ “भारत छोडो” ही लिखना काफी नहीं होगा । उस क्रान्ति के झण्डे पर कुछ और भी उद्देश्यों की घोषणा हो—जैसे “जो जोते, उसकी जमीन” “जो पैदा करे, उसका धन” “देशी रियासतों में प्रजा-राज्य कायम हो” आदि । क्रान्ति की सेना में किसानों, कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों, विद्यार्थियों, शहर के गरीब और मध्यवित्त लोगों की बड़ी से बड़ी जमात का शामिल होना जरूरी है । ऐसी क्रान्ति हिन्दुस्तान में सिर्फ प्रजातंत्र ही नहीं कायम करेगी बल्कि वह हमें समाजवाद के रास्ते पर भी बहुत दूर तक ले जायगी । ऐसी क्रान्ति के बाद जो प्रजातंत्र बनेगा, उस पर पूँजीपतियों का बोलबाला न होगा, जैसा कि मैंने कल्पना की थी, बल्कि मेहनत करनेवाले वर्गों और मध्यवित्त लोगों का ही उस पर दबदबा रहेगा । ऐसी क्रान्ति एक ही झटके में पूँजीवाद का नाश तो नहीं करेगी, लेकिन उसे इतना कमजोर बना देगी कि वह पनाह माँगता फिरेगा ।

ऐसी क्रान्ति किस तरह की जा सकती है ? क्या आज की जो हालत हैं उसे देखते हुए ऐसी क्रान्ति की अनिवार्यता पर विश्वास किया जा सकता है ? मैं तो इस पर विश्वास करता हूँ । हिन्दुस्तान आज एक क्रान्तिकारी दौर से गुजर रहा है । जनता में असन्तोष है, किसानों, मजदूरों और देशी राज्य की प्रजाओं में असन्तोष है । देश के नवयुग वैचैन हैं । अँग्रेजों की चाल-

जयप्रकाश की विचारधारा

राजियों पर चारों ओर गुस्ता और हेकारत फैली हुई है। दंगों और आपसी खून खराबियों से लोग ऊब उठे हैं। कमी है तो सिर्फ इस बात की कि क्रान्ति की इन शक्तियों को इकट्ठा नहीं किया जा रहा है।

अब तक कांग्रेस ही हमारी राष्ट्रीय क्रान्ति का नेता रही है, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि कांग्रेस के नेतृत्व ने निश्चित रूप से क्रान्ति की ओर से मुंह मोड़ लिया है; ज्योंही क्रान्ति का नाम लीजिये, हमारे नेताओं की खोरियाँ बदल जाती हैं और वे उसके नाम लेनेवालों की खिल्ली उड़ाने और नीचा दिखाने से भी बाज़ नहीं आते। नेताओं के इस व्यवहार का असर सारे कांग्रेस संगठन पर पड़ता है और यह भी साफ है कि यह संगठन तो आज कांग्रेस सरकारों का पुच्छला मात्र रह गया है। इतने पर भी वास्तविकता यह है कि अंग्रेजी राज्य के खिलाफ राष्ट्रव्यापी संघर्ष तभी शुरू किया जा सकता है जब कांग्रेस उसकी शुरुआत करे।

इस तरह हम एक कठिन परिस्थिति में फँसे हुए हैं। जो कांग्रेसजन क्रान्तिकारी संघर्ष पर विश्वास रखते हैं, उन्हें दो काम करने पड़ेंगे:—

(१) जनता को कांग्रेस-संगठन द्वारा (जहाँ सम्भव हो) और मजदूर संघों, किसान, समाजों, छात्र संघों और स्वयंसेवक दलों आदि द्वारा क्रान्तिकारी संघर्ष के लिए तैयार करना। (२) कांग्रेस पर भीतर से ज्यादा दबाव डालना ताकि वह क्रान्तिकारी पथ पर चलने को मजबूर हो। यह संभव है कि इस दूसरे काम में हमें सफलता न मिले, लेकिन जहाँ तक निकट भविष्य को मैं समझ सका हूँ, मेरा विश्वास है कि १९४२ की ही तरह फिर कांग्रेस को क्रान्ति के पथ पर आना ही पड़ेगा। इसलिए कांग्रेस के कर्णधारों से हमारे विचारों को सहायता मिले या न मिले हमें उस घड़ी के लिए तैयार रहना चाहिए।

मैं ऊपर कह चुका हूँ कि हमारी क्रान्ति की सफलता का दारुमदार

समाजवाद—किस रास्ते ?

इस बात पर है कि वह जनता की आर्थिक और सामाजिक जरूरतों का कहां तक प्रतिनिधित्व करती है । इसलिए समाजवादी कांग्रेसजनों, खास कर सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों का यह कर्तव्य है कि उस क्रान्ति की तैयारी करने के सिलसिले में जनता की सामाजिक चेतना को जाग्रत करने और उनकी वर्ग-संस्थाओं एवं संघों को जो-दार बनाने पर खास ध्यान रखें क्योंकि संघों के द्वारा ही वर्गचेतना प्रस्फुटित और प्रतिष्ठित होती है ।

कांग्रेस को राष्ट्रीय क्रान्ति का अलमबरदार रहना ही है । यह खुशी की बात है कि वह धीरे-धीरे जनता की आर्थिक बेजबानी को समझ रही है । मेरठ कांग्रेस ने सामाजिक उद्देश्यों के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव पास किया है वह बहुत दूर तक समाजवाद की राह पर हमें ले जा सकता है । लेकिन कठिनाई यह है कि कांग्रेस का वह हिस्सा जो उसपर सबसे ज्यादा प्रभाव रखता है और जो अन्दर से तो पूँजीवादी विचारों से प्रेरित होता है किन्तु जो महात्माजी के नाम की आड़ में मनमानी करता है, वह कांग्रेस की सामाजिक उद्देश्योंवाली घोषणाओं का उपयोग जनता को अपने काबू में रखने और उसकी सहायता न खो देने के लिए ही करता आया है । यदि हम केन्द्र और प्रांतों में स्थापित कांग्रेस-सरकार के कार्यों को देखें तो हमें यह नहीं पता चलता कि कांग्रेस की घोषणाओं और प्रस्तावों में निर्धारित उसकी सामाजिक और आर्थिक नीति का कोई असर इनपर है । हो सकता है कि कहीं शब्दों में आप पा भी जायें, लेकिन उनके कार्यों में ऐसी कांग्रेस नीति की अनिवार्यता का कोई भी प्रमाण पाना आपके लिए मुश्किल होगा । इसलिए समाजवाद तक पहुँचने के रास्ते का निर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित करने में सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि कार्यों में, समाजवादी आंदोलन को कहां तक सफलता मिलती है । यह प्रभाव ज्यादा से ज्यादा हम किस तरह डाल सकते हैं । कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी

जयप्रकाश की विचारधारा

इस उद्देश्य की पूर्ति, कांग्रेस के भीतर और बाहर काम करके करती आई है। किन्तु अब तो राष्ट्रीय आंदोलन और समाजवादी आंदोलन को पृथक करने की आवाज भी उठने लगी है। यदि अंग्रेजों से खुली लड़ाई लेने की सम्भावना नहीं होती और इस लड़ाई में अन्ततः कांग्रेस के घसीटकर आ जाने की सम्भावना नहीं होती और इस बात की सचाई में शक होता कि कांग्रेस के द्वारा ही राष्ट्रीय संग्राम छेड़ा जा सकता है न कि उसका विरोध करके तो मुझे यह सलाह देने में जरा भी हिचकिचाहट न होती कि समाजवादी आंदोलन को कांग्रेस से अपना पिण्ड छुड़ा लेना चाहिये। किन्तु ये सम्भावनाएँ और ये विचार ऐसे कदम उठाने से हमें रोकते हैं—क्योंकि ऐसा करना, खतरों की क्या बात, सर्वनाश तक को बुला सकता है। किन्तु जब हम यह देख लेंगे कि कांग्रेस ने क्रांतिकारी रास्ते को छोड़ दिया है और किसी भी तरह के समझौते की कीमत पर भी वह सरकारी गद्दियों पर बैठे रहने का निश्चय कर चुकी है तो फिर हमारे लिए यह लाजिमी हो जायगा कि हम उसका साथ छोड़ दें। ऐसी हालत में कांग्रेस दिन-ब-दिन स्थिर स्वार्थियों की मुद्रियों में आती जायगी और उसका ढांचा कठोर और अप्रजातान्त्रिक होता जायगा जिसके अन्दर समाजवादी शक्तियों के विकास की गुंजाइश ही नहीं रह जायगी। इन दोनों सम्भावनाओं को मद्देनजर रख कर ही हमें आगे बढ़ना है।

टेढ़े-मेढ़े रास्ते !

इस छानवीन के बाद यह साफ हो जाता है कि समाजवाद तक पहुँचने का रास्ता सीधा-सादा नहीं है। कितनी ही मोड़ों और चौराहों को हमें पार करना है। इसलिए समाजवाद का संक्रान्तिकाल वैसा होगा और उनमें हनें किन नीतियों का पालन करना होगा—इसके बारे में हमें कौरा सिद्धांतवादी नहीं होना है। प्रजातान्त्रिक समाजवाद में अपना

समाजवाद—किस रास्ते ?

विश्वास मैंने फिर से दुहराया है ! मैं उसे ही सच्चा समाजवाद मानता हूँ । मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि अवाधपूर्ण प्रजातन्त्र में मैं समाजवाद तक पहुँचने के लिए प्रजातान्त्रिक पथ को ही पसन्द करूँगा । लेकिन आज तो हम अप्रजातान्त्रिक या प्रजातन्त्र-विरोधी शक्तियों से ही घिरे हुए हैं और इन्हें बिना हराये और बिना नाश किये समाजवाद का सपना ही नहीं देखा जा सकता है । इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें सघर्षों और उत्पातों से भरे सक्रान्ति काल से गुजरना पड़े । हमें एक ऐसे क्रान्तिकारी दौर को पार करना पड़े जिसके दम्यान हम प्रजातान्त्रिक क्रान्ति को तो पूरा कर लेंगे ही, समाजवाद की ओर भी काफी कदम बढ़ा चुके होंगे । इस तरह क्रान्ति को आग में स्नान कर जो राज्य या समाज हमारे देश में उदित होगा, उसी में प्रजातान्त्रिक पद्धति से हम पूरे समाजवाद की स्थापना कर लेंगे ।

विकास की इस योजना में कितने तरह की गड़बड़ियाँ पैदा हो सकती हैं । जिस क्रान्ति की हमने कल्पना की है वह आ भी न सके और हमारे श पर अनियंत्रित शासन ही लाद दिया जाय । ऐसी हालत में प्रजातान्त्रिक रीकों की चर्चा भी फिजूल होगी । एक नये क्रिम की क्रान्ति करनी पड़ेगी, जिसका नेतृत्व समाजवादी शक्तियाँ करेंगी और जिसे भिन्न-भिन्न वर्ग मदद पहुँचायेंगे । ऐसी हालत में हिन्दुस्तान में सभी समाजवादी शक्तियों के सकलन से सगठित एक स्वतन्त्र भारतीय समाजवादी पार्टी की स्थापना आवश्यक होगी । यह भी सम्भव है कि आने वाले समय की गड़बड़ियों से फायदा उठा कर हमारे देश की पूँजीवादी, समान्तवादी और सम्प्रदायवादी शक्तियाँ एक साथ मिलकर आगे बढ़ें और राष्ट्रीय आंदोलन के दक्षिणपक्ष से मिल कर एक तानाशाही राज्य कायम कर लें । उस परिस्थिति में प्रजातन्त्र के तरीके किसी काम के नहीं होंगे । उस समय सिर्फ एक ही चारा रह जायगा कि हम इस प्रतिक्रियावादी आक्रमण के खिलाफ क्रान्तिकारी शक्तियों को लेकर खड़े

जयप्रकाश की विचारधारा

हैं और श्रमिक जनता को अधिनायकतंत्र कायम करें। लेकिन यह अधिनायकतंत्र भी किसी पार्टी या मजदूर वर्ग का नहीं होगा, बल्कि सारे मजदूरों किसानों और शहरी गरीबों का अधिनायकतंत्र होगा। दूसरी हालतों में हम दूसरे तरीकों, दूसरे हलों से काम करना पड़ेगा।

मैंने शुरू में कहा था कि अपने लक्ष्य तक पहुँचने का हमारे लिए सिर्फ एक रास्ता है। फिर ये तरह-तरह के रास्ते बता कर क्या उस बात का खंडन हमने स्वयं नहीं कर दिया है? सच बात तो यह है कि एक निश्चित परिस्थिति में सही रास्ता भी एक ही हो सकता है। लेकिन बदलती हुई परिस्थितियों में भी हम उसी निश्चित रास्ते पर चलते जायें तो हम अपने उद्देश्य के निकट नहीं बल्कि सर्वनाश के निकट पहुँच जायेंगे। हमने ऊपर जो कुछ भी लिखा वह एक निश्चित परिस्थिति की कल्पना करके। अपने विचारों को स्थिरता से रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक था। लेकिन हम किसी प्रयोगशाला की बंधी हुई हालतों की तरह समाजवाद का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने उद्देश्यों पर ध्यान रखते हुए और अपने मौलिक सिद्धांतों से दूर न होते हुए हमें बदली हुई परिस्थिति की माँग के मुताबिक अपने रास्ते और तरीके में अंदोल बदल करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं जानता हूँ कि इस रास्ते पर खजों और खतरों की कमी नहीं किन्तु कठोर सिद्धांतवादी बने रह कर सर्वनाश कर लेने की अपेक्षा खतरों का सामना करना कहीं अच्छा है।

संक्रान्ति काल में समाजवाद जो भी रूप ले, अन्त में मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि समाजवाद की स्थापना के लिए सब से आवश्यक चीज़ है एक मजबूत समाजवादी पार्टी जिसे मजदूरों, किसानों, नौजवानों, (स्वयं-सेवक और विद्यार्थी) एवं शहर के गरीबों का पूरा समर्थन और सहयोग प्राप्त हो। एक छोटी-सी शुरुआत से सोशलिस्ट पार्टी आज की इस ताकत

समाजवाद—किस रास्ते ?

और असर को हालत में पहुँचो है । सोशलिस्ट पार्टी ही इस देश में समाज-वाद की एक मात्र पार्टी है । यही भविष्य की पार्टी है । देश की ही तरह सोशलिस्ट पार्टी भी सन्नान्ति काल से गुजर रही है और उसे उस ऊँचाई तक पहुँचना है जहाँ वह देश की पीड़ित और दलित जनता की राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व कर सके ।

मार्क्सवाद : अनुभव से छन कर .

लोग मुझसे पूछते हैं क्या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी मार्क्सवादी दल है ? वे जानना चाहते हैं कि वह मार्क्सवादी समाजवाद को मानती है या गांधीवादी समाजवाद को । मेरा उत्तर है कि हम मार्क्सवादी दल के हैं और मार्क्सवादी समाजवाद को मानते हैं । लेकिन मुश्किल तो यह है कि केवल मार्क्सवाद कहने से ही आज किसी के विचारों का पूरा पता नहीं लगता । मार्क्सवाद के नाम पर कम्युनिस्टों और रायवादियों ने न जाने क्या-क्या किया है । ट्राट्स्की के अनुगामी भी जो दो दलों में बँट गये हैं, अपने को मार्क्सवादी कहते हैं । हिन्दू धर्म की तरह आज मार्क्सवाद का कुछ भी अर्थ निकाला जा सकता है । इसलिए अब पुराने नारों को दुहराते रहना बेकार है । हमें मार्क्सवाद की अपनी व्याख्या करनी पड़ेगी । इसमें हमें अपने अनुभवों और व्यावहारिक परिस्थितियों का सहारा लेकर चलना होगा । हमारे देश में किसानों की आवादी काफी बड़ी है और हमारा किसान वर्ग अत्यन्त दरिद्र है । इसलिये यह स्पष्ट है कि हमारे समाजवाद पर कृषकवर्ग का छाप

होनी चाहिये और उसमें उनकी आर्थिक और राजनीतिक आकांक्षाओं का प्रकट होना अनिवार्य है। इसलिए आज हमारे समाजवाद की रूपरेखा कृषक समाजवाद की होगी।

मैं मार्क्स को मानता हूँ। मैं अपने को मार्क्सवादी कहता हूँ। मैं स्टालिन तथा कितने ही अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अच्छा मार्क्सवादी हूँ। यह केवल मैं यों ही नहीं कह रहा हूँ। मैं इसे जोर के साथ कहता हूँ। मार्क्सवाद मेरे विचार का आधार है। किन्तु मार्क्सवाद को मैं एक विज्ञान मानता हूँ। विज्ञान दर्शन की भाँति सत्य की शोध करता है और सत्य सापेक्ष वस्तु है।

कोई व्यक्ति ऐसे सत्य के पाने का दावा नहीं कर सकता जो सदा के लिए सत्य हो। हम लोगो ने संपूर्ण सत्य को न पाया है, न पा सकते हैं। एंगल्स का, जिसने इस सिद्धांत की विवेचना बड़ी ही योग्यता से की है, कहना है कि हम लोग सापेक्ष सत्य तक ही पहुँच सकते हैं। सापेक्षिक सत्य से हम लोग असत्य को निकाल देते हैं और इस प्रकार पूर्ण सत्य तक पहुँचते हैं। इसी तरह से ज्ञान की वृद्धि होती है, सभी विज्ञानों की अभिवृद्धि होती है।

डार्विन, जो मार्क्स का समसामयिक था, एक बड़ा वैज्ञानिक था। अमेरिका में मेरे जीवशास्त्र के प्रोफेसर डार्विन की 'जीव की उत्पत्ति' नामक पुस्तक को महत्व में बाइबिल के बाद दूसरा स्थान देते थे। लेकिन आज उसके विकासवाद का सिद्धांत अमान्य कर दिया गया है। उसकी आधारभूत मान्यताएँ अब प्रामाणिक नहीं मानी जातीं। फिर भी विज्ञान के क्षेत्र में उसका स्थान अप्रतिम है। विकासवाद के सिद्धांत के लिए विज्ञान उसका आभारी है। तत्कालीन मानव विज्ञान के ज्ञान के आधार पर एंगल्स ने "कुटुम्ब की उत्पत्ति—व्यक्तिगत सम्पत्ति और राज" नाम पुस्तक लिखी थी।

जयप्रकाश की विचारधारा

युस्वखा कबीले के बीच रहकर लुहस मार्गन ने जो खोज की थी, वही उसका आधार थी। किन्तु आज के मानव-विज्ञान-वेत्ता मार्गन की खोज को स्वीकार नहीं करते।

अगर ऐंगत्स आज जीवित होता तो वह अपने कुछ अनुयायियों की तरह न विचारता, न सोचता। उसको अपनी उक्तियों में सुधार करना पड़ता। किन्तु उसकी और मार्क्स की विचारधारा की पहुँच और पद्धति में कोई परिवर्तन न होता। इतिहास के समझने और समझाने में उसका उपयोग हमें अवश्य करना है। वर्तमान ज्ञान और विज्ञान की प्रगति के आधार पर हम लोगों को हिन्दुस्तान में अपनी रीति से मार्क्सवाद को व्यक्त करना चाहिए।

यद्यपि जो पद्धति मार्क्स ने प्रतिपादित की है, वह अब तक सत्य है, तथापि उसकी कुछ स्थापनाओं तथा भविष्यवाणियों में आज सुधार करना होगा। उदाहरणार्थ, मार्क्स ने सोचा था कि मध्यम श्रेणी सामाजिक विकास के दौरान में समाप्त हो जायगी और सामाजिक कार्यों में उसका कोई महत्व न रह जायगा। इतिहास ने उस मान्यता को गलत सिद्ध किया है। किसान, जो मध्यम श्रेणी में गिना जाता है, अमेरिका जैसे अत्यन्त औद्योगिक और पूँजीवादी देश में भी एक बहुत बड़ी सामाजिक आर्थिक ताकत है।

इसके सिवा डॉक्टरों, इंजीनियरों, कारीगरों, अव्यापकों, सेक्समैनों, कमीशन एजेण्टों और अन्य सफेद पोश लोगों आदि को मिलाकर एक नये मध्यम वर्ग का उदय हुआ है। इन परिस्थितियों में वर्ग शक्तियों और वर्ग सन्तुलन के विवेचन में मध्य वर्ग की उपेक्षा करना सम्भव नहीं है। यदि हम लोग वैसा करते हैं तो असफल होंगे।

सोवियत रूस के अनुभव

तब मजदूर अधिनायकत्व की समस्या आती है। मैं इसमें विश्वास करता था, और अब भी विश्वास करता हूँ। किन्तु इससे मेरा क्या मतलब है, ऐसे

स्पष्ट कर दूँ। मजदूरों का अधिनायकत्व पूँजीवाद को समाजवाद में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक है। यह प्रारम्भिक अवस्था की चीज है, यह समाजवाद की निर्माणावस्था के लिए लागू है। जब समाजवादी व्यवस्था स्थापित हो जाती है, जब समाजवादी समाज का अस्तित्व कायम हो जाता है तब दैसा नहीं होना चाहिए। सोवियत रूस में अब केवल एक वर्ग है और इसलिए वहाँ तानाशाही के स्थान पर प्रजातांत्रिक सरकार स्थापित होनी चाहिए।

जिन दिनों वहाँ वर्गसंघर्ष चल रहा था और पुराने शासक वर्ग को हटाने के लिए तानाशाही की आवश्यकता थी, उन दिनों भी क्या जरूरी था कि रूस में सिर्फ एक पार्टी—कम्युनिस्ट पार्टी रही होती? अमेरिका में जहाँ पूँजीवादी सरकार अब भी मजबूत है वहाँ पूँजीपतियों की दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियाँ हैं। उसी प्रकार मजदूर वर्ग में भी एक से अधिक दल हो सकते हैं। इस लिए रूस कम्युनिस्ट पार्टी के अतिरिक्त मजदूरों के अन्य दलों को क्यों नहीं पनपने देता? किसी देश में एक से अधिक दलों के रहने पर ही प्रजातांत्रिक प्रणाली का अस्तित्व रह सकता है।

आज का रूस एक विस्तृत वन्दीगृह है। आज रूस में किसी ऐसी आलोचना या सूचना का जो सोवियत सरकार नहीं चाहती पूर्ण अभाव मिलेगा। रूस के बाहर भी सोवियत नेताओं की नीतियों की टीका टिप्पणी रूस की जनता नहीं कर पाती। आज रूस में वहाँ की जनता अपने विचारों को आपस में भी व्यक्त नहीं कर सकती। यह असह्य है। ऐसी तानाशाही का अस्तित्व यह प्रकट नहीं करता है कि इस देश में वर्गों का मिटाना बाकी है। आज के रूस में वे सभी एक या दूसरे प्रकार के मजदूर हैं, इसलिए साधारणतः उनका एक ही वर्ग है। आज उस देश में तानाशाही का अस्तित्व यह प्रकट करता है कि मजदूरों का एक हिस्सा दूसरे हिस्से पर तानाशाह बन बैठा है। एक नये शासक वर्ग का उदय हुआ है, जिसमें पार्टी के अधिकारी वर्ग, प्रबन्धक वर्ग, सेना संचालक और सिविल सर्विस के लोग इत्यादि सम्मिलित

जयप्रकाश की विचारधारा

हैं। वे परोक्ष रूप से सरकार का नियंत्रण करते हैं। इस प्रकार रूस में शक्ति एक दल-विशेष के हाथ में चली गई है।

यह रूस में नौकरशाही की वृद्धि एक नयी स्थायी सेना की स्थापना तथा एक नये शासक वर्ग के उद्भाव का द्योतक है। इससे राज्य के समाजवादी स्वरूप पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा। यह मार्क्सवाद को भ्रष्ट करना है। आज का रूस समाजवादी राज्य नहीं है, अपितु वह समाजवादी आर्थिक आधार पर स्थित एक राष्ट्रीय राज्य है। ठीक ठीक मार्क्सवादी पद्धति का अनुसरण करने पर आज के रूस को पूर्ण रूप से प्रजातान्त्रिक राज्य हो जाना चाहिए था और उसे साम्यवाद की अन्तिम अवस्था में प्रवेश करने की तैयारी करते नजर आना चाहिए था, जिसमें राज्य समाप्त होने की प्रक्रिया भी सम्मिलित होती। ऐसा न होकर वहाँ तानाशाही का बोलबाला है। कोई नहीं जानता कि राज्य कब नष्ट होगा अथवा यह कभी होगा या नहीं।

निस्संदेह यह तब तक नहीं होगा जब तक उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि नहीं होती, जब तक परिपूर्णता नहीं स्थापित होती। केवल ऐसे समाज में ही 'प्रत्येक को आवश्यकतानुसार दिया जाय और उससे योग्यता के अनुसार काम लिया जाय' के सिद्धांत के अनुसार कार्य किया जा सकता है। यह विचार महात्मा गांधी और समाजवादियों को समान रूप से ग्राह्य है। महात्मा गांधी राज्यहीन और वर्गहीन समाज के आदर्श को स्वीकार करते हैं। गांधीजी और लेनिन दोनों इस विषय में एकमत हैं। लेकिन सोवियत रूस में जैसी तानाशाही है उसका तो गांधीजी विरोध ही करेंगे। क्या मार्क्सवादी होने के नाते हम लोग इसका इस रूप में समर्थन करने के लिये बाध्य हैं? कुछ परिस्थितियों में क्या यह संभव नहीं है कि समाज को एक ऐसे निरपेक्ष शासकवर्ग के हाथों में सौंपे बिना ही पूँजीवाद के स्थान पर समाजवाद को प्रतिष्ठित किया जा सके—ऐसा शासकवर्ग जिसमें सबके सब मजदूर वर्ग के भी

नहीं हों, बल्कि जिसमें नौकरशाही तथा एक नयी स्थायी सेना भी शामिल हो।

परमाणु ज्ञान के इन दिनों में हमारे सामाजिक साधन अत्यधिक बढ़ गये हैं। अपने बड़े हुए साधनों के सदुपयोग से हम लोग निकट भविष्य में अपने समाज को पूरा पूरा बदल सकते हैं। हम लोग परिपूर्णता का युग स्थापित कर सकते हैं। यह सत्य है कि जनसंख्या भी बढ़ती जा सकती है और उससे वैसा होना कठिन हो जा सकता है। किन्तु जनसंख्या की वृद्धि नियंत्रित की जा सकती है। हाल के यूरोपीय अनुभव इस प्रकार की आशाओं का समर्थन करते हैं। हमें अपने सामाजिक विकास को इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि रूसी विकास के अवांछित तथा दुःखद पहलुओं से गुजरे बिना हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें।

रूस में लेनिन एक विशेष ऐतिहासिक परिस्थिति में काम कर रहा था। शायद इतिहास ने लेनिन को दूसरा कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। राजनीतिक दृष्टि से प्रतिकूल तथा अत्यधिक दमन वाली रूसी परिस्थिति ने उसे सशस्त्र क्रान्ति के लिये बाध्य किया। लेकिन जैसा मार्क्स और एंगल्स का विश्वास था, प्रजातांत्रिक और शांतिपूर्ण उपायों से समाजवादी परिवर्तन सम्भव है। और उनके समय के बाद आज यह विश्वास और भी दृढ़ हो गया है। मार्क्स और लेनिन के समय के मुकाबले आज दुनियाँ में बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। प्रजातंत्र ने बहुत प्रगति भी कर ली है और हिटलर मुसोलिनी की हार के बाद से समाजवादी शक्तियाँ भी बहुत मजबूत हुई हैं। इस संवध में तो मेरे विचार बिल्कुल स्पष्ट हैं कि एक विशेष समय और स्थान में प्रजातांत्रिक और शान्तिपूर्ण तरीके से समाजवादी परिवर्तन के लिए अगर अवस्था अनुकूल हो तो प्रजातांत्रिक तथा शान्तिपूर्ण रीति का उपयोग करना चाहिये। एक उदाहरण लीजिये। अगर भारतवर्ष में राष्ट्रीय सरकार स्थापित हो जाती है और कांग्रेस

जयप्रकाश की विचारधारा

के हाथ में शक्ति आ जाती है तो समाजवादी पार्लमेन्टरी पद्धति द्वारा अपने समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रयास कर सकते हैं। जब वैधानिक तथा शान्तिपूर्ण उपायों से शक्ति प्राप्ति की जा सकती है, तो सशस्त्र क्रान्ति पर जोर देना मूर्खता है।

रूस के उदाहरण से यह स्पष्ट है कि सशस्त्र क्रान्ति के जरिये जिस राज्य की स्थापना होती है, वह समाजवादी ही हो, यह जरूरी नहीं; वल्कि शान्तिपूर्ण और प्रजातांत्रिक ढंग से एक अच्छे समाजवादी समाज की स्थापना कहीं अधिक सम्भव है। क्रान्ति, आक्रमण और तानाशाही न हो, तो समाजवादी नीति के विकृत होने का खतरा और रूस की तरह मार्क्सवाद के भ्रष्ट होने का भय भी नहीं हो सकता। संयोग से समाजवाद की ओर बढ़ने की गति धीमी हो सकती है, पर वह सुनिश्चित होनी चाहिये। गति धीमी होवे ही, यह भी जरूरी नहीं। भारत का ही उदाहरण लें। यहाँ की जनता आज समाजवाद के इतने पक्ष में है कि या तो सत्ता हस्तान्तरित होने के बाद यहाँ कोई पूँजीवादी राज स्थापित नहीं होगा और यदि पूँजीवादी राज स्थापित हो भी गया, तो प्रजातांत्रिक ढंग से उसे हटाया जा सकेगा।

जनता द्वारा सशस्त्र आक्रमण करके पूँजीवादी राज से सत्ता हस्तगत करने में जितनी सामाजिक क्षति होगी, उससे कम ही क्षति इस पद्धति से होगी। इस प्रकार समाजवाद के रास्ते में जो राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाधाएँ उत्पन्न होती हैं और जिनका सामना अपने समाजवादी पुनर्निर्माण के सिलसिले में रूस को करना पड़ा, उनसे बचे रहने की सम्भावना इस नीति का उपयोग करने में अधिक हो सकती है।

ऐसा कहने का अर्थ यह नहीं है कि मेरी सोवियत रूस से कोई दुश्मनी है। मैं रूस से दोस्ती करने में विश्वास रखता हूँ। एक राष्ट्रवादी होने के नाते भी हमें एशिया के इस सशक्त पड़ोसी से मित्रवत व्यवहार करना चाहिये।

इसके सिवा रूसी राज का आधार समाजवादी है। कम-से-कम इस नाते ही हमें रूस की आलोचना को नरम कर देना चाहिये तथा उसके प्रति मित्रवत आचरण करना चाहिये। किन्तु मित्रता की नीति का मतलब रूस के चारों ओर स्थापित कठपुतली राज्यों को स्वीकार करना नहीं है। रूस की रक्षा के नाते इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। वैसा करना रूस की आत्मरक्षात्मक राष्ट्रीयता को स्वीकार करना होगा। यह समाजवादी मैत्री न होगी।

दुनिया बदल रही है

तब आप कह सकते हैं कि कम से कम इस देश में मैंने मजदूरों के अधिनायकत्व का परित्याग कर दिया है। बेशक, मैं सभी देशकाल और वातावरण में इसे अनिवार्य नहीं समझता। हमें उन राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना होगा जिनमें हम काम कर रहे हैं। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं, वह काफी बदल गई है। जिस दुनिया में समाजवाद की प्राप्ति के लिए भारत प्रयत्न करेगा वह उससे बिल्कुल भिन्न होगी, जिसमें लेनिन के रूस ने इसके लिए प्रयत्न किया था। अतएव यह जरूरी नहीं है कि रूस के लिए जो अनिवार्य रहा हो, वह हमारे लिए भी आवश्यक हो। यूरोप में इस समय पूँजीवाद का नाश हो रहा है और साम्राज्यवाद रक्षात्मक हो गया है। सम्पूर्ण यूरोप में सामाजवादी पार्टियाँ बलवती होती जा रही हैं। ब्रिटिश पार्लमेन्ट में मजदूर दल का विशाल बहुमत है। फ्रांस में समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टियों का बहुमत कायम हो गया है। आज फ्रांस में कोई भी पार्टी इस बात का समर्थन नहीं करती कि सशस्त्र विद्रोह के जरिये अधिकार हस्तगत किया जाये। अमेरिका में परिस्थितियाँ भिन्न हैं। वहाँ पूँजीवाद अभी भी प्रबल है। वहाँ उस देश के जन-साधारण में वैसे ढग की गरीबी भी नहीं है। वहाँ शासक वर्ग अब भी अच्छी

जयप्रकाश की विचारधारा

तरह अधिकारालु है। उस वर्ग के बीच अभी कोई कमजोरी या विघटन नहीं पैदा हुआ है। अभी उनका पर्दाफाश नहीं हुआ है और जनसाधारण भी अभी पूर्णतः निर्भ्रान्त नहीं हुआ है। फलतः वहाँ पूँजीवादी राज्य बना हुआ है। यहाँ भारत में पूँजीवाद अभी कायम नहीं हुआ है और वह इतना मजबूत नहीं है और न होने ही पायगा कि राज्यसत्ता पर अधिकार कर ले तथा पूँजीवादी राज्य यहाँ कायम हो जाय। जब तक जनता उसका समर्थन न करे, तब तक तो यह असंभव ही रहेगा। जनता में जो आर्थिक चेतना उत्पन्न हो गई है और राष्ट्रियता का जो नया सामाजिक आधार हो रहा है, उसके कारण यह बड़ा कठिन हो जायगा।

इसलिए यह मुमकिन है कि आज भारत में पूँजीवादी सफल प्रतिरोध करने में न समर्थ हो और हमें उन्हीं बाधाओं का मुकाबला न करना पड़े, जिनका दूसरे स्थान पर और दूसरे समय में लोगो को मुकाबला करना पड़ा था। यूरोप के दूसरे देशों को सामन्तशाही से उसी प्रकार लोहा नहीं लेना पड़ा, जिस प्रकार १७८९ में फ्रांस को प्रतिरोध करना पड़ा था। इसी कारण से मार्क्स और एंगल्स ने यह नहीं कहा कि केवल हिंसात्मक क्रान्ति द्वारा ही समाजवाद की स्थापना की जा सकती है। इस संबंध में उन्होंने इंग्लैंड तथा दूसरे पश्चिमी लोकतंत्रवादी देशों का नाम लिया, जिनके बारे में उनका ऐसा ख्याल था कि शांतिमय और लोकतन्त्रात्मक उपायो से ये देश समाजवादी राष्ट्रों के रूप में बदल जायेंगे। एटली के नेतृत्व में चलनेवाला मजदूर दल रैमसे-मैकडौनल्ड के नेतृत्व में चलनेवाला मजदूर दल नहीं है। एटली का दल अगले १० वर्षों में इंग्लैंड से पूँजीवाद का खात्मा कर देगा। जैसा ख्याल था, ब्रिटिश पूँजीवाद मजबूती के साथ मुकाबला नहीं कर रहा है। अतएव समाजवादी आक्रमण सफल हो सकता है। जिस पूँजीवाद ने शताब्दियों तक संसार का शासन किया है, वह आज समाजवादी आक्रमण का मुकाबला करने

माक्सवादः अनुभव से छनकर

में असमर्थ है। ब्रिटेन में मजदूर दल की विजय समाजवादियों के लिए एक महान् घटना है। समाजवादी नीति रीति, साधनो और उपायो सबधी हमारे विचार पर इसका असर पड़ना अनिवार्य है। ऐसा कहने का यह मतलब नहीं है कि ब्रिटिश मजदूर दल साम्राज्यवाद से मुक्त हो गया है और हमारे सामने का रास्ता विलकुल साफ है। पर इसका यह मतलब जरूर है कि हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में आनेवाला साम्राज्यवादी और पूँजीवादी प्रतिरोध सम्भवतः बहुत बड़ा न होगा। फिर भी हमें सभी परिणामों के लिए तैयार रहना चाहिए; ताकि अगर प्रजातांत्रिक तरीके से हमें सफलता मिलती न दीखे, तो हम क्रांतिकारी उपायो का भी प्रयोग कर सकें, क्योंकि किसी भी हालत में हमें मौका हाथ से नहीं जाने देना है।

विश्व में महान् परिवर्तन हो गया है और हमारे पूर्व स्थिर नियमों में भी परिवर्तन होना ही चाहिए। हमें इस बात से नहीं डरना चाहिये कि लोग सुधारवादी कहकर पुकारने लगेंगे। पर जो कुछ मैं सामने रख रहा हूँ, वह सुधारवाद नहीं है। हम माक्स द्वारा प्रस्तुत आधार तथा जीवन और वस्तुओं के बारे में उनके दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं और जीवन की परिवर्तित परिस्थितियों में उसे लागू करते हैं। उदाहरणार्थ गांधीजी को ले लीजिये। वे महान् भारतीय हैं और हमारे जीवन में उनका अपना एक स्थान है। हम उन्हें पूर्णतः अंगीकार भले ही न करें, पर हम उन्हें पूर्णतः अस्वीकार भी नहीं कर सकते। हमें उनके उन विचारों को ग्रहण करना चाहिये जो हमारे लिए उपादेय हैं। गांधी जी विकेन्द्रीकरण के समर्थक हैं। हमें अपने देश में इसे चरितार्थ करने की आवश्यकता है। हमारा देश अत्यन्त विशाल है और एक केन्द्र से सभी बातों की व्यवस्था करना सम्भव नहीं है। इसके अलावा हमारे कल कारखाने पूरी अतिरिक्त आबादी को काम नहीं दे सकते और न उद्योगीकरण की प्रगति इतनी तीव्र की जा सकती है कि अतिरिक्त आबादी को शीघ्रता

जयप्रकाश को विचारधारा

से काम मिल जाये। कृषि पर पहले से ही बहुत आदमी निर्भर हैं, इसलिए वह भी सबको काम नहीं दे सकती। अभी तक जो लोग इसमें लगे हुए हैं, उनमें से २५ प्रतिशत तो कृषि का राष्ट्रीयकरण होने पर बेकार हो जायेंगे। अतएव सबको काम देने के लिए हमें गाँवों में छोटे उद्योगों की जरूरत पड़ेगी। पर हम समाजवादी होने के कारण यह चाहेंगे कि उन्हें सहकारिता के आधार पर चलाया जाय। राष्ट्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार को इसे अपने हाथ में लेना पड़ेगा। और उसका विधान करना पड़ेगा। यही हमारे ग्राम्य कार्यक्रम का आधार होगा।

इसके अलावा केन्द्रीय आर्थिक व्यवस्था से नौकरशाही की उत्पत्ति होती है। केन्द्रीकरण के फलस्वरूप सोवियत रूस में यही बात हुई है। इसने मैनेजरोँ और वेतनभोगी कर्मचारियों का एक वर्ग पैदा कर दिया है। वे संख्या में इतने अधिक और इतने महत्वपूर्ण हैं कि वे देश के आर्थिक जीवन को तो नियंत्रित करते हैं, पर उनका नियंत्रण नहीं हो पाता। वे पदों की ओट से संचालन करते हैं। इसलिए आज इस नौकरशाही को हटा कर उसके स्थान पर प्रजातांत्रिक रीति से अर्थव्यवस्था करने की समस्या समाजवादियों के सामने है। इस केन्द्रीकरण के कारण शक्ति रूस में नौकरशाही और उनकी तरह के कुछ खास लोगों के हाथों में है, जिनको 'प्रबन्धक वर्ग' कहा जा सकता है और जिनमें सेना आदि के लोग भी शामिल हैं। हम अपने देश में यही बात नहीं चाहते। निश्चय ही हमारे देश में बड़े बड़े उद्योग होंगे जिन पर राष्ट्रीय स्वामित्व और नियंत्रण रहेगा, पर गाँवों में और नगरों में भी सहकारिता के आधार पर स्थापित हमारे छोटे उद्योगों का जाल बिछा रहेगा।

नैतिक आदर्शों की उपेक्षा नहीं

यदि मुक्तसे पूछा जाय कि समाजवाद क्या है तो जैसा कि मैंने १९३५

मैं अपनी पुस्तक 'ह्वाइ सोशलिज्म — समाजवाद ही क्यों ?' में कहा था; वह उत्पादन, विनिमय और वितरण के साधनों का राष्ट्रीय करण है। हमारी समझ में इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आधार मिल जाता है और मनुष्य के व्यक्तित्व का स्वतंत्र तथा सम्पूर्ण विकास हो पाता है। रूस में समाजवादी आधार पर राष्ट्र का निर्माण हुआ है। फिर भी वहाँ आज ऐसी राजनीतिक परिस्थितियाँ नहीं हैं, जो मनुष्य के व्यक्तित्व के स्वतंत्र तथा सम्पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं। यदि ऐसा होता तो वर्तमान रूस ने श्रेष्ठतर संस्कृति तथा और भी अच्छे मानव पैदा किये होते। पर यहाँ यह बात नहीं पाई जाती है। समाजवादी की हैसियत से हम परिस्थिति और सामाजिक ढाँचे पर जोर देते हैं। हमारा ऐसा विश्वास है कि आर्थिक परिवर्तनों के फलस्वरूप सामाजिक और वैयक्तिक परिवर्तन होते हैं। यह बिल्कुल सच है, किन्तु हाल में जो अनुभव हुए हैं, खासकर रूस में, उनसे पता चलता है कि इस विकास में कोई अनिवार्यता नहीं है। इतिहास तो यह बताता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था स्वतः सम्यक् जीवन की ओर नहीं ले जाती।

इसलिए नैतिक आदर्शों की हम उपेक्षा नहीं कर सकते। नैतिक मूल्यों का अपना एक सामाजिक स्थान होता है। समाज में उनका एक सृजनात्मक तथा रचनात्मक भाग होता है। हमारी मौलिक मानवता नैतिकता की एक व्यवस्था देती है, कुछ सामाजिक 'नियम' निर्धारित करती है। ये ही नैतिक नियमों का रूप लेते हैं। हमें व्यक्तिगत जीवन और आचरण पर जोर देना ही चाहिये, सदाचारी मानवों का निर्माण हमारा लक्ष्य होना चाहिये। हाँ, इस मामले में बेशक हम सामाजिक परिस्थिति की उपेक्षा नहीं कर सकते। परन्तु गांधीजी जैसे महापुरुषों की आदर्शनिष्ठा भी सामाजिक कल्याण की दृष्टि से अत्यावश्यक है। यहीं पर वस्तुतः डाक्टर भगवानदास जैसे विद्वानों की भी

जयप्रकाश की विचारधारा

आवश्यकता प्रकट होती है । कम्युनिस्ट आन्दोलन इस बात की बिल्कुल उपेक्षा कर देता है । वह इस बात को मानकर चलता है कि राष्ट्रीयकरण होने के बाद समाजवादी समाज की स्थापना अनिवार्यतः हो जायगी ।

समाजवाद और भारतीय संस्कृति

यह प्रायः कहा जाता है कि हिन्दुस्तान की हालत एक खास किस्म की है, कि हिन्दोस्तान की परम्परा ही दूसरी है, कि हिन्दुस्तान औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ देश है, कि इसलिए हिन्दोस्तान पर समाजवाद नहीं लागू किया जा सकता ।

यदि इसका मतलब यह हो कि समाजवाद के मूल सिद्धान्तों का प्रयोग हिन्दोस्तान में नहीं किया जा सकता, तो इससे बढ़कर शल्लत बात दूसरी कुछ नहीं हो सकती ।

धन किस तरह इकट्ठा होता है, वह हिन्दोस्तान पर भी, और देशों की ही तरह, लागू है और धन का एक जगह इकट्ठा होना, दूसरे देशों की ही तरह, हिन्दोस्तान में भी एक ही उपाय से रोका जा सकता है । हिन्दोस्तान में उसकी खास हालत की वजह से समाजवाद के सिद्धान्तों को किस तरह और किन भंजिलों में लागू किया जा सकता है, इसमें दूसरे देशों से फर्क आ सकता है । लेकिन, हिन्दोस्तान में समाजवाद के सिद्धान्त बदल नहीं ,

जयप्रकाश की विचारधारा

जायेंगे। यदि संसार के दूसरे हिस्से में शोषण और असमान वितरण को रोकने के लिए उत्पादन के साधनों पर सामाजिक सत्वाधिकार का क्रायम किया जाना आवश्यक है, तो भारत में भी ऐसा ही करना पड़ेगा।

जहाँ तक भारतीय परम्परा की बात है, वह जीवन के साधनों और सुविधाओं को सम्मिलित रूप में उपभोग के प्रतिकूल नहीं है। यह कहा जाता है कि भारतीय सभ्यता का मुख्य रूप रहा है—व्यक्तिवाद, इसलिए हमारे यहाँ समाजवाद की बात चल नहीं सकती। लेकिन, समस्या को इस रूप में रखना शब्दों के पीछे परीशान होना और मुख्य आदर्श को भूल जाना है। हाँ, हमारी संस्कृति का मुख्य प्रेरणा व्यक्तिवादी रही है, लेकिन, उसका अर्थ सिर्फ यह है कि व्यक्तिगत पूर्णता हमारे आदर्श का ध्येय रहा है। उसका अर्थ तुच्छ और संकीर्ण व्यक्तिवाद नहीं रहा है, जो कि पूँजीवादी समाज का मुख्य ध्येय है। और, अगर व्यक्तिगत पूर्णता जीवन का ध्येय हो, तो हम समाजवादी यह दावे के साथ कह सकते हैं कि इसकी प्राप्ति सार्वजनिक हित या जनता के अधिक-से-अधिक हिस्से के हित को लक्ष्य रख कर ही की जा सकती है। क्या ट्रॉट्स्की ने हमें यह नहीं बताया है कि समाजवादी समाज में ही साधारण मानवता अफलातून और कार्ल मार्क्स की ऊँचाई तक पहुँच सकती है? अंत में, हिन्दोस्तान का औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े होने से हमें निराश नहीं होना चाहिए। एक दृष्टि से यह पिछड़ा होना हमारे लिए मददगार ही साबित होगा। क्योंकि समाजवाद का उतना उग्र विरोध हमारे देश में न हो सकेगा, जितना कि पूर्ण विकसित देशों में हुआ। रह गई बात औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए प्रदेशों में समाजवाद की स्थापना की सफलता के विषय में, सो इस संबंध में रूस की ओर इंगित करना ही काफी होगा, जहाँ संसार के सबसे पिछड़े प्रदेशों में समाजवाद का प्रयोग सफलता के साथ हो रहा है।

हम पर यह दोष भी मढ़ा जाता है कि हम भारत पर एक विदेशी पद्धति

समाजवाद और भारतीय संस्कृति

नादना चाहते हैं—भारत की तो अपनी खास समस्या है और उसकी हालत भी कुछ दूसरी ही है।

मैं स्पष्ट कर दूँ कि भारत की खास समस्या को मैं नज़रअन्दाज नहीं करता और न कभी यह भूलता हूँ कि हमारा देश सांस्कृतिक दौड़ में बहुत पीछे पड़ गया है। यदि हम ऐसा करे, तो यह तो मार्क्स की शिक्षा-दीक्षा के बिल्कुल विपरीत होगा। हमने भारतीय दार्शनिकों की विचार-प्रणाली की छानबीन की है और उसकी वारीकी और गहराई के कायल हैं। किन्तु हमारे देश की सामाजिक स्थिति इतना अधिक बदल गई है और इस बदली हुई परिस्थिति ने ऐसी समस्याये ला दी हैं कि हमारे दार्शनिकों के हल उन पर लागू ही नहीं होते। कुछ ऐसे व्यापक सिद्धांत हैं, जो सब काल में लागू हो सकते हैं किन्तु इन व्यापक सिद्धांतों का दुरुपयोग उस समय नहीं किया जा सकता जब किसी खास बुराई को हटाने के लिए किसी खास उपाय की खोज की जा रही हो।

हमारे पुराने सिद्धान्त उस समय निर्मित हुए जब सभ्यता बहुत सीधी-सादी थी। न कृषि का उतना विकास हुआ था, न उद्योग धंधे का। उस समय आदमी का शोषण बड़े पैमाने पर किया ही नहीं जा सकता था। उत्पादन उस समय छोटे और व्यक्तिगत पैमानों पर किया जाता था। जन-संख्या कम थी और प्रकृति उदार थी। सभी स्वस्थ पुरुष के लिए यह सम्भव था कि वे जंगलों को काट कर अपने लिए जमीन और घर का प्रबन्ध कर लें।

किन्तु आज की हमारी कृषि की दशा देखिये या उद्योग-धंधों की। उस समय से कितना अन्तर हो गया है। जमीन्दारी प्रथा हमारे देश की चीज नहीं है और न ये कारखाने और मिलें ही हमारे देश की पैदावार हैं। हिन्दो-स्तान में विदेशी सरकार आई और उसने कितनी ही विदेशी समस्याएँ हमारे सामने खड़ी कर दीं। जिस समय मनु महाराज का राज्य था, उस समय-

जमीन या उत्पादन के अन्य साधनों पर एक मुट्ठी लोगों के सर्वाधिकार की बात ही कहाँ थी ? और आजकल की जो हमारी समस्याएँ हैं, वे तो इसी से पैदा हुई हैं ।

ये समस्याएँ जिस तरह भारत के प्राचीन अतीत से कोई सम्बन्ध नहीं रखती हैं, उसी तरह वर्तमान संसार से उनकी अटूट एकता है । चीन, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका सब देशों के लोगों के सामने ये ही समस्याएँ हैं । उत्पादन के साधनों का विकास होने से, दूसरे शब्दों में भाफ और बिजली के आविष्कार होने से, मनुष्य के शोषण करने की प्रणाली इतनी विकसित हो चुकी है जैसी कभी नहीं हुई थी । इस विकसित प्रणाली का ही दूसरा नाम है पूँजीवादी उत्पादन और वितरण की प्रणाली ।

इसी पूँजीवादी प्रणाली की प्रतिक्रिया है समाजवाद । जहाँ जहाँ पूँजीवाद है, वहाँ वहाँ समाजवाद भी लागू होगा । समाजवाद की कोई देशीय सीमा हो नहीं सकती । इसकी जन्मभूमि जिस तरह इंग्लैंड है उसी तरह जापान, जिस तरह जर्मनी उसी तरह चीन, जिस तरह अमेरिका उसी तरह भारत । जहाँ जहाँ पूँजीवादी शोषण का बोलबाला होगा, वहाँ वहाँ समाजवाद का उदय होगा, हिन्दोस्तान उसका अपवाद न हो सकता है और न है ।

हिन्दोस्तान में सामंतशाही के जो ख़सावशेष हैं, उनके चलते उसके रूप में थोड़ा अन्तर हो सकता है, किन्तु उसका स्वभाव सर्वत्र एक रहेगा । शोषित जनता के भिन्न भिन्न स्तरों के बीच शक्ति के समतुलन में अन्तर हो सकता है, समाजवाद की स्थापना की गति में मन्दता हो सकती है, किन्तु उसका उद्देश्य और लक्ष्य यानी पूँजीवादी-सामंतवादी शोषण से जनता को मुक्त करना और जनता का राज्य एवं समाजवादी समाज की स्थापना करना—यह तो पूँजीवादी देशों के समान ही एक रहेगा ।

यह काम तो उन लोगों का है, जो हमपर पश्चिम का अनुकरण करने का

समाजवाद और भारतीय संस्कृति

दोष लगाते हैं, कि वे हमारी वर्तमान समस्या का कोई भारतीय निदान पेश करें। भारत की विशेषताओं के गीत बहुत गाये जाते हैं—किन्तु कोई ऐसी व्यवस्था नहीं पेश की जाती है जो हमारी वर्तमान समस्याओं को सुलझा सके। मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीयता की दुहाई वर्तमान शोषण पर पर्दा डालने और उसे जारी रखने के लिए दी जाती है। फिर आपने जितनी विदेशी चीजें ले ली हैं, क्या समाजवाद उनसे भी ज्यादा विदेशी है? विधान-परिषद, धारा-सभा, लोकल बोर्ड, मिल का धुआँ, इंजिन की चीख—क्या इनसे भी ज्यादा विदेशी और 'अभारतीय' हमारा समाजवाद है?

हममें से कुछ लोग गांवों से निकटतम सम्बन्ध ही नहीं रखते, बल्कि वे उससे चिपके हुए हैं। वे लोग समझते हैं कि चूंकि समाजवाद में मशीन का उपयोग अनिवार्य है, अतः समाजवाद कायम होते ही गांव की स्वावलम्बी अर्थनीति समाप्त हो जायगी, गांव के सुन्दर स्वस्थ वातावरण का नाश हो जायगा और वहाँ भी शहर के शोषण के साथ शहरी अवगुण भी आ जायेंगे।

आजकल के शहरों से मुझे भी चिढ़ है, मैं भी उनका दुश्मन हूँ। राक्षस के मुँह ऐसी अट्टालिकायें, भीड़भाड़, गन्दगी, कुरूपता और फिर मजदूरों के नरक ऐसे मुहल्ले—इन्हें देखकर किसके मन में विद्रोह और घृणा के भाव नहीं आते। ये सुन्दर जीवन के दुश्मन हैं। अधिकांश लोगों के लिए शहर रौख का आवास है। शहरों में मनोरंजन के साधन भी हैं, किन्तु वे आनन्द और सौन्दर्य की वस्तु नहीं हैं बल्कि थके हुए शरीर और तनी हुई नसों के लिए मादक पदार्थ है। शहरों का निर्माण जनता के शोषण की नींव पर हुआ है। शहरों ने गांवों को दूहा है, इसलिए शहरों और गांवों में स्वाभाविक शत्रुता का भाव है। ज्ञान, कला, आराम, चैन सबके सामान शहरों में केन्द्रित कर रखा गया है, इधर गांव अविकसित और उपेक्षित रूप में सड़ रहे हैं।

जयप्रकाश की विचारधारा

यह सब सही है, किन्तु यह समझना गलत है कि समाजवाद में इस अभ्राकृतिक विकास को कायम रखा जायगा या प्रोत्साहन दिया जायगा। समाजवाद तो समाज के निर्माण के उस कौशल का नाम है जो सम्पूर्ण समाज के समान और सुन्दर विकास को अपना लक्ष्य बनाता है। समाजवाद के बाद जो गाँव बसेंगे या शहर बसेंगे—वे आज के शहरों और गाँवों से बिल्कुल पृथक होंगे और इन दोनों में आज की तरह की शत्रुता और प्रतियोगिता भी नहीं रहेगी।

इसमें शक नहीं कि समाजवादी मशीनो को पसंद करते हैं। किन्तु समाजवादी कभी मशीन को शोषण का साधन नहीं मानता और न ऐसा शोषण यंत्र समझता है जो मानवता की हड्डियों को चूर-चूर और मानव आत्मा का खून कर देता है। मशीन को हम मजदूरों का, श्रमिकों का मित्र समझते हैं। मित्र भी ऐसा—जो मेहनत कम कर दे, पैदावार बढ़ा दे और हमारे लिए हवा-पानी सबपर विजय प्राप्त कर सके। यह सोचना ही गलत है कि मशीन के उपयोग का अर्थ ही होगा शहरों का बोलबाला और गाँवों की दुर्दशा। मशीन पर जब व्यक्तिगत अधिकार हो, तब ऐसा होना लाजिमी है। किन्तु ज्यों ही सारे समाज का अधिकार उसपर हुआ कि वह सारी जनसंख्या के हित में उत्पादन का सर्वोत्तम माध्यम बन गई।

समाजवादी समाज में एक ओर हम गहरों को नये ढंग से बसायेंगे, उसमें उद्योगधंधों का सिलसिले से इन्तजाम करेंगे तो दूसरी ओर हम इन गाँवों को भी भोपड़ों और घरों का अटपटा भुंड नहीं रहने देंगे—सड़कों से दूर, ससार की हलचलो से दूर। हम गाँव को उन्नतिशील जनसंघ में परिणत कर देंगे जहाँ बिजली, रेल, टेलिफोन, रेडियो, सिनेमा, मोटर सबका सुख सब आदमी के लिए सुलभ हो। गाँव में भी हम उद्योगधंधों का प्रचार करेंगे और वहाँ ऐसा जनराज्य कायम करेंगे जो अपना रक्षा,

समाजवाद और भारतीय संस्कृति

स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन आदि का प्रबंध स्वयं कर ले—बाहरी सत्ता का मुँह नहीं जोहे ।

यो आप जिस दृष्टि से देखिये, समाजवाद भारतीय संस्कृति, परम्परा या स्थिति के प्रतिकूल नहीं जाता । समाजवाद, ससार की तरह, भारत के लिए भी कल्याण का मार्ग सिद्ध होगा ।

समाजवादी एकता

कुछ दिन हुए कलकत्ते में एक सवाल के जवाब में पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था—“कम्युनिज्म और सोशलिज्म में यह दोष है कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट दोनों अपने दुश्मनों से लड़ने के बदले आपसी लड़ाई में ही अपनी ताकत खर्च किया करते हैं।” पण्डित नेहरू सोशलिस्ट हैं, फिर भी वह किसी सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य नहीं हैं। वह इसके गद्दोंगुवार से और इसके दिल दुखानेवाले भगड़ों से दूर रहते हैं। इसलिए उनके लिए यह सम्भव है कि वह इस तरह का निर्लिप्त भाव रख सकें यद्यपि एक समाजवादी का कर्तव्य इसके प्रतिकूल है। मगर वह सभी लोग जो समाजवाद की उन्नति दिल से चाहते हैं उन्हें इस भगड़े के कारणों को जानना पड़ेगा और उन्हें दूर करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर यह न हो सके तो सिद्धान्त और कार्य रूप में जिसमें अधिक सत्यता उन्हें मालूम हो उस ओर अपनी ताकत लगा देनी होगी।

यह बात बड़े अफसोस की है, फिर भी सच है कि सारी दुनिया में कम्युनिस्ट और समाजवादी अपनी ज्यादा ताकत आपस में लड़ने में ही खर्च करते

हैं। मगर यहाँ तो हमें अपने देश की हालत से खास मतलब है। यह ठीक है कि इस देश में भी कम्युनिस्ट और समाजवादी एक दूसरे से लड़ते पाये जाते हैं। जो लोग दोनों को समान रूप से दोषी समझते हैं वह समाजवादियों के साथ अन्याय ही नहीं करते हैं बल्कि बातों को जनता के सामने उस शक्ल में नहीं रखते जो कि समाजवादी आन्दोलन की भलाई के लिए जरूरी है। फिर भी यह सम्भव नहीं कि देश में समाजवादो एकता के लिए जो कोशिश की गई है उसका उन्हें कोई पता न हो।

कांग्रेस समाजवादी पार्टी और हिन्दुस्तान को कम्युनिस्ट पार्टी इस देश की दो मुख्य समाजवादी पार्टियाँ रही हैं। इन दोनों में कांग्रेस समाजवादी पार्टी हिन्दुस्तान की सर जमीन से पैदा हुई चीज है। कम्युनिस्ट पार्टी तो बाहरी चीज है, कलमी पौधा है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय आन्दोलन से निकली है। इसकी स्थापना भारतीय राजनीति के विकास में एक बड़ी उल्लेख योग्य वस्तु थी। जो लोग समाजवाद का भला चाहते हैं और यह चाहते हैं कि आजादी का आन्दोलन समाजवादियों के प्रभाव में आये उन्हें इसका स्वागत करना चाहिये था। मगर इस नन्हीं सी पार्टी का कम्युनिस्ट पार्टी ने किस प्रकार स्वागत किया ? उसने फौरन उसपर चौतर्फी बार शुरु कर दिया। इसमें ग्रेट ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े-बड़े नेताओं ने भी, जो कि हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी के मालिक मुख्त्यार हैं, हिस्सा लिया। कां० स० पार्टी को 'सोशल फैसिस्ट' की उपाधि दी गयी, इसे भारतीय पूँजीवादी गिरोह का प्रगतिवादी पोषक बताया गया और एक जहरीली उपज समझकर इसे खत्म कर देने की नीति निर्धारित की गई।

मगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने इस अखाड़े में कूदने से इन्कार किया। खुल्लमखुल्ला विरोध का सामना करते हुए, समाजवादी एकता की नीति अस्तिथार की और सभी मार्क्सवादी समाजवादी गिरोहों और व्यक्तियों को मिलाकर

जयप्रकाश की विचारधारा

हिन्दुस्तान की एक बड़ी समाजवादी पार्टी का यह महान उद्देश्य नहीं सफल हुआ। “समाजवादी एकता” नाम की पुस्तिका में इस प्रयत्न और उसकी असफलता की पूरी कहानी बड़ी अच्छी तरह दी गई है। वह सारी कहानी तो यहाँ नहीं दोहरानी है। उस असफलता की बुनियादी वजह क्या थी उससे यहाँ मतलब है। फिर भी इस मामले को समझने के लिए जरूरी है कि उस कहानी की मुख्य बातें हमें मालूम हों।

एक साल से कुछ ज्यादा तक कम्युनिस्ट पार्टी ने हमारे खिलाफ यह लड़ाई चलाई। अन्त में जब कम्युनिस्ट इन्टरनैशनल की सातवीं कांग्रेस ने अपनी तोड़फोड़ की नाशकारी नीति बदली तो हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना रुख एक बार फिर बिल्कुल ही बदल दिया। इस बीच में अपनी इस नीति का नतीजा वह भोग चुके थे। इसी के कारण जर्मनी में नात्सियों के हाथ में ताकत आई। जहाँ कुछ ही साल पहले यह लोग राष्ट्रीय झण्डा जला चुके थे अब कम्युनिस्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लहराते झण्डे के साये में इकट्ठे होने लगे। यकायक कांग्रेस समाजवादी पार्टी का सोशल फैसिज्म जाता रहा। यह एक सच्ची समाजवादी पार्टी बन गई और पीछे चल कर एक क्रांतिकारी मार्क्सवादी पार्टी भी बन गई।

इस तब्दीली से हमें बड़ी खुशी हुई। उन्होंने अपनी नीति जब तक नहीं बदली थी तब भी हमने कम्युनिस्टों को अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता दे रक्खा था। उनके नीतिपरिवर्तन के बाद तो हम लोगों ने फौरन उनके साथ एक इकरारनामा किया। उसके अनुसार उन्होंने कांग्रेस समाजवादी पार्टी में शामिल होने, उसे मजबूत करने और आगे बढ़ाने का वादा किया और कम्युनिस्ट पार्टी को मिलाकर एक संयुक्त समाजवादी पार्टी बनाने के उद्देश्य को स्वीकार किया और अपनी ओर से हमने यह वादा किया कि दोनों

पार्टियों को मिलाने के काम में मदद करने के ख्याल से हम लोग अपनी पार्टी में उन्हें शामिल कर लेंगे ।

वह हमारे लिए गर्व का दिन था । मगर हमने अपने दोस्तों को पहचाना नहीं था । जैसे-जैसे दिन बीतते गये यह साफ होता गया कि कम्युनिस्टों को एकता में कभी विश्वास नहीं था । उन लोगों के लिए एकता का नारा तो सिर्फ कांग्रेस समाजवादी पार्टी, उसके मंच, सगठन और प्रभाव से फायदा उठाने के लिए था । अपने मेम्बरो को कम्युनिस्ट पार्टी ने बराबर यह कहा कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी एक असमाजवादी सस्था है, जिस पर उन्हें कब्जा करना या अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिये । उन्हें बराबर यह भी कहा गया कि सही माने में क्रान्तिकारी समाजवादी पार्टी तो एक ही हो सकती है यानी कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल की शाखा ।

यह अन्दर अन्दर की धोखे और दगावाजी की नीति ने बहुत सारे मगड़े और कठिनाइयाँ पैदा कीं । लेकिन कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने, और इसे हम उसकी कमजोरी समझते हैं, इन सब बातों की ओर से आँखें बन्द कर लीं और कम्युनिस्ट पार्टी की सभी चालबाजियों को सब्र के साथ बर्दाश्त करती गयी । यह ठीक है कि उसने एकता की भावना से प्रभावित होकर ऐसा किया, मगर वह इस भावना में बहुत दूर तक बह गई ।

इसके बाद युरोपीय महायुद्ध का समय आया । कुछ ही महीनों के अन्दर कम्युनिस्ट पार्टी ने देश की सभी राजनीतिक सस्थाओं का विरोध करना शुरू कर दिया । कांग्रेस (गान्धी जी और जवाहर लाल के सहित), सुभाष बोस और फॉरवर्ड ब्लॉक, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, एम० एन० रायवादी, असल में, अपने को छोड़कर कम्युनिस्ट सभी चीज और सभी संस्था के खिलाफ हो गये । वस्तु में उनका ख्याल था, जैसा कि एक कम्युनिस्ट नेता ने लेखक को बताया, कि युद्ध के क्रान्तिकारी समय में जनता के सामने उसके सच्चे

‘जयप्रकाश की विचारधारा

क्रान्तिकारी नेता की शक्त में सिर्फ ‘कम्युनिस्ट’ पार्टी को ही आना चाहिये । इसलिए और सभी पार्टियों का भण्डाफोड़ करना आवश्यक हो गया ।

जब कम्युनिस्ट इस अवस्था में पहुँचे और कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर उन्होंने धावा बोल दिया तब कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लिए अपनी पार्टी से कम्युनिस्टों को निकाल देने के अलावा और कोई उपाय नहीं रह गया । इससे कम वह कर ही क्या सकती थी । मगर अब भी वह इससे आगे नहीं जाना चाहती थी । अस्तु, उसने स्वतन्त्र समाजवादी पार्टियों की तरह कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर काम करने की इच्छा प्रकट की । लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी अपना स्वतन्त्र क्रान्तिकारी रूप नष्ट होने देना नहीं चाहती थी । इसलिए वह ‘लिये लुकाठी हाथ’ आगे बढ़ती गई । उसका सबसे पहला काम कांग्रेस समाजवादी पार्टी को तोड़ना और मजदूरों, किसानों और विद्यार्थियों की संस्थाओं में उसका प्रभाव नष्ट करना हो गया । इस आक्रमण के सामने कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लिए लौटकर मुकाबला करने के सिवाय और कोई चारा ही नहीं रह गया । वह आपस की लड़ाई नहीं चाहती थी मगर उसे अपना काम तो करना था और हिन्दुस्तान की जनता के प्रति अपना जो कर्तव्य वह समझती थी उसे तो पूरा करना था ।

इस तरह एकता की आगएँ हवा के साथ उड़ गईं । क्या हम पूछ सकते हैं कि इन बातों का ख्याल करते हुए किस तरह लोग आज के भगड़ेकी जिम्मेदारी कांग्रेस समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों पर बराबर रखते हैं ।

भगड़े की जड़—कम्युनिस्ट इन्टरनैशनल

मगर इस सवाल को छोड़िये । इससे ज्यादा महत्त्व इसी बात का है कि एकता के ये प्रयत्न क्यों निष्फल हुए । अगर हम यह कहें कि इसकी

जिम्मेवारी कम्युनिस्टों को बेईमानी और फिर्कापरस्ती पर है तो इस मामले को बहुत ज्यादा सीधा-सादा बना देना होगा। इसका कारण बहुत बड़ा था। वह कारण खुद कम्युनिस्ट इंटरनैशनल था। जब से रूस में स्टालिन का प्रभुत्व हो गया तब से लेनिन का वह मशहूर अन्तर्राष्ट्रीय सच, जो कि विश्वक्रान्ति का साधन बननेवाला था, धीरे धीरे सोवियेट रूस के विदेशी विभाग का हिस्सा बन गया और उससे सम्बन्धित सारी पार्टियाँ सोवियेट विदेशी नीति के विज्ञापन आफिस का काम किया करती थीं। हमारा ख्याल है कि सनदयापता कम्युनिस्ट पार्टियों के अलावा और कोई इसका विरोध नहीं करेगा। जिस तरह कम्युनिस्ट हिन्दुस्तान में ही नहीं, सारी दुनिया में इस लड़ाई के दम्यान चक्कर काटते रहे हैं उससे बढ़कर इसका और सबूत क्या हो सकता है ? इस लड़ाई के बाद, कम्युनिस्ट इंटरनैशनल को तोड़ देने पर भी, नीति वही चलती रही। इंटरनैशनल के बदले अन्दरूनी तरीके से सोवियेट रूस की हुकूमत का प्रभुत्व है।

तो इस मामले को पकड़ यहीं पर है। हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट इंटरनैशनल की एक शाखा थी। जब तक हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी जैसी थी वैसी रहती तब तक हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी या कहीं और की कम्युनिस्ट पार्टी दूसरी किसी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर कम्युनिस्ट इंटरनैशनल से अलग कोई संयुक्त समाजवादी पार्टी नहीं बना सकती थी। अगर उसने ऐसा किया भी हो तो वह सिर्फ एक चाल थी। उसमें चलकर, फिर वक्त पाकर, उस संयुक्त पार्टी को तोड़ा जाय और अगर हो सके तो ज्यादा ताकत के साथ कम्युनिस्ट इंटरनैशनल से सम्बन्ध स्थापित किया जाय। कैटलोनिया (स्पेन) में ठीक ऐसा ही हुआ। इससे भी ज्यादा सम्भव है। एक कम्युनिस्ट पार्टी के लिए किसी दूसरी समाजवादी पार्टी से एकता स्थापित करना असम्भव है। वह दूसरी किसी पार्टी को मार्क्सवादी पार्टी

जयप्रकाश की विचारधारा

नहीं मान सकती। इस तरह मार्क्सवादी आन्दोलन, 'रोमन धर्म' की तरह चीज हो गई है, जिसका धर्मस्थान मास्को है, जिसका "पोप" स्टालिन है।

तो फिर उपाय क्या था ? या तो सभी समाजवादी कम्युनिस्ट इन्टर-नैशनल की मातहत अख्तियार कर लेते और उसकी किसी न किसी शाखा के सदस्य बन जाते या जो ऐसा नहीं कर सकते थे वे कम्युनिस्ट इन्टरनैशनल से स्वतन्त्र अपनी अलग पार्टी बनाते। इस तरह वे अन्तर्राष्ट्रीयता से हाथ थोड़े ही धो बैठते। जब लेनिन द्वितीय इन्टरनैशनल से अलग हो गया और जब तक उसने तृतीय इन्टरनैशनल नहीं बनाया था, उसकी बोलशेविक पार्टी किसी इन्टरनैशनल समाजवादी संस्था से सम्बन्धित नहीं थी। इस कारण वह उन वर्षों में सिद्धान्त या कार्य में कम अन्तर्राष्ट्रीय थोड़े ही हो गई थी ? एक समाजवादी पार्टी अगर अवस्था विशेष के कारण अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध नहीं स्थापित करती तो वह अन्तर्राष्ट्रीयता से परे नहीं हो जाती। वह सिर्फ यह कहती है कि इस समय मजदूरों की कोई सही माने में अन्तर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है। द्वितीय इन्टरनैशनल खत्म हो गया। अगर जिन्दा भी है तो ऐसी गिरी हुई हालत में है, क्रांतिकारी उसूलों से इतनी दूर है कि विश्वक्रांति में उसका हाथ नहीं हो सकता। तृतीय इन्टरनैशनल भी खत्म हो गया। वह भी तो नाम को ही अन्तर्राष्ट्रीय था। वह तो सراسर स्टालिन की हुक्मत के हाथ में था। मास्को के एजेण्टों को छोड़ कर और कोई समाजवादी यह मानने को तैयार नहीं होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी आन्दोलन इस हुक्मत के मातहत कर दिया जाय। मुझे भरोसा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू तो ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। एक समाजवादी की हैसियत में कम से कम वह तो मास्को का हुक्म मानने को तैयार नहीं होंगे यद्यपि अन्य समाजवादियों की तरह वह सोवियेट यूनियन के साथ मिल कर काम करने को बड़े उत्सुक होंगे। चतुर्थ इन्टरनैशनल तो इस तरह एक फिक्के की चीज है कि वह दुनिया

के क्रान्तिकारी मजदूरों की व्यापक सस्था नहीं बन सकती। इन्टरनैशनल कम्युनिस्ट विरोधी सघ के लिए भी यही बातें सच हैं। अन्तर्राष्ट्रीय क्रान्तिकारी समाजवादी एकता सघ की विभिन्न देशों में स्वतन्त्र क्रान्तिकारी पार्टियाँ हैं मगर उन देशों में भी उनके पीछे जनबल नहीं है।

आज समाजवादियों में जो विभिन्नता पाई जाती है, क्या हिन्दुस्तान में और क्या बाहर, वह एक तरफ क्रान्तिकारी मार्क्सवाद और दूसरी तरफ तरह तरह के निम्नमध्यमवर्गीय सुधारवादी समाजवाद को लेकर नहीं है बल्कि वह एक तरफ तो क्रान्तिकारी मार्क्सवादको पूरी तरह माननेवालों मगर मास्को की मातहतता न कबूल करनेवालों और दूसरी तरफ जो लोग इस मातहतता को कबूल करते हैं उनके बीच के झगड़े पर निर्भर हैं।

कांग्रेस समाजवादी क्रान्तिकारी मार्क्सवाद को पूरी तरह कबूल करते हैं मगर वह आज किसी इन्टरनैशनल से नाता नहीं जोड़ना चाहते। कांग्रेस समाजवादियों का विश्वास है कि मार्क्सवादी सिद्धान्तों को हिन्दुस्तान की अवस्था पर घटाना उनका काम है। लन्दन या मास्को में बैठे हुए लोगों का यह काम नहीं है। अपने निर्णयों में वे अवश्य अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति, दुनिया के एकमात्र समाजवादी राज्य की हालत और दुनिया के मजदूरों का ख्याल करेंगे। मगर अन्तिम निर्णय तो उन्हीं का होगा। अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी आन्दोलन की आज जो अवस्था है उसमें दुनिया की सभी समाजवादी पार्टियों के लिए समान केन्द्रीय निर्देश जारी करना असम्भव है। वास्तव में यह विचारणीय है कि दुनिया की सभी समाजवादी पार्टियों के लिए कम्युनिस्ट इन्टरनैशनल की तरह केन्द्रीय निर्देश का देना सम्भव है या नहीं। चीन में इसका कैसा नतीजा हुआ यह एडगर स्नो ने अपनी पुस्तक 'रेड स्टार ओवर चाइना' में अच्छी तरह दिखाया है। अगर एक सही माने में क्रान्तिकारी समाजवादी अन्तर्राष्ट्रीय सघ स्थापित हो जाय, उसका कार्य प्रजातान्त्रिक रीति

जयप्रकाश की विचारधारा

से हो और वह दुनिया के समस्त या प्रायः समस्त समाजवादी आन्दोलन पर प्रभाव रखता हो तो भी भिन्न भिन्न पार्टियों के कार्य का परस्पर सम्बन्ध करने, आन्दोलन की पूरी ताकत को प्रत्येक पार्टी के लिए उपलब्ध करने और कुछ बड़े बड़े नियम निर्धारित कर देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया जा सकता। क्या हम आशा करें कि इस युद्ध के फलस्वरूप दुनिया के मजदूरों का एक सही माने में अन्तर्राष्ट्रीय संघ जन्म लेगा? कम से कम, हम सब उसके लिए प्रयत्न तो करें।

तो समाजवादियों और स्टालिनवादी कम्युनिस्टों में भलाइ की दुनियादी वजह यह है। यह याद रहे कि हम मास्को का नेतृत्व इस लिए नहीं मानने से इन्कार करते कि मजदूरों के सबसे पहले राज्य के लिए हमारे हृदय में प्रेम नहीं है या हम उसके महत्व को नहीं समझते। इस मामले में हमारा कम्युनिस्टों से कोई भलाइ नहीं है। मगर हमारा विश्वास है कि सोवियट राज्य की भलाई इसमें नहीं है कि वहा की हुकूमत जो कुछ करे सभी में हम उस का हाँ में हाँ मिलाया करें। वास्तव में अपने तरीकों के द्वारा कम्युनिस्ट समाजवाद तथा सोवियट का फायदा करने के बदले उनका नुकसान करते हैं। ब्रिटिस साम्राज्यशाही युद्ध में बिना शत्रु सहायता करने की बात कहकर कम्युनिस्टों ने कम्युनिज्म को ही बदनाम नहीं किया बल्कि सोवियत के खिलाफ भी, जिसके सनदर्यापता एजेंट होने का वे दम भरते हैं, सन्देह पैदा किया।

रूस से लौट आने पर सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने रूस के नौजवानों की वीरता और त्याग की प्रशंसा करते हुए कहा था—“अपने देश में भी ऐसे ही वीर और सामर्थ्यवान युवकों की आवश्यकता है। हमारा लक्ष्य भी अनिवार्यतः वही होना चाहिये जो कि सोवियत युवक का है। लेकिन उस लक्ष्य तक पहुँचने के मार्ग का स्वरूप हमारे अपने वातावरण द्वारा निर्धारित होना चाहिये

न कि रूस अथवा अन्य किसी देश द्वारा ।” इसी तरह भारतीय वातावरण को मास्को नहीं समझ सकता । इसे तो वे ही समझ सकते हैं जो हिन्दुस्तान में जन्म लेते और मरते हैं ।

इसके अलावा कांग्रेस समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी के इस सिद्धान्त को अमान्य समझते हैं कि झुठाइयों, धोखेबाजी और जालसाजी के द्वारा ही क्रान्तिकारी सिद्धान्तों पर अमल किया जा सकता है । चालबाजी के जरिये कभी क्रान्ति नहीं लायी जा सकती । जहाँ हम एक तरफ भलाई और बुराई के सम्बन्ध में मध्यमवर्गवालों की मिथ्या धारणाओं को अस्वीकार करते हैं, वहाँ दूसरी तरफ हमारा यह पक्का विश्वास है कि क्रान्तिकारी कार्यों का आधार ईमानदारी, क्रान्तिकारी आदर्शवाद तथा सत्य के प्रति अधिक से अधिक सम्मान होना चाहिये । हम इसमें भी विश्वास नहीं करते कि हृदय-हीनता क्रान्तिकारी कार्य का अंग है । क्रान्तिकारी उद्देश्य में अडिग विश्वास रखते हुए, हम, हृदयहीनता को क्रान्तिविरोधी मान कर, उसकी निन्दा करते हैं और उसे मार्क्सवाद के विरुद्ध समझते हैं । मानव प्रेम तबतक मध्यमवर्गीय उदारता है जबतक वह सामाजिक परिवर्तन के एक वैज्ञानिक सिद्धान्त से सम्बन्धित नहीं है परन्तु सामाजिक क्रान्ति के सहयोगी की हैसियत से वह मार्क्सवाद का मूल है ।

कम्युनिस्टों के साथ मतभेद के एक और विषय की हम चर्चा करेंगे । यह है राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रश्न और समाजवाद और मध्यम श्रेणियों के सम्बन्ध की समस्या । अगर पिछले दो महायुद्धों के बीच के वर्षों में कोई बात देखने में आयी है तो वह यह है कि मध्यम वर्गों और राष्ट्रीयता की भावना की उपेक्षा समाजवादियों के लिए घातक ही हो सकती है । हिन्दुस्तान ऐसे मुल्क में, जो कि अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है, राष्ट्रीयता का प्रश्न और भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है । जर्मनी में समाजवादियों और कम्यु-

जयप्रकाश की विचारधारा

स्टों के पतन और नात्सीवाद के उत्कर्ष के पश्चात् तृतीय इण्टरनेशनल की कार्यपद्धति से यह पता चला कि अन्ततोगत्वा उसने इन प्रश्नों के महत्व को समझा। इन्टरनेशनल की सातवीं कांग्रेस ने तो वास्तव में इन नसीहतों की रोशनी में अपनी पूरी नीति को एक नया रूप दिया और इसी का यह परिणाम था कि हिन्दुस्तान के कम्युनिस्टों की नजर में राष्ट्रीय कांग्रेस यकायक संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा बन गयी किन्तु हाल की घटनाओं से यह पता चलता है कि इस कदर ज्यादा नुकसान उठाकर हासिल की गई नसीहतों का कम्युनिस्ट विचार धारा पर कोई गहरा असर नहीं पड़ा। हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी फिर इस तरह चल रही है मानो कांग्रेस जैसी संस्था का, जिसके ४० लाख सदस्य हैं बाकायदा मेम्बर न होते हुए भी करोड़ों दूसरे भारतीय जिसके फरमावरदार हैं और जो कि सचमुच आजादी की लड़ाई लड़ रही है, कोई वजूद ही न हो। यह बेवकूफी की हद है और इसका नतीजा सिर्फ यही हो सकता है कि हिन्दुस्तान की जनता से समाजवाद का सम्पर्क जाता रहे और अन्त में हिन्दुस्तान में वह नाकामयाब साबित हो।

इस प्रसंग में यह याद रखने की चीज़ है—लेकिन इस बात की आवश्यकता पर बहुत जोर देता था—कि अत्याचारी देश की असहनीय राष्ट्रीयता तथा अत्याचार पीड़ित देशकी क्षम्य राष्ट्रीयता के अन्तर पर ध्यान दिया जाय। स्वयं लेनिन के शब्दों में “जिस व्यक्ति ने इस अन्तर को नहीं समझा है उसे निस्सन्देह राष्ट्रीय प्रश्न पर मज़दूर वर्ग के रुख के विषय में कुछ भी नहीं मालूम है।”

कांग्रेस समाजवादियों की नीति कम्युनिस्ट पार्टी की नीति के ठीक विपरीत है और पहले भी रही है। राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ घनिष्ठ सहयोग के साथ काम करना हमारी मौलिक नीति रही है। वाक्या यह है कि राष्ट्रीय क्रान्ति के अर्थ में हमने अपने कर्तव्य की कल्पना की है। इस राष्ट्रीय

क्रान्ति की सिद्धि समाजवादी पार्टी के जरिये नहीं बल्कि स्वयं राष्ट्रीय आन्दोलन से हो सकती है। हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि सामाजिक (आर्थिक) शक्तियों को राष्ट्रीय शक्ति से सन्बन्धित करें और समाजिक शक्तियों को आगे लावें। इस प्रकार हम न केवल राष्ट्रीय क्रान्ति को सफल बनायेंगे बल्कि उसके सामाजिक महत्व और उसकी दिशा में भी परिवर्तन करेंगे।

राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीयता का भावना का प्रश्न इससे सम्बन्धित विषय है। 'मजदूरों की कोई पितृभूमि नहीं, यह एक ऐसा नारा है जिसे एक पिछड़ा हुआ मजदूर वर्ग जितना कम मात्रा में समझता है उतनी ही अधिक मात्रा में राष्ट्रीयतावादी मध्यमवर्ग उससे नाराज होता है। हिन्दुस्तान की अपनी एक संस्कृति है। इस पर प्रत्येक भारतीय को, जिसमें समाजवादी भी शामिल हैं, गर्व होना चाहिये। मार्क्स, एंगेल्स और लेनिन ने अपनी राष्ट्रीय संस्कृति में जो श्रेष्ठ बातें थीं उनका सदैव समर्थन किया; उनकी अन्तर्राष्ट्रीयता इस कारण उन्हें अपनाते से नहीं हिचकी। रूस से रेडियो पर जो भाषण ब्राडकास्ट किये जाते रहे हैं वे इस बात को स्पष्टः बताते हैं कि सभी रूसी किसानों और मजदूरों में किस हद तक राष्ट्रीय भावना विद्यमान है और किस प्रकार एक समाजवादी सरकार इस राष्ट्रीय भावना का सहारा लेने से नहीं हिचकती। तब भी भारतीय कम्युनिस्टों ने प्रत्येक भारतीय वस्तु के प्रति अपनी घृणा दिखाकर, भारतीय संस्कृति को, जो कि एक समाजवादी भारत की अनिवार्य पृष्ठभूमि होगी, अस्वीकृत करके, अपनी तोते की तरह रट्टू तरीके से काम करने की आदत से और इस बात की जिद से कि भारतीय मजदूरों और समाजवादियों की पितृभूमि सोवियत रूस है, समाजवाद और कम्युनिज्म के प्रति घोर विरोध पैदा कर दिया है। इसके कारण इस देश में समाजवाद का भविष्य ही अंधेरे में पड़ गया है।

सोवियेट रूस बनाम विश्वक्रान्ति

एक अन्तिम प्रश्न की समीक्षा करना और शेष रह जाता है। वह यह है कि कम्युनिस्ट पार्टियाँ हर बात में मास्को के आह्वानुसार क्यों चलती हैं ? क्या मास्को से नैतिक और आर्थिक सहायता प्राप्त करने की और एक शक्तिशाली सरकारके सम्पर्क से बल प्राप्त करनेवाली भावना इसमें काम करती है ?

इसमें सन्देह नहीं कि यह एक कारण है। पर इससे पूर्णतः इस प्रश्न का समाधान नहीं होता। सच्ची बात यह है कि समाजवादी सरकार की स्थापना और पूँजीवाद के समुद्र में उसकी एकान्त स्थिति ने इस गलत मार्क्सवादी विचार को जन्म दिया कि अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादो आन्दोलन के प्रत्येक स्वार्थ, विश्वक्रान्ति के प्रत्येक स्वार्थ तथा उपनिवेशों की आजादी के आन्दोलन के प्रत्येक स्वार्थ से उस समाजवादी सरकार से स्वार्थ ऊपर होने चाहियें। साधारणतः इस विचार को अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृति प्राप्त होने का कोई अवसर नहीं था। लेकिन प्रथम मजदूर सरकार के केन्द्रस्थल से इसका प्रचार किये जाने और उसके समस्त प्रचार के साधनों का उसके समर्थन में उपयोग होने से यह तथाकथित कम्युनिस्ट इन्टरनैशनल का मौलिक विचार बन गया। रूस का प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसकी इस सिद्धान्त में आस्था नहीं थी, खत्म कर दिया गया। रूस से बाहर जिस किसी ने भी इससे मतभेद रखा उसे इन्टरनैशनल से घुरी तरह निकाल दिया गया। इस प्रकार एक समूचे अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त का विकाश किया गया। इसे मार्क्सवादी भाषा के आवरण में आच्छादित किया गया।

इस सिद्धान्त के अनुसार सोवियत रूस की वैदेशिक नीति में तब्दीली होने के साथ ही कम्युनिस्ट भी पलटे खाते रहे। जर्मनी के कम्युनिस्ट सोशल डेमोक्रेटों से लड़ते रहे और चुनावों में उन्होंने हिटलर का भी साथ दिया।

यूरोप के कम्युनिस्टों ने अवीसीनिया के युद्ध के जमाने में डॉक-मेजदूरों को हड़ताल को इसलिए भग किया कि रूसी तेल फासिस्ट इटली को भेजा जा सके (यद्यपि स्वयं कम्युनिस्ट इण्टरनैशनल ने इटली के बहिष्कार का एलान कर रखा था)। यूरोपीय कम्युनिस्ट पार्टियों ने पूँजीवादी पार्टियों से सहयोग करना शुरू किया और फौजी रकमों पर अपनी मजदूरी देने लगी। फ्रांस के कम्युनिस्टों ने सशुक्त मोर्चे के जमाने में फ्रॉन्च उपनिवेशों के राष्ट्रीय आन्दोलनों का विरोध किया। जर्मन कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से रूस जर्मनी समझौते के जमाने में एलान किया गया कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद ससार की सबसे बड़ी प्रतिगामी शक्ति है और उसका नाश इसलिए आवश्यक है कि उसके एजेन्ट-थीसेन का गुट या सोशल डेमोक्रेट—जर्मन मजदूरों के ऊपर अपना आधिपत्य न कायम कर ले। ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी ने पहले चेम्बरलेन को मजदूरों का दुश्मन नं० १ और हिटलर को दुश्मन नं० २ बतलाया और बाद में चेम्बरलेन के उन्नाधिकारी को बिना किसी हिचक के पूरी मदद दी ताकि जिसे पहले दुश्मन नं० २ कहा गया था उसे हराया जा सके। भारतीय कम्युनिस्टों ने पहले तो यह एलान किया कि इन्क्लाब आ रहा है और ब्रिटिश साम्राज्यशाही के विरुद्ध जन संग्राम की माँग की और उसके बाद वे उसी साम्राज्यशाही, की बिना शर्त सहायता के लिये भी तैयार हो गये। मार्क्सवाद के प्रति यह सारा अविश्वसनीय विश्वासघात इसलिए किया गया कि सोवियत रूस की भलाई के लिए वह जरूरी था अथवा यह कहा जाय कि रूस की सरकार अपनी भलाई के लिए ऐसा जरूरी समझती थी और कम्युनिस्टों को तो हुक्म की पाबन्दी करनी थी। दूसरे शब्दों में, कम्युनिस्टों ने सभी मार्क्सवादी सिद्धान्तों को तिलाजलि देकर, उसके स्थान पर इस नये सिद्धान्त को प्रतिष्ठित किया है कि सोवियट सरकार जो हुक्म दे उसे बजा लाना हमारा फर्ज है। यह बात भी ध्यान देने की है कि रूस की भलाई किस बात में है, इसका

जयप्रकाश की विचारधारा

निर्णय भी अकेले स्टालिन पर छोड़ दिया गया है, अर्थात् यह समझा जाता है कि स्टालिन से गलती हो ही नहीं सकती। कम्युनिस्टों को इससे कोई सरोकार नहीं कि स्टालिन की गलतियाँ काकेशस पर्वत की बड़ी से बड़ी चोटी से भी बड़ी क्यों न हों। चूंकि आखिरी फैसला स्टालिन के हाथों में है इसलिए गलतियाँ करना और उनको दुरुस्त करना उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया जाता है। अनुचर का काम केवल नम्रतापूर्वक आदेशों का पालन करना है।

हमें इस प्रकार के मार्क्सवाद में विश्वास करने से पूरा इन्कार है। जब कि केवल एक ही देश में समाजवादी शासन कायम हुआ हो, इससे बढ़ कर दूसरी स्वाभाविक बात क्या हो सकती है कि पूँजीवादी देश उसके विनाश की बात सोचें ? ऐसी अवस्था में समाजवादी राज्य को बचाने का एक मात्र क्रान्तिकारी उपाय यही है कि सभी देशों में पूँजीवाद को कमजोर करने और उसकी जड़ खोदने की कोशिश की जाय। अगर इस रास्ते पर चला जाय तो समाजवादी राज्य की हार भी (अगर हार हुई भी तो) केवल क्षणिक सिद्ध होगी। उसके पश्चात् न सिर्फ उसी का पुनरुत्थान होगा, बल्कि संसार भर में पूँजीवाद की इमारत चकनाचूर हो जायगी। इस सिद्धान्त में विश्वास न करने का अर्थ यह विश्वास करना है कि पूँजीवादी अवस्था और फासिज्मकी अवस्था कायम रहेगी और साथ ही मजदूर जमात की क्रान्तिकारी शक्ति में अपना अविश्वास प्रकट करना है। यह मानना कि समाजवाद की स्थापना सुदूर भविष्य में, केवल सोवियत रूस की शक्ति से हो सकती है, मार्क्सवाद पर पानी फेरना है। पहले उत्साहहीनता से अपनी रक्षा करने की नीति का अनुसरण करने, फिर राजनीतिक अवसरवाद के अटपटे रास्ते को पकड़ने और दूसरे देशों के समाजवादी आन्दोलनों को रूस की वैदेशिक नीति के अनुसार ढालने की कोशिश करने (ऐसे छोटे-छोटे मामलों तक में जैसे तेल की बिक्री करने के लिए मजबूर करने) के बदले अगर सोवियत संघ ने साहस के साथ काम

समाजवादी एकता

किया होता और विश्वक्रांति के हितों को दृढ़ता के साथ अपने सामने रखा होता या, कम से कम, विभिन्न देशों के क्रान्तिकारी आन्दोलनों में हस्तक्षेप न करके उन्हें अपने इच्छानुसार प्रगति करने दिया होता तो आज यूरोप का इतिहास दूसरा होता। स्टालिन को जानना चाहिये कि जहाँ क्रान्ति जबर्दस्ती नहीं की जा सकती वहाँ 'कुलकों' (समृद्ध किसानों) के बचाव और आत्म-हनन की भावना को अपना कर भी क्रान्ति नहीं की जा सकती। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि रूस के हित विश्व क्रान्ति के हितसे अलग नहीं हैं और सोवियत संघ की रक्षा मात्र ही कोई ध्येय नहीं हो सकता। सोवियत संघ जिन विचारों का प्रतिनिधित्व करता है वे अमर हैं। फासिस्टों की बड़ी से बड़ी विजय भी उन्हें नष्ट नहीं कर सकती। हमें घबराकर पीछे भागने और जो कुछ है उसे ही बचाने की ओर दौड़ने की जरूरत नहीं है। क्रान्ति के झण्डे को आगे लेकर बढ़ते जाना हमारा कर्तव्य है। इस विश्वास के साथ कि संसार में शोषितों का राज्य कायम होकर ही रहेगा।

समाजवादियों और कम्युनिस्टों के झण्डे इन प्रश्नों को लेकर हैं। प्रत्येक समाजवादी का कर्तव्य है कि इन्हें समझकर अपना कर्तव्य निश्चित करे। इन झगड़ों से अपने को तटस्थ रखना जिम्मेदारी से भागना है।

सोशलिस्ट पार्टी: सिंहावलोकन

१.

पार्टी का जन्म १९३४ में हुआ और यह उसका १४ वां वर्ष गुजर रहा है। इन वर्षों में पार्टी बराबर आगे बढ़ती गई है और यद्यपि इसकी मेम्बरी सक्रिय कार्यकर्ताओं को जमात तक ही सीमित है, आज लोकप्रियता के लिहाज से यह देश की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है।

बम्बई के म्यूनिसिपल चुनाव को छोड़कर अब तक इस पार्टी ने स्वतन्त्र राजनीतिक पार्टी की हैसियत से काम नहीं किया है। वेगक इसकी मेम्बरी अलग रही है, इसके कायदे-कानून अलग रहे हैं, किसान और मजदूर हत्कों में भी इसने स्वतन्त्र रूप से काम किया है, मगर राजनीतिक दृष्टि से यह पार्टी कांग्रेस का हिस्सा रही है। राजनीतिक कामों के लिए पार्टी कभी कांग्रेस से अलहदा नहीं थी, और उन मामलों में अपने विचारों का प्रचार करने और उन्हें कांग्रेस कमेटियों के आगे पेश करने के सिवा कुछ नहीं किया। अल्पमत होने के कारण पार्टी की नीति ज्यादातर मौके पर कांग्रेस में नामजूर कर दी जाती रही है। इस वजह से लोगों को लगता है कि पार्टी का रुख हमेशा नकारात्मक रहा है। मगर इसका कारण यह नहीं था कि

हमारी नीति ही वैसी थी, बल्कि अल्पमत होने के कारण उन नीतियों को कांग्रेस से मजूर करवाने, यानी उसकी बुनियाद पर काम करवाने में पार्टी असमर्थ थी। अल्पमत का—या उस मानी में विरोधी दल का ढग लाचारी उसे समय तक नकारात्मक दीख पड़ता है, जब तक कि वह बहुमत में आने की ताकत न हासिल कर ले।

मगर सचचाई तो यह है कि हर बड़े मसले पर, जो देश के आगे आया पार्टी की अपनी स्वतन्त्र नीति थी। जिस साल पार्टी का जन्म हुआ, कांग्रेस में वैधानिक मनोवृत्ति का दौर-दोरा था, हालाँकि पाँच साल पहले पंडित मोतीलाल नेहरू ने लाहौर कांग्रेस में एलान कर दिया था कि आजादी हासिल किए वगैर वैधानिक कार्यक्रम को चलाने का उनका प्रयोग नाकामयाब रहा और उन्हें उस प्रोग्राम की कमजोरियों का विश्वास हो गया। सन् १९३४ में कांग्रेस के बाजाब्ला सविनय अवज्ञा आन्दोलन वापस करने के पहले ही डा० असहरी और डा० विधानचन्द्र राय ने नई स्वराज्य पार्टी का नारा बुलन्द किया था। इस चाल के आगे मई १९३४ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को झुकना पड़ा, न सिर्फ सविनय अवज्ञा आन्दोलन वापस किया गया, बल्कि यह भी फैसला हुआ कि कांग्रेस केन्द्रीय असेम्बली के चुनाव में हिस्सा ले।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पटना अधिवेशन के एक दिन पहले यह पार्टी कायम हुई और इसका पहला नकारात्मक काम हुआ वैधानिक मनोवृत्ति और केन्द्रीय असेम्बली में फिजूल दौड़-धूप करने की नीति का विरोध। पार्टी का तर्क था कि इस नीति से देश का ध्यान अगली लड़ाई की तैयारियों से हट जायगा और कार्यकर्ताओं की शक्ति बेजान बहस-मुवाहिसों में बर्बाद होगी।

पार्टी का दूसरा 'नकारात्मक' काम १९३५ के विधान में मन्त्रिपद ग्रहण करने की नीति का विरोध था। इस विरोध में सिर्फ यह पार्टी ही नहीं थी,

जयप्रकाश की विचारधारा

बल्कि स्वयं पंडित नेहरू और दूसरे प्रमुख कांग्रेसी नेता भी थे । पार्टी के सुझाव पर कांग्रेस जनों की मंत्रिपद-विरोधी कमेटी सरदार शार्दूल सिंह कवीश्वर की अध्यक्षता में बनाई गई । सरदार शार्दूल सिंह कवीश्वर ने इस सवाल पर कांग्रेस कार्यसमिति से इस्तीफा भी दे दिया । श्री रफी अहमद किदवाई और श्री मीनूमसानी उस कमेटी के संयुक्त मंत्री बनाए गए । मसानी उस समय अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी के भी संयुक्त-मंत्री थे ।

वह विरोध एक प्रकार का 'नकारात्मक' रख था । किन्तु इतने वर्ष बाद भी उस घटना पर विचार करने पर मेरा विश्वास बना हुआ है कि उस समय मंत्रिपद ग्रहण करना बुरा हुआ । उससे फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उसके चलते कांग्रेस में ताकत और ओहदा पाने की ऐसी मनोवृत्ति पैदा हो गई कि आज कांग्रेस का सर्वनाश होने का खतरा है ।

इतने वर्षों तक कांग्रेस के अन्दर रह कर पार्टी ने जो कुछ काम किया, उसका व्योरा मैं यहाँ नहीं देना चाहता । मेरा मकसद सिर्फ़ पोछे मुड़कर उन कामों का लेखा-जोखा लेना है । मैं देखता हूँ कि इन वर्षों में हम लोगों का सारा समय कांग्रेस के कामों में या कांग्रेस पर अपना असर डालने में खर्च हुआ ।

यहाँ मैं कह देना चाहता हूँ कि कांग्रेस के अन्दर हमलोगों की हैसियत वामपक्षीय अल्पमत की थी फिर भी बहुत से ऐसे मौके आये जब कि बहुमत के विचारों से हमारा पूरा-पूरा इत्फाक था । खासकर राष्ट्रीय संग्राम के मौकों पर पार्टी के मेम्बरो ने कांग्रेस के उत्साही सिपाहियों की तरह काम किया और दूसरे कांग्रेस जनों के कन्धे से कन्धा भिड़ाया । हमारे आलोचक आम तौर पर हमारे इस काम को नजरअन्दाज कर जाते हैं ।

कांग्रेस के अन्दर रहकर हमने जो-कुछ किया, उसका हिसाब-किताब करने पर कोई भी कह सकता है कि हमने बराबर समझौते की नीति की

रोक-थाम को ; हमने कांग्रेस को लड़ाई का मोर्चा बनने की ताकत दी और हमलोगो ने कांग्रेस के अन्दर समाजवाद के लिए मुफ़ीद आबोहवा पैदा की । आज हर कांग्रेसी, सचमुच वह समाजवादी हो या नहीं, अपने को समाजवादी करार देने को परेशान रहता है ! यह हमारी पार्टी के कामों की मकबूलियत और तारीफ है ।

कांग्रेस के अन्दर अपने कामों के सम्बन्ध में एक और आलोचना है, जिसके मुतल्लिक मैं कुछ कहना पसन्द करूँगा । हमने जिस हद तक कांग्रेस के रचनात्मक कार्यों में हाथ बँटाया, उससे कहीं ज्यादा हमें करना चाहिए था । हमने ख्याल पैदा किया कि सब रचनात्मक कार्य गैरइन्कलाबी हैं और सोशलिस्टों के लिए वक्त की बर्बादी । इस तरह के ख्याल की जिम्मेवारी हमलोगों पर और खासकर मुझ पर सबसे ज्यादा है । मैं दर्ज करना चाहूँगा कि वह ख्याल बिल्कुल गलत था ! अगर हम उन तामीरी कामों में लगे होते तो मुमकिन है, हम उनमें कितने ही बेशकीमती पहलुओं का इजाफा करते । लेकिन, यह सब किस हद तक हो पाता, आज पूरे भरोसे के साथ नहीं कहा जा सकता, फिर भी इसमें कोई शक नहीं उन कामों से अलग रहकर हमने तजुर्वे की बहुत-सारी दौलत खो दी । उन कामों में हमारे लिए बड़े पैमाने पर जनता के पास पहुँचने का और हिन्दुस्तान के देहात की समस्याओं को नजदीक से समझने का मौका था ।

हालाँकि हमारा ज्यादा वक्त कांग्रेस के अन्दर के कामों में लगा, फिर भी हमारे काम सिर्फ कांग्रेस तक ही महदूद नहीं थे । शुरू से ही हमारे कामों के दो प्रधान विभाग थे : एक कांग्रेस के अन्दर और दूसरा कांग्रेस से बाहर । जबकि हमारे राजनीतिक कार्य कांग्रेस के अन्दर या उसके इर्द-गिर्द चलते हम आर्थिक और समाजी तबकों से सम्बन्धित अपने कार्य बिल्कुल स्वतंत्र रूप से करते थे । वर्गगत अन्याय को दूर करने और वर्ग की फौरी

जयप्रकाश की विचारधारा

माँगों को पूरी करने की लड़ाई चलाने के लिए किसानों और मजदूरों का संगठन बनाना हमारी पार्टी के प्रोग्राम का पहला काम रहा। यह विश्वास भी बिल्कुल सही था कि इस काम से जनता न सिर्फ समाजवाद कायम करने के लिए तैयार होगी बल्कि फौजी तौर पर साम्राज्यशाही के खिलाफ लोहा भी लेगी।

जिस समय पार्टी कायम हुई, देश का मजदूर-आन्दोलन तीन-संस्थाओं में बँटा हुआ था—(१) अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (२) कम्यूनिस्ट रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस और (३) नेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन्स। इन तीनों में से हम ने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस को अपने लिए चुना क्योंकि यही संस्था राजनीतिक ख्यालों में हमसे सबसे ज्यादा करीब थी। शुरू में ही पार्टी और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बीच समझौता हो गया जिसके मुताबिक पार्टी ने ट्रेड यूनियन कांग्रेस को मजदूरों का केन्द्रीय संघटन माना और अपनी मजदूर-यूनियनों को उससे सम्बद्ध करना मजूर किया, ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने भी सोशलिस्ट पार्टी को मजदूर-वर्ग की राजनीतिक पार्टी कबूल करके उसे अपनी मदद देना स्वीकार किया।

ट्रेड यूनियन कांग्रेस की पूरी सहमति से पार्टी ने ट्रेड यूनियन आन्दोलन की एकता का नारा बुलन्द किया और तीनों संस्थाओं को एक करने में बहुत बड़ा काम किया। मेल हो जाने के बाद संयुक्त संस्था का नाम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ही रखा गया, क्योंकि इस नाम की संस्था ही मूल संघटन थी जिससे बाकी दोनों दल फूट निकले थे।

समझौते के बाद से तीनों संस्थाओं के एक हो जाने तक अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस में पार्टी का ही बोलबाला था। यह पार्टी द्वारा

चलाये गये मजदूर-कायों की वजह से नहीं, बल्कि बहुत-से प्रमुख ट्रेड यूनियन नेताओं के पार्टी में दाखिल हो जाने से हुआ था। हमें स्वीकार करना चाहिए कि उस समय के ट्रेड यूनियन सम्बन्धी हमारे कामों में वैसी कोई बात नहीं थी जिसके लिए हम खास तौर से फख करे। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि आजादी की लड़ाई के तकाजे उस समय इतने महत्वपूर्ण थे और हम में से अधिकतर लोग उससे इतने नजदीक थे कि दूसरी तरह के कामों के लिए हमें बहुत कम वक्त मिलता था। अगस्त क्रान्ति के बाद पार्टी में नया खून दौड़ा और बहुत सारे नए लोग आए और तब हम मजदूर-आन्दोलन में चारों ओर फैल सके। इसके बाद से इस क्षेत्र में जो कुछ काम हुआ है उसके लिए पार्टी को वाजिब फख हो सकता है। अफसोस की बात है, पंजाब में हमारे इन कामों का बहुत बड़ा हिस्सा उस दुखी इलाके की बर्बादियों में खत्म हो गया है।

पिछली लड़ाई के जमाने में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस में कम्युनिस्टों के कारनामों से जो फूट पैदा हुई है, वह इतनी हाल की बात है कि उसका तफसील में जिक्र करना फिजूल है। अफसोस की बात है कि मजदूर-आन्दोलन में इस तरह फूट पड़ जाय। लेकिन अगर राजनीति, उसूलों में इतना फर्क आ जाय और अच्छे बुरे की परवाह किए बगैर राजनीतिक मकसदों के लिए मजदूर-वर्ग का इस्तेमाल किया जाय तो फिर फूट बिल्कुल लाजिम हो जाती है। अगर कांग्रेस गाँधीवादी सिद्धान्तों का मजदूर-आन्दोलन में प्रयोग करने के नाम पर मजदूर आन्दोलन को सरकार की दुम में बाँधने की कोशिश नहीं करती तो मजदूर आन्दोलन में हिस्सा लेनेवाली गैरकम्युनिस्ट ताकतें कम-से-कम एक पाँत में खड़ी रहतीं। राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की सङ्कुचित और मनमानी नीति की वजह से उन ताकतों के लिए अलग हो जाने के सिवा कोई चारा नहीं था। मुझे तो जान पड़ता है कि इन

जयप्रकाश की विचारधारा

ताकतों को देश की किसी दूसरी मजदूर संस्था में लाजिमी तौर पर संघटित होना ही है ।

इस देश के किसान हालाँकि बेतरह पीड़ित और शोषित हैं, सोशलिस्ट पार्टी के जन्म के समय उनका कोई सुन्दर संघटन नहीं था । युक्तप्रात में अवध के किसान-आन्दोलन की तरह छिटफुट किसान आन्दोलन चलते थे । बिहार में भी प्रांतीय कांग्रेस ने १९२९ में प्रान्तीय सरकार और जमीन्दारों की साजिश से लागू किए गए रयतवारी कानूनों की मुखातिफत के लिए एक किसान-सभा बनाई थी । लेकिन प्रधानतः सोशलिस्ट पार्टी की मेहनत से और स्वामी सहजानन्द सरस्वती और फिर प्रो० एन० जी रंगा की जोर-दार मदद से अखिल भारतीय किसान सभा कायम की गयी । शुरु में कम्युनिस्टों का कही से कोई पता नहीं था लेकिन समाजवादी एकता की खतरनाक नीति कबूल हो जाने के बाद, वे भी उसमें दाखिल हो गए । उसके बाद से इस संस्था का इतिहास फूट और गुटबन्दियों की ऐसी कहानी है, जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के इतिहास से भी ज्यादा तकलीफदेह है । आज पार्टी के आगे एक मुश्किल सवाल यह भी है कि किस तरह किसान-आन्दोलन का मुनासिब संघटन किया जाय । क्या हम पुरानी किसान सभाओं से ही काम चलाते रहे, जो वर्ग-संघटन से ज्यादा राजनीतिक अखाड़ा हैं या हम कोई ज्यादा दुरुस्त संघटन बनावें ! मैं उम्मीद करता हूँ कि यह कान्फ्रेंस इस सवाल का सही जवाब देगी ।

विद्यार्थी और स्वयं-सेवक-आन्दोलन भी पार्टी के दो ऐसे कार्यक्षेत्र हैं, जिनका जिक्र किया जा सकता है । जहाँ-कहीं पार्टी ने कांग्रेस स्वयंसेवक संघटन से अलग होकर अपना संघटन बनाया, हमारा काम वक्त की गरिज को झेल सका है । अब तमाम प्रान्तीय और जिला स्वयंसेवक संघटनों को एक

सोशलिस्ट पार्टी : सिंहावलोकन

राष्ट्रीय सघटन में समन्वित करने का काम बाकी है और उसे हमलोगो को पूरा करना है ।

विद्यार्थी आन्दोलन को कम्यूनिस्टों के असर का लाजिमी नतीजा भुगतना पड़ा है । अखिल भारतीय छात्र-संघ के निर्माण में पार्टी का भी बड़ा हाथ था लेकिन वह शीघ्र ही कम्यूनिस्ट पार्टी का रंगमंच बन गया और उसका नतीजा हुआ आपसी फूट । छात्र-कांग्रेस के ऊपर पार्टी का अच्छा-खासा असर है और इस सघटन ने आजादी की लड़ाई में शानदार हिस्सा भी लिया, लेकिन आज फिर छात्र आन्दोलन में गड़बड़ी पैदा हो गई है । मेरी उम्मीद है कि तमाम गैरकम्यूनिस्ट विद्यार्थी एक होकर रहेंगे और कम्यूनिस्टों की एकता के झूठे नारों से सावधान होकर उनके साथ जाने से इंकार करेंगे । मेरा शुरु से ख्याल रहा है कि छात्र-कांग्रेस में हमारी पार्टी के जितने विद्यार्थी हैं वे ओहदे के लिए कोशिश नहीं करेंगे । हाल की घटनाओं के बाद से मेरा यह विचार और भी दृढ़ हो गया है । मुझे लगता है कि अगर हमारे विद्यार्थी भाई अध्ययन और वाद-विवाद के लिए सोशलिस्ट छात्र क्लब बनावे और पार्टी के रास खास काम करें, तो ज्यादा अच्छा हो ।

यहाँ अगर हम समाजवादी एकता की नुकसानदेह नीति का जिक्र नहीं करें तो फिर हमारे पिछले कामों का यह लेखा-जोखा अधूरा हो रहेगा । करीब-करीब अपनी पैदाइश से ही पार्टी ने इस नीति पर भ्रमल किया और इसका जो नतीजा भुगतना पड़ा वह हम सब को अच्छी तरह मालूम है । उसका वर्णन पार्टी द्वारा प्रकाशित पुस्तक में भी आ गया है । इसलिए इन बातों की तफसील में यहाँ जाने की जरूरत नहीं । कम्यूनिस्टों के विश्वासघात और दुर्गति चाल की वजह से दक्षिण भारत में पार्टी की पुरानी ताकत आज-तक नहीं लौट पाई है । लेकिन, हालाँकि उस नीति का नतीजा बहुत नुकसानदेह साबित हुआ, तबुँ के लिहाज से उस गलती की भी एक कीमत

जयप्रकाश की विचारधारा

है। क्योंकि उससे हमें ऐसा सबक मिला है जिसे कभी भूला नहो जा सकता। सिद्धांतों या दूसरे देशों के तजुर्बे से हम कम्यूनिस्टों को उतनी अच्छी तरह नहीं जान पाते, जितना कि हमने खुद अपने तकलीफदेह तजुर्बे से जाना है। आज वह सबक हमारे काम आयेगा, क्योंकि कम्यूनिस्टों ने फिर वामपक्षीय एकता का नारा लगाना शुरू किया है।

पार्टी के कामों को दो और साधारण आलोचनाओं का जिक्र करने के बाद, मैं इस ब्योरे को खत्म करूँगा।

पिछले कुछ महीनों से देश के अन्दर जो घरेलू फसाद जारी है, उसके सम्बन्ध में कुछ लोगों का कहना है कि यह सब अगस्त क्रान्ति के जमाने में हिंसा के प्रचार का नतीजा है।

यह घरेलू फसाद बुनियादी तौर पर यों आप-से-आप शुरू नहीं हुआ, बल्कि यह सब एक योजना के मुताबिक चलाया गया है। इसकी जड़ें साम्राज्यवादी नीति में छिपी हुई हैं। फसाद का उसूल और तौर-तरीका यूरोप के फासिज्म से जी खोलकर उधार लिया गया है। इसपर तानाशाही और विश्वयुद्ध की वजह से पैदा हुई इन्सानो अराजकता का भी असर है। अगस्त-क्रान्ति के काले पहलुओं की भी इसमें थोड़ी जिम्मेवारी हो सकती है। लेकिन इतना कबूल कर लेने के बाद समाज के डाक्टरों को राष्ट्रीय रोग के एक दूसरे लक्षण की ओर भी ध्यान देना चाहिए। घरेलू फसाद के साथ देखा जाता है कि सार्वजनिक चरित्र भी अचानक काफी नीचे गिर गया है। जो लोग कल तक ऊँचे आदर्श और अहंसा की बात करनेवाले थे, आज अपने सारे आदर्शों को ताक पर रख कर सियासी ताकतबाजी में और रिश्तेदारों को ओहदों पर बिठाने में हो लगे हैं। और कुछ तो भ्रष्टाचार में भी गर्क हैं ऐसा क्यों है? क्यों हमारी राष्ट्रीयता भी बहुत मामलों में बिगुल छिछली साबित हुई है? क्यों हमारे दिलों में साम्प्रदायिकता आ गया है? क्यों और

सोशलिस्ट पार्टी : सिंहावलोकन

प्रान्तीयता, जातीयता और ऐसे ही दूसरे-दूसरे जहर भी हैं ? मैं कह सकता हूँ जिस अहिंसा और सत्य की बढ-बढ कर दुहाई दी जाती थी, वह सिर्फ लोगों को खामख्याली थी। सत्य और अहिंसा उनके विश्वास की वस्तु होकर कमजोरियों को छिपाने का बहाना है। मेरा तो ख्याल है 'कि अहिंसा और सत्य को नकाब के तौर पर इस्तेमाल करने के बनिस्वत हिंसा के साफ-सुथरे हथियार में विश्वास करना ज्यादा अच्छा है। 'मगर इसके मानी ये नहीं कि मैं हिंसा की सिफारिश करता हूँ क्योंकि इसकी भी एक नैतिक सीमा है। मेरा इतना हो कहना है कि अगर हिंसा के नतीजे बुरे हो सकते हैं, तो झूठी अहिंसा उससे भी ज्यादा नुकसानदेह साबित होगी।

हमारी दूसरी आलोचना, जो पिछले दिनों हुई है, वह यह कि हम आनेवाली घटनाओं का अनुमान करने में हमेशा असफल रहे हैं या भावी घटनाओं का हमारा अनुमान हमेशा गलत साबित हुआ है। उदाहरण के लिए कहा जाता है कि हमने केबिनेट भीशन के नाकामयाब होने की बात कही थी और बताया था कि अंगरेजों के साथ एक और संघर्ष अवश्यभावी है। उसी तरह इल्जाम लगाया जाता है कि हमारा विधान-परिषद का बहिष्कार करना और कहना कि इसे आजाद हिन्दुस्तान के लिए विधान का मसविदा तैयार करने का आखिरी अस्तिथार नहीं है—बिल्कुल गलत निकला। कहावत है कि ठस लगने पर अक्ल बढती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो तजुबों से सबक लेना नहीं जानते।

मैं समझ नहीं पाता कि किस तरह इतिहास ने हमारे फैसलों को गलत साबित किया। यदि हम अपने सिद्धान्तों को नहीं छोड़ते तो अंगरेजों से हमारी लड़ाई अवश्यभावी थी। हाँ, यह कहना मुश्किल है कि उस लड़ाई की क्या सूरत होती ? बावेल और जिन्ना का पड़यंत्र सफल हो जाने के बाद कांग्रेस के लिए तमाम पुराने समझौते को खत्म कर फिर लड़ाई छेड़ने के

जयप्रकाश की विचारधारा

सिवा दूसरा कोई चारा नहीं था। लेकिन गहरी कीमत चुकाकर हमने अपना बचाव किया—हालाँकि हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि कांग्रेस किसी दशा में इतनी गहरी कीमत चुकायगी।

सोशलिस्ट पार्टी का युद्ध-कौशल और परिस्थिति का अध्ययन इसी बुनियाद पर कायम था कि कांग्रेस देश का बँटवारा कभी मजूर नहीं करेगी। अगर बँटवारा मजूर नहीं किया जाता, तो कांग्रेस को अन्तरिम सरकार से इस्तीफा देकर, पूर्ण स्वाधीनता के सवाल पर अंगरेजों का सामना करना पड़ता। वेशक कांग्रेस ने अपने समाजवादी पक्ष की समिति के साथ ही आत्म-निर्णय के सिद्धान्त को मजूर किया था, लेकिन उस सिद्धान्त का प्रयोग अंगरेजों के चले जाने पर होनेवाला था, न कि उनकी मदद और उनकी देख-रेख में। बँटवारे को कबूल करके कांग्रेस ने सिर्फ अधकचरी आजादी पाई। और यह सब करनेवालों के लिए तो यही मुनासिब था कि वे दूसरों पर घटनाओं के गलत अनुमान का इल्जाम नहीं लगाते।

मैं फिर एक बार कह देना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस अपनी सच्ची राह से भटक नहीं गई होती, और अपने सिद्धान्तों पर झुकी नहीं होती, तो सोशलिस्ट पार्टी के सुझाव के मुताबिक काम करने के सिवा उसके लिए कोई दूसरा चारा नहीं था।

विधान परिषद् के सम्बन्ध में भी कहा जाता है, कि हमने एक बार इसका बहिष्कार किया और अब नक्शे में अपनी कोई जगह न देखकर अफसोस कर रहे हैं। लोगों की आम आदत है कि अपने मापदण्ड से ही वे दूसरों को भी मापते हैं। जहाँ तक हमलोगों का सवाल है, हमें विधान परिषद् के बहिष्कार का कतई अफसोस नहीं है। बहिष्कार करके हम देश को साफ-साफ जता देना चाहते थे कि अंगरेजों के साथ समझौता बुनियादी तौर पर गलत हुआ। उस समझौते को पूरा-पूरा नामजूर करना चाहिए था। क्योंकि

सोशलिस्ट पार्टी: सिंहावलोकन

उसके एक हिस्से को छोड़ कर बाकी को कबूल करना हृदय की राजनीतिक अवसरवादिता होती। घटनाएँ आगे बढ़ी और मुस्लिम लीग विधान परिषद से बाहर हो गयी, फिर तो उसके बाद साफ हो गया कि विधान परिषद का जो हिस्सा बाकी बचा है, वह आजाद हिन्दुस्तान के लिए विधान बनाने में असमर्थ है। तब सिर्फ एक ही काम बच गया था। और जैसा कि मैं ऊपर कह चुका हूँ, समझौते को फाड़कर अंतरिम सरकार और विधान परिषद से कांग्रेस को निकल आना चाहिए था, और जनता द्वारा चुनी गयी सच्ची विधान परिषद बुलायी जानी चाहिए थी। तभी वह विधान परिषद इन्कलाबी ताकत का केन्द्र होती और आखिरी मुकाबले के लिए अगरेजों को चुनौती दे पाती। वैसे विधान परिषद के साथ सोशलिस्ट पार्टी पूरा सहयोग करती और उसके फैसलों को अमल में लाने की पूरी जिम्मेवारी लेती।

हमलोगों से कहा गया कि वैसे करने से गृहयुद्ध होगा और पाकिस्तान मंजूर कर लेने से हम उस युद्ध से बच जायेंगे। हमने जवाब में कहा था कि पहले तो हमें उस खतरे को लेना चाहिए और दूसरे, पाकिस्तान को कबूल करने से वह खतरा दूर नहीं होगा, बल्कि बढ़ जायगा। लेकिन सालों से हासिल होनेवाली ताकत को अपनी चपकलिश थी, जिसके लालच से बचना नामुमकिन था। किंतु इतिहास ने उसके अफसोसनाक नतीजे भी दिखा दिये। इतना कुछ होने के बाद भी ऐसे लोग हैं जो अपनी जीत की डींग झाँकते हैं और दूसरों के सिर सिर्फ गर्मागर्म बहस करने का दोष मढ़ते हैं।

दूसरे दलों की तरह सोशलिस्ट पार्टी ने भी गलतियाँ की हैं, लेकिन अगरेजों के सम्बन्ध में उसने जो नीति बनायी थी वह उन गलतियों में नहीं है, बल्कि वह ऐसी नीति थी, जिसके लिए पार्टी को हमेशा फख्र हो सकता है।

आगे का रास्ता

अब मैं ऐसे सवाल पर विचार करूँगा जिस पर बहुत दिनों से वाद-विवाद चल रहा है और अब जिसका अन्तिम फैसला जरूरी हो गया है। हमलोग बहुत दिनों से बहस करते आ रहे हैं कि पार्टी कांग्रेस के अन्दर रहे या निकल आवे ? दोनों ओर से वजनी दलीलें पेश की जाती हैं लेकिन इधर हाल से एक ही पक्ष की दलील अधिक वजनी पड़ रही है। कुछ हफ्ते पहले मैंने इस सवाल के पक्ष और विपक्ष का विश्लेषण करते हुए एक लेख प्रकाशित किया था जिसमें मैंने अपने निजी विचार प्रकट किये थे।

उस लेख के प्रकाशित होने के बाद ऐसी घटनाएँ हुईं जिनसे मसला और भी साफ हो गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिल्ली अधिवेशन ने कांग्रेस के नये विधान के लिए कुछ दुनियाद्वी उसूल मजूर किये हैं। इन उसूलों से यह साफ है कि कांग्रेस अब एक राष्ट्रीय मोर्चा नहीं रही—यहाँ तक कि राष्ट्रीय सकटकाल में भी नहीं। कांग्रेस अब एक पार्टी की शकल अख्तियार करेगी और कांग्रेस, जो सारे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती थी, जिसने इसकी आजादी को लड़ाई लड़ी और जिसमें सारी जनता का विश्वास था, वह कांग्रेस अब न रही, सिर्फ उसका नाम रह गया है। दर असल उसका नाम भी हटा देना चाहिए था ताकि कांग्रेस के नाम जो महान परंपरा जुड़ी हुई है, वह दलबन्दी से پاک रहती !

ऐसी परिस्थिति में पार्टी को कांग्रेस से जरूर अलग हो जाना चाहिए। हिन्दुस्तानी समाजवाद की जरूरतों की यही तकाजा है।

इन दलीलों के अलावा और भी कुछ ऐसी दलीलें हैं जो कि इसी नतीजे पर हमें ले जाती हैं। ऊपर मैंने जिस लेख का जिक्र किया है, उसमें एक

विरोधी पार्टी की ज़रूरत की ओर सरसरी तौर पर इशारा किया गया है ।
इधर वह ज़रूरत और बढ़ गयी है ।

अपने बीच गाँधीजी के रहने से नागरिक अधिकार और जनता की आजादी सुरक्षित थी । अब जब वे हमारे बीच नहीं हैं तब तानाशाही हुकूमत के खतरे बढ़ गये हैं । अगर देश में एक विरोधी पार्टी न रही तो ये खतरे और भी बढ़ जायेंगे, लेकिन विरोधी पार्टी ऐसी हो जिसको देशभक्ति और लोकतन्त्र में विश्वास अटूट हो ।

आज जो लोग सरकार चला रहे हैं वे व्यक्तिगत तौर पर अच्छे लोग हैं और बेशक देश की सेवा करना चाहते हैं लेकिन जहाँ उनमें से कुछ कट्टर लोकतन्त्रवादी हैं, वहाँ कुछ लोगों ने जनता के अधिकार की उपेक्षा तक की है । जो शासन मशीनरी ब्रिटिश सत्ता के हित के लिए गठित की गयी थी और जिसे जनता को इच्छा तथा भलाई की उपेक्षा करने को सिखाया गया था, वही पुरानी शासन मशीनरी आज भी ज्यों की त्यों कार्य कर रही है । एक वाक्य में आज की हालत को हम इस तरह लिख सकते हैं कि अंग्रेज चले गये हैं, आई० सी० एस० वाले आ गये हैं ।

जब अंग्रेजी राज यहाँ था, तब कांग्रेस जनता की चेतना का प्रतिनिधित्व करती थी और उसके हित के लिए लड़ने वाली सत्ता थी । अब कांग्रेस हुकूमत में इतनी घुलमिल गयी है कि उसने जनता के अधिकार की हिफाजत की ताकत खो दी है । दर असल कांग्रेस का आज प्रमुख कार्य है सरकार का पक्ष लेना और जनता के सामने इसकी हर कार्रवाई को उचित करार देना, चाहे वह गलत हो या सही हो ।

इन्हीं सब बातों के कारण आज भयानक स्थिति पैदा हो गई है । टीका-टिप्पणी यहाँ तक कि लाभदायक टिप्पणी का भी विरोध किया जाता है और आलोचना की जवान को बन्द कर देने की कोशिश की जाती है । ऐसी मिसालें

जयप्रकाश की विचारधारा

भी हैं कि आपत्तिजनक लेकिन सही खबर या विचार प्रकाशित करने के लिए प्रकाशक पकड़े गये हैं। सरकार के हाथ में जो प्रचार के साधन हैं, जैसे ऑल इन्डिया रेडियो, उनका हुक्मत करने वाली पार्टी द्वारा अपनी पार्टी के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हुक्मत की ताकत राजनीतिक कार्यकर्ताओं के कार्यों पर बिना सोच-विचार के रोक लगा रही है क्योंकि ये कार्यकर्ता सरकार के समर्थकों की राह के कांटे बन जाते हैं। इन्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नेताओं की सिफारिशों के मुताबिक मजदूर कार्यकर्ताओं को जेलों में बन्द करने की भी मिसालें हैं। प्रतिद्वन्द्वी राजनीतिक दलों को दवाने के लिए दफा १४४ और १०७ का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है। जन-सुरक्षा कानून का भी इस्तेमाल उसी मकसद के लिए किया जा रहा है। ऐसे लोगों के भी उदाहरण हमारे पास हैं जिन्हें सोशलिस्ट पार्टी के प्रति हमदर्दी दिखाने तथा इसके फड में चन्दा देने के कारण धमकी दी गयी है कि उसका नतीजा बहुत बुरा होगा। सरकारी कर्मचारियों को हुक्मत करने वाली पार्टी का गुलाम बना दिया गया है। जहाँ तिजारती, औद्योगिक तथा इस तरह के अन्य सार्वजनिक महकमों के कर्मचारियों को छोड़ कर बाकी सभी को सक्रिय दलंगत राजनीति से अलग रखना चाहिए, वहाँ अपनी इच्छा के मुताबिक उन्हें किसी भी पार्टी में शामिल होने और चुनावों में उसके लिए वोट देने की आजादी होनी चाहिए वरन् कि वह पार्टी खुले तौर पर और कानून के अन्दर रहकर कार्य करने वाली हो। आज कर्मचारियों को यह हक नहीं दिया जा रहा है। ऐसी भी बेहूदी मिसालें हैं जब कि स्कूल के शिक्षकों तक को राजनीति से अलग रहने का आदेश दिया गया है। हम जैसे-जैसे समाजवाद की ओर बढ़ेंगे सरकारी नौकरियों में शामिल होने वाले लोगों की तादाद बढ़ती ही जायगी। और अगर उन सब को राजनीति में भाग लेने का मौका नहीं दिया गया तो फिर हम एक भयानक तानाशाही-प्रणाली कायम करेंगे जिसमें हुक्मत

सोशलिस्ट पार्टी : सिंहावलोकन

करनेवाली पार्टी के अलावा किसी भी दूसरी पार्टी के रहने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी । इन्हीं सब गंभीर बातों पर विचार करने से एक विरोधी पार्टी का रहना जरूरी जाना पड़ता है । एक पार्टी शासन अथवा एक विरोधी पार्टी, जो लोकतंत्र में विश्वास रखती हो और जो देश तथा राज्य के प्रति वफादार हो, ऐसी पार्टी के रहने से तानाशाही के विकास को निश्चय ही प्रोत्साहन मिलेगा खास तौर से आज जब कि बिगड़ी हुई हालत के कारण अधिकारियों को बहुत हक मिल गए हैं ।

देश की आज जो हालत है, उसमें केवल सोशलिस्ट पार्टी विरोधी पार्टी की जरूरत पूरा कर सकती है । यह कोई बड़ा-चढ़ाकर नहीं कहा जा रहा है, दर असल यह वास्तविक स्थिति की सच्ची तस्वीर है ।

इस तरह सवाल के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि हमें अब कांग्रेस छोड़ देना चाहिए और एक स्वतंत्र राजनीतिक पार्टी के रूप में काम करना चाहिए । मुझे इसमें शक नहीं कि आप सब भी इसी नतीजे पर पहुँचेंगे ।

कांग्रेस से अलग होने का फैसला हम पर बड़ी-बड़ी जिम्मेदारियाँ डालता है । मैं यहाँ बड़े अदब के साथ कुछ बुनियादी उसूल का जिक्र करना चाहता हूँ जो हमें नये राजनीतिक जीवन में रास्ता दिखायेगा ?

सबसे पहली बात यह है कि कांग्रेस से अलग होने का हमारा फैसला हमारे बहुत-से ऐसे दोस्तों को चिन्तित करेगा जिनका दलबन्दी से स्वार्थ नहीं है लेकिन जिनका राष्ट्र के भविष्य से गहरा सम्बन्ध है । मैं खास तौर से उन दोस्तों की बात कह रहा हूँ जो यह विश्वास करते हैं कि राष्ट्रीय सकट काल में अलग होने की नहीं, कन्धे में कन्धा मिलाकर चलने की जरूरत है ।

हम ऐसे दोस्तों को आश्वासन दें और उनके शक को दूर करें । अपने देश में लोग पार्लमेटरी सरकार के तरीकों से परिचित नहीं हैं, अतः वे लोक-

जयप्रकाश की विचारधारा

तान्त्रिक विरोध के स्वरूप को भी नहीं जानते। विरोध को लोग उसी अर्थ में समझते हैं जिस मानी में कांग्रेस ब्रिटिश हुकूमत का विरोधी थी। ब्रिटिश हुकूमत की जड़ उखाड़ने के लिए कांग्रेस ने सीधी चोट का तरीका अस्तित्वार किया था।

लोकतांत्रिक ढाँचे में विरोध का वह ढग नहीं हो सकता है। जब लोक-तांत्रिक सरकार हो, तब हुकूमत करनेवाली पार्टी और विरोधी पार्टी (वर्शतें वह लोकतांत्रिक पार्टी हो) दोनों में राज्य के प्रति वफादारी निभाने और लोकतांत्रिक तरीकों पर अमल करने के सवाल पर एकता रहती है, राष्ट्रीय सकट काल में भेद-भाव भुलाकर और अपनी-अपनी पार्टी का अलग अस्तित्व कायम रखते हुए दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। एक लोकतांत्रिक ढाँचे में विरोधी पार्टी अराष्ट्रीय पार्टी नहीं रहती है, बल्कि यह पार्टी राष्ट्र-सेवा के लिए हुकूमत करनेवाली पार्टी से भिन्न और अपने अनुसार बेहतर तरीकों की वकालत करनेवाली होती है। अंग्रेजों के जमाने में कांग्रेस विरोधी होना राष्ट्र-विरोधी होना था क्योंकि कांग्रेस विदेशियों के विरुद्ध सारे राष्ट्र की ओर से लड़ती थी। अब जब देश आजाद है, तब लोगों के मन में यह विचार बिठाना होगा कि कांग्रेस का विरोध करना अराष्ट्रीय कार्य नहीं, बल्कि हुकूमत की कुछ नीतियों और तरीकों का विरोध करना है और साथ ही दूसरे रास्ते की वकालत करना। इसके अलावा कांग्रेस के विरोधी होने का मतलब है लोकतांत्रिक तरीकों द्वारा हुकूमत करनेवाली पार्टी को हटाना।

देश बड़े राष्ट्रीय सकट काल से गुजर रहा है और साथ ही इस पर बड़े-बड़े बाहरी खतरे हैं—इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। ऐसे वक्त एक मकसद तथा आदर्श रखने वाली पार्टियाँ सहयोग करे और सकट का मुकाबला करें। कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी में कुछ समानता है,

सोशलिस्ट पार्टी : सिद्धान्तलोकन

लोकराज में उनका विश्वास उन्हें देश को दूसरी किसी भी पार्टियों से अधिक नजदीक करार देता है ।

इसका मतलब यह होता है कि सोशलिस्ट पार्टी राज्य तथा लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए ओर फिरकापरस्त तथा प्रतिक्रियावादी ताकतों के खिलाफ बराबर लड़ने के लिए तैयार रहेगी । इस तरह की लड़ाई में पार्टी कांग्रेस के साथ हाथ बँटावेगी ।

देश को इन बातों का भरोसा लफ्जों के बदले काम के जरिए देना हमारा फर्ज होगा ।

इस बारे में मैं एक आखिरी बात कह भी दूँ । मैं यह जानता हूँ कि कांग्रेस से अलग होने पर हम बहुत-से दोस्तों और अच्छे साथियों को पीछे छोड़ देंगे, लेकिन जिनसे हम लोगों का व्यक्तिगत और उसूली रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा । अलग होकर भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम उनका साथ दें ; और मैं उम्मीद करता हूँ कि विरोधी दल के रूप में कार्य कर हम लोग उनका काम आसान कर देंगे ।

अब, मैं ऐसे मसले पर विचार करने की इजाजत चाहता हूँ जिस पर इधर हाल से मैं बहुत सोचता-विचारता रहा हूँ । वह मसला है साधन और लक्ष्य का । कांग्रेस से अलग होने का जो फैसला हम लेने जा रहे हैं उसको ध्यान में रखकर और साथ ही इधर हाल की दुर्घटनाओं की रोशनी में यह मसला ज्यादा अहम हो जाता है ।

पश्चिमी देशों में विरोधी पार्टियाँ प्रतिद्वन्द्वी पार्टी को बदनाम करने के लिए झूठ के इस्तेमाल को गलत नहीं मानती हैं , चुनाव में कामयाबी हासिल करने के लिए वे धूसखोरी और भ्रष्टाचार तक की मदद लेना गलत नहीं समझती । कुछ ऐसी पार्टियाँ हैं जो झूठ और भ्रष्टाचार से भी बहुत आगे तक बढ़ जाती हैं । उनके लिए हत्या, लूट तथा आग लगाना राजनीतिक दाव-पेंच

जयप्रकाश की विचारधारा

का हिस्सा है। पिछले महीनों में इस किस्म के दाव-पेंच के चलते जो घृणित कांड हुए हैं उनको हमने देखा है।

जमानेदराज से ऐसे राजनीतिज्ञ हुए हैं जिन्होंने कहा है कि राजनीति में नीतिवाद की कोई जगह नहीं। खैर, पुराने समय में इस अनीतिवादिता का बुरा प्रभाव राजनीति से सबध रखने वाले थोड़े लोगों की जमात तक ही महबूद रहा और राज्य के नेताओं तथा मंत्रियों के भ्रष्ट कार्यों के प्रभाव से आम जनता मुक्त रही। लेकिन तानाशाही के उदय से, जिसमें फासिज्म, नाजीवाद और स्टालिनवाद भी सम्मिलित है, इस सिद्धान्त पर बड़े पैमाने पर अमल हुआ है और आज समाज का हर आदमी इसके प्रभाव से ग्रसित है। नतीजा यह हुआ है कि आज सामाजिक जिन्दगी में नैतिक मूल्यों का इतना पतन हो गया है कि न केवल राजनीति में बल्कि जिन्दगी के हर क्षेत्र में, और यहाँ तक कि पारिवारिक जीवन में भी अधेरा छा गया है।

रूस में स्टालिनवादी तरीकों की कामयाबी के बाद यह आम तौर पर विश्वास किया जाता है कि मार्क्सवाद में नैतिक मूल्यों की कोई जगह नहीं। जो समाजवादी इस तरह की बात करते पाये जाते हैं, उन्हें गद्दार या पथ-विचलित कहा जाता है। लेकिन मैं आपके सामने यह साफ कह देना चाहता हूँ कि निजी तौर पर मैं यह मानने लगा हूँ कि समाजवाद कायम करने के लिए साधन का ख्याल करना बहुत ही जरूरी है। भिन्न-भिन्न लोग समाजवाद का भिन्न-भिन्न मतलब लगाते हैं, लेकिन हम अगर समाजवाद से ऐसे समाज का अर्थ लगाते हैं जिसमें हर इन्सान की भौतिक जरूरतें पूरी हो जाती हो और जिसमें व्यक्ति सस्कृत और सम्य हो, आजाद और बहादुर हो, दयालु और उदार हो, तो मेरी यह निश्चित राय है कि हम इस मंजिल तक बिना कुछ मानवीय मूल्यों को स्वीकार किये और चरित्र का मान बनाये रखे पहुँच नहीं सकते। इस पर अक्सर विश्वास किया जाता है कि समाज में

सोशलिस्ट पार्टी : सिंहावलोकन

अगर शोषण न हो और हर व्यक्ति के खाने, पहनने और रहने की अच्छी व्यवस्था हो तो फिर सब बात आप से आप ठीक हो जायगी। लेकिन केवल अच्छे खाने, पहनने और रहनेवालों का समाज, समाजवादी समाज से बहुत दूर की चीज है।

महात्मा गांधी ने हमें बहुत-सी शिक्षाएँ दी हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी शिक्षा है कि साधन ही लक्ष्य है। उनका कहना है कि बुरे तरीको को अख्तियार कर हम अच्छे नतीजे हासिल नहीं कर सकते, अतः न्यायोचित लक्ष्य के लिए न्यायपूर्ण साधनों की जरूरत है। हम लोगों में कुछ लोग भले ही इस बात की यथार्थता पर शक करते हो। लेकिन हाल में हुई दुनिया की तथा अपने देश की घटनाओं को देखकर मेरा पक्का विश्वास हो गया है कि अच्छे तरीको को अख्तियार कर ही हम अच्छे समाज यानी समाजवादी समाज की मजिल तक पहुँच सकते हैं। कुछ दिन पहले जब मैंने एक वक्तव्य में आत्मिक पुनरुत्थान की बात कही थी, तब आप लोगों में से कुछ ने सोचा होगा कि मैं हाल की दुर्घटनाओं से इतना घबरा गया हूँ कि मैं जिन्दगी के कटु सत्यो से भागना चाहता हूँ। ऐसा जिन लोगों ने सोचा होगा, वे बिल्कुल भूल में हैं। मुझे आध्यात्मिक बातों का ज्ञान नहीं, अगर आध्यात्मिकता को धार्मिक या दार्शनिक अर्थ में समझा जाता है। और न एका-एक आत्मा या ब्रह्म में मैं विश्वास ही करने लगा हूँ। मेरा दर्शन केवल मानवी है। समाजमें हम कैसे लोगों के साथ रहना पसन्द करेंगे, केवल इसी समस्या से मेरा सम्बन्ध है। यह साफ है कि मैं झूठे और हत्यारो के समाज में, निर्दयी, असहिष्णु तथा स्नेह, भाईचारे की भावना से विहीन लोगों के बीच नहीं रहना चाहता हूँ।

कोई भी यह नहीं बता सकता कि मानव स्वभाव क्या है, लेकिन इतना तो कहा ही जा सकता है कि मानव स्वभाव हमारे द्वारा बनाया जाता है।

जयप्रकाश की विचारधारा

जन्म से ही कोई अच्छा आदमी नहीं होता। वह शिक्षा के द्वारा अच्छा होता है। अतः हमारी पार्टी का लक्ष्य केवल अच्छा खाने, पहनने और रहनेवालों का निर्माण नहीं, बल्कि अच्छे लोगों का निर्माण करना है, तो मैं कहूँगा कि हमारे सभी राजनीतिक कार्य के पीछे कुछ नैतिक मूल्यों की प्रेरणा जरूर हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस पर उचित रूप से गौर करेंगे।

मैं अब एक दूसरे मसले पर एक और दृष्टिकोण से विचार करने की इजाजत चाहता हूँ।

कुछ लोग यह मानते हैं कि राजनीतिक कार्य का मतलब होता है ताकत हासिल करना। मैं इस ख्याल को बहुत खतरनाक मानता हूँ।

मैं इस विचारधारा के दो अहम पहलू पर विचार करूँगा। पहले, हम देखें कि इसका असर हमारे पार्टी-संगठन पर कैसा पड़ेगा। जो उक्त विचार को माननेवाले हैं वे स्वभावतया पार्टी के अन्दर ताकत हासिल करने की हर कोशिश करेंगे। मैं यह नहीं कहता कि वे वास्तव में ऐसा कर रहे हैं। और जब इस सिद्धान्त के मुताबिक राजनीति का सार ताकत हासिल करना है तब इसके लिए हर तरह के तरीकों को, यहाँ तक कि झूठ, निन्दा और पार्टी के चुनावों में धोखा देना, इन सभी तरीकों को मुनासिब करार दिया जा सकता है। यह साफ है—मैं समझता हूँ मुझसे सब कोई सहमत होंगे—ऐसे तरीकों से पार्टी का संगठन बिल्कुल बिखर जायगा। अतः मैं आशा करता हूँ और अर्ज भी करता हूँ कि इसमें सब कोई इन तरीकों को नामजूर करेगा और पार्टी के अन्दर ताकत हासिल करने की भावना को दूर कर देगा। सराहना पाने की ख्वाहिश और प्रभाव तथा नेतृत्व की आकांक्षा करना इन्सान के लिए स्वाभाविक है। लेकिन उद्देश्य के लिए अपने द्वारा किये गए कामों और सेवाओं के बल पर ही ऐसी स्थिति तक पहुँचने की ख्वाहिश करनी चाहिए।

मैं अब सवाल के दूसरे पहलू पर विचार करना चाहता हूँ। इस पहलू का

सोशलिस्ट पार्टी : सिंहावलोकन

अधिक गहरा और व्यापक महत्व है। सभी राजनीति का मतलब है ताकत हासिल करना—इस सिद्धान्त का मूल आधार है—यद्यपि इस सिद्धान्त के माननेवालों को इसकी वाकफियत न हो, यह ख्याल कि राज्य सामाजिक भलाई का एकमात्र अन्न है। दूसरे शब्दों में, इस सिद्धान्त को मानने वाले विश्वास करते हैं—अगर वे स्वार्थ-साधन चाहनेवाले न हो क्योंकि ऐसा होने से वे विचार करने के लायक ही नहीं होंगे—समाज की सेवा तथा अपनी इच्छा के मुताबिक सामाजिक तबदीली लाने के लिए हुक्मत पर कब्जा करना जरूरी है।

मैं इस विचार को बिलकुल ही नामजूर करता हूँ। कांग्रेस ने आज हुक्मत पर कब्जा कर लिया है लेकिन हर समझदार कांग्रेस-जन हमसे इस बात पर सहमत होंगे कि अगर सामाजिक परिवर्तन और विकास की हर कोशिश के लिए कांग्रेस केवल हुक्मत पर भरोसा करेगी तो वह अपनी ताकत के आधार को कमजोर करेगी। दरअसल कांग्रेस के रचनात्मक कार्य-कर्त्ताओं का यह आम ख्याल हो रहा है कि पार्लियामेंट को मशीन से वे अपना रिश्ता तोड़ दें और समाज तथा राज्य की सेवा के लिए अलग होकर आजादी के साथ काम करें।

तानाशाह मुल्को के तजुर्वे ने, चाहे वे फासिस्त या कम्युनिस्ट हो, दिग्वा दिया है कि हुक्मत को अगर सामाजिक पुनर्निर्माण का एक मात्र अस्त्र माना जाता है तो केवल एक यन्त्रवत् समाज का निर्माण होता है जिसमें हुक्मत सर्वशक्तिमान रहती है और सार्वजनिक क्रियाशक्ति दबी रहती है और व्यक्ति व्यापक अमानवीय मशीन का केवल पहियावाला दाँत बना रह जाता है। निश्चय ही ऐसा समाज हमारी पार्टी का लक्ष्य नहीं है, और न इस तरह का समाज कभी भी लोकतांत्रिक समाजवादी समाज के विकास का मध्यवर्ती काल ही हो सकता है।

लोकतन्त्र का तकाजा है कि जनता हुक्मत के भरोसे पर कम-से-कम

जयप्रकाश की विचारधारा

रहे। और महात्मा गांधी तथा कार्ल मार्क्स दोनों के ही अनुसार लोकतंत्र की आखिरी मजिल वही है जब राज्य की बुनियाद नहीं रह जाती है। लाखों मेहनतकशों का हारे हुए मुट्ठी-भर स्वार्थी लोगों के वर्ग पर सक्रान्तिकालीन डिक्टेटरशिप से बिल्कुल भिन्न जो तानाशाही है, वह कभी पूर्ण लोकतंत्र के विकास का बीच का रास्ता नहीं हो सकता। पूर्ण लोकतंत्र के विकास के लिए जरूरी है कि सार्वजनिक प्रयास का पूरा मौका मिले और तरह-तरह के आर्थिक सांस्कृतिक संगठनों तथा संस्थाओं के जरिए जनता अपनी हालत सुधारने और अपनी व्यवस्था करने के लायक बने।

मतलब यह कि पार्टी के अन्दर मैं जिस मनोवृत्ति के विकास को पसन्द करूंगा, वह यह है कि हममें से सब कोई इसकी ओर ध्यान न दे कि कौन प्रधान मंत्री बनता है, कौन मजदूर कार्यकर्ता है अथवा कौन फील्डवर्कर है। मैं विश्वास करता हूँ कि हुकूमत चाहे हमारे हाथ हो या न हो, अगर हम रचनात्मक कार्य द्वारा मजदूर आंदोलन को ऐसा बना सकें कि मजदूर उद्योग-धन्धों को चलाने के काबिल हो जायँ, अगर हम मजदूर वर्ग को नागरिक कला की शिक्षा दे सकें, गाँवों में अगर सहयोगी समाजका निर्माण कर सकें, युवकों और बच्चों को राष्ट्र का स्वयंसेवक बना सकें, ऐसा सांस्कृतिक वातावरण तैयार कर सकें जो सबसे अधिक पिछड़े हुए लोगों तक फैला हो; अगर हम जातिभेद, अन्धविश्वास, कट्टरता दूर कर सकें; हम ऐसे हजारों-लाखों निःस्वार्थ कार्यकर्ताओं का सहयोग प्राप्त कर सकें, जिन्हें पद के लिए आकर्षण नहीं—अगर हमें ये सब काम करने में कामयाबी हासिल होती है, तो हम समाजवादी समाज का निर्माण करने में भी कामयाब होंगे। वैसी परिस्थिति में हुकूमत समाजवादी हुकूमत हो जायगी। इस तरह की हुकूमत जनप्रिय समाजवादी आन्दोलन का अस्त्र होगी—अर्थात् समाजवादी जीवन-प्रणाली के लिए राज्य से अलग होकर संगठित जनता का अस्त्र होगी।

सोशलिस्ट पार्टी : सिंहावलोकन

वसी दशा में हुकूमत सभी तरह की शक्तियों का स्रोत होगी।

हमलोग जो ऐतिहासिक फैसला लेने जा रहे हैं, उसके प्रसंग में इन विचारों की खास अहमियत है। विरोधी पार्टी के सदस्यों को पद हासिल करने की तृष्णा बहुत अधिक रहती है। हमें इस तृष्णा पर जरूर ही काबू रखना चाहिए। आज हमें धाढ़ रखना है और आनेवाले दिनों में भी भूलना नहीं है कि पार्लमेंट में विरोधी नीति अथवा दूसरों की गलतियों से बेजा फायदा उठाकर नहीं, बल्कि रचनात्मक कार्य और सेवा के बल पर ही हम लोकतांत्रिक समाजवादी समाज के निर्माण करने में कामयाब होंगे।

उमर मैंने जो कुछ कहा है उसकी एक महत्वपूर्ण उपपत्ति की ओर मैं अब संक्षेप में कुछ कहूँगा। एक क्रांतिकारी पार्टी में, अर्थात् बुनियादी सामाजिक तबदीली का मकसद रखनेवाली पार्टी में, एक पार्लमेंट का कार्य करनेवालों का गिरोह और दूसरा जनता के बीच काम करनेवालों का गिरोह रहता है। ऐसा एक समय आता है जब दोनों गिरोह में कौन किस पर हावी हो जाय, इसके लिए संघर्ष पैदा होता है। ऐसा संघर्ष उस कांग्रेस में पैदा हो चुका है, जो पहले क्रांतिकारी कार्य कर चुकी है, और पार्लमेंट में काम करनेवाले गुट की जीत भी हो चुकी है। ऐसी हालत में जनता के बीच काम करनेवाले या रचनात्मक कार्य करनेवाले कांग्रेसजन शायद अलग हो जायें और लोक-सेवकों का अलग दल तैयार करें। हम अपनी पार्टी का ऐसा विकास करें कि रचनात्मक और पार्लमेंट का कार्य एक-दूसरे से घुला-मिला हो और रचनात्मक काम करनेवालों की आवाज आखिरी हो। तभी हमारी पार्टी पूर्ण लोकतंत्र का सच्चा साधन बन सकती है।

समाजवादी कार्यक्रम

सोशलिस्ट पार्टी भारत में जनतांत्रिक समाजवादी समाज की स्थापना चाहती है।

समाजवादी समाज का निर्माण एक दिन में नहीं होता। समाज के वर्तमान और भावी स्वरूप के बीच सक्रांति का काल भी आता है।

सोशलिस्ट पार्टी का विश्वास है कि जिन देशों में प्रजातंत्र और नागरिक स्वतंत्रता है, वहाँ समाजवाद की स्थापना शांतिपूर्ण और प्रजातांत्रिक साधनों के द्वारा होनी चाहिए।

समाजवादी समाज का अन्तिम स्वरूप क्या होता है इसे तो सभी जानते हैं। यह एक ऐसा समाज होता है जिसमें सभी श्रमिक होते हैं यानी समाज वर्गहीन होता है। यह वह समाज है, जिससे व्यक्तिगत मुनाफे के लिए मनुष्य के श्रम का शोषण नहीं होता। जिसमें सारी सम्पत्ति राष्ट्रीय या सर्व-साधारण की होती है। जिसमें अनुपाजित आय और अधिक आय की असमानता नहीं होती। जिसमें मानव-जीवन और उसकी प्रगति योजनात्मक ढंग से चलती है और जहाँ सबके लिए सब जीवित रहते हैं।

समाजवाद के इस अंतिम स्वरूप से तो लोग बहुत परिचित हैं, परन्तु इस अन्तिम लक्ष्य तक पहुँचने के लिए किसी देश को किन-किन दशाओं को पार करना पड़ता है, इससे सभी अभिज्ञ नहीं और यह प्रत्येक देश की अपनी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इन दशाओं का निर्णय और उसकी योजना इतनी महत्वपूर्ण होती है कि उसके सिलसिले में की हुई एक भूल समाजिक विकास के सारे क्रम को पलट सकती है और देश को ऐसे लक्ष्य तक पहुँचा दे सकती है जो समाजवाद से बहुत भिन्न होता है।

अपने देश की हालत पर पूरी तरह विचार करके सोशलिस्ट पार्टी नीचे लिखा कार्यक्रम प्रस्तुत करती है, जो भारत को समाजवाद की ओर ले जाने में पहली मंजिल का काम देगा।

१ राजनीतिक

(क) नया विधान

सोशलिस्ट पार्टी की राय में यह अत्यन्त आवश्यक है कि भारत का नया विधान कुछ महीनों में ही लागू होने के लिए तैयार कर लिया जाय और जैसे ही विधान लागू हो, औपनिवेशिक दर्जे का अंत कर दिया जाय। नए विधान के अन्तर्गत सन् १९४८ के मध्य तक चुनाव और उसके तुरत बाद ही प्रजातंत्र (गणतंत्र) की स्थापना हो जानी चाहिए। इसके लिए बहुत शीघ्र मतदाताओं की सूची तैयार करने का काम हाथ में ले लिया जाय।

नया विधान ऐसा हो जो पूर्ण प्रजातन्त्र—राजनैतिक और सामाजिक प्रजातंत्र—की स्थापना कर सके।

नया भारतीय राज्य सर्वसत्तात्मक जनतांत्रिक साधिक प्रजा राज्य होना चाहिए।

जयप्रकाश की विचारधारा

जनता की इच्छा को ही राज्य का आधार और अधिकारों का स्रोत समझा जाय ।

नागरिकता के अधिकार सबके लिए समान हों ।

राज्य का कोई अपना धर्म न हो अर्थात् वह धर्मरहित राज्य हो । सभी धार्मिक सम्प्रदायों को समान रूप से विचार और पूजापाठ की स्वतन्त्रता मिले ।

जाति, सम्प्रदाय, लिंग या धर्म का कोई ख्याल किये बिना सभी नागरिकों को सम व्यवहार की गारंटी मिलनी चाहिए । समाज की पिछड़ी हुई और दलित जातियों की आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए विशेष सुविधाएँ मिलें । अल्पसंख्यकों को पूर्ण सांस्कृतिक स्वशासन मिलना चाहिए ।

विधान परिषद् नागरिकों को (सब में सम्मिलित देशी राज्यों के निवासियों सहित) उन मौलिक नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का विश्वास दिलावे, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लागू किये जा सकें ।

राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिए यह आवश्यक है कि सब लोगों की सम्पत्ति पर राज्य का अधिकार माना जाय और व्यक्तिगत व्यवसाय का उसी हद तक समर्थन किया जाय, जिस हद तक वे समाजवाद के विकास में बाधक नहीं हो जाते । व्यक्तिगत सम्पत्ति या व्यक्तिगत व्यवसाय का मुआवजा देकर या बिना मुआवजा के ही कानून के जरिये स्वामित्व छीना जा सकता है या उसका समाजीकरण किया जा सकता है । अगर मुआवजा देना ही हो तो उसकी तादाद का फैसला सरकार पर छोड़ दिया जाय ।

उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण और सामाजिक स्वामित्व के आधार पर आर्थिक जीवन को व्यवस्थित तथा विकसित करने के लिए विधान में कानूनी संस्थाओं (Statutory bodies) जैसे आर्थिक कौंसिलों और योजना-कमीशनो के निर्माण की व्यवस्था की जानी चाहिए । प्रजाराज्य और उसकी विधायक इकाइयों (ग्रान्तों और रियासतों) का विधान जनतात्रिक होना

चाहिए, अर्थात् उनकी कार्यकारिणी (मंत्रिमंडल) को व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए !

सभी व्यवस्थापिका सभाओं में एक भवन (Unicameral) हो, और सभी चुनाव जिसमें सभ की धारा-सभा भी शामिल है, सयुक्त निर्वाचन प्रणाली पर सीधे, गुप्त और वयस्क मताधिकार के आधार पर हों । चुनाव क्षेत्र कई सदस्यवाले हों और मतदान एकत्रित मतों (Cumulative votes) की पद्धति पर हो ताकि अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व हो सके ।

विधान में एक शक्तिशाली सघीय केन्द्र की व्यवस्था हो । किन्तु केन्द्र को शक्तिशाली बनाने का यह तात्पर्य नहीं कि किसी इकाई की अपनी जनता की इच्छानुसार सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक उन्नति का कार्यक्रम अपनाने की स्वाधीनता कम हो जाय ।

निर्वाचित व्यवस्थापिका सभा के अतिरिक्त राज्य के किसी भी अधिकारी को आर्डिनेन्स लगाने और इसी तरह के अन्य असाधारण अधिकारों को काम में लाने का हक नहीं होना चाहिए ।

सरकारी नौकरी में कर्मचारी की नियुक्ति और पद-वृद्धि योग्यता के आधार पर होनी चाहिए । अपवादस्वरूप पिछड़ी हुई जातियों की नियुक्ति में कुछ खास रियायतें दी जानी चाहिए ।

एक ही अफसर के जिम्मे शासन और न्याय सम्बन्धी कार्य न सौंपे जायें ।

केन्द्र और सभ की इकाइयों में एक सामाजिक तथा आर्थिक कौंसिल होनी चाहिए जो आर्थिक और सामाजिक कार्यों की योजना बनाये ; अपने सामने पेश की गई आर्थिक, सामाजिक या अन्य योजनाओं या मामलों की जाँच-पड़ताल तथा छीन-बीन करे और साधारणतया ऐसे मामलों पर सरकारों को सलाह दे जिनमें विशेष या विशिष्ट सलाह की आवश्यकता होती है ।

जयप्रकाश की विचारधारा

इन कौंसिलों का निर्माण पेशे (functional) के आधार पर होना चाहिए और उनमें अन्य लोगों के अतिरिक्त वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, डाक्टरों, सर्जनों, शिक्षा-शास्त्रियों, राजनीतिज्ञ और शासन-विशेषज्ञों, व्यापार, अथ और कृषि-विशेषज्ञों तथा मजदूर पचायतों, सहयोग समितियों, किसान संगठनों और इसी तरह की दूसरी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए ।

इन कौंसिलों का वही स्थान होगा जो आजकल की राज्य परिषदों (लेजिस्लेटिव कौंसिलों) का है और उनका कार्य होगा उपर्युक्त समितियों द्वारा सांस्कृतिक और आर्थिक नीतियों का निरीक्षण कराना ।

(ख) शासन पद्धति में सुधार

वर्तमान नौकरशाही का शासन-यंत्र जो अपने ढंग से पुलिसराज के सीमित कार्यों के लिए तो ठीक था, पर एक समाज-सेवी राज्य में उसके ऊपर जो कार्य आयेंगे, उनके लिए वह बिल्कुल बेकार और अनुपयुक्त है, नई परिस्थितियों के अनुकूल और नए सामाजिक उद्देश्यों को पूर्ति के लिए इसका पुनर्संगठन होना चाहिए । कर्मचारियों में एक नया दृष्टिकोण—सेवा और राष्ट्र निर्माण का दृष्टिकोण—तथा सैनिकों की तरह का अनुशासित उत्साह उत्पन्न होना चाहिये । अधिकांश पुराने कर्मचारी, विशेषतया जो उच्च पदों पर हैं, अब तक दूसरी तरह से ही संचालित-विचारते और काम करते आये हैं । उनकी जगह पर नवीन दृष्टिकोण और उच्च सामाजिक आदर्शों से प्रेरित नए आदमी रखे जाने चाहिए । कुछ नई नौकरियों का, उदाहरण के लिए, आर्थिक नौकरियों का निर्माण भी करना होगा । ओहदों पर तरक्की पाने के लिए, विशेषतया ऊँचे ओहदों पर तरक्की पाने के लिए, सीनियर होना ही पर्याप्त न समझा जाय, वरन् उन पदों पर योग्य कर्मचारियों को खास तरक्की देकर रखा जाय या सीधे नियुक्ति की जाय ।

समाजवादी कार्यक्रम

सबसे ऊँचे और सबसे नीचे पदों के कर्मचारियों के बीच जो घोर विषमता है, उसका अन्त हो जाना चाहिए।

सरकारी नौकरियों के लिये भरती साधारणतः प्रतियोगिता द्वारा होनी चाहिये। भरती हो जाने के बाद रगरूटों को आवश्यक और विशिष्ट शिक्षा देनी चाहिये।

जनतन्त्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि सरकारी नौकर ईमानदार और बेदाग हो। इसलिए सरकारी नौकरियों से भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने की हर तरह से कोशिश करनी चाहिये। लेकिन जनता का सहयोग मिले बिना, यह असम्भव है। आज यदि भ्रष्टाचार का बोलबाला है तो इसके लिए जनता भी उतनी ही दोषी है, जितने भ्रष्ट सरकारी नौकर। राष्ट्रीय जीवन की पवित्रता हरेक के पवित्र होने पर निर्भर करती है।

इस कार्यक्रम में समाज की आर्थिक व्यवस्था के परिवर्तन के लिए जो सुझाव दिये गये हैं, उनसे सामाजिक जीवन का भ्रष्ट करनेवाले कई प्रभावशाली कारण तो स्वतः दूर हो जायेंगे, लेकिन मन्त्रियों का यह भी कर्तव्य है कि वे कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के लिए कड़ा-से-कड़ा दण्ड दें। इसके लिए यह भी जरूरी होगा कि कर्मचारियों के कार्यों और निर्णयों में गैर-कानूनी ढंग से किसी प्रकार का हस्तक्षेप सार्वजनिक व्यक्तियों द्वारा न किया जाय।

यदि जनता अपने दायित्व के प्रति जागरूक हो जाय तो यह एक बड़ी चीज़ होगी। सरकारी कर्मचारियों में जिम्मेवारी और तवज्जह की भावना लाने के लिए यह आवश्यक है कि उनमें और जनता में परस्पर घनिष्ठ प्रजातांत्रिक सम्पर्क हो। इसके अलावा शासन-सम्बन्धी नौकरियों पर स्थानीय स्वशासन के अधिकारियों या इसी काम के लिए नियुक्त किसी सलाहकार-समिति का नियन्त्रण होना भी आवश्यक है।

कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पाठ्य दूसरा तरीका यह

जयप्रकाश की विचारधारा

सुझाती है कि हरएक सरकारी नौकर समय-समय पर अपनी सम्पत्ति का व्यौरा दे ।

इन साधारण बातों पर विचार करने के बाद हम यहाँ अपने खास सुझाव रखते हैं—

शासन सम्बन्धी सारे ढाँचे का आधार वयस्क मताधिकार पर चुनी हुई ग्राम-पंचायत होनी चाहिए । शांति और व्यवस्था कायम रखने से लेकर ग्राम-पंचायतों को शासन सम्बन्धी सारे कार्य करने चाहिए । उनको स्थानीय स्वशासन का कार्य और गाँव की सड़को, प्रारम्भिक शिक्षा, सफाई आदि का प्रबन्ध भी करना चाहिए । ग्राम-पंचायतों को न्याय सम्बन्धी अधिकार नहीं होने चाहिए ।

चूँकि शुरू-शुरू में ग्राम-पंचायतों का काम बहुत पेचीदा रहेगा, गाँव की दलबन्धियाँ और साम्प्रदायिक भावना भी उनके कार्य में रोड़े अटकाएँगी, इसलिए कुछ समय के लिए राज्य कर्मचारी को पंचायतों का मंत्री नियुक्त करना आवश्यक होगा ।

ऊँचे दर्जे के शासन-कार्यों के लिए यह जरूरी होगा कि शांति व्यवस्था स्थापित रखने वाले तथा नित्यप्रति का शासन-कार्य देखने वाले विभागों और उन विभागों में कुछ अन्तर रखा जाय, जो राष्ट्र निर्माण के कार्यों, जैसे—सहयोग-समितियों और योजना-निर्माण आदि से सम्बन्धित हो । जिला अफसर को कई तरह के अधिकार न होकर, जैसा कि आज है, एक सीमित क्षेत्र में शांति और व्यवस्था कायम रखने तथा राजस्व एकत्र करने का अधिकार ही रहना चाहिए । विकास कार्यों की देखभाल करने के लिए कुछ दूसरे अफसर भी नियुक्त किये जाने चाहिए, जिनको अपने क्षेत्र में उनके समान ही अधिकार प्राप्त हों । हर एक विभाग से संबंधित अधिकारियों द्वारा इन अफसरों को सलाह-मशविरा देने के लिए सलाहकार बोर्ड नियुक्त किये जाने चाहिए । इन बोर्डों

को मुख्यतः निर्धारित कार्यों को सम्पन्न करने का अधिकार हो, पर वे नीति-निर्धारण के मामलों पर भी अफसरों को परामर्श दे सकेंगे। जिन प्रश्नों पर मतभेद हो, उनका निपटारा करने के लिए भी नियम बनाने चाहिए। ऐसी दशा में व्यवस्थापिका सभा की सम्बन्धित कमिटी के पास मामला भेज देना चाहिए। जब तक निर्णय न हो, अफसर अपनी न्याय बुद्धि के अनुसार कार्य करेगा।

प्रान्तीय शासन में, विभिन्न विभागों के अध्यक्षों को सहायता देने के लिए संबन्धित हितों के प्रतिनिधियों के सलाहकार-बोर्ड होने चाहिए। हर एक मंत्री को सहायता और सलाह देने के लिए भी व्यवस्थापिका सभा की एक कमिटी होनी चाहिए। इन कमिटियों को अपने क्षेत्र के किसी भी मामले की जांच करने और उसके लिए कोई भी प्रासंगिक प्रमाण एकत्र करने का तथा नीति-निर्धारण करने का अधिकार होना चाहिए।

जिलों से लेकर ऊपर तक इन सलाहकार-बोर्डों का निर्माण समुचित ढंग से हो। इसके लिए आवश्यक है कि प्रान्तीय सरकार भिन्न-भिन्न पेशों को उनके संगठन में सहायता करे।

शासन की इस नूतन पद्धति में तालुका, परगना और जिला बोर्डों जैसी शासित स्थानीय संस्थाओं के लिए स्थान होना चाहिए। शासन ऐसा हो जिसके द्वारा विशिष्ट टेक्निकल सुझाव मिल सकें और जिसमें शासन-पटुता हो, जिसमें स्थानीय संस्थाओं के लिए स्थान हो, जनता को जिससे प्रेरणा मिलती हो जो जनता के दृष्टिकोण को समझता हो और प्रजातांत्रिक अधिकारों की गारंटी देता हो।

स्थानीय स्वशासन की समस्या पर पूरी तरह विचार होना चाहिए। हम प्रयत्न करेंगे कि बाद में इसका एक स्पष्ट चित्र जनता के सम्मुख उपस्थित कर सकें।

(ग) कानून-जासा में सुधार

हमारे देश का कानून अपनी जटिलता और उलझनों के लिए प्रसिद्ध है। उसको सरल बनाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त कानून विदेशी भाषा में लिखे गये हैं इससे एक बड़ी तादाद में जनता उसको समझ नहीं पाती।

इस प्रकार कानून से बिल्कुल अनजान होकर वह पेशेवर वकीलों की दया पर निर्भर रहती है। इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि कानून का अनुवाद भारतीय भाषाओं में कर दिया जाये।

कानून से भी अधिक तो कानून के व्यवहार में सरलता लाने की आवश्यकता है। कचहरियों को जनता के निकटतम सम्पर्क में आना चाहिए और घुमा-फिराकर अनावश्यक विलम्ब लगाने वाली कार्य-पद्धति को सरल बनाना चाहिए।

सोशलिस्ट पार्टी इसके बड़े निम्नलिखित न्याय-पद्धति का सुझाव रखती है—

(अ) दीवानी

(१) निर्वाचित ग्राम-अदालतों द्वारा ही निश्चित छोटी रकम के मामलों का फैसला हो जाना चाहिए। ऊपर की कचहरियों में इनकी अपील केवल तभी हो सकती है जब कि निर्णय पक्षपातपूर्ण रहा हो या उसके पीछे भ्रष्टाचार का हाथ हो।

(२) बड़े-बड़े मामलों का फैसला अस्थायी अदालतों पचायतों द्वारा होना चाहिए। इन पचायतों को वादी और प्रतिवादी न्याय-विभाग की ओर से निर्धारित व्यक्तियों की सूची में से चुनेंगे। अगर पचायत चाहे तो वह किसी सुदक्ष जज को अपने साथ बैठने के लिए आमंत्रित कर सकती है या

किसी कानूनी प्रश्न पर उसकी सम्मति ले सकती है। जब तक पक्षपात, भ्रष्टाचार या अन्याय की बात न होगी, अदालती पंचायत के फैसले के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकेगी।

(३) कुछ खास मामलों की, जिनमें कानूनी पेचीदगी होगी, सुनवाई सुदक्ष जजों द्वारा ही असेसरी की सहायता से होनी चाहिए।

अदालत नं० १ और २ में, जिनका वर्णन ऊपर हो चुका है, वकीलों के जाने की अनुमति न होगी।

(आ) फौजदारी

(१) अपमान, मामूली चोट, गाली और अनधिकार प्रवेश आदि साधारण अपराधों के मुकदमों की सुनवाई निर्वाचित गाँव-अदालतों में ही हो जायगी।

(२) संगीन अपराधों के मुकदमों का फैसला अस्थायी भिन्न-भिन्न पंचायतों द्वारा होगा जिन्हें आवश्यकतानुसार सुदक्ष जज की सहायता भी मिल सकेगी। तथ्य संग्रह करने और दण्ड देने के कार्यों को एक-दूसरे से पृथक् कर देना चाहिए।

जाँच-पड़ताल करने का काम ग्राम-सभा के सुपुर्द नहीं होना चाहिए। इससे यह खतरा है कि शायद सभा के सदस्य शंभीरता से जाँच न करें और जिन मामलों से वे स्वयं सम्बन्धित हों, उनकी जाँच में वे गलत तरीकों का सहारा भी लें। जैसा कि रूस में है, जाँच करने के लिए एक अफसर अलग से नियुक्त होना चाहिए, जो पुलिस अफसर न होकर न्याय-विभाग का अफसर हो। यह बात केवल संगीन अपराधों के लिए ही लागू होगी।

(इ) खास अदालतें

इन अदालतों की स्थापना भी ऊपर लिखे सिद्धान्तों के आधार पर होनी चाहिए, अर्थात् न्याय करने के लिए जनता का सहयोग प्राप्त करना। उदाहरण

जयप्रकाश की विचारधारा

के लिए बालको के अपराधों पर विचार करने के लिए अलग अदालतें हों, जिनमें अध्यापक, डाक्टर, सम्मान्य स्त्री-पुरुष नागरिक हों। तलाक वाली अदालतों में फैसला करनेवाले स्त्री-पुरुष नागरिक और डाक्टर हों।

वकीलों को इन अदालतों में नहीं जाने देना चाहिए।

(ई) अपील के लिए अदालतें

मातहत अदालतों को अधिकार होगा कि वे कानूनी मसलों पर अपील की इन अदालतों से आखिरी फैसला करा सकें।

(उ) कानूनी पेशा

कानूनी पेशा में बहुत उलट-फेर करके उसको फिर से सगठित करने की आवश्यकता है। पार्टी का सुझाव है कि इस की तरह भारत में भी वकीलों के सघ (कॉलेजियम) कायम करने चाहिए। शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद वकील इस सघ (कॉलेजियम) में भर्ती होंगे। यहाँ उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें काम दिया जायगा और उनका पारिश्रमिक निश्चित कर दिया जायगा।

२. आर्थिक

कुछ आम बातें

अब जो भी आर्थिक योजना बनायी जाय, उसका प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय ज्यव्यवस्था की उन्नति होना चाहिए। यदि हमारा अंतिम लक्ष्य समाजवाद की स्थापना करना है तो देश को उस राह पर चलाने के लिए अभी से प्रयत्न करना चाहिए।

कांग्रेस सरकारों की वर्तमान नीति की न कोई दिशा है, न उसका कोई लक्ष्य ही। मौजूदा हालत को बनाए रखने के सिवाय वह हमें अन्यत्र कहीं नहीं ले जा सकती। वर्तमान अर्थ-व्यवस्था व्यक्तिगत उद्योगों पर आधारित है, अर्थात् व्यक्तिगत मुनाफे और मजदूरों के शोषण पर उसकी बुनियाद है। इस-

लिए यह स्पष्ट है कि इस अर्थ-व्यवस्था से समाजवाद तक नहीं पहुंचा जा सकता ।

समाजवाद की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक है कि वर्तमान अर्थ-व्यवस्था को सामाजिक नियंत्रण में ला दिया जाय और विकास की एक विस्तृत योजना के अनुसार उसका संचालन हो । उसके कुछ भागों का तो तुरत समाजीकरण हो जाना चाहिए । पूँजी का सरकार द्वारा नियंत्रण और संचालन हो । आय की असमानता भारी कर लगाकर दूर कर देनी चाहिए । जमींदारी प्रथा जैसे साम्प्रतिक सम्बन्धों को खत्म कर देना चाहिए और मजदूरी और अच्छे मकानों की गारंटी मिलनी चाहिये ।

इतना हो जाने पर देश समाजवाद के रास्ते पर चल चुकेगा । लेकिन आज के लिए जो आर्थिक व्यवस्थाएँ जरूरी हैं, वे इतने से ही खत्म नहीं हो जाती ।

इनके साथ-साथ आर्थिक उन्नति के लिए दूसरी महत्वपूर्ण चीज है उत्पादन में वृद्धि करना, अर्थात् वर्तमान साधनों तथा जन-शक्ति का अच्छा से अच्छा उपयोग और कृषि तथा उद्योगों की और अधिक उन्नति करना ।

जिन समस्याओं पर तुरत ध्यान देना चाहिए और जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, वे हैं— खाद्य, वस्त्र और मकानों की कमी ।

अंतिम समस्या है मनुष्य की । राज्य के हरेक व्यक्ति में सामाजिक उत्तरदायित्व की एक नई चेतना जगानी चाहिए । व्यक्ति को नई प्रेरणा की प्रति जागरूक और बड़े उत्तरदायित्वों को संभालने के लिए तैयार रहन चाहिए ।

इन साधारण बातों की ओर दृष्टिपात करने के बाद हम अपनी आर्थिक नीति का थोड़ा विस्तृत चित्र सामने रखते हैं—

(क) उद्योग

(अ) योजना

हमारी पहली आवश्यकता एक ऐसी आर्थिक योजना तैयार करने की है, जिसमें विभिन्न आर्थिक गति-विधियाँ परस्पर सामञ्जस्य रखती हुई चले। यदि सभी आर्थिक साधनों को योजनात्मक ढंग से संयोजित किया जाय, तो समाज की आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नति उस परिमाण में हो, जिसका सपना भी स्वतंत्र व्यवसाय उद्योगों में मिलना असम्भव है।

आर्थिक साधनों और जन-शक्ति का जो उपयोग आज किया जा रहा है, उसके पीछे मुनाफे की भावना काम कर रही है। इस पद्धति में अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की ओर ध्यान नहीं दिया जाता और केवल ऊँचे मुनाफे के लिए अनावश्यक कार्यों की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है। यह खयाल किए बिना कि हरेक व्यक्ति को क्या मुनाफा रहता है, जब तक हमारे साधनों और जन-शक्ति को एक केन्द्रीय योजना के अनुसार उत्पादन में नहीं लगाया जाता, तब तक आर्थिक व्यवस्था गतिरुद्ध और असंतुलित ही रहेगी। व्यवसाय में लगी कुछ पूँजी अपने-आप में बहुत उत्पादनशील नहीं होती, पर सारे क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ाने में उसका महत्वपूर्ण भाग होता है। उदाहरण के लिए भूमि की उर्वराशक्ति बढ़ाने, जंगल लगाने और नदियों पर बांध बाँधने की योजना में लगाई हुई पूँजी को लिया जा सकता है। केन्द्रीय योजना इन कामों में पूँजी का रुख मोड़ सकती है।

केन्द्र और प्रान्तों में योजना समितियाँ और बोर्ड तो बनाने ही पड़ेंगे, किन्तु जब तक सारी जनता योजना को कार्यान्वित करने में भाग नहीं लेती, तब तक यह सहयोगी अध्यक्षता नहीं होगा और न जन साधारण में वह उत्साह ही पैदा हो सकेगा, जिसके बिना कोई भी योजना सफल नहीं हो

सकती। हरेक गाँव और हरेक औद्योगिक कारखाने को इस महत्वपूर्ण कार्य में हाथ बँटाना होगा।

समाजवादी पुनर्निर्माण के प्रारम्भ में सहयोगी आर्थिक व्यवस्था निश्चित रूप से मिश्रित आर्थिक व्यवस्था होगी, अर्थात् समाजवाद और व्यक्तिगत अर्थ-व्यवस्था दोनों कुछ दिनों तक साथ-साथ चलेगे लेकिन आर्थिक योजना के अन्दर सारे देश की सम्पूर्ण व्यवस्था को लाने के लिए यह आवश्यक होगा कि व्यक्तिगत उद्योगों पर भी नियन्त्रण रखा जाय ताकि देश में समान रूप से आर्थिक प्रगति हो सके।

(आ) समाजीकरण

सोशलिस्ट पार्टी की सम्मति में कोयला और अवरक की खानों, लोहा, इस्पात और अन्य धात्विक उद्योगों, कच्चा लोहा आदि की खानों, रक्षा-कार्य के लिए समान और हवाई जहाज तथा सामुद्रिक जहाज निर्माण करनेवाले और विजली-उत्पादन करनेवाले उद्योगों का तुरन्त या शीघ्र ही राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिए। ये बुनियादी उद्योग हैं और सामाजिक विकास के लिए उनका राष्ट्रीयकरण होना आवश्यक है।

इसके अलावा पार्टी सूती मिलों के राष्ट्रीयकरण की भी सिफारिश करती है, क्योंकि इस उद्योग से जनता की एक प्रमुख आवश्यकता की पूर्ति होती है।

रेलवे का तो प्रायः राष्ट्रीयकरण हो ही चुका है। विजली से चलनेवाली सवारियों का राष्ट्रीयकरण करने या उनको म्युनिसिपैल्टी के प्रवध में देने की सिफारिश भी सोशलिस्ट पार्टी करती है।

जिन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण या समाजीकरण हो चुका है, उनके प्रबन्ध के लिए राष्ट्रीय, प्रान्तीय या स्थानीय कानूनी बोर्ड कायम किये जाने चाहिए। इन बोर्डों में सरकार, उपभोक्ता और मजदूरों (टेकनीशियनो सहित) के प्रतिनिधि नियुक्त होने चाहिये।

(इ) नियंत्रित उद्योग

दूसरे उद्योगों को सरकारी नियंत्रण में ला देना चाहिए। नियंत्रण इस प्रकार लगाना चाहिए—

(१) उद्योगों के स्थान और आकार को निश्चित करने के लिए उन्हें लाइसेंस कराने का तरीका चलाया जाय।

(२) पूँजी लगाने पर नियंत्रण।

(३) भवन-निर्माण की सामग्री पर नियंत्रण।

(४) शक्ति-साधनों का नियंत्रण।

(५) मजदूरों के वेतन और रहने तथा काम करने की स्थिति के सम्बन्ध में कानूनों के लागू होने की अनिवार्यता।

(६) व्यवस्था-विभाग के पारिश्रमिक और मुनाफे पर नियंत्रण।

(७) सरकार की ओर से अनिवार्य रूप से आदर्श विवरण पत्रिका के आधार पर हिसाब-किताब की जाँच।

(८) कच्चे माल और तैयार माल की कीमत पर तथा उनकी तायदाद और सिफन पर नियंत्रण।

हमारा देश अत्यंत गरीब है। यद्यपि गल्ले की बेहद कमी है, पर खेतिहर मजदूरों को काम के घंटों की उसी दर से मजदूरी नहीं मिलती जिस दर से खेती से अलग काम करने वाले मजदूरों को मिलती है। यह अन्यायपूर्ण है।

आमदनी के साधारण स्तर को ध्यान में रखकर ही उत्पादन की प्रेरणा की समस्या पर विचार करना होगा। ऐसी हालत में उद्योग का मुनाफा सरकार द्वारा निश्चित उच्चतम वेतन में अधिक नहीं होना चाहिये।

(ई) नये उद्योग

औद्योगीकरण के कार्यक्रम के तिलसिले में सरकार को यह ध्यान रखना

होगा कि किस उद्योग को पहले विकसित किया जाय और किसको बाद में । हिन्दुस्तान में हमारे लिए यह सम्भव नहीं है कि हम मध्यम श्रेणी के और उपभोग्य वस्तुओं के उत्पादक उद्योगों को छोड़कर अपना ध्यान भारी और बुनियादी उद्योगों की ओर केन्द्रित कर सकें, क्योंकि स्वामित्व और भूमि के आकार के पुनर्संगठन के कारण एक बड़ी सख्या में स्त्री-पुरुष बेकार हो जायेंगे जिनके लिए खास तौर से देहातो में रोजगार दिलाना होगा ।

सभी बुनियादी उद्योग प्रातीय या केन्द्रीय सरकार द्वारा शुरू किये जाने चाहिए । उनका मालिक और प्रबन्धक भी सरकार ही रहे ।

अन्य उद्योगों में से कुछ का विकास जन सस्थाओं और सहयोग-समितियों द्वारा होना चाहिए ।

कुछ उद्योग का विकास—व्यक्तिगत उद्योग में—सरकार को साझेदारी से होना चाहिए ।

दूसरे उद्योगों को व्यक्तिगत उद्योग के द्वारा विकसित होने देना चाहिए, किन्तु उनपर जनता का नियन्त्रण रखना चाहिए, जैसा कि ऊपर सुझाया गया है ।

औद्योगिक विकास के लिए योजना बनाने के लिए आवश्यक है कि सरकार तुरत देश व्यापी जाँच-पड़ताल कराके राष्ट्रीय साधनों, पूँजी, वर्तमान उत्पादन, उपभोक्ता की आवश्यकताएँ, जीविका-वितरण और राष्ट्रीय आय आदि मद्दों के सम्बन्ध में आवश्यक आँकड़े इकट्ठा कर ले ।

(ख) मजदूर

अगर समाजवाद की शुरुआत करनी है तो उद्योगों और समाज में श्रमिकों की स्थिति पर विशेष ध्यान देना होगा । समाज के सभी क्षेत्रों में श्रम को महत्व समझना होगा, मालिक और मजदूर के सम्बन्धों में परिवर्तन

जयप्रकाश की विचारधारा

कराना होगा, और इसके लिए मजदूरों को मालिक (राज्य हो चाहे व्यक्ति) के समान स्तर पर लाना होगा ।

किसी भी व्यवसाय में मजदूरों को बराबर का साझीदार समझना चाहिए ।

जिन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण और समाजीकरण हो गया है, उनके प्रबन्ध में कारखाने के मजदूरों के प्रतिनिधियों का भी हाथ होना चाहिए । किन्तु जहाँ-कहीं मजदूरों की सामूहिक सामाजिक भावना, माल की किस्म को अच्छा करने और उत्पादन बढ़ाने का उत्तरदायित्व अनुभव नहीं करती, वहाँ उनको इन अधिकारों से वंचित किया जा सकता है । उनको ये अधिकार तभी दिए जाएँगे जब वे उत्पादन की पुष्ट इकाई सिद्ध हों । व्यक्तिगत उद्योगों में भी कार्य-संचालन समितियाँ स्थापित होनी चाहिएँ जिनमें ऊपर लिखी शक्तों पर उद्योग को चलाने के लिए मजदूरों के प्रतिनिधियों को भी स्थान मिले ।

व्यक्तिगत या सामाजिक उद्योगों में जो मुनाफा हो, उससे पहली आवश्यक चीज है—मजदूरों की प्रारम्भिक आवश्यकता-निर्वाह योग्य वेतन और उपयुक्त गृह की पूर्ति करना । जैसे-जैसे उत्पादन में वृद्धि हो, मजदूरों और उनके परिवार को सामाजिक सुविधाएँ देना भी उद्योग का प्राथमिक कर्तव्य हो जाता है ।

उद्योगों के राष्ट्रीयकरण और समाजीकरण हो जाने पर मजदूरों को मजदूरी देने के पहले वाले सिद्धान्तों में भी परिवर्तन हो जाना चाहिये । व्यक्तिगत उद्योगों में मजदूरों की मजदूरी उत्पादन के व्यय पर चढ़ा दी जाती है और उसे कम-से-कम करने की कोशिश की जाती है ताकि मुनाफा अधिक-से-अधिक हो । किन्तु राष्ट्रीय उद्योगों में मजदूरी और मुनाफा दोनों को वर्तमान मान्यता बदल जानी चाहिए । मजदूर की मजदूरी से ही उद्योग के कुल उत्पादन में उसका हिस्सा तय होना चाहिये । उद्योग की आवश्यकताओं

और राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से सामंजस्य रखते हुए, उत्पादन में वृद्धि के साथ-ही-साथ मजदूरों की मजदूरी भी बढ़ती जाना चाहिए। इसी तरह राष्ट्रीय उद्योगों में मुनाफा की मान्यता भी बदल जानी चाहिए। अब यह निजी आमदनी का साधन न रहे, बल्कि इससे यह तय किया जाए कि कुल आय का कौन-सा हिस्सा उद्योग को वृद्धि में और कौन-सा अर्थ राष्ट्रीय व्यवस्था के विकास में लगाया जाय।

(ग) बैंक और व्यापार

पाटों सभी तरह के बैंकों और बीमा कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण को सिफारिश करनी है।

वैदेशिक व्यापार पर तो राज्य का एकाधिकार हो हो, किन्तु भीतरी व्यापार पर भी मूल्य नियंत्रण तथा राशानेज के जरिए उसका कंट्रोल रहना चाहिए।

(घ) टैक्स

सरकारी राजस्व व्यवस्था का पुनः संगठन व्यावहारिक रूप से होना चाहिए। इसके मानी यह है कि आर्थिक कारवाइयों को परख राजस्व पद्धति के परम्परागत सिद्धान्ता से न को जाय, बल्कि हरेक कार्य का परिणाम देखकर यह निर्दिष्ट किया जाय कि अमुक कार्य वाछनीय है या नहीं।

सारी कर-व्यवस्था की जाँच आलोचनात्मक दृष्टि से करनी होगी। इस बात का खयाल रखना जायगा कि कर का बोझ किसके ऊपर पड़ता है। कालान्तर से कुछ कर बहुत बोझीले हो गये हैं। कुछ प्रकार के व्यवसाय करके बोझ को उचित मात्रा में नहीं वर्द्धित करते। कुछ काम न करने वाले मालिक उन लोगों की अपेक्षा जो उत्पादन बढ़ाने में बड़ा योग देते हैं, बहुत कम कर देते हैं। आय को दो बर्गों में बाँट देना जरूरी है। एक तो बिना कमाई की

जयप्रकाश की विचारधारा

पूँजी जो राष्ट्रीय साधनों पर स्वामित्व रखने के कारण भेंट स्वरूप मिलती है। दूसरे, उत्पादन में योग देने के कारण प्रत्यक्ष रूप से कमाई गयी पूँजी, इन दोनों वर्गों की पूँजी पर कर की दर तथा तरीके की स्पष्ट परिभाषा की जानी चाहिए। इस कर-व्यवस्था में हमारे सामाजिक दृष्टिकोण की स्पष्ट मूलक मिलनी चाहिए।

यह जरूरी हो जाता है कि आय और सम्पत्ति का वार्षिक विवरण तैयार कराया जाय। युद्धकालीन नफे को कर द्वारा खत्म कर देना चाहिए। कर-व्यवस्था को सामाजिक नीति का साधन बनाने का स्पष्ट तरीका है कि लाभ-कर, मृत्यु कर तथा पूँजी-कर लगाये जाएँ।

सोशलिस्ट पार्टी की राय है कि चोरबाजारी को खत्म करने के लिए कड़े उपाय काम में लाये जायें। ये उपाय ताजीरी तथा आर्थिक दोनों हैं।

अब तक काम में लाये गये ताजीरी तरीके नाकाफी रहे हैं। पार्टी की राय में सजा को पुरअसर बनाने के लिए चोरबाजारी करने वालों की जायदाद पर कब्जा कर लेना चाहिए तथा उनसे नागरिक अधिकार छोन लिये जायें।

चोर-बाजारी का अन्त करने के लिए पार्टी नीचे लिखे आर्थिक उपाय पेश करती है।

जिन चीजों पर, जैसे कपड़ा, राशनिंग है, उनको इस्तेमाल करनेवाली फैक्टूरियों की उत्पादन-शक्ति का अन्दाज श्रम प्रतिनिधियों की सहायता से सरकारी विशेषज्ञों को लगा लेना चाहिए। इसके बाद हरेक फैक्ट्री को सरकार के लिए चीजों को तैयार करने का कौटा दे देना चाहिए। इस माल को सरकार नियंत्रित कीमत की दूकानों तथा उपभोक्ता सहयोगी-समितियों के द्वारा, जिनके सदस्य एक निश्चित आय से नीचेवाले ही लोंग हो, उपभोक्ताओं में बाँटे। हरेक फैक्ट्री को अधिकार रहेगा कि वह नियत कौटा से अधिक सामान पैदा करे तथा अनियंत्रित खुले बाजार में बेचे।

(च) कृषि

कृषि हमारे आर्थिक जीवन का केन्द्र-बिन्दु है। इसमें हमारी जनशक्ति का तीन चौथाई भाग लगा हुआ है और हमारे दो तिहाई प्राथमिक साधन इसमें सन्निहित हैं। फिर भी पिछली सरकार और पूँजीवादी ढग के औद्योगिक योजनाकारों ने इस पर बहुत कम ध्यान दिया है। किन्तु जब तक हमारी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन नहीं होते, तब तक हमारी आर्थिक व्यवस्था का पूर्ण और सन्तुलित विकास नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ बता देना आवश्यक होगा कि परिवर्तन किस दशा में हो और इस सम्बन्ध में तत्काल क्या किया जा सकता है। इस योजना में पार्टी के तात्कालिक उद्देश्य ये हैं—

(अ) कृषि में लगी सरकारी पूँजी की वृद्धि करना, ताकि कृषि के लिए अधिक रकबे की जमीन मिल सके और हर खेतिहर मजदूर की उत्पादन शक्ति में वृद्धि हो सके। कृषि के उत्पादन को दिवालियापन से बचाने के लिए यह भी आवश्यक है कि खेतिहर मजदूर के प्रति घण्टे काम की मजदूरी की जाँच उद्योगों में लगे हुए मजदूरों की प्रति घण्टे की मजदूरी के आधार पर की जाय।

(आ) भूमि के स्वामित्व में इस प्रकार क्रांतिकारी परिवर्तन करना, ताकि हरेक व्यक्ति के लिए पर्याप्त सामान्य भूमि, जो वैज्ञानिक कृषि योग्य भी हो, निकल सके।

(इ) अतिरिक्त श्रम-शक्ति को काम देने के लिए गाँवों में नयी अर्थिक व्यवस्थाएँ करना—जैसे, सहयोग और बहुधवी समितियाँ, अनाज बैंक, मध्यम श्रेणी के उद्योग-धन्धे, विशेषतया उत्पादकों की सहयोग-समितियाँ आदि स्थापित करना।

(ई) कई प्रकार के जमींदार, महाजन और व्यापारी—इन्हीं तानों के द्वारा आज किसानों का शोषण किया जाता है। इसीलिए, किसान की समस्या

जयप्रकाश की विचारधारा

को नए सिरे से सुलझाने के लिए सभी तरह की ज़म्मेदारी को खत्म करना जरूरी है। राज्य और खेतिहर के बीच कोई बेकार लगान वसूल करने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। इस समय ऐसे मध्यस्थों की कमी नहीं है।

जमोन को अपने-आप पूर्ण बनाने के लिए चक्रवन्दी का अनिवार्य होना आवश्यक है।

इन सब चीजों का आवश्यक परिणाम यह होगा कि खेती के चकले का निश्चय जमीन के किस्म (नम या सूखी) के आधार पर किया जाय।

अगर ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को अव्यवस्थित नहीं रखना है और आर्थिक शोषण को रोकना है, तो यह भी जरूरी है कि खेतिहर मजदूर की स्थिति पर भी नए सिरे से विचार किया जाय। हर एक कृषि-क्षेत्र के लिए न्यूनतम मजदूरी तय कर दी जाय।

इसके लिए यह देखना होगा कि खेती के मौसम में हर एक खेतिहर मजदूरों को प्रति मनुष्य कुल कितने घंटे काम करना पड़ता है, और साल-भर में उनकी औसत कितने घंटे प्रति दिन पड़ती है। काम थोड़ा है और आदमी उसमें ज्यादा लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त श्रम को आसपास में स्थापित मध्यम श्रेणी के उद्योगों में लगाया जा सकता है।

ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था—जितना प्रयत्न उद्योग और व्यापार की आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने में किया गया, उतना प्रयत्न कृषि के आर्थिक पहलू को संभालने में नहीं किया गया। इस समय देहातों में जो अर्थ-व्यवस्था प्रचलित है, वह न किसानों के लिए न्यायोचित है और न निर्वाह योग्य सुविधा प्रदान करती है। गुजारे लायक खेत बन जानें और कानून के जरिए खेतों के छोटे टुकड़ों को मिलाकर बड़ा चक्र बना देने के बाद सरकार को कृषि में पूंजी लगाने में सुविधा हो जायगी और मौसमी फसल की बोआई में वह किसानों को आर्थिक सहायता दे सकेगी। नए खेतों की स्थिति दृढ़ करने के

समाजवादी कार्यक्रम

लिए फसलों का बीमा कराना भी जरूरी है। किसानों को चालू आर्थिक सहायता देने के लिए सबसे उपयुक्त साधन है—समग्र-ग्राम-सहायक-समिति (मल्टि, परपस सोसाइटी) और अनाज बैंक। कानूनन हरेक किसान को इस समिति में शामिल होना ही पड़ेगा। यह समिति ग्राम के सहयोगपूर्ण जीवन की परिचायिका होगी। समिति को किसानों के आर्थिक कार्यों का संगठन करना चाहिए। किसी भी किसान को अपने सिवा किसी और किसान का लेन-देन करने का अधिकार न होगा। फसल के दिनों में ऋण देने, अच्छे और छाँटे हुए बीजों तथा कृषि के आधुनिक औजारों का प्रबन्ध, अच्छी नस्ल के मवेशी तथा देहाती उपज की बिक्री आदि की व्यवस्था व्यक्तिगत रूप से न होकर इन समग्र-ग्राम-सहायक-समितियों के जरिए ही होनी चाहिए। इसी प्रकार उप-भोक्ताओं के लिए भी सहयोग के आधार पर चलनेवाली फुटकर सामानों की दुकानें होनी चाहिए।

इन मौसमी सहायताओं के अतिरिक्त किसानों के भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने, नालियाँ निकालने, जगल लगाने, बिजली-घरों और मध्यम श्रेणी के उद्योग-धन्धों को कायम करने और छोटे पैमाने पर सिंचाई के लिए नहरें तथा गाँव की सड़कें आदि बनवाने के लिए भी किसानों को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। इन कार्यों को प्रान्तीय सरकार की जिला-संस्थाओं को अपने हाथ में लेना चाहिए और इसमें ग्रामीण समितियों का भी सहयोग प्राप्त करना चाहिए। जैसा पहिले तय किया जा चुका है इन कार्यों के लिए श्रम-शक्ति गाँवों से प्राप्त होगी और आर्थिक सहायता बाहर से जुटानी पड़ेगी। गाँवों के सहयोग से जिले में जब इन कार्यों का संगठन हो जायगा तो इससे बहुत से नए लोगों को काम मिल जायगा और बेरोजगार मजदूर-रोजगार पा जायेंगे और इस प्रकार गाँवों के खेतों का फिर से बन्दोबस्त करने के काम में सहूलियत पैदा हो जायगी।

जयप्रकाश की विचारधारा

फिर भी इस योजना को सुविधा से कार्यान्वित करने में दो बाधाएँ उपस्थित होंगी—

अनिवार्य चकबन्दी से छोटे काश्तकारों का भूमि का स्वामित्व सीमित हो जायगा। उनमें से कुछ तो खेतिहर मजदूरों की स्थिति में पहुँच जाएँगे और बेकार तक हो जा सकते हैं। दूसरी ओर खेतिहर मजदूर को इससे निश्चित रूप में लाभ पहुँचेगा और जमीन के छोटे-छोटे बिखरे हुए और अपर्याप्त टुकड़ों के मालिक किसान से उसकी हालत कहीं अच्छी हो जायगी। गाँव में जिन में इनकी उद्योगशीलता नहीं है, वे ही खेतों पर टिके हुए हैं। ऐसे लोगों की सख्या भी थोड़ी नहीं है। वे इस तरह की किसी नई व्यवस्था के विरुद्ध दृढ़ प्रतिरोध भी करेंगे, जिसकी हमें उपेक्षा नहीं करनी है। समग्र ग्राम-समिति के कार्यों के सम्बन्ध में हमें इस तथ्य को ध्यान रखना होगा कि किसान किसी भी नए परिवर्तन का प्रतिरोध करेगा।

हम ऊपर बता चुके हैं कि खेतों पर काम करनेवाला मजदूर और अन्यत्र काम करनेवाले मजदूर के घण्टे काम की मजदूरी में कितनी असमानता है। ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था पर इसका चिन्तनीय प्रभाव पड़ा है। उद्योगी, साहसी महत्वाकांक्षी और योग्य व्यक्तियों को गाँव छोड़कर शहर में रोजगार खोजने जाना पड़ा है जिनमें इतनी उद्योगशीलता नहीं है, वे ही खेतों पर टिके हुए हैं। अपरिवर्तनशील और अगतिशील ये गाँव आज बाहरी दुनिया से तिरस्कृत से पड़े हैं। एक बड़ी बाधा यह भी है कि ग्रामीण जनता आगे बढ़ कर कोई काम शुरू नहीं करना चाहती। इससे गाँव आज कई समाज-विरोधी शक्तियों के शिकार हो गए हैं जो गाँव के सामाजिक जीवन पर सामन्तशाही की तरह शासन कर रही हैं। इन ऐक्य-विरोधी और समाज विरोधी ग्रामीण 'प्रभुओं' के कार्यों पर रोक-थाम लगाना और गाँववालों में आगे आकर काम करने की भावना और योग्यता पैदा करना आदि कार्य ऐसे हैं

समाजवादी कार्यक्रम

जिनके लिए हमें विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा। जब तक यह नहीं होता, देहाती जीवन का आर्थिक और राजनैतिक स्रोत गँदला और उसकी गति अवरूद्ध बनी रहेगी। इन्हीं कारणों से यह जरूरी है कि इस योजना के प्ररम्भ में जिले अधिकारी को पथ-प्रदर्शन करना चाहिए। कार्य की प्रगति के लिए गाँव के कुछ चुने हुए नौजवानों को ग्राम-सेना तैयार करना भी सहायक होगा ऐसी ग्राम-सेनाओं को ६ महीनों की ट्रेनिंग दे देने से जन-शक्ति के अभाव की संभावना न रहेगी। इससे अच्छी तरह और मिल-जुल कर काम करने की भावना में भी वृद्धि हो सकेगी। सधारणतया गाँव का कोई लड़का ६ सप्ताह की लगातार शिक्षा के बाद एक अच्छा सैनिक बन जाता है। इसी प्रकार यदि ग्राम पुनर्संरगठन के लिए भी ग्रामीणों की सेना भिन्न साधनों और औजारों से तैयार की जाय, तो ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए गाँव वालों का समर्थन प्राप्त किया जा सकता है। इस कारण पहले-पहल कार्य प्रारम्भ करने को उत्तरदायित्व जिला का होना चाहिए। जैसे-जैसे ग्राम सेना तैयार होती जाय, वैसे-वैसे एक गाँव के बाद दूसरे गाँव में काम शुरू होता जाय।

फिर भी इस तरह की योजना टी० बी० ए० के नमूने पर बनी हुई होनी चाहिए। जब तक इस तरह का चौमुखी प्रयत्न न किया जायगा, हमारे राष्ट्रीय जीवन में ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को समुचित स्थान नहीं मिल पायगा। सोशलिस्ट पार्टी सिफारिश करती है कि हर एक राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की योजना को पहले इन ग्रामीण समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा ध्येय है एक नए ग्रामीण और आदर्श ग्राम का निर्माण।

छ) गाँव के सहायक और छोटे उद्योग

ऊपर जिन साधनों और नीतियों का हमने उल्लेख किया है, यदि उनको

जयप्रकाश की विचारधारा

कार्यान्वित किया गया तो इसमें शक नहीं कि किसान का जीवन आर्थिक दृष्टि से प्रगतिशील हो जायगा। किन्तु ये कार्यक्रम अपने आप में पूर्ण नहीं हैं। ग्रामीण और छोटे उद्योग धंधों को पुनर्जीवित करने की भी आवश्यकता होगी। इस विकास के लिए स्थानीय परिस्थितियों का अध्ययन भी बहुत जरूरी है, लेकिन स्थूल सिद्धान्त तो निश्चित किये ही जा सकते हैं।

जहाँ तक समभव हो ऐसे सभी उद्योग-धन्धे औद्योगिक सहयोग-समितियों के अन्तर्गत चलाए जाने चाहिए।

उद्योग से उत्पादन और टेकनिक में उन्नति करने के लिए हर तरह से कोशिश होनी चाहिए।

गाँववालों को उत्साहित करने के लिए विशेषयता उन्हीं उद्योगों को चलना चाहिए जिनकी टेकनिक विस्तृत उत्पन्न की मशीन टेकनिक से बहुत दूर न हो।

उन उद्योगों को यथाशीघ्र सस्ती बिजली प्राप्त करने की सुविधा कर देनी चाहिए।

जयप्रकाश की विचारधारा

द्वितीय खंड

क्रान्ति की लपटों में

आजादी के सैनिकों के नाम

पहला पत्र

[१९४२ की क्रान्ति के समय हजारीबाग सेन्ट्रल जेल से भाग जाने के कुछ दिनों बाद जयप्रकाश ने यह पत्र प्रकाशित किया]

इन्कलाबी सलाम,

साथियो,

सबसे पहले मैं आप लोगों को और उन साथियों को जो युद्ध के बन्दा बना लिये गये हैं अपना हार्दिक अभिनन्दन आप लोगों द्वारा दुश्मन से लड़ी गई शानदार लड़ाई के लिए अर्पित करता हूँ। मुद्दों से कुचले गये हमारे इस पीडित देश में इस तरह की घटना न कभी घटी और न इसको उमीद की जाती थी। निस्सन्देह ही यह “खुली बगावत” थी, जैसी कि हमारे अनुपम नेता महात्मा गाँधी ने कल्पना की थी।

यह “बगावत” दबा दी गई है, इस समय ऐसा ही मालूम पड़ता है। किन्तु मेरा ख्याल है, और आप भी इस बात से सहमत होंगे कि हमारी बगावत कुछ ही समय के लिए दबाई जा सकी है। इसपर हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिये। आश्चर्य की बात तो यह होती कि हम अपने पहले धावे में

जयप्रकाश को विचारधारा

ही इस साम्राज्यवाद को चकनाचूर करके पूरी तरह सफलता प्राप्त कर चुके होते। दुश्मन द्वारा यह स्वीकार कर लिया जाना कि यह बगावत करीब-करीब उसकी सत्ता को नष्ट कर चुकी थी, साबित करता है कि अपनी राष्ट्रीय क्रान्ति की पहली मंजिल में हम कितने सफल हुए हैं !

और हमारी क्रान्ति की यह पहली मंजिल भी किस तरह कुचली गई ? क्या दुश्मन को सैनिक शक्ति—उसकी गुंडागिरी, लूट, अगलगी और हत्या की हुकूमत—ने यह काम किया ? “बगावत कुचल दी गई”—ऐसा सोचना भी गलत है। हर क्रान्ति का इतिहास बताता है कि क्रान्ति कोई छिटपुट घटना नहीं हुआ करती है। क्रान्ति तो एक सामाजिक प्रक्रिया है और क्रान्ति के विकास के सिलसिले में ज्वार और भाटे आया ही करते हैं। इस समय हमारी क्रान्ति का पानी उतार पर है। हमारी क्रान्ति ऊपर से ऊपर उठती हुई विजय पर विजय नहीं प्राप्त कर सकी, तो इसका कारण साम्राज्यवादी लुटेरों की पाशविक शक्ति की प्रबलता नहीं, बल्कि इसके दो अन्य कारण हैं।

सबसे पहली बात तो यह है कि राष्ट्रीय क्रान्तिकारी शक्तियों के पास कोई चुस्त संगठन नहीं था जो इस क्रान्ति से पैदा हुई महान शक्तियों का नेतृत्व कर सके। कांग्रेस एक महान सस्था है, किन्तु जिस ऊँचाई पर यह क्रान्ति जा पहुँची, उसके अनुरूप वह भी अपने को सिद्ध नहीं कर सकी। संगठन की कमी का यह हाल था कि प्रमुख कांग्रेसी नेता और कार्यकर्त्ता भी नहीं जानते थे कि क्रान्ति कहाँ पर किस मंजिल तक पहुँच चुकी है। और, बहुत दिनों तक तो यह विवाद ही चलता रहा कि यह कांग्रेस के कार्य-क्रम से कहाँ तक मेल खाती है। इस दुखद सत्य को भी हमें स्वीकार ही कर लेना है कि बहुत से प्रभावशाली कांग्रेसजन अपने दिमाग को आजादी को इस अन्तिम लड़ाई की ऊँची सतह तक ले जाने में असमर्थ सिद्ध हुए। महात्मा गाँधी, डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद या सरदार पटेल में जिस गम्भीरता, शीघ्रता

आजादी के सैनिकों के नाम

और दृढ़निश्चय का रुख था, उसका प्रतिविम्ब सभी क्रांग्रेस नेताओं के दिल और दिमाग में नहीं देखा गया था ।

दूसरी बात यह, कि क्रान्ति की जब पहली मजिल खत्म हुई, तो जनता के सामने आगे का कोई कार्यक्रम नहीं रह गया । अपने हत्को में अङ्गरेजी राज्य का खात्मा करके जनता ने मान लिया कि उसका कर्तव्य पूरा हो गया, वह चुपचाप अपने घर जाकर बैठ रही । इसमें उसका कोई कसूर नहीं था । यह तो हमारी गलती थी—यह हम थे जिन्हें जनता को आगे का कार्यक्रम देना था । जब हमने वह कार्यक्रम नहीं दिया, तो क्रान्ति की धारा रुक गई और अब ज्वार के बाद हम भाटे का दृश्य देख रहे हैं । अङ्गरेजी फौज के पहुँचने के पहले ही यह भाटा गुरु हो गया था, उसने तो हटती हुई तरंग को धक्के देकर और जल्द हटा दिया । यहाँ सवाल उठता है कि क्रान्ति की इस दूसरी मजिल में कौन सा कार्यक्रम हमें देना था । इसका जवाब क्रान्ति की प्रकृति पर निर्भर करती है । क्रान्ति सिर्फ सत्यानाश करने वाली शक्ति नहीं होती, वह निर्माण की बहुत बड़ी प्रेरिका शक्ति है । कोई क्रान्ति सफल हो नहीं सकती, जो सिर्फ नाश ही नाश करे । यदि क्रान्ति को जिन्दा रहना हो, तो जिस शक्ति को वह नाश करती है, उसकी जगह पर तुरत नई शक्ति का सृजन करे । हमारी क्रान्ति बड़े-बड़े हत्कों में अङ्गरेजी राज की सत्ता नष्ट कर चुकी थी, अब उसे उसकी जगह पर किसी नई सत्ता का निर्माण करना था । अङ्गरेजी हाकिमों को भगा कर ओर हुकूमत की कड़ियों और प्रतीकों को तोड़फाड़ या जला कर ही सन्तोष नहीं कर लेना था, बल्कि उन हत्कों में फौरन ही नई क्रान्तिकारी सरकार का संगठन कर लेना चाहिये था और उसके लिए फौज और पुलिस की टुकड़ियाँ भी तैयार कर लेना था । यदि ऐसा किया गया होता, तो लोगो में कल्पनातीत उत्साह और शक्ति का संचार हो गया होता, रचनात्मक कार्य के लिए एक विस्तृत क्षेत्र खुल गया होता जिससे क्रान्ति की

जयप्रकाश की विचारधारा

लहर ऊँची से ऊँची सतह पर चढ़ती जाती, उन हल्कों में भी वह फँस जाती जहाँ ऐसी लहर नहीं आई थी और अन्ततः हम अपने समूचे देश में एक सर्वोच्च सत्ता की सृष्टि कर लिये होते ।

चुस्त सगठन का अभाव और राष्ट्रीय क्रान्ति के लिए एक पूरे कार्यक्रम की कमी—हमारी बगावत के उतार के कारण ये ही दो हैं ।

अब सवाल यह है कि इस समय हम क्या करें ? सबसे पहला काम तो यह है कि हम अपने और जनता के दिमाग से पस्ती की भावना दूर करें और जो सफलता मिल चुकी या जो आगे मिलने वाली है उस ओर ध्यान आकृष्ट कर देश भर में आशा और उत्साह की भावना पैदा करें ।

दूसरा काम यह है कि हम अपने और जनता के दिमाग के सामने इस क्रान्ति की प्रकृति को स्पष्टता और दृढ़ता से रखें । हमें यह समझ लेना है कि यह हमारी आजादी की आखिरी लड़ाई है । इस लिए हमारा उद्देश्य एकमात्र विजय है, इसके नीचे कुछ नहीं । हम बीच में रुक नहीं सकते, रुकने की जगह नहीं है । राजगोपालाचारी ऐसे लोग राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए जो उछलकूद मचा रहे हैं, उससे हानि ही हानि है । ऐसे कामों से जनता का ध्यान मुख्य प्रश्न से हट जाता है । “भारत छोड़ो” और “राष्ट्रीय सरकार” के बीच में समझौता हो नहीं सकता । जो लोग कांग्रेस और लीग में सुलह करना चाहते हैं, वे साम्राज्यवादी प्रचार को लाभ पहुँचा रहे हैं । एकता की कमी की वजह से राष्ट्रीय सरकार नहीं बन रही है, जो इस तरह सोचते हैं वे गलती में हैं । सही बात यह है कि विदेशी हुकूमत अपने को यहाँ से हटाना नहीं चाहती है और तरह-तरह के बहानों की शरण लेती है । चर्चिल ने यह साफ कर दिया यह कह कर कि वह साम्राज्य को डुबोने के लिए बादशाह के वजीरेआजम नहीं बने हैं । वे लोग इतिहास के बेवकूफ विद्यार्थी हैं जो सोचते हैं कि साम्राज्यवाद आप ही खुदकुशी कर

आजादी के सैनिकों के नाम

लेगा। कल तब जो अपने को 'क्रान्तिकारी' समझते थे, वे यदि अजियों और आरजू-मिश्रों के जोर से भारतीय साम्राज्य के खात्मे का स्वप्न देख रहे हैं, तो उनसे बढ़ कर बेवफूफ इतिहास किसको मानेगा ?

भारतीय समाज के हर फिरके या तबके के बीच एकता स्थापित की जाय, आज की माँग हमसे यह नहीं है। समय की पुकार यह है कि राष्ट्र की सभी क्रान्तिकारी ताकतों में एकता हो। यह एकता कांग्रेस के भंडे के नीचे स्थापित हो चुकी है। कांग्रेस और लीग में एकता हो जाने से इन क्रान्तिकारी शक्तियों को बल नहीं मिलेगा, बल्कि उनका कदम धीमा पड़ जायगा क्योंकि मुस्लिम लीग क्रान्ति के पथ पर जाते ही डगमग करने लगेगी।

साम्राज्यवाद का बिल्कुल खात्मा—अपने इस उद्देश्य को हमें कभी नहीं भूलना है। इस सम्बन्ध में हम कोई समझौता कर नहीं सकते—चाहे हम हारे या जीते। और हम हार नहीं सकते। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमने अन्त तक लड़ते रहने का निश्चय कर लिया है, बल्कि ससार में ऐसी शक्तियाँ पैदा हो रही हैं जो फासिज्म के साथ ही साम्राज्यवाद को भी अन्त कर देंगी। यह कभी नहीं सोचिये कि युद्ध के बाद विजयी राष्ट्रों द्वारा आयोजित कोई शान्ति-सम्मेलन लड़ाई के बाद के ससार के भाग्य का निबटारा करेगा। युद्ध एक अजीब प्रयोगशाला है ? इसके तहखानों में ऐसी शक्तियाँ तैयार और सग्रहीत होती रहती हैं, जो एक ही विस्फोट में विजयी और पराजित दोनों की योजनाओं को हवा पर फेंक दें। पिछली लड़ाई के किसी शान्ति-सम्मेलन ने यह नहीं तय किया था कि चार विशाल साम्राज्य नष्ट कर दिये जायँ—रूस, जर्मनी, आस्ट्रिया और तुर्की के साम्राज्य। और, रूस, जर्मनी या तुर्की में जो क्रान्तियाँ हुईं, उनपर लायड जार्ज, क्रिमेसो या विल्सन ने दस्तखत नहीं किये थे।

जहाँ कहीं भी युद्ध हो रहा है, आदमी मर-कट रहे हैं, वहाँ-वहाँ

जयप्रकाश की विचारधारा

युद्ध की वह प्रयोगशाला अपना काम कर रही है। भारत में जो कुछ हुआ है, वह उसी का खेल है। इस युद्ध के बाद की दुनिया का भविष्य चर्चिल-रूजवेल्ट या हिटलर-तोर्जो पर निर्भर नहीं करेगा। जो शक्ति हमारी इस खुली बगावत के रूप में सामने आई है, ऐसी ही शक्तियाँ अपने ऐतिहासिक कार्य को सम्पन्न करेगी। क्या इसमें सन्देह की गुंजायश है कि क्रान्तिकारी शक्तियों ने चारों ओर उथलपुथल मचाना शुरू कर दिया है ? क्या हम इस पर विश्वास कर सकते हैं कि आज लाखों-करोड़ों लोग जो इतना कष्ट सह रहे हैं, वे अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे होंगे ? क्या हम इसपर विश्वास करें कि सभी देशों की जनता अपने शासकों द्वारा फँसाई गई झूठ पर आँख मूँद कर विश्वास कर रही है ? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता !

इसलिए अपने भविष्य पर दृढ़ विश्वास करके हमें आगे बढ़ते जाना है। तो, हम इस समय कोन-सा निश्चित काम करें ? जब कोई सेनापति हारता या जीतता है, तो क्या करता है ? वह विखरी शक्तियों को केन्द्रित कर दूसरे मोर्चे की तैयारी करता है। एल-अमीन में अपनी विजय के बाद रोमेल रुक गया, जिससे आगे बढ़ने के लिए वह तैयारियाँ कर ले। हारा हुआ एलेक्जेंडर भी सगठन और तैयारी में लगा और अपनी पराजय को विजय बनाकर ही रहा। हम तो हारे भी नहीं हैं। पहली लड़ाई में तो हम जीत गये जब हमने देश के एक बड़े हिस्से से विदेशी लुटेरों को बिल्कुल खदेड़ दिया। अब जनता यह जान गई है कि अँगरेजी राज किस तरह ताण का घर है। एक ही फूँक में उसकी पुलिस, उसकी कचहरी, उसके जेल, उसके थाने हवा में उड़ जा सकते हैं। जनता अपना सगठित शक्ति को पहचान गई है—अब वह उसे भूल नहीं सकती और अगली लड़ाई में वह वहीं से शुरू करेगी।

इसलिए हमारा तीसरा और सबसे बड़ा काम यही है कि हम अगली

ग्राजादी के सैनिकों के नाम

चढ़ाई के लिए तैयारियाँ करें। सगठन और अनुशासन—ये ही दो हमारे उद्देश्य-शब्द हैं।

अगली चढ़ाई—अगला धावा ! हमारी अगली चढ़ाई कब शुरू होगी ? कुछ लोग समझते हैं कि अगामी पाँच-छः वर्षों के अन्दर जनता फिर उभड़ नहीं सकती। यह अन्दाजा शान्ति के जमाने के लिए ठीक हो सकता है, किन्तु लड़ाई के जमाने के लिए ऐसा सोचना गलत है—क्योंकि लड़ाई के जमाने में सबकी गति में शिप्रता आ जाती है। ससार भी तेजी से बदलता है इस दौरान में। अँगरेजी फासिस्टों ने—लिलिथगो, हैलेट, स्टीवार्ट और उसके भाईबन्दों ने तथा उसके जूते चाटनेवाले हिन्दोस्तानियों ने—ऐसे झगड़े मारे कि जनता को लेट जाने को भुले ही लाचार हो जाना पड़ा हो, किन्तु सारे देश में कहीं भी जनता ने उठकर उनसे हाथ नहीं मिलाया। नाजी-नरक के अँगरेजी रूप देश के जिन कोनों में हमें देखने को मिला, वहाँ-वहाँ की जनता असन्तोष, घृणा, क्रोध आदि प्रतिशोध की भावनासे छटपट कर रही है। ज्यों ही जनता को मालूम हो जाय कि क्रान्ति की हम एक विशाल आयोजन कर रहे हैं, त्यों ही वह हिम्मत बाँधकर खड़ी हो जायगी और हमारी योजनाओं में क्रियात्मक भाग लेने लगेगी। ज्योंही उनमें सहयोग और अनुशासनपूर्ण कार्य की भावना आई, हम धावा चोल देंगे। अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ भी हमारी मदद करेंगी। और, फिर गाँधीजी के आमरण उपवास की बात हम नहीं भूलें—वह कभी भी हमारे सामने आ सकता है, इसलिए हमें न तो ढिलाई करनी है, न हिचक में पड़ना है, न आराम से बैठना है।

हमारी अगली चढ़ाई के सवाल के साथ क्रान्ति की अगली मजिल की रूप-रेखा नश्यी है। यह अगली मजिल होगी क्रान्तिकारी सरकार की स्थापना की। क्रान्तिकारी सरकार के साथ फौज रखने और हिंसा का प्रयोग करने का

जयप्रकाश की विचारधारा

सवाल भी उठ खड़ा होता है। मैं चाहता हूँ कि इस संवध में भी अपने विचार आपके सामने रख दूँ, क्योंकि मेरे खयाल में क्रान्ति के भविष्य को यह बहुत ही प्रभावित करेगा।

सबसे पहले मैं अंगरेजों द्वारा फैलाये गये इस होहल्ला पर दो शब्द कहना चाहता हूँ कि क्रान्ति के दरम्यान हिंसा की गई। मैं मानता हूँ कि अधिक उत्तेजना के वशीभूत कई स्थानों में हिंसा भी हो गई; किन्तु जितनी बड़ी बगावत थी और लोगो ने जैसी व्यक्तिगत और सामूहिक अहिंसा का परिचय दिया उनको देखने हुए यह हिंसा नगन्य ही समझी जानी चाहिये। लोग यह भूल जाते हैं कि हजारों अंगरेजों या अंगरेजी सरकारके हिन्दोस्तानी अफसरो की जान कुछ दिनों तक जनता की दया पर निर्भर करती थी और उन्होंने न सिर्फ उनकी जान के प्रति बल्कि उनकी दौलत के प्रति भी अजीब दया और सयम का भाव दिखलाया। फिर जरा उन हजारो नौजवानो और बूढ़ो की हिम्मत ओर बहादुरी की तारीफ कीजिये जिन्होंने दुश्मन की गोलियाँ अपनी छाती पर हँमते-हँसते ली और अपने होठो पर 'इन्कलाब जिन्दाबाद' की मुहर लगाते गद्दीद हो गये। इस दैवी साहस पर 'अंगरेजो' ने प्रगसा के कितने शब्द कहे हैं ?

किसी भी हालत में अंगरेजों के लिए यह शोभा नहीं देता कि वे दूसरे द्वारा की गई हिंसा पर उँगली उठायें। आखिर हिन्दुस्तान में उनका राज्य किस चीज पर निर्भर है ? वह हिंसा पर निर्भर है, वह खून से लथपथ है, वह दिन-रात ऐसी क्रूर हिंसाएँ किया करता है जिसकी मिसाल नहीं। वह करोड़ो आदमियों को दिन-रात पीसता और उनके प्राण रक्त को चूसता है। अंगरेजों को यह पूछने का कौन-सा मुँह है कि हम आजादी की अपनी लड़ाई किस हथियार से लड़ेगे ? क्या हम पूरी अहिंसा निभावें तो वे अहिंसा को अपनाने को तैयार हैं ? क्या हजारों अहिंसक सत्याग्रहियों को उन्होंने

आजादी के सैनिकों के नाम

गोलियों से नहीं भून डाला है ? हम चाहे अहिंसा का प्रयोग करें या हिंसा का, अंगरेजों के पास हमारे दमन के लिए एक ही हथियार है वह है गोली, वह है लठ्ठ, वह है औरतों पर बलात्कार। इसलिए उन्हें चुप ही रहना चाहिए। हम किस तरह लड़ेगे, किस हथियार से लड़ेगे—इसका निर्णय करना बिल्कुल हमारा काम है।

जहाँ तक अपने लोगों का स्वाल है, इस पर विचार करते समय मैं आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूँ कि गाँधीजी की अहिंसा की धारणा में और कार्यममिति और अखिल भारतीय कांग्रेस समिती की धारणा में बहुत अन्तर है। गाँधीजी किसी भी हालत में अहिंसा से हटने को तैयार नहीं हैं। अहिंसा उनके लिए जीवन-सिद्धान्त है, धर्म है। किन्तु, कांग्रेस के लिए ऐसी बात नहीं है। इस लड़ाई के दम्यान कांग्रेस ने कई बार इस बात को दुहराया है कि यदि हिन्दुस्तान आजाद हो जाय या राष्ट्रीय सरकार कायम की जाय, तो यह चर्चा करनेवालों का सानना हथियार से करने का तयार है। यदि हम लोग जापान और जर्मनी से हथियार लेकर लड़ने को तैयार हैं, तो फिर हम अंगरेजों से हथियार की लड़ाई क्यों न लड़े ? इसका जवाब सिर्फ एक ही सकता है कि यदि कांग्रेस का सरकार होगी तो उसके पास फौज भी रहेंगी। लेकिन, आज तो ऐसी कोई बात नहीं है। किन्तु, मान लीजिये कि एक क्रांतिकारी सेना संगठित की गई या आज की हिन्दुस्तानी सेना या उसके किसी हिस्से ने विद्रोह कर दिया, तो क्या यह अमगत नहीं होगा कि पहले हम सेना को विद्रोह करने को कहें और फिर विद्रोही सैनिकों को सलाह दें कि वे अपने हथियार नीचे डालकर अंगरेजों की गोली गুলी छातों पर लें ?

मैं यह साफ कह देना चाहता हूँ कि बहादुरों की अहिंसा में मेरा पूरा विश्वास है और यदि यह बड़े पैमाने पर प्रयोग में लाई जाय तो हिंसा की कोई

जयप्रकाश की विचारधारा

जहरत नहीं रह जाती। किन्तु, जहाँ ऐसी अहिंसा का अभाव है, वहाँ शास्त्रीय सूक्ष्मताओं की आढ में प्रचारित कायरता को मैं क्रान्ति के विकास का बाधक और उसकी असफलता का कारण नहीं बनने दे सकता।

अपनी क्रान्ति की अन्तिम मंजिल की पूरी तस्वीर दिमाग में रख कर हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने को संगठित करें, आगामी युद्ध की तैयारी करें, और क्रान्ति की फौज को शिक्षित और अनुशासित बनायें। यह सब करत हुए हमें हमेशा यह याद रखना है कि सिर्फ़ षड्यन्त्र हमारा लक्ष्य नहीं है। पूरी जनता एक साथ बगावत कर दे, हमारा लक्ष्य यह है। इस लिए क्रान्ति के टेक्निकल कामों को करते हुए भी हमें जनता में व्यापक कार्य करना है, गाँवों के किसानों में और कारखानों, खानों, रेलवे और दूसरे उद्योग-धंधों के मजदूरों में हम लगातार काम करते जायें। उनके बीच हमें लगातार प्रचार करना है और उनकी आये दिन की तकलीफों में मदद पहुँचाना है। सामयिक मांगों के आधार पर उनका संगठन करते जाना है और उनमें से अपने लिए सैनिक भी भर्ती करते जाना है। फिर, इन सैनिकों को राजनीतिक शिक्षा और टेक्निकल ज्ञान भी हमें देना है। यदि हमने शिक्षित सैनिकों की अच्छी टोलियाँ बना लीं, तो फिर एक मुट्ठी लोग वह कर दिखायेंगे कि जिसे हजारों नहीं कर सकें। हर तालुका और थाने में, हर कारखाने और दूसरे औद्योगिक केन्द्र में हमें नौजवानों की ऐसी लड़ाकू टोलियाँ चाहिये जो अगली बगावत के लिए दिमाग से और सामान में तैयार रहे।

फिर हमें हिन्दुस्तानी फौज और सर्विसों के बीच काम करना है। प्रचार और प्रदर्शन का काम भी है। स्कूलों में, कार्जेजों में, बाजारों में भी काम करना है। देशी राज्यों में और हिन्दुस्थान की सरहदों पर भी हमें डटना है। यह मेरे लिए संभव नहीं कि सारी तैयारियों को हम यहाँ गिना सकें। इतना

आजादी के सैनिकों के नाम

ही कहना काफी है कि बहुत से काम करने हैं और सब आदमी के लिए काम है। हम बहुत कुछ कर रहे हैं किन्तु ज्यादा काम करने को ही बरे पड़े हैं।

सिवा नौजवानों के ये सारे काम कौन करेगा ? क्या मैं आशा करूँ कि हमारे विद्यार्थी साथी जिन्होंने इस बगावत में इतना किया है, वे इस काम में भी डट जायेंगे और अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति करेंगे ? इसका जवाब हम उनसे चाहते हैं।

मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि तैयारी का यह मतलब कभी नहीं है कि अबतक जो काम हो रहे हैं, वे रोक दिये जायें ! नहीं, हाथापाई, सरहदी कार्रवाइयाँ, छोटी-छोटी मुठभेड़—ये सब तो चलते ही रहना चाहिये। ये सब चढ़ाई की तैयारियों में ही शुमार किये जा सकते हैं।

जनता में पूरा विश्वास रख कर और अपने उद्देश्य में पूरी भक्ति रखते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है। हमारे कदम मजबूती से उठें, हमारा हृदय चंचल न हो, और हमारी आँखें साफ देखें। हिन्दुस्थान की आजादी का सूरज क्षितिज पर उग चुका है, हमारी शकयें, हमारे आपसी भग़ावे, हमारी निष्क्रियता, हमारी विश्वासहीनता वादल बन कर कहीं उस सूरज को ढँक न लें और कहीं हम फिर अपने ही पैदा किये हुए अधिकार में भटकने न लगे।

अन्त में, साथियों, मुझे यह कहते बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मैं एक बार फिर आपलोगों के बीच आकर अपनी सेवायें आपको समर्पित करने का अभिमान अनुभव कर रहा हूँ। आपकी सेवायें करते हुए अपने नेता को 'करो-या-मरो' का नारा मेरा ध्रुवतारा होगा और आपकी आज्ञा का पालन ही मेरा एकमात्र आनन्द।

हिन्दुस्तान के किसी कोने से

—जयप्रकाश नारायण

आजादी के सैनिकों के नाम

दूसरा पत्र

साथियो,

आज से कई महीने पहिले, दुश्मन के कैदखाने से निकल भागने के बाद ही, मैंने अपनी राष्ट्रीय क्रांति के सबध में अपने विचार तथा इस सिलसिले में अपने कुछ सुझाव आपके सामने रखे थे तब से छः महीने गुजर गये और बहुत कुछ उलटफेर भी हुए अतः मैं समझता हूँ कि पिछले महीनों पर गौर कर लेना और अपनी लड़ाई की मौजूदा स्थिति को समझ लेना हमारे लिए अच्छा होगा ।

(१)

अपनी क्रांति की प्रगति के पिछले आधे वर्ष के साथ निकट सम्पर्क में रहने के बाद मैं देखता हूँ कि शुरू में जो मेरे खयाल थे, उन्हें बदलने की कोई वजह नहीं । साथ ही अपनी पिछली चिट्ठी में मैंने जो विटलेपण किया था उसमें भी, एक बात को छोड़ कर जो बहुत मौलिक न होते हुए भी महत्वपूर्ण है, किसी विशेष संशोधन की जरूरत मैं नहीं समझता ।

पिछले दिसम्बर में मुझे ऐसा मालूम हुआ कि कुछ ही महीनों में एक-

(१४६)

बार फिर जन-विप्लव की संभावना है। यह जन-विप्लव अभी तक नहीं हो सका है और, मानना पड़ेगा कि, निकट भविष्य में होता नहीं नजर आता। अब सवाल यह है कि इस बात का हमारी वर्तमान नीति और हमारी लड़ाई के ऊपर क्या असर पड़ता है। इस सवाल के जवाब के लिए जरूरी है कि हम जनता के अब तक दोबारा न उभड़ सकने की थोड़ी तह में जायें।

मैं समझता हूँ कि इससे यह नतीजा निकालना गलत होगा कि जनता की आजादी की भावना को कुचल डाला गया या उनमें लड़ाई का कोई दम ही नहीं रह गया। लोगों में अंग्रेजी राज के लिये उतनी नफरत कभी न थी, जितनी आज और वे उससे छुटकारा पाने के लिए आज-जैसे बेचैन और कटिबद्ध कभी न थे। इसमें शक नहीं कि आज लोगो में कुछ कमजोरी भी नजर आती है लेकिन वह यदि पूर्णतः नहीं, तो मुख्यतः शहरों में और समाज के ऊँची सतह के लोगों में ही है। देहातो में जहाँ दमन का नगा नाच हुआ था, लोग झुकने के बजाय बदला लेने की उत्कट इच्छा से जल रहे हैं। उपयुक्त मौका मिलते ही वे उठ खड़े होंगे और ब्रिटिश शासन की धज्जियाँ उड़ाके छोड़ेंगे। जिन गावों के लोग ब्रिटिश गुंडाशाही के शिकार होने से किसी तरह बच गये थे, वे ही अब भी कभी-कभी डर के लक्षण दिखलाते हैं और किसी न किसी तरह जोखिम से बचना चाहते हैं। लेकिन मेरा विश्वास है कि जब घड़ी आ पहुँचेगी तब इन लोगों को भी अपने दूसरे भाइयों के साथ-साथ आगे बढ़े चलने के लिए तैयार किया जा सकेगा। यह बात सही है कि वे विद्यार्थी जिन्होंने पिछले विप्लव में अहम भाग लिया था, फिर से अपने स्कूलों और कॉलेजों में चले गये हैं। लेकिन जहाँ तक मैं समझ सका हूँ वे बिल्कुल हतोत्साह नहीं हुए हैं और वे हमें

जयप्रकाश की विचारधारा

आनेवाले विप्लव की अगली कतार में तैयार मिलेंगे। खाद्य-संकट की नित्य बढ़ती हुई उलझने, जीवन-निर्वाह की बढ़ती हुई कठिनाइयाँ और मजदूरों के पैसों का रोज गिरता हुआ मोल, क्या ये सब सरकार के युद्ध-प्रयत्नों के लिए मजदूरों के दिल में हमदर्दी पैदा करेंगे ? यदि और जब दूसरी खुली बगावत हुई तो उसमें मजदूरों का हिस्सा पिछले अगस्त-सितम्बर से कम नहीं, बल्कि अधिक ही रहेगा। पुलिस विभाग के निम्न कर्मचारी ऊपर से तो मुजरिमाना हुकूम के प्रति फिर से बफादार बन गये, मालूम होते हैं जरूर, लेकिन वे, उससे सतुष्ट होने की बात तो अलग रहे, उल्टे अगले जन-सघर्ष के मौके पर १९४२ की वनिस्वत कहीं कम विश्वास-पात्र साबित होंगे। लड़ाई के दौरान के साथ-साथ हिन्दुस्तानी फौज के सिपाहियों और अफसरों का असतोष घटने के बजाय और बढ़ गया है और कमान्डर-इन-चीफ की, उनके वेतन इत्यादि के सवन्ध की, नयी स्कीम भी शायद उसे कम न कर पावेगी।

अब यह पूछा जा सकता है कि अगर ऊपर दिया गया चित्र सही है, तो फिर दूसरी बगावत क्यों नहीं हुई और इसके निकट भविष्य में हो सकने की संभावना क्यों नहीं है ? मेरे ख्याल से इसका कारण गूढ़ मनोवैज्ञानिक तत्वों में निहित है। अक्सर इन तत्वों के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती यद्यपि इनको सही तौर पर समझना नेताओं का कर्तव्य है। इस सवन्ध की अनेक आवश्यकताओं में से एक है जनता के दिल में यह विश्वास पैदा हो जाना कि शासकों का दम उखड़ गया है और वे अपनी अन्तिम घड़ियाँ गिन रहे हैं। गत वर्ष अगस्त के पूर्व के महीनों में विद्रु-युद्ध की ऐसी अवस्था हो गई थी कि भारतीय जनता को यह निश्चय हो गया था कि ब्रिटिश साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो रहा है और उनके एक धक्का मात्र से वह ढह पड़ेगा। वर्तमान में और इसके कुछ पहिले लोगों के दिमाग में या तो इस

आजादी के सैनिकों के नाम

धारणा का अभाव है या वह इतनी क्षीण हो गई है कि जोश और उत्साह की जगह भिन्नक पैदा हो गई है। लक्ष्मणों से ऐसा मालूम पड़ता है कि अमेरिका ने झुबते हुए ब्रिटिश साम्राज्य को बचाकर उसके टूटे हुए अंगों को जोड़ कर उठाने का जिम्मा लिया है। लेकिन सच तो यह है कि यह अभाग साम्राज्य पूर्ववत् विनाश की ओर बढ़ता जा रहा है और तुराँ यह कि इसमें अमेरिकन लोग भी हाथ बँटाये बिना न रहेंगे, क्योंकि इसके जिन इलाकों को वे दुश्मन के हाथों से “मुक्त करेंगे” उन पर वे अपना अव्वल हक जमाये बिना न रहेंगे। लेकिन यह बात साधारण दृष्टि में नहीं आती और इसीलिए जनता के दिल में ठंडक आ गई है।

यह भिन्नक दो हालतों में मिट सकती है : या तो यदि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में सुधार हो, अर्थात् वह ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतिकूल हो, अथवा एक संगठित क्रांतिकारी ताकत दुश्मन पर लगातार दब-प्रहार करके जनता के मन में यह विश्वास पैदा कर दे कि अपनी विशाल सेना के बावजूद ब्रिटिश साम्राज्य विद्रोही भारत के मुकाबिले असमर्थ है और साथ ही उनमें इस आशा का संचार कर दे कि आनेवाली क्रांति का नेतृत्व मजबूत हाथों में होगा और उसके सफल होने की पूरी उम्मीद है।

पिछले साल के अगस्त में अनुकूल मानसिक वातावरण पैदा करने में सिर्फ लड़ाई की परिस्थिति ने ही नहीं मदद पहुँचाई, बल्कि इस बात ने भी कि कांग्रेस पूरी ताकत से देश का नेतृत्व कर रही थी। जनता को अपने नेताओं पर भरोसा था और इसलिए जब उनकी पुकार हुई तब वह पूरे विश्वास और उत्साह के साथ मैदान में आ कूदी। आज ये नेता जेलों में बन्द हैं और इसलिए जनता की नजर में लाचार दीख रहे हैं। इस तरह विद्रोह के लिए अनुकूल सार्वजनिक मानसिक वायुमंडल पैदा करने का दूसरा कारण भी आज मौजूद नहीं है।

लेकिन, यद्यपि हम ऊपर बतलाई हुई पहली हालत तो पैदा करने में असमर्थ हैं, फिर भी दूसरी हालत के सम्बन्ध में तो हम स्थिति में सुधार कर ही सकते हैं और हमें यह करना चाहिये ही। इस झूठे बहाने की ओट में कि जनता आगे नहीं बढ़ना चाहती, वह हमारा साथ नहीं देती, युद्ध-क्षेत्र से दूर हटने की प्रवृत्ति इधर-हमारे सैनिकों में बढ रही है। यह तो एक तरह से पराजय की मनोवृत्ति है। जब तक जनता को आगे बढ़ा सकने का दम हम में नहीं होगा, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकती। जब तक हम अपनी कार्रवाइयों से, अपने संगठन की ताकत और कुशलता से जनता का विश्वास नहीं हासिल कर सकेंगे, तब तक वह हमारा साथ नहीं दे सकती। जनता ने तो एक बार अपना फर्ज अदा किया ही, चूक हमारी ही ओर से रही। वह फिर अपना कर्त्तव्य पूरा करेगी बशर्ते कि हम भी अपने कर्त्तव्य से न चूकें। पिछले वर्ष के अगस्त में जनता की आँखों के आगे कांग्रेस की ठोस ताकत और महात्मा गांधी का नेतृत्व था। आज यदि लोग यह समझने को मजबूर हों कि वे अकेले रह गये हैं और देश में कोई भी ऐसी संगठित तथा अपराजित शक्ति नहीं रह गई है जो लड़ाई को जारी रख सके तो ऐसी हालत में वे स्वभावतः ही निराशा में डूब जायेंगे और भाग्य के भरोसे बैठ जायेंगे।

अतः वर्तमान स्थिति में उन लोगों को आगे आना चाहिये, जिन्होंने क्रांति के सिपाहियों में अपने नाम दर्ज कराये हैं और जो आजादी की लड़ाई से किसी भी हालत में मुँह मोड़ने वाले नहीं। उन्हें अपने संगठन को मजबूत बनाकर दुश्मन से अनवरत लड़ाई जारी रखनी है। कैसा भी कष्ट, कितना भी बलिदान हमारे लिए थोड़ा ही है। कोई विवाद, कोई प्रलोभन, किसी तरह की झूठी आशा हमें पथ से विचलित न कर पावे। लड़ाई के सभी रास्ते हमारे सामने खुले पड़े हैं। हमारे धर्म और मत चाहे जो भी हों, हमारे हथियार और तरीके चाहे जैसे भी हों, हमारा रास्ता स्पष्ट है—हमें लड़ाई को जारी

रखना है। लड़ाई चाहे एक साल चले या दस साल, हमें इसकी परवाह नहीं। अमेरिका को अपनी आजादी के लिए सात साल तक लड़ना पड़ा था, चीन के स्वतंत्रता-संग्राम ने सातवें वर्ष में प्रवेश किया है। हमारी लड़ाई का तो अभी पहिला ही साल खतम हुआ है। अमेरिका और चीन की लड़ाइयों में ऐसे मौके आये थे, जब मालूम पड़ता था कि कोई आशा शेष नहीं रह गई, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग और उनके नेता हिम्मत नहीं हारे। अन्त में अमेरिका की विजय होकर रही और चीन की भी होकर रहेगी। हमारी लड़ाई की वर्तमान स्थिति तो निराशा की घड़ी से कोसों दूर है, फिर भी पस्त-हिम्मतों और बुज-दिलों ने आवाज उठाने की हिम्मत दिखलाना शुरू कर दिया है। ऐसे लोग देश के दुश्मन हैं और इन्हें अपने रास्ते से दूर फेंककर हमें आगे बढ़ते जाना है। हमें इससे भी घुरे दिन देखने पड़ सकते हैं। लेकिन कष्टों और मुसीबतों से हमें घबड़ाकर पीछे नहीं हटना है, हममें तो इससे और दृढ़ता आनी चाहिये। तभी हम जनता के विश्वास के पात्र हो सकेंगे और तभी लोग हमारा साथ दे सकेंगे।

(२)

पिछले कुछ महीनों से, खासकर गांधी जी और बड़े लाट के पत्र-व्यवहार के प्रकाशित होने के बाद, हमारे साथियों में हिंसा और अहिंसा को लेकर एक विवाद उठ खड़ा हुआ है। इस सम्बन्ध में मैं अपने पहले पत्र के जरिए अपने विचार स्पष्ट रूप से आपके सामने रख चुका हूँ और मैं आज भी उन पर कायम हूँ। मैंने उसमें जो कुछ कहा उसे यहाँ दोहराने की कोई जरूरत नहीं, फिर भी इस विवाद के बारे में दो-एक शब्द कह देना चाहता हूँ। मेरे खयाल में इस विषय पर इस समय किसी तरह का विवाद उठाना बेमतलब है। आजादी का हर सैनिक अपना तरीका खुद चुन लेने के लिए स्वतंत्र है। जिनके तरीके एक-से हैं, उन्हें मिलकर पूरे अनुशासन में रहकर काम करना चाहिये।

जयप्रकाश की विचारधारा

और, जो मित्र भिन्न रास्ते पर चलना चाहते हैं उन्हें कम-से-कम इतना तो ख्याल रखना ही चाहिये कि वे एक-दूसरे के लिए बाधक न हों और व्यर्थ के आपसी झगड़ों में अपनी शक्ति बरबाद न करें। “करो या मरो” के मंत्र को लेकर जहाँ आगे बढ़ना है, वहाँ आपसी झगड़ों की कोई गुंजायश ही कहाँ है! जो अहिंसा में विश्वास रखते हैं, उन्हें हिंसावादियों से यह डर हो सकता है कि वे गांधीजी के मर्यादा को धक्का पहुंचावेंगे। लेकिन यह डर निर्मूल है। अहिंसा में गांधी जी की आस्था इतनी पूर्ण है और इस सम्बन्ध में उनकी स्थिति इतनी स्पष्ट है कि लाखों चर्चिल और एमरी उन्हें बदनाम नहीं कर सकते! हमें यह भी याद रखना चाहिये कि हम चाहे जो भी करें, चाहे हम जितनी भी कोशिश क्यों न करें, हम अंग्रेज राजनीतिज्ञों को, चाहे वे टोरी हो या मजदूर दल के, झूठ बोलने से कभी रोक नहीं सकते, क्योंकि झूठ हो उनके साम्राज्य का एक मुख्य स्तंभ है। यह भी याद रहे कि अगर हिन्दुस्तान में हिंसा है भी, तो उसके लिये खुद अंग्रेजी सरकार दोषी है।

गांधी-वायसराय-पत्र-व्यवहार के प्रकाशन के बाद से एक यह भी विवाद उठ खड़ा हुआ है कि आज की मौजूदा लड़ाई कांग्रेस ने छेड़ी है और इसे ‘कांग्रेस की लड़ाई’ कहा जा सकता है या नहीं। कुछ लोग, जो यह कहने की जुर्रत करते हैं कि आल इंडिया कांग्रेस कमिटी के मुट्ठी-भर बचे-खुचे मेम्बर बैठ कर बम्बई प्रस्ताव को रद्द कर दें, वे तो यहाँ तक दावा करते हैं कि चूँकि लड़ाई की घोषणा कर सकने के पहले ही गांधी जी तथा दूसरे कांग्रेस नेता गिरफ्तार कर लिये गये, इसलिये यह लड़ाई कतई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है। इस तर्क का तो यह मतलब हुआ कि यदि अंगरेज नेताओं को ऐन मौके पर गिरफ्तार कर लिया करें, तो कभी कोई लड़ाई वाजाव्ता कांग्रेस की ओर से छेड़ी ही नहीं जा सकती। ऐसी अवस्था में तो कांग्रेस सिर्फ एक मखौल की चीज होकर रह जायेगी। जो मौजूदा लड़ाई को कांग्रेस के नाम और

श्राज्जादी के सैनिकों के नाम

मुहर से वचित रखना चाहते हैं, उनके विचार से अगस्त में नेताओं की गिरफ्तारी की कारगरतापूर्ण कार्रवाई के बाद देश को क्या करना चाहिये था ? उनकी समझ के अनुसार महात्मा गांधी और वर्किंग कमिटी के लोग अपनी गिरफ्तारी की अवस्था में लोगों से क्या उम्मीद रखते थे ? क्या इन रण-छोड़ों को इससे खुशी होती अगर नेताओं की गिरफ्तारी की कोई प्रतिक्रिया न हुई होती और देश ने साम्राज्यवादी लुटेरों के आगे चुपचाप गर्दन झुका ली होती ? क्या वे यह चाहते हैं कि सिर्फ विरोध समाएँ होती जिनमें नेताओं की रिहाई के प्रस्ताव पास होते (जैसा कि अब तक के क्रांतिकारी कहे जानेवाले लोगों का विचार है) और इतने पर भी उन्हें न छोड़ा जाता तो फिर और मीटिंगें होतीं और यह सिलसिला तब तक जारी रहता कि जब तक उन सभाओं में आनेवाले ऊबकर उनमें आना वन्द न कर देते और इतना कर के ये “विरोधवादी” भलेमानस आत्मसतोष के साथ चुप बैठ जाते । यदि ऐसा ही था तो बम्बई अ० भा० का० क० के उस बहादुराना प्रस्ताव का और उसमें देश के महापुरुषों के मुँह से निकले हुए उन बहादुराना शब्दों का क्या तथ्य रह जाता है ? लेकिन यदि यह सही नहीं है और जनता से यह उम्मीद की जाती थी कि वह अंगरेजी हमले के जवाब में उठ खड़ी हो, यदि वास्तव में नेताओं की गिरफ्तारी जन-सर्घर्ष की पूर्व सूचना थी तो फिर मौजूदा लड़ाई को काग्रसी और बेजाब्ता बतलाकर उसकी निन्दा करना कहाँ की ईमानदारी है ? लड़ाई के रास्ते चलने वाले के लिए दुश्मन से यह उम्मीद रखना कि वह शान्तिकाल के विधान के अनुसार सभी जाबते की कार्रवाइयों को पूरी करने के लिए मौका देगा — मूर्खता नहीं तो और क्या है ? इसलिए मेरे ख्याल से यह दिखलाने की कोशिश करना कि हमारी राष्ट्रीय लड़ाई जो १९४२ के ९ अगस्त में छिड़ी, कांग्रेस के जाबते और मुहर से वचित है— नीचता और कारगरता है ।

जयप्रकाश की विचारधारा

हाँ, अलवत्ता यह दूसरी बात है कि मौजूदा लड़ाई के प्रोग्राम को गांधीजी ने या वर्किंग कमिटी ने मजूर किया है या नहीं ? यह बात वस्तु जगत की है, न कि सिद्धान्तों और राजनैतिक आचारों की । और इसकी वास्तविकता के बारे में कोई विवाद नहीं है । जाहिर है कि वर्किंग कमिटी ने कोई कार्यक्रम तैयार न करके सिर्फ लड़ाई का नेतृत्व गांधीजी को सौंपा था । गांधीजी के पास भी कोई कार्यक्रम नहीं था । उन्होंने अपने भाषण में अ० भा० का० क० के सामने उसकी रूपरेखा मात्र रखी थी । उनका यह नक्शा और हरिजन के लेख हो जनता के सामने रह गये थे और इन्हीं के आधार पर उन बचे-खुचे कांग्रेस-कर्मियों ने व्यापक कार्यक्रम तैयार किया, जिन्होंने म्हापट बम्बई में इकट्ठे होकर उस गैर-कानूनी कांग्रेस के संगठन की नींव रखी जो तब से काम कर रही है । वही प्रोग्राम आज भी हमारे राष्ट्रीय युद्ध का आधार है । इसमें न तो हत्या के लिए कही गुजायश है और न किसी के शरीर पर चोट पहुँचाने की । अगर हिन्दुस्तान में हत्याये हुईं—और वेशक हुईं—तो उनमें से ९९ फीसदी ब्रिटिश फैसिस्ट गुंडों के द्वारा और केवल १ फीसदी क्रोधित और क्षुब्ध जनता के द्वारा । हर अहिंसात्मक तरीके से अंग्रेजी राज के लिए ज़िन्दा करना, उसे पगु बना कर उखाड़ फेंकना ही उस प्रोग्राम का मूल मन्त्र है और “अहिंसा के दायरे में सब कुछ कर सकते हो” यही है हमारा ध्रुव तारा । यद्यपि यह सच है कि कुछ लोग अहिंसा के नाम पर इस प्रोग्राम के कुछ अंशों को अब अस्वीकार कर रहे हैं, जिन्हें उन्होंने पहिले खुद मजूर किया था और श्री किशोरी लाल मशहवाला जैसे अहिंसा के आचार्य का दिल भी जिनकी निन्दा करने या जनता को उनपर अमल करने से मना करने को तैयार न हो सका था, तो भी इसमें शक की कोई गुजायश नहीं कि जिस प्रोग्राम पर १९४२ के अगस्त से अब तक कांग्रेस सस्थाओं ने अमल किया है उसका बौद्धिक आधार अहिंसा है—उस अर्थ में अहिंसा जैसा, उसके अधिकारी

आजादी के सैनिकों के नाम

पुरुषों ने इस असें में बताया है। जिन लोगों ने यह प्रोग्राम बनाया वे इसकी जिम्मेवारी से भागना नहीं चाहते और अवसर आने पर वे बेशक कांग्रेस के मंच के सामने खड़े होकर “अत्यंत नाजुक मौके पर अपने कर्तव्य-पालन के लिए” प्रशसापत्र प्राप्त करेंगे।

चाहे और जो हो लेकिन अगस्त प्रोग्राम को गांधीजी के मत्थे मढ़ना एक ऐसा फरेब है जो सिर्फ अंग्रेज शासक ही कर सकते हैं।

३

पिछले दो महीनों से एक ऐसी बीमारी के लक्षण नजर आ रहे हैं जो उपरोक्त विवादों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। हमारी लड़ाई के छिड़ने के समय से ही कुछ हिन्दुस्तानियों का एक गिरोह रहा है जिन्हे बम्बई (अ० भा० का० क०) की कार्रवाई नापसंद रही है और जो अपने पुराने ढंग के अनुसार “जिंच को दूर करने” की कोशिश करते रहे हैं। मेरे खयाल से कांग्रेस-जन को न तो कभी उनमें कोई दिलचस्पी रही है और न आज होने की जरूरत है। हर बार जब हिन्दुस्तान अपनी आजादी के लिए लड़ाई छेड़ता है तब यह गिरोह “जिंच (deadlock) को दूर करने के लिए” निकल पड़ता है। श्री राजाजी, भूला भाई और मशी जिनकी उपयुक्त जगह आजादी के सैनिकों के बीच थी, आज स्वतंत्रता आंदोलन को व्यर्थ करानेवालों की जमात में जा मिले हैं, इस बात से स्थिति में कोई अंतर नहीं आना चाहिये।

लेकिन, जैसे जैसे समय बीतता जाता है और हमारे साथी जेलों से छूट कर बाहर निकलते हैं उनमें से कुछ—यद्यपि इनकी संख्या बहुत थोड़ी है—थकान और कमजोरी दिखाते हैं। आज उन्होंने भी “जिंच को हटाओ” का नारा लगाना शुरू कर दिया है और इसके लिए तरह-तरह के सुझाव भी उन्होंने रखे हैं। जब कि हमारे सेनानायक लड़ाई के अगले मोर्चे पर हैं, तब इन कांग्रेसजनों का पीछे कदम हटाने की नीति का जन्म देना महान्

जयप्रकाश की विचारधारा

विश्वासघात है। अनुशासन की असली जाँच तो लड़ाई के मैदान में ही होती है। जब तक कोई विषय विचाराधीन है तब तक उसकी आलोचना करना या उससे मतभेद जाहिर करना जनतंत्र प्रणाली में जायज है। लेकिन, असल में और खास कर लड़ाई के दौरान में सख्त से सख्त अनुशासन होना जरूरी है। आज हमारे अनुशासन का यही तकाजा है कि कांग्रेसजन लड़ाई के मोर्चे पर डटे रहे और पीछे हटने या आत्मसमर्पण का खयाल भी मन में न लवें। इन विषयों पर विचार करना सेनापतियों का काम है। महात्माजी और मौलाना आजाद जेल में हैं, लेकिन लड़ाई या सुलह को कुंजी आज भी उन्हीं के हाथों में है, जैसा कि किसी लड़ाई के उभय पक्ष के नेताओं के हाथों में सदा से रहती आई है। महात्मा जी चाहे जब भी आत्मसमर्पण करके आसानी से “जिंच को हटा सकते थे।” लेकिन उन्होंने ऐसा करना पसंद नहीं किया। उसका यही मतलब है कि वे चाहते हैं कि हमारी लड़ाई जारी रहे या इसको घुरे से घुरे रूप में लें तो जिंच बनी रहे।

अब हम इस जिंच के मामले पर जरा ज्यादा डूब कर सोचें। यह तो हर किसी को मानना होगा कि जिंच दूर करना ही ध्येय नहीं है। यह बे-मतलब होगा अगर यह हमारे राष्ट्रीय ध्येय को आगे नहीं बढ़ाता, हमें अपने उस लक्ष्य की ओर एक कदम आगे नहीं बढ़ाता जिसे हमने अपने आगे रखा है और जिससे हम डिग नहीं सकते।

इस बात को मद्दे नजर रखते हुए अब हम जरा जिंच को दूर करने के तरीकों पर भी विचार कर लें। इसकी तीन संभावनाएँ हो सकती हैं: (१) या तो हम अंग्रेजी सरकार को अपनी माँगों को मान लेने को मजबूर करें, (२) यदि हम आत्मसमर्पण कर दें, (३) या हिन्दुस्तान और इंग्लैंड में समझौता हो जाय। पहिली संभावना का मतलब है हिन्दुस्तान की पूरी जीत—और वह तो लड़ाई के तरीके से ही हो सकती है। अब जो लोग जीत की उमीद

आजादा के सैनिकों के नाम

से बैठे हैं और मौजूदा जिच्च से ऊब कर असेम्बलियों और कौंसिलों के नाटक में भाग ले सकने को ललक रहे हैं, उनके सामने आत्मसमर्पण का रास्ता है। लेकिन, इससे तो कांग्रेस बिल्कुल मुर्दा हो जायेगी और देश की प्रतिरोध की भावना कम-से-कम एक पुस्त तक बुझ जायेगी। इसका अर्थ होगा कि ब्रिटेन की पूर्ण विजय।

अब हमारे सामने रह जाती है समझौते की सभावना, जिसका ऊपरी आकर्षण बहुत-से ईमानदार लोगों को भी इसके जाल की ओर खींचता है। समझौते में दोनों पक्षों को कुछ लेना और कुछ छोड़ना पड़ता है। ऐसी हालत में कांग्रेस को कम से-कम फायदा यह हो सकता है कि जो राष्ट्रीय लड़ाई के सिलसिले में कैद में है उन्हें छोड़ दिया जाय और कांग्रेस तथा उसकी सहायक संस्थाओं को फिर से कानूनी करार दिया जाय। ब्रिटेन को इससे जो कम-से-कम फायदा हो सकता है वह है उस भयकर बोझ से छुटकारा पा जाना, जो अंग्रेजी राज को हमारी लड़ाई के चलते उठाना पड़ रहा है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि ऐसे समझौते में ब्रिटेन को फायदा ही फायदा है और कांग्रेस का भारी नुकसान। अब हम जरा इस तरह के समझौते के लाजिमी अर्थों पर भी विचार करें। युद्ध के सम्बन्ध में कांग्रेस की क्या स्थिति होगी? गत वर्ष के अगस्त के बाद ऐसी कोई बात नहीं हुई जिससे कांग्रेस युद्ध के बारे में अपनी राय बदले या वह उसमें शरीक हो जब तक कि वह अपने को भारतीय जनता की ओर से उनके हित के लिये लड़ाई चला सकने की स्थिति में न पावे। उल्टे पिछले साल भर में ऐसे भयंकर कांड हुए हैं जिनके चलते कोई खुददार कांग्रेसी किसी हैसियत से किसी रूप में भी उन गुंडों और हत्यारों के साथ सहयोग नहीं कर सकता जो आज हिन्दुस्तान पर शासन कर रहे हैं और जिन्होंने हमारे देश को नरक की भट्टी में जलाया है—जिस नरक को लपटें आज तक भी बुझ नहीं पाती हैं। मैं इसकी कल्पना भी नहीं

जयप्रकाश की विचारधारा

कर सकता कि कांग्रेसजन उन लोगों के सामने अपने हाथ कभी कैसे बढ़ा सकते हैं जिन्होंने हमारे भाइयों और बहिनो के खून से अपने हाथ रंगे, घर ढाहे और जलाये, बलात्कार किये तथा कोमल बालकों पर जेल की काल-कोठरियों के अन्दर भयकर अत्याचार किये हैं। उपरोक्त कारण से और इस कारण से भी कि कांग्रेस बिना पूरे अधिकार प्राप्त किये पद-ग्रहण नहीं कर सकती, मैं तो यह कल्पना भी नहीं कर सकता कि कांग्रेस फिर से १९३५ के विधान को अमल में लाना कबूल करेगी। कांग्रेस ने एकबार इस विधान को तोड़ने का ध्येय लेकर इसको आजमा चुकी है और इस प्रयत्न में खुद ही प्रायः टूटने के करीब पहुँच चुकी है। युद्ध ने इस मनहूस फरेव को अच्छी तरह तोड़-फोड़ दिया है और जैसा कि मौलवी फजलुल हक ने बंगाल असेम्बली में अपने उस महत्वपूर्ण वक्तव्य में बतलाया है, नौकरशाही शासन के भद्दे नंगापन पर पर्दा डालने को प्रांतीय स्वतंत्रता की एक धज्जी भी शेष न रह गई। (सरसरी तौर पर मैं यहाँ यह कह दूँ कि इस योग्यता से प्रांतीय स्वतंत्रता की पोल खोलने के बाद भी मौलवी हक और बंगाल असेम्बली के अन्य राष्ट्रवादी मेम्बर जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो किसी न किसी कांग्रेसी भडे को माननेवाले हैं, अभी भी निरर्थक वैधानिकता के मोह में फँसे हुए हैं। मेरी समझ से उस महान वक्तव्य के बाद उनके सामने एक ही मनुष्योचित और देशभक्तिपूर्ण रास्ता रह गया है और वह है मौजूदा असेम्बली को स्थायी रूप से छोड़ कर गैर-वैधानिक तरीकों से राक्षसी हवर्ट-अमलशाही को उखाड़ फेंकने की कोशिश करना।) अब हम अपने असली विषय पर आ जायें। प्रांतीय स्वराज्य की असलियत जानने के बाद कांग्रेस से यह उमीद करना तो निरा राजनैतिक पागलपन होगा कि वह फिर प्रांतों में अपने मंत्रियों को भेज कर इस (मुर्दा) फरेव को फिर से जिन्दा करेगी। १९३५ का विधान मर चुका, अब हमें इसके पास तक फटकना नहीं है, इस

बात को हम खूब समझ लें। साथ ही हिन्दुस्तान अब उन जालिमों के साथ अमन से नहीं रह सकता जिन्होंने उसके साथ अवर्णनीय दुर्व्यवहार और पाशविक अत्याचार किये हैं, हम इसे भी गाठ बांध लें।

इस तरह के समझौते से कांग्रेस की स्थिति बड़े संकट में पड़ जायेगी। कांग्रेस को “कानूनी स्वतंत्रता” मिल तो जायेगी, लेकिन फिर भी उसे साम्राज्यवादी युद्ध और उन सभी आर्थिक तथा राजनैतिक कार्रवाइयों का विरोध करना होगा जो ब्रिटिश पूंजीवाद के स्वार्थ के लिए युद्ध को चालू करने के लिए करेगी। वह देश के शासन में हाथ बँटाने में या आर्डिनेन्स—यदि उसके लिए उपयुक्त शब्द का प्रयोग करें तो, फैसिलिटाश को थोड़ा से थोड़ा भी जनतन्त्रात्मक रूप दे सकने में एकदम असमर्थ रहेगी। वह जनता के कष्टों को दूर नहीं कर पाएगी, भूखों को अन्न, नंगों को वस्त्र, आश्रयहीनों को आश्रय दे नहीं सकेगी। संक्षेप में यो कहे कि अगर कांग्रेस अपने सिद्धान्तों पर ईमानदारी से कायम रही तो उसे हर कदम पर ब्रिटिश अधिकारियों का विरोध करना होगा और फिर वह अपने को जेल-खाने की सीधी और छोटी सड़क पर पावेगी और इस तरह “जिंच का हल होना” व्यर्थ हो जायगा।

इसके अलावा कांग्रेस को एक और भी भारी घाटा होगा। ज्योंही महात्मा गाँधी, मौ० आजाद, पंडित नेहरू और दूसरे नेता जेल से बाहर आ जायेंगे, त्यो ही दुनिया हिन्दुस्तान को भूल जायेगी। ससार के भाग्य का सूत्र आज जिन लोगों के हाथ में है उनके दिल से जिंचका असर अचानक दूर हो जायगा और चर्चिलो तथा एमरियो को सुख की नींद सोने का मौका मिल जायेगा। और, वे सोचेंगे कि चलो, कम-से-कम कुछ दिनों के लिए तो हिन्दुस्तान का मसला हल हो ही गया और जब तक पगला गाँधी अपनी भेड़ों को फिर जेल की ओर हाँक लाने की बात न सोचे, तब तक के लिए

जयप्रकाश की विचारधारा

तो फुर्सत मिल ही गई। जेल से छूटकर पंडित नेहरू वक्तव्य जारी करेंगे, जिन्हें अमेरिकन सवाददाता बड़े चाव से अपने पत्रों में भेजेंगे, लेकिन वे वक्तव्य सुन्दर और मार्मिक होते हुए भी बेजान होंगे। इस तरह सुन्दर वक्तव्य से बड़े-बड़े देशों के राजदूतों को मुग्व करनेवाले नेहरू की अपेक्षा बन्दी नेहरू रुजवेल्टों और चर्चिलों के लिये कहीं बड़ी समस्या हैं।

कहा जा सकता है कि ऊपर जो चित्र खींचा गया है, समझौते का आधार कांग्रेस के लिये उससे ज्यादा लाभदायक भी हो सकता है। अब जरा देखे कि वह आधार क्या हो सकता है। ब्रिटेन क्रिप्स योजना से आगे नहीं जाना चाहता — जिसका अर्थ है लड़ाई के दौरान में कोई अधिकार मिलने को नहीं तथा लड़ाई के बाद के लिए झूठा वादा। कांग्रेस ने क्रिप्स योजना को ठुकरा कर ठीक ही किया और कोई भी होश वाला आदमी यह उमीद नहीं कर सकता कि वह आज उसे फिर कबूल कर ले। कांग्रेस की कम-से-कम मांगें, जिनसे मैं सहमत नहीं हूँ और मुझे इसमें शक है कि आज वकिंग कमिटी भी उस पर कायम रहेगी, अप्रिल १९४२ में शैतान के वकील (क्रिप्स) के आगे रख दी गई थी। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें नामजूर कर दिया। अगर थोड़ी देर के लिए मान ले कि कांग्रेस उन्हीं मांगों से सतुष्ट हो जायेगी तो जो लोग जिच हटाने के लिए इतने बेचैन हैं वे इन मांगों को ब्रिटिश सरकार से कैसे मनवावेंगे? क्या लड़ाई के सिवाय कोई दूसरा जरिया उनके कामयाब होने का है? अतः हम फिर जिच ही पर आ बैठते हैं।

इस तरह हम देखते हैं कि जिच अनिवार्य है। कांग्रेस की शर्तों को पूरी करवाये वगैर किसी और तरीके से इसका हल करना देश के लिए घातक साबित होगा। लेकिन इसका यह मतलब हर्गिज नहीं है कि हम निश्चित बैठे हैं। हमारी लड़ाई चालू है, हमारा प्रतिरोध जारी है। हम राष्ट्रीय तथा

आजादी के सैनिकों के नाम

अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के हर उलट-फेर से फायदा उठाने के लिए तैयार बैठे हैं। ब्रिटिश शासन के प्रति हमारा विरोध मात्र ही, सिर्फ यही बात कि हिन्दुस्तान के सर्वश्रेष्ठ लोग जेल में बन्द हैं, इस बात की गारंटी है कि भारत पराजित नहीं हो सका है, कि प्रतिरोध की भावना कुचली नहीं जा सकी है; कि हिन्दुस्तान का मसला एक दुनिया का मसला है; कि एशिया और अफ्रिका की गुलाम कौमों को हिन्दुस्तान के संघर्ष से बल और प्रोत्साहन मिलता है; कि ब्रिटेन और मित्रराष्ट्रों के मजदूरों को बराबर यह चेतावनी मिल रही है कि उन्हें किस तरह के जनतंत्र के लिए लड़ना पड़ रहा है; कि युद्ध के बाद एक बेहतर दुनिया की संभावना ज्यादा नजदीक आ रही है और हिन्दुस्तान ससार के उन जनसाधारण का नेतृत्व प्राप्त करता है जिनका युद्ध के दोनों पक्षों के बाहर एक तीसरा पक्ष है और जिन्हें न तो मित्र और न धुरी देशों की विजय से ही मुक्ति या आनन्द की कोई आशा है। अतएव यदि लड़ाई के अन्त तक केवल जिंच ही बना रहा तो मुझे इतने से भी सतोष होगा। कोई यह नहीं कह सकता कि लड़ाई और कितने दिनों तक चलेगी, वह कब क्या रुख अख्तियार करेगी और किन-किन शक्तियों को उभारेगी। लड़ाई जितना ही अधिक दिनों तक चलेगी उतना ही न सिर्फ हिन्दुस्तान में बल्कि दुनिया के हर देश की भीतरी स्थिति बिगड़ती जायेगी। लड़ाई की एक नई करवट, किसी एक नई सामाजिक शक्ति का उभड़ पड़ना ही हिन्दुस्तान में परिस्थिति को इस कदर बदल दे सकती है कि यह जिंच ही आज हमारे लिए एक लम्बी उछाल की आरम्भ-भूमि बन जा सकता है। लेकिन, अगर हम फिर साधारण परिस्थिति की ओर पीछे लौटें तो यह साधारण परिस्थिति ही हमारे पावों में एक जबरदस्त बेड़ी बन जा सकती है। भविष्य की हमारी सफलता के लिए यह जिंच ही सब से बड़ी गारंटी है।

(१६१)

जयप्रकाश की विचारधारा

यह वहस उठ सकती है कि ज़िच को जारी रख कर हम ब्रिटेन के हाथ का खिलौना बन रहे हैं, क्योंकि ब्रिटेन भी चाहता है कि हिन्दुस्तान में राजनीतिक ज़िच बना रहे। लेकिन ऐसा सोचना ब्रिटिश-नीति का गलत अर्थ लगाना होगा क्योंकि ब्रिटेन हिन्दुस्तान में राजनीतिक ज़िच नहीं, बल्कि राजनीतिक 'रोशनी गुल' (Black out) चाहता है। वह कांग्रेस को कुचल कर उसकी आवाज बन्द कर देना चाहता है, जनता की प्रतिरोध की भावना और आजादी की चाह को मिटा देना चाहता है जिससे कांग्रेस की ताकत बढ़ती है, प्रतिरोध की भावना दृढ़ बनी रहती है, आजादी की लड़ाई चलती रहती है; जिससे ब्रिटेन की प्रतिष्ठा तथा प्रभुता जहाँ हर रोज़ मिटती जाती है, वहाँ विद्रोहियों की बढ़ती जाती है, ऐसे ज़िच से ब्रिटेन का उद्देश्य विफल हो जायेगा और इससे खुद उसका अपना हथियार ही उसकी पराजय का साधन बन जायेगा।

राष्ट्रीय सरकार और कांग्रेस-लीग समझौते का भी ऊपर की बातों से गहरा सम्बन्ध है। माना, राष्ट्रीय सरकार जरूर बने। लेकिन इस सिलसिले में सबसे मजेदार बात तो यह है कि जहाँ कांग्रेस ऐसी सरकार के लिए लड़ती और कष्ट झेलती है वहाँ दूसरे लोग सिर्फ़ बातें बनाते हैं। अगर राष्ट्रीय सरकार १९३५ के विधान की मातहत संयुक्त मंत्रिमंडलों से या वायसराय की शानदार कौंसिल से भिन्न कोई और चीज़ है तो वह कान्फ़्रेंसी के जरिये नहीं बन सकती। वर्षों हुए, कांग्रेस ने इस निकम्मे रास्ते को त्याग दिया है और यदि हमारे कम्युनिस्ट दोस्त अपने साम्राज्यवादी आकाओं के पास प्रार्थनापत्र भेजकर ही ऐसी सरकार कायम कर ले सकेंगे, तो उन्हें यह जी-हुजूरी मुबारक हो! लेकिन उन्हें इससे जनता के उपहास तथा अपने मालिकों की हिकारत के सिवाय और कुछ हाथ न लगेगा। राष्ट्रीय सरकार के लिए कांग्रेस-लीग समझौते को अनिवार्य आवश्यकता कह कर उसके लिए प्रचार

करना कोई नई बात नहीं है और मेरे लिए यहाँ इसकी चर्चा करना जरूरी नहीं था। लेकिन कुछ कांग्रेस जनों के निराशावाद ने, जो बैधानिकता के रास्ते पर फिर से लौटना चाहते हैं, एक बार फिर उन्हें इस निष्फल आन्दोलन की तरफ ला घसीटा है। “सीधी चोट” के रास्ते से घबड़ाकर वे इस आसान राह को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि इस आन्दोलन के जनक श्रीराजगोपालाचारी अभी जिन्ना साहब के महल के फाटक पर ही ठोकरे खा रहे हैं और लीगी नेता के नाम महात्मा गाँधी का पत्र अभी तक उन्हें नहीं दिया जा सका (यद्यपि अप्राप्त तथा बेपत्ती हुई चीट्टी का जवाब पढ़ सकने का दुर्लभ सौभाग्य हमें मिल चुका है)। इसी वजह से इस विषय का भी मुस्तसर जिक्र मैंने जरूरी समझा।

बुद्धिमान लोगों को भी अँगरेजों की प्रचार-कला का शिकार होते देख कर उसकी तारीफ करनी पड़ती है। या तो यह सही है, नहीं तो मानना पड़ेगा कि हम राष्ट्रीय पतन के गहरे गर्त में जा गिरे हैं। यदि अँगरेजों का प्रचार भोले अमेरिकनो को चक्रमे में लाता है (यद्यपि मुट्ठी भर ऐसे अमेरिकन भी हैं जो इस चाल को ताड़ जाते हैं), तो बात समझ में आ सकती है, लेकिन जब कोई हिन्दुस्तानी भी इसके घपले में आ सकता है तो हमें इसको दुनिया के महान आश्चर्यों में गिनना होगा। हिन्दुस्तान की ताजी घटनाओं ने अँगरेजों के हर झूठे दावे की धजियाँ उड़ा दी हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के असली रूप और उद्देश्य पर किसी तरह का पर्दा नहीं रह गया। इतने पर भी ऐसे हिन्दुस्तानी हैं जो मानते हैं और देशवासियों से भी मनवाना चाहते हैं कि अगर हिन्दुस्तान की आजादी की राह में कोई बाधा है तो वह है कांग्रेस और लीग के बीच समझौते का न होना।

अगर पिछले कुछ महीनों में अँग्रेजों को नीति से कोई बात साफ झलकती है तो वह है अपने भारतीय साम्राज्य को जकड़ रखने का अँग्रेजों

जयप्रकाश की विचारधारा

का दृढ़ निश्चय । क्रिप्स वार्ता से यह बात साफ झलक गई कि अंग्रेजों ने यह पक्का निश्चय कर लिया है कि वे लड़ाई के दौरान में हिन्दुस्तान को वास्तविक अधिकार नहीं देगे चाहे देश में कितनी भी एकता क्यों न हो जाय । क्रिप्स ने साफ तौर पर एलान कर दिया था कि यदि कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिल कर भी असली राष्ट्रीय सरकार की मांग करें तो वह लड़ाई के दौरान में मजूर नहीं की जा सकती । लेकिन अंग्रेजों के भावी वादों में किसका विश्वास रहा है या है ? ब्रिटिश नीति के इस स्पष्टीकरण के बाद भी कांग्रेस लीग समझौते के आन्दोलन का सिवाय इसके कोई दूसरा फल न होगा कि चर्चिल्लों और एमरियों को उन झुठाइयों को बल और प्रतिष्ठा मिले जो वे अथक रूप से सारी दुनिया में फैलाते रहते हैं । ऐसी परिस्थितियों में कांग्रेस-लीग समझौता का हो हल्ला भी राष्ट्रीय भारत के विरुद्ध साम्राज्यवाद के हमले का एक अंग बन जाता है ।

अब यह पूछ सकते हैं कि यदि कांग्रेस-लीग समझौता हिन्दुस्तान को राष्ट्रीय सरकार देने के लिए ब्रिटेन को न भी मजबूर कर सके तो क्या इससे आजादी की ताकतें और मजबूत नहीं होंगी ? अगर हाँ, तो क्या यह खुद एक ऐसी अभीष्ट चीज नहीं है जिसके लिए कोशिश की जाय ? यदि इसका आधार सही है तो फिर यह निष्कर्ष भी सही माना जायेगा । लेकिन यहाँ तो आधार ही एकदम गलत है । हमारे देश में आजादी की सिर्फ वही ताकतें हैं जो आजादी के लिए लड़ने और कष्ट भेलने को तैयार हैं । मुस्लिम लीग ने अपने सारे जीवन में न तो कभी लड़ाई और मुसीबतों के रास्ते को अपनाया है और न उसे आज भी अपनाने को तैयार है । हिन्दुस्तान बिना लड़े अपनी आजादी हासिल नहीं कर सकता । पर जब मुस्लिम लीग लड़ाई में भाग लेने को तैयार ही नहीं है तो फिर उसके साथ समझौता करने से आजादी की शक्तियाँ मजबूत नहीं हो सकतीं । पंडित नेहरू के वे शब्द खोखले नहीं थे

जब उन्होंने कहा था कि यदि लीग आजादी की लड़ाई में शामिल होने को तैयार हो, तो उसके साथ कभी भी समझौता हो जाना एकदम आसान हो जाय।

यहाँ तक तो कांग्रेस-लीग एकता की बात हुई। अब जरा दो शब्द लीग की असली नीति के बारे में भी कह दूँ। पहिले इसे स्पष्ट समझ लेना चाहिये कि लीग ब्रिटेन को मेली है। जिन्ना साहब जानबूझ कर देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं और वे वर्तमान काल के मीरजाफर हैं। उन्हें यकीन है कि वे जो कुछ भी चाहते हैं वह उन्हें ब्रिटेन से मिल जायगा। लेकिन ब्रिटेन अपने कठपुतलों को अपने साम्राज्य के टुकड़े सौंपने का आदी नहीं है। इसमें कोई सदेह नहीं कि जिन्ना साहब का पूरा इस्तेमाल कर चुकने के बाद वह उन्हें टूटे फूटे औजारों के कूड़ेखाने में फेंक देगा जैसा कि वह पहिले भी औरों को फेंक चुका है, जिनमें मीरजाफर भी शामिल है। मुसलमानों को याद रखना चाहिये कि आज बंगाल का शासन मीरजाफर की औलाद के हाथ नहीं बल्कि क्लाइव के नीच भाई बंदों के हाथ में है। जिन्ना साहब अपने को अलबत्ता बहुत होशियार समझते हैं, लेकिन उनकी सारी मगरूरियत और हिटलरी अदाओं के बावजूद इतिहास इसका साक्ष्य देगा कि उन्हें एक ऐतिहासिक बेवकूफ बनाया गया।

जिन्ना साहब अपना पाकिस्तान चाहते हैं। लेकिन अगर वे इस मामले में सजीदा हैं, तो उन्हें इसके लिये मरना होगा, बलिदान करना होगा, शायद मरना भी पड़े। लेकिन यहीं आकर तो गाढ़ी अटक जाती है। यही तो जिन्ना साहब और उनके अनुयायी कभी करने को तैयार नहीं। इसीलिये तो जिन्ना साहब पाकिस्तान की अपनी माँग की चीख महात्मा गांधी को सुनाते हैं। लेकिन जिन्ना साहब का पाक बतन तो विचारे गांधी के पास है नहीं। वह तो साम्राज्यवाद के खून में डूबे हुये पाँवों के तले पड़ा हुआ है जो उसे कुचल

जयप्रकाश की विचारधारा

रहे हैं तथा भ्रष्ट और नापाक कर रहे हैं। यदि जिन्ना साहब अंग्रेजों से अपने 'वतन' ले सके तो इसमें कांग्रेस को कोई एतराज नहीं होना चाहिये—इससे कम-से-कम हिन्दुस्तान का एक हिस्सा तो आजाद हो जायेगा। लेकिन, वे उसे नहीं ले सकेंगे क्योंकि वे इसकी कीमत चुकाने को तैयार नहीं। इसलिये वे कांग्रेस को धमका कर बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अन्त में चर्चिल जिन्ना को धमका कर रहेगा। यदि 'पार्लमेन्टों की जननी' के तत्वावधान में कभी हिन्दुस्तान का वेंटवारा हुआ, तो साम्राज्यवाद का स्वार्थ इस बात में होगा कि वह हिन्दुस्तान के तथाकथित मुस्लिम राष्ट्र को अलग आजादी न दे। अलस्टर से आयरिश लोगो को कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन वह आयरलैंड के सीने में चुभाई हुई ब्रिटेन की छुरी है।

लीग की असली नीति साम्राज्यवाद की चालवाजियों और कौमो गद्दारी का एक कुलूप फरजन्द है।

(५)

आप को तो शायद यह मालूम ही होगा कि श्री सुभाषचन्द्र बोस ने शोनान (सिंगापुर) में एक अस्थायी भारतीय सरकार की स्थापना की है जिसे जापानी सरकार ने मान लिया है। उन्होंने एक भारतीय राष्ट्रीय सेना का भी संगठन किया है जो तेजी से विस्तार कर रही है। ये घटनाएँ हमारे लिये कुछ महत्व रखती हैं। यहाँ पर आपको यह भी सूचित कर दूँ कि सुभाष सरकार ने जो पहिला काम किया है वह है हमारे लिये इतना चावल भेज देने का जिम्मा लेना जितना कि बंगाल के भूखों मरते हुये लोगों को खिलाने के लिये जरूरी हो; लेकिन अंग्रेजी सरकार को तो यही कबूल है कि देशी खटमल-पिस्तू मल मर जायें।

किसलिंग करार टे कर सुभास को गाली देना आसान है। जो खुद ही ब्रिटेन के किसलिंग हैं वे बड़े इतमीनान के साथ आज उन्हें गालियाँ दे रहे

आजादी के सैनिकों के नाम

हैं। लेकिन राष्ट्रीय भारत तो उन्हें एक उत्कट देशभक्त तथा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जानना है जो देश की आजादी की लड़ाई के मैदान में सदा आगे रहा है। हम तो यह सोच भी नहीं सकते कि वह कभी अपने देश को बेच डालने के लिये तैयार हो सकता है। यह सच है कि जो भी धन या सामान उनके पास है वह सब उन्हें धुरी राष्ट्रों से मिला है। लेकिन, वे लोग जो उनकी सरकार या राष्ट्रीय सेना में हैं, सभी ऐसे भारतीय हैं जिन्हें अंग्रेजी राज से नफरत है और जिनमें अपनी मातृभूमि को आजाद करने की इच्छा जल रही है। इसके अलावे हमें यह भी खयाल रहे कि उन सभी भगोड़ी यूरोपियन सरकारों का सारासाजों सामान जो आज मित्र-राष्ट्रों की छात्रछाया में चल रही हैं, उन्हें इन्हीं राष्ट्रों से मिला है। फिर कोई यह भी तो नहीं कह सकता कि आज की इस भूमडल-व्यापी लड़ाई का कौन-सा दांव जाने किस शक्तिशाली राष्ट्र को अपनी गरज के चलते एक छोटे और अशक्त देश के आगे दबने को न मजबूर करे। जापानियों द्वारा बर्मा की आजादी की घोषणा का काफी प्रचार है और यहाँ तक खबर है कि इससे सोवियत सरकार को इतनी दिलचस्पी हुई है कि उसने तो सरकार को उसकी इस उदारता के लिये बधाई तक दे डाली है। बात चाहे जो हो, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं मालूम पड़ता कि बर्मा वालों को आज एक फैसिस्ट सरकार की छात्रछाया में उससे कहीं अधिक आजादी प्राप्त है जो उन्हें “ब्रिटिश जनतंत्र” के अधीन थी। अब हम श्री सुभाष बोस की बात को लें। जाहिर है कि उन्होंने, राजनीति के उस पुराने सिद्धान्त के अनुसार जो मैशिवेली तथा कौटिल्य से भी पुराना है, अपने देश के दुश्मनों के दुश्मनों से मदद लेना गवारा किया है। इस तरह एक तीसरे पक्ष से मदद लेकर वे अन्त में ठगे भी जा सकते हैं, लेकिन इस बात से उनको नेकनीयत तथा बुद्धिमानी में कोई फर्क नहीं आता। अपने देश की आजादी हासिल करने में वे कितनी मदद पहुँचा सकेंगे, यह

जयप्रकाश की विचारधारा

तो ऐसी घटनाओं पर निर्भर है जिन पर उनका या किसी भी देश के किसी राजनीतिज्ञ का अधिक वश नहीं।

शोनान की भारत सरकार और राष्ट्रीय सेना के महत्त्व को स्वीकार करते हुए भी मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि हमारी आजादी का सबसे ज्यादा दारोमदार है हमारा अपनी ताकत और तैयारियों पर। बाहरी मदद की उम्मीद में निठल्ले बन कर बैठ जाना तो खुदकुशी की नीति होगी। कोई भी बाहरी मदद अकेले हमें आजाद नहीं करा सकती। यह सोचना भारी मूर्खता होगी कि सुभाष की फौज, चाहे वह कितनी ही बड़ी क्यों न हो, हिन्दुस्तान-स्थित मित्र-राष्ट्रों की फौजों को हरा सकेगी। यदि कोई फौज उन्हें परास्त कर सकती है तो जापान की। लेकिन यदि जापानी हिन्दुस्तान में अंग्रेजों को हरा भी देते हैं, तो वे चुपचाप हिन्दुस्तान हमारे हाथों सौंप नहीं देंगे—चाहे तोजो और सुभाष में इस विषय पर कैसा भी समझौता क्यों न हो चुका हो। हमें इसके लिये तैयार रहना है कि हिन्दुस्तान में मित्रों और धुरी के सघर्ष छिड़ने पर हम खुद अधिकार छीन लें। यदि हम ऐसा प्रयत्न करने को तैयार रहेंगे तभी सुभाष की फौज जैसी मदद से हम फायदा उठा सकते हैं। यह कह सकना कठिन है कि सुभाष हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय दाँव-पेंच के इस पहलू से किस हद तक वाकिफ हैं।

अब हम इस सवाल पर आ जाते हैं कि अंगर लड़ाई हमारे घर में आ पहुँची तो हम क्या करें? अंग्रेजों की नीति ने औसत हिन्दुस्तानियों को आज इतना ब्रिटिश-विरोधी बना रखा है कि यदि वे जापान का स्वागत करने को तैयार नहीं, तो कम-से-कम ब्रिटिश-जापान सघर्ष से तटस्थ तो जहर रहना चाहते हैं। यही तटस्थता हमारी मौत बुला सकती है। हमें इसे दूर करके अनिश्चित क्रियाशीलता की नीति अपनाने की जी-तोड़ कोशिश करनी है। जिन

हल्कों में लड़ाई होती है या जापानियों का कब्जा हो जाता है या जापानी घुस पड़ते हैं वहाँ विदेशियों का सिविल शासन या तो एकदम निर्बल पड़ जायेगा या एकदम टूट हो जायेगा। इन इलाकों में हमें स्वराज्य सरकार कायम कर लेना होगा। इसी सरकार के नाम पर पोछे हटती हुई हिन्दुस्तानी फौज को एक कर जनता की फौज में परिणत हो जाने की अपील करनी होगी। उसी दिन से हमें हिन्दुस्तान के पूर्वी सूबा में एक ऐसी सरकार बनाने के लिये तैयारी करना होगी जो समय आने पर सारे देश पर अधिकार कर लेगी। इस तैयारी के काम के सिलसिले में बहुत-से ऐसे सवाल उठ खड़े होते हैं जिन पर हम यहाँ विचार नहीं कर सकते। इतना ही काफी होगा कि हम साधारण नीति की ओर इशारा कर दें और अपने सैनिकों तथा सारे देश का ध्यान इसकी ओर खींचें।

(६)

इस पत्र को समाप्त करने के पहिले युद्ध के बारे में भी कुछ कह दें। देश को जीवन-भरा की ठाढ़ में लड़ाई के रूप को लेकर आज भी मजेदार चर्चा छिड़ी हुई है। दुश्मन से मित्र हुए देशद्रोही स्वभावतः अभी भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि यह जनता की लड़ाई है। ऐसे लोग जिनके लिये राजनीति का अर्थ और इति सिर्फ विवाद में है इस विषय को लेकर भयकर जोश में आकर शाब्दिक विवाद करते-करते कभी-कभी मारपीट तक कर बैठते हैं। लेकिन भारत की जनता को ब्रिटेन की लड़ाई के रूप के बारे में या उसका समर्थन करनेवाले अपने देश के भाइयों के बारे में कोई शक नहीं है। अब उन्हें बताने की कोई जरूरत नहीं रह गई कि फैसिज्म क्या चीज है या यह कि यह लड़ाई उनकी अपनी ही है। पिछले साल ब्रिटिश फैसिज्म ने अपनी भयकर क्रूरताओं के जरिये उनके आगे अपनी कलाई खोल दी है जो जेलों में सड़ रहे हैं, जिनके प्रियजन उस देश-व्यापी भयकर

(१६६)

जयप्रकाश की विचारधारा

हत्याकांड के चलते उनसे सदा के लिये बिछड़ गए जिसके जरिये अंग्रेजों ने फिर से अपना “अमल और कानून” कायम किया, जिनके घर लूटे और जला दिये गये, जिनकी स्त्रियों की इज्जत लूटी गई, जो आज सड़कों और गलियों में चूहों की तरह बिलबिला कर भूखों मर रहे हैं—कोई जरा इनसे पूछे कि यह किस तरह की “जनता की लड़ाई” है। एक अंग्रेज जेनरल ने वावर के बश के शाहजादों के सिर उतार कर उन्हें एक तश्तरी में सजा कर उन अभाग शाहजादों के बाप अन्तिम मुगल बादशाह के पास रानी विक्टोरिया की ओर से उपहार के रूप में भेजा था। इस घटना के एक सौ पचास साल बाद टोटेनहम ने अमेरिकन पत्र सबाददाताओं के सामने (गांधी जी के उपवास के मौके पर) शेखी बधारते हुए कहा कि उसने गांधी की लाश को जलाने भर को काफी चन्दन की लकड़ी मंगा रखी है। इन सभी कारनामों को और ब्रिटिश शासन के शुरू से अन्त तक (इसका अन्त निकट ही है) के सारे काले कारनामों को भारत अच्छी तरह जानता है और उसे मार्क्सवाद की नकली वेश में फिरनेवाले देशद्रोहियों के मुँह से वह नहीं सुनना है कि फैसिस्टवाद क्या चीज़ है ?

लड़ाई का पाँचवा साल शुरू हुआ। लोगों की जान और सुख की जो भयंकर बर्बादी इसमें हुई है उसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती। उभय पक्षों के साधारण जनो के हितों का यह तकाजा है कि वह जल्द से जल्द खतम हो जाय। लेकिन चर्चिल-रूजवेल्ट और हिटलर-तो जो इसको खतम नहीं कर सकते। यदि वे आज इस नृशस हत्या को बन्द भी करा दें, तो सिर्फ इसलिये कि जिसमें वे भविष्य में और अधिक भयंकर नृशसता के लिये और अधिक घातक हथियार बना सकें। लड़ाई के बाद की दुनिया के लिये मित्र-राष्ट्रों की जो योजना है और जिसकी एक मामूली झलक साधारण जनो को मिल चुकी है, उसमें उन्हीं विशेष स्वत्वों की, एक वर्ग तथा राष्ट्र का दूसरे वर्ग

या राष्ट्र पर अत्याचार की पूजावादी प्रतियोगिता तथा अराजकता की उसी पुरानी दुनिया का जिक्र है जिसने एक ही पीढ़ी में दो महासहारी युद्धों को जन्म दिया और निश्चय ही एक तीसरे को भी पैदा करेगी ।

इन परिस्थितियों में भारत ही सारी दुनिया के अधिकार-च्युत तथा लुटित कौमो की आकाक्षाओं एवं अभिलाषाओं का क्रियात्मक प्रतिनिधित्व कर रहा है । हिन्दुस्तान की आजादी को लड़ाई साम्राज्य विरोधी (और फ़ैसिस्ट विरोधी भी, चूँकि साम्राज्यवाद ही फ़ैसिस्टवाद को भी जन्म देता है) साथ ही साधारण जनो द्वारा हस्तक्षेप के जरिए लड़ाई का अन्त करने का एक प्रयास भी है । हमारा ध्येय न तो मित्रों की विजय है और न धुरी की और न इनमें से किसी एक पर हमारी उम्मीद ही टँगी हुई है । हम दुनिया के जन-साधारण के हाथों साम्राज्यवाद तथा फ़ैसिस्टवाद दोनों ही की पराजय के लिये कोशिश करते हुए अपनी लड़ाई के जरिए लड़ाइयों का अन्त करने तथा काले-गोरे और पीले लोगों की मुक्ति का रास्ता दिखलाते हैं ।

(७)

मैंने आपका बहुत समय ले लिया और अब इसे खतम करूँगा मैंने ऊपर यह दिखलाने की कोशिश की है कि हमारे लिए लाभ का सिर्फ एक ही रास्ता है और वह है लड़ाई को जारी रखना । लेकिन हम लड़ें किस तरह ?

मैं यह बतला चुका हूँ—मौजूदा स्थिति ऐसी है जिसमें मुख्यतः तुले हुए सैनिक अपना जौहर दिखला सकते हैं ।

इन सैनिकों का पहला काम है अपने सगठन को बनाये रख कर उसे मजबूत और व्यापक बनाना । सगठन के बिना कोई भी फौज—चाहे वह अहिंसात्मक ही क्यों न हो—नहीं लड़ सकती । जन-संघर्ष प्रायः एक खुद से उभरनेवाली चीज है और वह सामाजिक शक्तियों के परिणाम के रूप

(१७१) -

जयप्रकाश की विचारधारा

में होता है ; लेकिन उसकी आकृति को ठीक करने और निर्णयात्मक बनाने के लिए चुने हुए क्रांतिकारियों का एक सगठन अत्यंत आवश्यक है । जन सघर्ष का अपने-आप उभरना भी ऐसे चुने हुए क्रांतिकारियों का जनता में सगठित काम का एक सम्मिलित फल है । हमारी लड़ाई के हाल के इतिहास में उसके नेताओं ने सगठन के मसलों के बारे में बहुत बेपरवाही दिखलाई है । नेता अपनी गिरफ्तारी की हालत में सदा से सब—कुछ जनता की मर्जी पर छोड़ते आये हैं । बेशक सगठन के मामले में इस बेपरवाही को जड़ में अहिंसा और गोपनीयता का परस्पर विरोध रहा है । अहिंसा छिप-छिपाकर काम करने की इजाजत नहीं देती । फिर भी लड़ाई की हालत में सगठन को गुप्त रखना ही होगा । मेरा यह दावा नहीं है कि मैंने इस धर्म-सकट का हल निकाल लिया है । मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि जब तक अहिंसा के विशेषज्ञ इसका कोई हल नहीं खोज पाते, तब तक अहिंसा के कट्टर से कट्टर अनुयायियों को भी कार्य संचालन के खयाल से अपने सिद्धान्त से कुछ झुककर भी गुप्त सगठन कबूल करना होगा । महात्मा गाँधी तक को भी ऐसा समझौता करना पड़ता है । सिर्फ गोपनीयता की निन्दा करके और खुलमखुला काम करने की नीति की प्रशंसा करके हम न तो अपनी कठिनाई को हल कर सकते हैं और न अपने उद्देश्य को ही आगे बढ़ाते हैं ।

अतः सगठन ही हमारी लड़ाई के प्रोग्राम का पहला अंश है । यह किसी भी सघर्ष का भूल आधार है । इस सिलसिले में मैं मौजूदा गैर-कानूनी कांग्रेस सस्थाओं को जिंदा और सुव्यवस्थित रखने पर बहुत जोर देता हूँ । ये ही सस्थाएँ हमारी लड़ाई को एक सूत्र में बाँध रखने की एकमात्र साधन हैं । यह सही है कि उनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है ; लेकिन सिर्फ उन्हीं के जरिए आज कांग्रेस अपने काम चला सकती है जनता तक पहुँच सकती तथा दुश्मन से लोहा ले सकती है । कुछ सूत्रों में ये सगठन ठीक से नहीं

आजादी के सैनिकों के नाम

काम कर रहे हैं। संगठन की इस कमजोरी का कारण कार्य-कर्त्ताओं की कमी नहीं है। अधिकांश जगहों में इसके कारण हैं धन का अभाव तथा योग्य संगठन करनेवालों की कमी। लेकिन इनमें से कोई भी असाध्य नहीं है। अखिल भारतीय कांग्रेस का केन्द्रीय डिरेक्टरेट प्रान्तों की कम-से-कम ज़रूरतों को पूरी करने की कोशिश करता रहा है और इस दिशा में वह एकदम नाकामयाब भी नहीं रहा है। अभी इसका मौका नहीं है कि हम इस पर विचार करें कि हिन्दुस्तान के धनियों का वर्तमान क्रान्ति में क्या भाग रहा है। यहाँ इतना ही कह देना काफी होगा कि उनमें समझ और दूरदर्शी का बिल्कुल अभाव रहा है। यदि उनकी नजर थोड़ी दूर भी पहुँच पाती तो वे इस बात को आसानो से समझ सकते कि यदि राष्ट्रीय आन्दोलन कुचल दिया गया तो फिर लड़ाई के बाद की समस्याओं से हैरान और परीशान ब्रिटिश पूँजीशाही उन्हें दम तक नहीं लेने देगी। अतः ओर कुछ नहीं ता सिर्फ अपने ही स्वार्थ के लिहाज से उन्हें दिल खोलकर राष्ट्रीय क्रान्ति में अपना धन लगाना चाहिये। लेकिन उन लोगों ने अपने को न सिर्फ घोर स्वार्थी बल्कि अत्यन्त हीन भी साबित किया है।

चाहे जो हो, लेकिन धन के अभाव की पूर्ति तो होनी ही चाहिए और जो इसमें मदद कर सकते हैं उन्हें करनी ही चाहिये। कुछ प्रान्तों में, जैसे यू० पी० में, कुछ भूतपूर्व कांग्रेसी मिनिस्टर जेल के बाहर हैं। वे लोग तथा जेल से छुटे हुए अन्य प्रमुख कांग्रेसी यदि और कुछ नहीं, तो कम से-कम सिर्फ अपने प्रान्तों की आर्थिक आवश्यकताओं की ही पूर्ति करा दें। जहाँ तक केन्द्रीय संगठन का सम्बन्ध है, उसका सबसे प्रमुख काम होना चाहिये प्रान्तों को धन की मदद देना। यदि उनके अमल में लाने के ज़रिए नहीं, तो सिर्फ प्रोग्राम और आदेश-पत्र भेजना बेकार-सा होगा।

ऐसे योग्य संगठनकर्त्ता और नेताओं के अभाव का संवाल, जो लोगों के

जयप्रकाश की विचारधारा

सामने नये कार्यक्रम बनावें और दूसरो से काम ले सके, जरा ज्यादा टेढ़ा सवाल है। फिर भी, इसमे आशिक सुधार तो इस तरह हो सकता है कि जो थोड़े-से लोग बचे रहे हैं, वे घूम-घूमकर दूसरे कार्य-कर्त्ताओं से मिलें, उनके साथ अपने व्यावहारिक मसलों पर विचार करें और उन्हें सलाह और शिक्षा दें जो संभव हों। सौभाग्य से जहाँ योग्य कार्यकर्त्ताओं की संख्या ज़रूरत से ज्यादा हो उनमें से कुछ को ऐसी जगहों में भेज दिया जाय, जहाँ या तो कोई भी नहीं या बहुत कम हो। नये कार्यकर्त्ताओं की, विशेषकर विद्यार्थियों से, भर्ती की जाय और जो जेल से छूटकर बाहर आ रहे हैं उनको खींच कर फिर मैदान में लाना चाहिये।

यदि पैसा, नये रगस्ट और उनकी शिक्षा का प्रबन्ध हो जाय तथा प्राप्त बुद्धि और अनुभव का अच्छा उपयोग किया जाय, तो हमारे संगठन के मसले हल हो सकते हैं।

दमन के सामने अपने संगठन को बनाये रखना हमारी लड़ाई का एक अंग है—लेकिन सिर्फ एक अंग मात्र। हमारे संगठन की हर टुकड़ी (यूनिट) का जनता से सम्पर्क रहना चाहिये। हमारे सैनिकों और जनता का सम्बन्ध किसी भी हालत में टूटने देना नहीं चाहिये। सम्पर्क की एक शब्द में व्याख्या करें तो उसे कहेंगे प्रचार—जवानी और लिखित प्रचार अर्थात् पंच पैम्फलेट, पोस्टर, रेडियो ब्रॉडकास्ट और देहातों में घूमते रहनेवाले सैनिकों की गतिशील टोलियाँ जो लोगों से मिलें और बातें करें। प्रचार-साहित्य का लिखना और छपवा कर तैयार करना जितना अहम है उतना ही उसका लोगो से बँट जाना भी, अतः हर काम पर बराबर ध्यान देना चाहिये। प्रचार के क्षेत्रों का भी पूरा अध्ययन कर लेना चाहिये। विद्यार्थी, मजदूर, दूकानदार, किसान—जैसे जनता के वर्गों के अलावे हमें अपनी आवाज सरकारी नौकरों तक, विशेषतः पुलिस और फौज के छोटे ओहदों वालों तक भी पहुँचानी

श्राजादी के सैनिकों के नाम

चाहिये । विदेशों में प्रचार करना भी हमारे काम का एक अंग होना चाहिये ।

प्रचार सिर्फ प्रचार ही नहीं, बल्कि हमारी लड़ाई का एक रूप भी है क्योंकि रेडियो चलाना, गैरकानूनी पर्चे निकालना, जहाँ मीटिंग करने की मनाही हो, वहाँ मीटिंग करना ऐसी बातें कहना जो गैरकानूनी हैं, ये सभी चीज लुटेरी सरकार के प्रति विद्रोह और उसके खिलाफ लड़ाई का एक अंग हैं ।

हम और अधिक क्या कर सकते हैं ? मेरा तो यह विश्वास है और मैं इसे खुलेआम कहने को तैयार हूँ कि जब तक अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति में परिवर्तन नहीं होता—जैसे रूस और जर्मनी में सधि, चीन और जापान में सधि, अंग्रेजी सेना की गहरी हार या हिन्दुस्तान की सरजमीन पर धमासान—तब तक हम कोई बड़ी चीज नहीं कर सकते । मैं चाहता हूँ कि हमारे सैनिक धोखे में न रहें । जो तात्कालिक फल की उम्मीद न होते हुए भी लड़ते रह सकते हैं वही विजयी हो सकते हैं । जो लोग इससे भिन्न हैं वे मैदान छोड़कर भाग खड़े होंगे और बड़ी-बड़ी बातें बनाकर राजनीतिज्ञ बनने का ढोंग रचाएँगे । लेकिन, इतिहास उन्हें ऐसे भगोड़ विश्वासहीन और कायर की उपाधि देगा जो कठों से उठकर अपना कर्तव्य छोड़ बैठे । हमारे बहुत-से साथी यह सोचकर निराश हो रहे हैं कि आज हम चाहे सत्याग्रह और हड़ताल के रूप में या तोड़-फोड़ के रूप में जिस पैमाने पर प्रतिरोध चला सकते हैं वह कारगर नहीं है । यह इस मानी में सही भी है कि यह इतना जबरदस्त नहीं है कि अंग्रेजी शासन का चलना रोक दे सके । लेकिन यह एक दूसरे अत्यन्त आवश्यक अर्थ में कारगर भी हो रहा है और वह यह कि यह एक जबरदस्त प्रोपगैन्डा है, इसमें जनता का साहस दृढ़ बना रहता है, यह आगे की बड़ी लड़ाई की उम्मीद को जिन्दा रखता है, इससे हमारे सैनिकों को

जयप्रकाश की विचारधारा

ट्रेनिंग मिलती है, इसके जरिये हमारी लड़ाई का बाहरी स्वरूप बना रहता है और दुश्मन को यह सोचकर परेशानी होती है कि उसका सारा दमन-कार्य व्यर्थ साबित हुआ। यह इस मानी में कारगर है कि यह हमारा आखिरी कारगर प्रतिरोध की एक तैयारी है। अतः हमें अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध प्रत्येक रूप में अपने-अपने विद्वास और प्रोग्राम के अनुसार अपना संघर्ष जारी रखना है।

वर्तमान के लिये हमारा कम-से कम प्रोग्राम यह होगा : सगठन, प्रचार और जाहिरा प्रतिरोध। इसके अलावे हमारे सामने तैयारी करने का समूचा विशाल क्षेत्र है। विद्यार्थियों और मजदूरों में हमारा काम चलते रहना चाहिए, फौज तथा सरकारी नौकरों के साथ हमारा सम्पर्क बना रहकर और बढ़ता जाय, तोड़-फोड़ के लिए हमारी तैयारी जारी रहे। हमारा लक्ष्य होना चाहिये ९ अगस्त की तरह का लेकिन उससे भी बड़ा और ज्यादा सगठित तथा संचालित संघर्ष। खाद्य-समस्या के बारे में भी एक शब्द कह देना चाहता हूँ। इसकी गंभीरता के बारे में कुछ कहना फिजूल होगा। वह तो सभी तरह जानते और समझते ही हैं। लेकिन, इस संबंध में लोग यह ठीक से नहीं समझ रहे हैं कि इसका वास्तविक समधान है स्वायत्त-सरकार। अंग्रेजों ने कुछ तो अपनी अयोग्यता के कारण और कुछ जान-बूझ कर इस समस्या को पैदा किया है और जब तक वे यहाँ बने हुए हैं तब तक दुर्भिक्ष अनिवार्य है। इस तरह आजादी की लड़ाई का मतलब हो जाता है रोटी की असली लड़ाई। लेकिन इतना ही कहना काफी न होगा। हमें आजादी की लड़ाई के ही एक अंग के रूप में रोटी की लड़ाई भी चलानी है। वर्तमान में तो खाद्य-संकट से जनता में एकमात्र प्रतिक्रिया हुई है दान देने की। वर्ग-समाज में दान की भी एक अपनी जगह है और हालांकि मैं एक साम्यवादी होने के नाते इसे समर्थन नहीं करता हूँ, फिर भी भूखों मरनेवालों को मौत

आजादी के सैनिकों के नाम

सैन्य बचाने का प्रयास करनेवालों की मानवता की भावना को खुशी से स्वीकार करता हूँ। यह सार्वजनिक प्रयास सराहनीय है। लेकिन, दान और भीख प्रयास नहीं हैं। इससे समस्या का हल नहीं होता। अतः हमारे सैनिकों का यह महान् कर्तव्य हो जाता है कि कंगलों और भुखमरों के दिल में क्षोभ और क्रोध की भावनाएँ जगावें और इन भावनाओं को उस विदेशी सत्ता के विरुद्ध उभारें जो उनकी इस दुर्दशा की जड़ में हैं। छुधार्त जनता ऐसी स्थिति पैदा कर दे जिसमें रोजमर्रे के ब्रिटिश शासन का चलना एकदम असंभव हो जाय। जहाँ-कहीं भी पा सके वहाँ से अन्न छीन लेने के लिए हम उन्हें सिर्फ यह कर ही न सतोष कर ले, बल्कि इसमें उनकी मदद भी करें। देहातों से हम गल्ला बाहर न जाने दें और ग्राम पंचायतों तथा इस तरह की दूसरी संस्थाओं के जरिये गल्ले का वितरण करावें, पर इसका खयाल रखना चाहिये कि इसमें हम सरकार या सरकार-परस्त संस्थाओं से दूर ही रहे। हमारे जो सैनिक गुरिल्ला-संगठनों में हैं उन्हें चाहिये कि वे सरकारी गुदामों और इसी तरह की दूसरी जगहों से गल्ला लूटकर उसे हाजतमन्दों में बाँट दें। सरकार द्वारा फसल या गल्ले का जबरदस्ती ले लेने का प्रतिरोध होना जरूरी है। शहरों में रहनेवाले भुखमरों और दरिद्रों की निष्क्रियता को भी हमें क्षोभ और क्रोध में बदल कर उसे प्रदर्शन तथा सीधी चोट का प्रगट और क्रियात्मक रूप देना चाहिये। सैनिक अक्सर मुक्तसे प्रोग्राम के बारे में पूछ बैठते हैं। उनके लिये यह तो एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे विदेशी और हिम्मत के साथ यदि चलाया जा सके तो सारा देश एक खौलती हुई कड़ाह बन जाय जिसमें पड़कर ब्रिटिश साम्राज्य जलकर स्वाहा हो जायेगा।

संगठन के सिलसिले में बात करते हुए मैंने सिर्फ कांग्रेस ही का नाम लिया है। जो लोग कांग्रेस की सैद्धान्तिक सीमा से परे जाना चाहते हैं, उन्हें तो अपनी विशेष तरह की कार्यवाइयों को चलाने के लिये स्वभावतः एक

प्रजयकाश की विचारधारा

अलग संगठन की जरूरत होगी। मैंने इस काम के लिये एक गुरिल्ला-संगठन की सलाह दी है और गुरिल्ला आंदोलन के विकास में कुछ प्रगति तो हो भी चुकी है। इस विषय में यहाँ कुछ विशेष कहना उचित नहीं होगा। इतना ही काफी होगा कि इस संबंध में मेरे विचार आसानी से उचित लोगों तक पहुँच सकते हैं और जिन्हें इस तरह के कामों से दिलचस्पी है उन्हें इसके संगठन के सम्पर्क में आने में विशेष कठिनाई नहीं होगी।

साथियों, अब मैं इस पत्र को यहीं समाप्त करता हूँ। मैंने मौजूदा स्थिति का ठठे दिल से विश्लेषण किया है और बिना शब्द जाल या तड़क-भड़क का सहारा लिये आपके सामने अपने विचार रख रहा हूँ। अब इसमें जो बातें आपके स्वीकार के लायक हों, उन्हें खुशी से चुन लें। मैं सदा आपकी खिदमत में हाजिर रहूँगा। “करो या मरो” मेरा और आपका भी ध्रुवतारा है। अतः हम करें या मरें।

हिन्दुस्तान के किसी कोने से

१ली अक्टूबर १९४३

आपका साथी

जयप्रकाश नारायण

आजादी के सैनिकों के नाम

तीसरा पत्र

साथियो,

जेल से छूटते ही जब मैंने “जनता” के जरिये आपको मुबारकवाद भेजा, तभी मैंने वादा किया था कि शीघ्र ही मैं वर्तमान परिस्थिति पर अपनी राय आपके सामने रखूँगा और हमारा आज क्या कर्तव्य है उस पर प्रकाश डालूँगा। मुझे दुःख है कि अपने वादे को पूरा करने में मुझे इतना विलम्ब हुआ। विलम्ब अनिवार्य ही था, क्योंकि यह जरूरी था कि मैं अपने सहयोगियों से मिलता और उनसे सलाह-मशविरा करता। सलाह-मशविरा के बाद अब मुझे मौका मिला है कि मैं निश्चित रूप से आपके सामने कुछ बातें रखूँ।

इसके पहले भी, मैंने और मेरे सहयोगियों ने वक्तव्यों के जरिए, जिन्हें अलग-अलग या हम सबने मिलकर साथ प्रकाशित किए हैं, आपके ख्यालात को आपके सामने रखने की कोशिश की है। गत अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी की गत बैठक में हमारी क्या नीति रही, उसे आप जानते ही हैं। नीचे मैंने अपने विचारों को—और मुझे यकीन है अपने साथियों के विचारों को भी—सिलसिलेवार और पूर्ण रूप से रखने की कोशिश की है। इसमें

जयप्रकाश की विचारधारा

मैंने यह भी बताने की कोशिश की है कि हमारे सामने क्या प्रश्न हैं, और उन्हें हल करने के लिए हमें किन-किन तरीकों पर अमल करना है।

वर्तमान स्थिति अस्थायी है, और शीघ्र बदलती रहती है। ए० आइ० सी० सी० ने यह निश्चय किया है कि कांग्रेस जनों को ब्रिटिश तत्वावधान में बुलाई गई विधान परिषद् में सम्मिलित होना चाहिए। एक मध्यकालीन सरकार ब्रिटिश वायसराय के मातहत शीघ्र ही बननेवाली है। यह सरकार जब भी बने, तबतक स्वतंत्र राष्ट्र की स्वतंत्र सरकार नहीं हो सकती, जब तक वायसराय, ब्रिटिश सेना और ब्रिटिश अफसर हिन्दुस्तान से चले नहीं जाते। इसकी प्रार्थना करना कि इस सरकार को स्वतंत्ररूप से चलने दिया जाय, परिस्थिति से आँखें मूढ़ लेना है। जिसके पास यह शक्ति है कि स्वेच्छा से जब चाहे हुक्मत दे दें, उसके पास यह भी शक्ति है कि स्वेच्छा से हुक्मत को जब चाहे वापिस भी ले ले। इसलिए हम इस बात के धोखे में न रहें कि (मध्यकालीन) अस्थायी सरकार “यथार्थ” में स्वतंत्र हिन्दुस्तान की सरकार होगी।

तब क्या तथाकथित विधान-परिषद् द्वारा हम स्वतंत्रता हासिल कर सकेंगे? दूसरे शब्दों में क्या वह विधान-परिषद् हिन्दुस्तान को एक स्वतंत्र प्रजातंत्र घोषित कर सकेगी और फिर उस घोषणा को कार्यान्वित कर सकेगी? मसलन, क्या वह एक ऐसी अस्थायी सरकार कायम कर सकेगी जिसके जिम्मे वायसराय देश की सारी हुक्मत सौंपकर हिन्दुस्तान से चले जायें? क्या यह अस्थायी सरकार ब्रिटिश सेना और ब्रिटिश अफसरों को यहाँ से विदा कर सकेगी? क्या वह सरकार ब्रिटिश पूँजी की दम धोतनेवाली रस्ती को, जो देश के गले पड़ी हुई है, तोड़कर फेंक सकेगी? क्या यह विधान-परिषद्, अंग्रेजों के चले जाने के बाद, स्वतंत्र अस्थायी सरकार को बालिग-मताधिकार के आधार पर चुने हुए प्रतिनिधियों की सच्ची विधान-परिषद् को

आजादी के सैनिकों के नाम

बुलाने का अधिकार देकर खुद अपने को भंग कर सकेगी ? क्या प्रस्तावित विधान-परिषद् इन सब कामों को कर सकेगी, जिनका सम्भव होना देश की पूर्ण स्वतंत्रता और प्रजातन्त्रवाद के लिए आवश्यक है ? यह सोचना बड़ी मूर्खता होगी कि वर्तमान परिस्थिति में और शक्तियों के मौजूदा संतुलन के रहते हुए यह विधान-परिषद् उपर्युक्त सभी कामों को करने के लिए कदम बढ़ा सकेगी और इनमें से किसी भी उद्देश्य की पूर्ति कर सकेगी । और यदि हम यह मान भी लें कि विधान-परिषद् इसके लिए प्रयत्नशील हो भी, तो निश्चित है कि ब्रिटिश सरकार उसके रास्ते में खड़ी हो जायगी । उस हालत में यदि परिषद् में ईमानदारी और सच्चाई है, तो उसे ब्रिटिश सरकार की चुनौती को मान लेना पड़ेगा और अपने मकसद पर पहुँचने के लिए देश की आम जनता की शक्ति का आह्वान करना पड़ेगा । ऐसी दशा में वायसराय जो परिषद् की बैठक खुद बुलाते अब उसे भंग करने का हुक्म जारी करेंगे । तब देश की आजादी की लड़ाई पूरी ताकत में शुरू हो जायगी, जिसके गर्भ से प्रजा की सच्ची विधान-परिषद् और एक स्वतंत्र, अविच्छिन्न भारतीय प्रजातन्त्र निकलेगा ।

लेकिन, प्रस्तावित विधान-परिषद् का इस रास्ते पर चलना सम्भव नहीं । राष्ट्रपति जवाहरलाल नेहरू जिसे परिस्थिति का दबाव कहते हैं, उसे ध्यान में रखते हुए यानी, अपनी पूर्ण स्वतंत्रता पर जो अवरोध है उसे ध्यान में रखते हुए अपनी कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए, इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि ब्रिटिश सरकार के पृष्ठपोषक और स्वतंत्रता तथा प्रजातन्त्रवाद के दुश्मन अपने बीच भरे पड़े हैं, ब्रिटिश वायसराय और ब्रिटिश सेना की मौजूदगी को भी ध्यान में रखते हुए—इन सब बातों को और इनके अलावा और भी जितनी बातें हैं उन सबों को मद्देनजर रखते हुए विधान-परिषद् उसी रास्ते को अपनाएगी जिसे मेरा विश्वास है, यथार्थवाद का मार्ग, कहा

जयप्रकाश की विचारधारा

जायगा। दूसरे शब्दों में परिषद् एक के बाद दूसरा समझौता करती जायगी और अन्त में ऐसी चीज कायम करेगी जिसे न स्वतंत्रता कहा जा सकता, न प्रजातंत्र और न राष्ट्रीय एकता। इस तरह देश को परीशान होकर और धोखे से निकल कर फिर उसी मार्ग पर आना पड़ेगा जिससे उसे आज विचलित किया जा रहा है—वह मार्ग क्रान्ति का मार्ग है, लड़ाई और मुकाबले का रास्ता है, स्वतंत्रता का सीधा परन्तु कठिन मार्ग है।

यों हम देखते हैं कि दोनों ही अवस्थाओं में, विधान-परिषद् “सफल” होती हो तो या मोर्चा लेकर “विफल” होती हो, स्वतंत्रता का सग्राम अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति जिसे देश के शक्ति-सन्तुलन का सही ज्ञान है, हमारे इस निष्कर्ष से सहमत होगा। आज, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लिए अभी भी संभव है कि हमारे मुकाबिले में “परिस्थिति के दबाव” को रखे। जब तक यह दबाव/क्रान्ति के जरिए हटाया नहीं जाता, तब तक स्वतंत्रता मृगमरीचिका ही रहेगी। न इसकी हमें उम्मीद करनी है कि मौजूदा परिस्थिति को वहस, समझौते और कूटनीति के कौशल से कोई भी बदल सकेगा।

अस्तु, हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं—इसे मैं दुहराना चाहता हूँ—कि ब्रिटिश के वैधानिक प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने पर स्वतंत्रता की लड़ाई का अन्ते नहीं हो जाता।

यह लड़ाई चलती रहेगी। वस्तुतः इस जंग का नक्शा और दायरा ज्यादा गहरा और विस्तृत होगा। आजादी की लड़ाई के साथ राष्ट्रीय एकता तथा रोटी की लड़ाई का भी गठबन्धन हो जायगा।

ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने पर ऐसी ताकतें अपना सर उठाएंगी जो राष्ट्रीय एकता के लिए घातक होगी। यह एक आम ख्याल है कि ब्रिटिश सरकार ने जो एक चीज हिन्दुस्तान को दी है वह है देश को

आजादी के सैनिकों के नाम

एकता के सूत्र में बाध देना। इसलिए अब यह आम शिकायत हो गई है कि वे अपनी इस उज्ज्वल कृति को स्वयं नष्ट करने पर उतारु हैं। इस धारणा से बढ़कर भ्रममूलक कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती। एकता की स्थापना करना तो दूर रहा, अंग्रेज हमेशा हमारे बीच फूट पैदा करने की भरपूर कोशिश करते आये हैं। उन्होंने हिन्दू-मुसलमानों को एक दूसरे से और हरिजनो को दूसरे हिन्दुओं से अलग करने में कुछ उठा नहीं रखा है। सिक्खों को एक अल्पमत जमात बनाने का, देशी रियासतों को देश के और भागों से अलग करने का और देशी नरेशों को प्रजा के खिलाफ उभाड़ने का उनका प्रयत्न रहा है। जमींदारों को ब्रिटिश हुकूमत का एक स्तम्भ बनाने की, और पूजा-वादी और मध्य वर्गों को रिशवत देकर मुल्क के दुश्मन बनाने की उनकी कोशिशें रही हैं। यानी, एक शताब्दी के शासन काल में उन्होंने सारी कोशिशें इस बात के लिए कीं कि ब्रिटिश हुकूमत ज्यों ज्यों कमजोर पड़ती जाय देश में अशान्ति और फूट फैले। जो एकता ब्रिटिश हुकूमत से स्थापित हुई है वह तानाशाही हुकूमत की एकता है, न कि जनता या राष्ट्र की एकता है। इस ढंग की सच्ची एकता तो कांग्रेस ने कायम की है, और आज यही एकता खतरे में है। इसलिए, राष्ट्रीय एकता की लड़ाई ब्रिटिश प्रस्तावों को मान लेने के बाद एक खास अहमियत अस्तित्वार कर लेती है।

दूसरी बात यह है कि होनेवाले वैधानिक परिवर्तन आर्थिक और वर्ग-सम्बन्धी प्रश्नों को निश्चय ही सामने लाकर रख देंगे। स्वराज की शक्ति के प्रश्न या इस तरह के प्रश्न कि स्वराज्य किसके लिए होगा? दूर के कितानी प्रश्न न रहकर तात्कालिक और जल्दी प्रश्न हो जायेंगे, जिनका अविलम्ब उत्तर देना आवश्यक हो जायगा। और ये सवाल हमारी राजनीति के ऊपर सैद्धान्तिक दृष्टि से नहीं, बल्कि व्यावहारिक दृष्टि से प्रभाव डालेंगे। यानी,

जयप्रकाश की विचारधारा

आर्थिक लड़ाई, जो हमेशा ही स्वतंत्रता की लड़ाई का एक अभिन्न अंग रही है, अब अधिक से अधिक महत्व हासिल करेगी ।

मैं इसे साफ कर देना चाहता हूँ कि ये तीनों प्रकार की लड़ाइयाँ, जिनका उल्लेख मैंने ऊपर किया है, पृथक् लड़ाइयाँ नहीं हैं, बल्कि जनता की एक ही आम लड़ाई के विभिन्न हिस्से या पहलू हैं । विभिन्न अवसरों पर इनमें से कोई एक-दूसरे से ज्यादा अहमियत हासिल कर लेता है, लेकिन वर्तमान वैधानिक योजना का ज्यो-ज्यों विकास होता जाएगा, ये तीनों समान महत्व रखने लगेंगे ।

वर्तमान वस्तुस्थिति में जनता की यह आम लड़ाई विधान-परिषद की पृष्ठ भूमि में लड़ी जायगी । यह सम्भव है कि मध्यकालीन सरकार फिर बाद में यूनियन सरकार या प्रान्तीय (Group) सरकारों के नक्शे में लड़ी जाय ।

ऐसा जान पड़ता है कि कांग्रेस, जिसके हम अंग हैं इन सब प्रगतियों से सम्बन्धित होगी । इसलिये यह निश्चित जान पड़ता है कि यदि कांग्रेस लड़े भी तो उसकी यह स्वाधीनता, एकता और रोटी की सम्मिलित लड़ाई अब राजकीय (State) और वैधानिक तरीकों से ही लड़ी जाएगी । अभी ही कांग्रेस एक वैधानिक पार्टी में परिणत की जा रही है । यदि यह रवैया अन्त तक रहा तो निश्चित जानिये कि कांग्रेस अपनी उस लड़ाई में कुछ ज्यादा कामयाबी नहीं हासिल कर सकेगी । वैधानिक या शासन के साधनों को खास मौकों पर काम में लाया जा सकता है, लेकिन जिस परिस्थिति में हम आज हैं उसमें जनता की लड़ाई मुख्यतः व्यवस्थापिका सभा या सरकारी महकमों के दरवाजे के बाहर ही लड़नी होगी ।

इस लड़ाई को जारी रखना हमारा—आजादी के सभी सिपाहियों का—काम है ।

(२)

किस तरह हम इस लड़ाई को चलायेंगे ? क्या आतंकवाद के जरिए ? या छिटफुट हिंसा के द्वारा ? आपस को खूनखराबी से ? डकैतियों के जरिए ? हरगिज नहीं । इस वक्त केवल एक ही तरीके से यह लड़ाई लड़ी जा सकती है, और वह है जनशक्ति का सृजन । जनशक्ति के निर्माण में पहली बात तो यह है कि जनता में लड़ाई के लिए मनोवैज्ञानिक तैयारी करना, दूसरी, जनता की संस्थाओं को संगठित करना, जैसे किसान सभा-मजदूर सघ, स्वयंसेवक दल, विद्यार्थी और युवक सघ, ग्राम पंचायत, जुलाहों की कोअपरेटिव (Co-operative) संस्था और इस तरह की अनेकों संस्थाएँ जिनसे जनता की सामूहिक शक्ति बढ़े और जिनके द्वारा जनता को अपनी शक्ति का परिचय हो । इन सब कामों के अतिरिक्त सबसे बड़ा काम यह है कि कांग्रेस को मजबूत और जानदार संस्था बनाया जाय और जनता को इसके प्रभावशाली सम्पर्क में लाया जाय और इस सम्पर्क को ज्यादा-से-ज्यादा बढ़ाया जाय । लड़ाई की मौजूदा हालत को ध्यान में रखते हुए मैंने जनशक्ति के निर्माण का पूर्ण चित्र नीचे हमारे कार्यक्रम (प्रोग्राम) के सिलसिले में दिया है ।

राष्ट्रीय एकता के प्रसंग में “जनशक्ति” का क्या अर्थ है उसे मैं आपके सामने रखूँ । राष्ट्रीय एकता ऊपर से जबरदस्ती लादी नहीं जा सकती । यह तो बुनियादी एकता—एकता जो नीचे से बनती आई हो—पर निर्भर करती है । इस तरह की एकता तब कायम होगी, या कम-से-कम इस एकता को कायम करने के प्रयत्न में काफी सफलता तब प्राप्त होगी, जब मुसलमानों के बीच राजनैतिक काम मिहिन्त और सभ्र के साथ किया जाय, जब आर्थिक या वर्ग सम्बन्धी-संस्थाओं को, जैसे किसान सभा, मजदूर सघ, जुलाहों का कोअपरेटिव बढ़ाया जाय, जब कि हिन्दुओं में सामाजिक सुधार सांस्कृतिक

(१८५)

जयप्रकाश की विचारधारा-

और मनोरजनात्मक कार्वाइयों द्वारा किया जाय, जब कि समाज की उन शक्तियों को सबल बनाया जाय जो स्वभावतः राष्ट्रीय एकता की सृष्टि करती हैं, जैसे देश के लिए मजबूत सीमा की आवश्यकता, या समग्र देश की आर्थिक आयोजना की आवश्यकता, या एक राष्ट्रभाषा की आवश्यकता, या और इस तरह की अन्यान्य आवश्यकताएँ। मुझे इसे बताने की जरूरत नहीं कि आजादी के सिपाहियों के लिए सबसे जरूरी यह है कि वे साम्प्रदायिक या जातीय भावनाओं या अहंकार से पूर्ण रूप से मुक्त रहें, और अपने व्यक्तिगत जीवन में मनुष्यमात्र की समानता के सिद्धान्त का अमल करें।

इस समय राष्ट्रीय एकता के लिए जिस जनशक्ति की जरूरत है उसका सर्वथा अभाव है। इस शक्ति का विकास हमारे कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण है।

कही गलतफहमी न हो इसलिए मैं यह बताना चाहता हूँ कि जनशक्ति के निर्माण-कार्य को भिन्न-भिन्न विभागों में नहीं बाँटा जा सकता, यानी, एक खास मकसद के लिए जिस जनशक्ति की आवश्यकता पड़ती है उसे दूसरे मकसदों से अलग नहीं किया जा सकता। राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक शक्तियाँ एक-दूसरे के साथ अभिन्न रूप से घुल-मिल गई हैं और उन्होंने एक होकर जनता के विशाल आन्दोलन का रूप धारण किया है।

(३)

हमारा आजका क्या कार्यक्रम है उसे बताने के पूर्व मुझे आजादी के सिपाहियों के संगठन के सम्बन्ध में अपनी और, मुझे यह बताने हुए खुशी है, अपने ज्यादातर साथियों की भी राय आपके सामने रखनी है। अगस्त क्रान्ति के जमाने में हमलोगों ने कांग्रेस के नाम पर काम किया। ऐसा करना ठीक ही था क्योंकि उस समय पूरे कांग्रेस की नीति लड़ने की नीति

(१८६)

थी। जो कांग्रेस-जन उस लड़ाई में नहीं आए थे जिन्होंने उसकी मुखालिफ्त की उन्होंने समूचे कांग्रेस का विरोध किया और उसके साथ विश्वासघात किया। आज की अवस्था भिन्न है। कांग्रेस की नीति आज लड़ने की या लड़ाई की तैयारी करने की नहीं है, बल्कि वह समझौते और वैधानिकता को नीति है। इसलिए हम लोगों के लिए, जो अब भी लड़ाई और क्रान्ति को नीति को अपनाए हुए हैं यह संभव नहीं कि कांग्रेस के नाम पर काम करें। लेकिन, साथ ही मेरे दिमाग में यह बात भी बिल्कुल साफ है कि हमें कांग्रेस को छोड़कर इसके मुकाबले में दूसरी जन-संस्था नहीं खड़ी करनी है। ऐसा करने से देश की स्वतंत्रता के हित में भारी धक्का पहुँचेगा। इसमें सन्देह नहीं कि धीरे-धीरे हमारे काम करने के तरीकों में और वर्तमान कांग्रेस के नेतृत्व के तरीकों के बीच अन्तर क्रमशः बढ़ता ही जायगा। लेकिन संस्था और नेतृत्व एक ही चीज नहीं। मौजूदा कांग्रेस को बनाने में हमारे प्रयत्नों का और हमारे वलिदानों का उतना ही हाथ है जितना इसके अन्दर रहनेवाली और किसी दूसरी जमातों का है। हमें इसके नाम पर बोलने का उतना ही अधिकार है जितना किसी और को। कांग्रेस देश की सबसे जबर-दस्त और सगठित राष्ट्रीय और सामाजिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, और जन-साधारण के दिमाग पर अभूतपूर्व और अपरिमित प्रभाव डाले हुई है। इस तरह यह जनता की लड़ाई का एक अनुपम साधन है। जब तक इसकी क्रान्ति के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए जाने की संभावना रहती है तब तक इसको छोड़ देना मूर्खता होगी। मेरा विश्वास है कि इसकी संभावना अभी मौजूद है। इसलिए मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि हमें कांग्रेस के अन्दर रहकर काम करना है, इसे ज्यादा-से-ज्यादा मजबूत बनाना है, और अपने कार्यों और सेवाओं के जरिए यह कोशिश करनी है कि वह हमारे विचारों को अपना ले। यदि वर्तमान नेतृत्व कांग्रेस को केवल

जयप्रकाश की विचारधारा

एक वैधानिक दल (Parliamentary) में परिणत करने की कोशिश में लगा रहे, जिसका कोई रचनात्मक कार्यक्रम न हो और जो बिल्कुल सरकारी साधनों के जरिए जनता की सेवा या उसके ऊपर हुकूमत करती रहे, जो शनैः-शनैः नौकरशाही में बदलती जाय और जो इनाम और ओहदों के वितरण के जरिए कांग्रेस संस्था पर अपना कब्जा बनाए रखे, तो हमें निसन्देह उसके विरोध में आ जाना पड़ेगा। लेकिन, साथ ही साथ यदि हम अपना काम जनता में जोश और श्रद्धा से करते जाय, तो वेशक कांग्रेस को सर्वसाधारण जनता को हम अपने साथ ले सकेंगे और कांग्रेस को इसके वैधानिक खडहर से उद्धार कर सकेंगे।

हम इस तरह दो अहम नतीजों पर पहुँचते हैं (१) इस वक्त यह सम्भव नहीं कि हम अगस्त आन्दोलन के जमाने में जिस तरह कांग्रेस के नाम कर काम करते थे वैसा अब कर सकें। (२) हमें कांग्रेस के अन्दर रहकर ही काम करते जाना है। सवाल उठता है कि हमें क्या करना है जिससे हम संगठित रूप से काम कर सकें, और आजादी के तमाम सैनिकों को एक राजनैतिक और सैद्धान्तिक केन्द्र उपलब्ध हो। इस सवाल की अहमियत इस बात से और ज्यादा बढ़ जाती है कि हमारा कार्य केवल इसके अन्दर ही सीमित नहीं है। हमें मजदूर-सघ, किसान-सभा और इस तरह को अनेको सस्थाओं में, जो कांग्रेस के अन्दर नहीं हैं, काम करना है। यदि हमें केवल कांग्रेस के अन्दर ही काम करना होता तो सम्भव है कि हम एक ढीली-सीली जमात के रूप में रहते, लेकिन यदि हमें अपनी मौजूदा जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाना है तो एक संगठित केन्द्र का, जिसका हवाला मैं ऊपर दे चुका हूँ, हमें निर्माण करना है।

मैंने इस प्रश्न पर काफी गौर किया है, और इसके मुतलिक अपने

आजादी के सैनिकों के नाम

साथियों से सलाह-मशविरा भी किया है, और मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि जिस तरह के सगठन की आज हमें जरूरत है उसके लिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पहले से ही बनी बनाई एक बुनियाद है। मुझे विश्वास है कि उचित तब्दीलियों तथा पुनर्संगठन के बाद का० सो० पार्टी हमारे काम लायक एक अच्छी चीज हो जायगी। का० सो० पार्टी के राजनैतिक कृत्यों का एक खासा अच्छा इतिहास है, और विरोधी आलोचक भी यह मानते हैं कि अगस्त-आन्दोलन में इस पार्टी ने जो भाग लिया वह प्रशंसनीय है। पुरानी पार्टी में कुछ सगठन की कमजोरियाँ जरूर थी, जिनमें कुछ कमजोरियाँ तो समाजवादी और वामपक्षी एकता के निस्वत पार्टी के प्रयोगों का परिणाम थी। इन कमजोरियों को हमें दूर करना है, और वे निश्चय ही दूर की जायेंगी। अगस्त के सिपाहियों से जो मेरा इधर सम्पर्क हुआ है उससे मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि यद्यपि कुछ ऐसे लोग भी उनमें हैं जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रति अपनी पुरानी विरोध भावना को छोड़ नहीं सके हैं, परन्तु उनमें बहुत अधिक सख्या में लोग का० सो० पार्टी की तरफ आशा से देखते हैं और उसके प्रति सद्भाव रखते हैं। इसलिए, जैसा कि मैंने ऊपर कहा है, मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि का० सो० पार्टी को आजादी के सभी सिपाहियों को जमात बन जानी चाहिए।

मेरे इस नतीजे पर पहुँचने का एक और भी कारण है जिसका जिक्र मुझे कर देना चाहिए। का० सो० पार्टी का ध्येय राष्ट्रीय आजादी के साथ समाजवाद की स्थापना करना भी है। मेरा विश्वास है कि आजादी के सिपाहियों में प्रतिशत पंचानवे सिपाही समाजवाद की तरफ काफी उन्मुख हैं। देश की स्वतंत्रता के साथ यदि समाजवाद भी न हो तो उन्हें सन्तोष नहीं मिल सकता। इसलिए का० सो० पार्टी का कायम रहना उनके लिए और भी अभ्यष्ट है।

वामपक्ष की एकता

संगठन के सवाल के साथ वामपक्ष की एकता का सवाल जुटा हुआ है। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस सम्बन्ध में बहुत भ्रम फैला हुआ है। वामपक्षी एकता का सवाल संसार के पेचीदा सवालों में एक है। मेरा ख्याल है कि जिस रूप में यह सवाल उठाया जाता है, उस रूप में इसका हल हो ही नहीं सकता। यदि वामपक्ष की एकता का मानी यह है कि तमाम वामपक्षी दलों और गिरोहों में एकता हो जाय तो यह असंभव है। जो लोग ऐसी एकता की बात करते हैं उन्हें पहले यह सवाल अपने से ही पूछ लेना चाहिए कि आखिर वामपक्ष में एकता की कमी आई ही क्यों। दूसरे शब्दों में, यह प्रश्न पूछना चाहिए कि विभिन्न वामपक्षी दल बने ही क्यों? मैं समझता हूँ कि इस बात पर यदि ठीक से गौर किया जाय तो पता चरेगा कि प्रारंभ में जिन कारणों से विभिन्न तथा संकीर्ण विचार उत्पन्न हुए उन्हीं के चलते बाद को एकता स्थापित नहीं हो पाती।

दुनियाँ के वामपक्षी आन्दोलन के तजुबों से यही मालूम पड़ता है कि वामपक्षी दल कुछ खास मौकों और कुछ समय को छोड़कर न तो आपस में एकता कायम कर सके हैं और न साथ काम ही कर सके हैं। इस ऐतिहासिक प्रमाण से हमलोगों को निश्चय ही सबक मिलता है।

अपने देश में भी हमारा अनुभव कुछ भिन्न नहीं हुआ है। दो अवसरों पर हमने वामपक्ष में एकता लाने की सख्त कोशिशें कीं। इन प्रयत्नों से उद्देश्य पूर्ति तो नहीं ही हुई, उल्टे मनोमालिन्य पैदा हुआ जिससे आज भी काम करने में रुकावट पहुँचती है। हमारा पुराना अनुभव बताता है कि हमारी पार्टी ने तो ईमानदारी से अपने दरवाजे को वामपक्षी तथा समाजवादी दलों के लिए खुला रखा और इनकी तरफ मित्रता के हाथ बढ़ाए, लेकिन

इन लोगो ने पार्टी की इस नीति को अपना प्रभाव बढ़ाने, अपने मेम्बर बनाने और सेल (cell) बनाने “भीतर से खोखला करने” तथा और दूसरे ढंग की चाल चलने—वे सभी बातें जो ससार भर में वामपक्षी की एकता के नाम में की गई हैं—का एक अवसर इसलिए जहाँ तक मेरा अपना ताल्लुक है मुझे वामपक्षी की तथाकथित एकता में विश्वास नहीं और मैं इस सम्बन्ध में और दूसरा प्रयोग नहीं करना चाहता । मैं समझता हूँ कि कहीं अच्छा तरीका यह होगा कि सभी वामपक्षी लोग अपनी अलग-अलग जमातों के लिए जो उत्साह रखते हैं उसे तथा सिद्धान्तों की कट्टरता को भूल जायें और मिलकर एक बड़ी प्रशस्त जमात में आयें और वामपक्षी तथा समाजवादी की पार्टी कायम करें । कां० सो० पार्टी आज इसी तरह की पार्टी है । इसमें कुछ दोष निकालना सम्भव है लेकिन छिद्रान्वेषण से कहीं अच्छा है आपस में मिलकर काम करना, अपने सैद्धान्तिक कोणों को कम करना और अपने को ऐसे प्रशस्त नक्शे में डालना जिसमें सैद्धान्तिक मतभेद एक उद्देश्य एक साधन और एक आदर्श के नक्शे के नीचे दब जायें । यदि हिन्दुस्तान में वामपक्षी तथा समाजवादी आन्दोलन को आगे बढ़ना है तो यह विभिन्न जमातों के अनिश्चित तथा अस्थिर मेल से नहीं हो सकता । ये जमातें तो मेल हो जाने के बाद भी अपने पृथक् अस्तित्व को सही बताना आवश्यक समझती हैं और एक साथ काम करते रहने पर भी नए मेम्बरो की भर्ती तथा एक पक्षीय प्रचार (प्रोपेगैण्डा) द्वारा अपनी अलग जमातों को मजबूत बनाने के लिए कार्यशील रहती हैं । वामपक्षी तथा समाजवादी आन्दोलन की उन्नति एक बड़ी पार्टी को सृष्टि से हो सकती है । कां० सो० पार्टी के अलावा मैं ऐसी कोई दूसरी पार्टी नहीं देखता जो यह काम कर सके । इसलिए मैं सभी सिपाहियों से अपील करता हूँ कि वे कां० सो० पार्टी को अपनी पार्टी बना लें । बहुत दूर तक बहुतों ने इसे अपना लिया है । मैं

दूसरो से भी ऐसा ही करने का अनुरोध करता हूँ । स्थानीय दिक्रतें, व्यक्तिगत तथा पुरानी विरोध भावनाएँ कुछ साथियों के सहयोग प्रदान करने में रुकावट डाल सकती हैं, लेकिन हम हर सिपाही को विश्वास दिलाते हैं कि हम यथा शक्ति इन दिक्रतों को दूर करेंगे और यह सम्भव कर सकेंगे कि ये साथी एक मजबूत संस्था बनाने में सहयोग प्रदान कर सकेंगे ।

(४)

हमारा मौजूदा कार्यक्रम:

मैं इस जगह किसी विस्तृत राजनैतिक कार्यक्रम को नहीं रखना चाहता । बाद को, शायद पार्टी की नीति के बयान में, इसको बताने का अवसर होगा । यहाँ केवल मैं उस काम का, जिसे हमें तुरत शुरू कर देना है, ख्वाका देना चाहता हूँ ।

यदि भविष्य में होनेवाली लड़ाई की तस्वीर हमारे सामने होती तो शायद हम अपने मौजूदा कार्यक्रम को ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते । मेरे सामने जो तस्वीर है वह तो यह है पहले, साम्राज्यवाद को बुशल तरीकों से बिलकुल उखाड़-पुखाड़ देना; दूसरे इसके साथ साथ शहर और गांवों में आजाद सरकार की यूनिटे कायम करना और उनकी रक्षा का प्रबन्ध करना । इन स्थानीय आजाद सरकारों को मिलाकर अन्त में सारे हिन्दुस्तान का स्वतंत्र प्रजातंत्र कायम होगा । इस नक्शे में ब्रिटिश सरकार से हर तरह का असहयोग तो निहित ही है । इसमें कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल को ब्रिटिश सरकार के साथ शासन प्रणाली के भीतर से मोर्चा लेना पड़ेगा । इसके साथ-साथ हिन्दुस्तान भर में आम मजदूर हड़ताल भी करनी पड़ेगी । किसान जमींदारों की जमीन पर अपना हक कायम करेंगे । देशो रियासतों की प्रजा-देशा नरेशों के विरुद्ध आन्दोलन शुरू करेंगी । यह लड़ाई पहले की सभी

आजादी के सैनिकों के नाम

लड़ाइयों से—१९४२ की लड़ाई से भी—भिन्न इस बात में होगी कि इसके दम्याँन, मेरी समझ में, स्थानीय सरकारों का प्रादुर्भाव होगा जो बाद की और जिम्मेदारियों को भी निभायँगी। इस तस्वीर को भरा जा सकता है, लेकिन, मेरी समझ में, उसका खाका ऊपर दिया जा चुका है।

इस तस्वीर को सामने रखकर मैं संक्षेप में अपने मौजूदा कार्यक्रम का स्वरूप आपके सम्मुख रखता हूँ।

जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं, हमारा फौरी मकसद आजादी के जग की तैयारी करना है। इस तैयारी के सिलसिले में बहुत किस्म के काम करने की जरूरत पड़ेगी। इनमें कुछ ऐसे भी काम हैं जिनका उल्लेख यहाँ किया नहीं जा सकता।

कार्यक्रम का उल्लेख करने के पूर्व मैं कार्यकर्त्ताओं के विषय में दो-एक बातें कह लेना चाहता हूँ। यदि मुझसे कोई पूछे कि इस वक्त हमारा सबसे मुख्य काम क्या है, तो मैं कहूँगा—कार्यकर्त्ताओं का चुनाव और उनकी शिक्षा। हमारी लड़ाई का जितना विकास हो चुका है उसमें अब केवल आन्दोलन (agitation) का जमाना खत्म हो गया। अब हम सचमुच क्रान्ति के दम्याँन हैं, जिसमें हमारा सबसे मुख्य काम शासन-सत्ता को हस्तगत करना है। आज हमें बिल्कुल दूसरे प्रकार के कांग्रेसजन, दूसरे प्रकार के पार्टी-मेम्बर चाहिए। गत महायुद्ध के पहले के ढग के कांग्रेसजन या पार्टी-मेम्बर से अब काम नहीं चलने का। आज के क्रान्तिकारी को केवल वायुमंडल के निर्माण में नहीं लगे रहना है, बल्कि उसे संगठन सम्बन्धी कार्य करना है। उसे रचनात्मक तथा और भी दूसरे प्रकार के कामों से परिचित होना है। उसे क्रान्तिकारी संस्था और जनता के बीच सबन्ध स्थापित करने का एक सबल माध्यम बनना होगा। यानी, उसे सिर्फ जनता में क्रान्ति की भावना को ही नहीं भर देना होगा, बल्कि उन्हें इस बात का भी ज्ञान करा देना होगा कि

जयप्रकाश की विचारधारा

क्रान्ति में उनका क्या स्थान और कर्तव्य होगा। उसे ईमानदार, निर्भीक, मिहनती, तथा अनुशासन में चलनेवाला सिपाही बनना होगा। प्रत्येक कार्यकर्त्ता हर काम को नहीं कर सकता, इसलिए आम तालीम के अलावा, चुने हुए कार्यकर्त्ताओं को उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार खास काम मिलना चाहिए, जैसे मजदूर संघ का काम, गाँव सम्बन्धी काम, प्रेस और प्रकाशन सम्बन्धी काम, सर्वे (Survey) का काम इत्यादि।

हमारा देश बहुत बड़ा है। इसलिए विशेष अवस्था में यह सम्भव नहीं हो सकता कि एक केन्द्र से देश के विभिन्न हिस्सों में फैले हुए क्रान्तिकारी कार्यकर्त्ताओं को आदेश भेजा जा सके। इसलिए यह आवश्यक है कि स्थानीय कार्यकर्त्ताओं को ऐसी शिक्षा दी जाय कि राष्ट्र की सकटावस्था में वे स्वयं अपना कर्तव्य निर्धारित कर सकें।

कार्यकर्त्ताओं को कार्यों तथा अध्ययन और वहस मुवाहिसे के जरिए शिक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षा के दूसरे भाग, जैसे अध्ययन और वहस-मुवाहिसे के लिए स्थायी या अस्थायी अध्ययन कैम्प और स्कूल खोलने की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए शिक्षक और साहित्य दोनों की आवश्यकता होगी।

कार्य-क्रम

अब मैं कार्यक्रम के विषय में कहूँगा। समझाने के ख्याल से मैं उस कार्यक्रम को, जिसका उल्लेख यहाँ किया जा सकता है, दो हिस्सों में बाँटूँगा। आम कार्यक्रम और विशेष प्रकार का कार्यक्रम। दूसरी कक्षा में मैं मजदूर संघ, किसान सभा, विद्यार्थियों तथा स्वयंसेवकों का संगठन, उत्पादन का संगठन, जैसे जुलाहों या ईख पैदा करने वालों की कोअपरेटिव (Co-operative) संस्थायें सामूहिक खेती और इस तरह के और दूसरे कामों को रखूँगा। इस प्रकार के विशेष ढंग के काम से हमारी थोड़ी बहुत जानकारी रही है। लेकिन इन कामों को सिलसिले से करना है; और इन्हें दूसरे नये

क्षेत्रों में भी करना है। शिक्षा, ज्ञान और अध्ययन की मदद से इन्हें सुचारु रूप से चलाना है। और, इन सबों के ऊपर हमारे जो क्रान्तिकारी मकसद और समाज-दर्शन हैं, उनसे हमारे कार्यक्रम को ओतप्रोत होना है जिससे वह श्रृंखलाहीन तथा छोटे-मोटे आन्दोलनों में न परिणत हो जाय, जिनका उद्देश्य तत्कालीन आर्थिक उन्नति रहता है, या वह केवल प्रदर्शनात्मक और आन्दोलनात्मक (agitation) ही न रह जाय। कोअपरेटिव या मजदूर-संघ या किसान आन्दोलन के बारे में हमेशा भय रहता है कि कहीं वह केवल आर्थिकवाद-ही में न सीमित हो जाय। इसे हमें रोकना है। फिर, आप स्वयंसेवक या विद्यार्थी आन्दोलन को लीजिये। यह काफी नहीं होता कि स्वयंसेवक दल कवायद और शारीरिक व्यायाम, जन-समूहों का नियंत्रण और प्रदर्शन में ही अपने को सीमित रखे। प्रत्येक स्वयंसेवक को कुछ ऐसी चीजें जरूर मालूम होनी चाहिए, चाहे वे कितनी भी साधारण क्यों न हों, जिनके द्वारा वह समाज की सेवा कर सके। स्वयंसेवकों के अफसरों को कम-से-कम इतना तो अवश्य ही जानना चाहिये कि आने वाली क्रान्ति में उनकी मातहत के स्वयंसेवकों का स्थान और कर्तव्य क्या होगा? विद्यार्थियों की कांग्रेस मुख्यतः केवल आन्दोलनात्मक ही रह गई है। यह काफी नहीं है। विद्यार्थी-कांग्रेस को चाहिये कि वह विद्यार्थियों के बीच तथा उस समाज के बीच जिसमें विद्यार्थी रहते हैं, रचनात्मक कार्य प्रारम्भ करे, उदाहरणार्थ, शिक्षण कार्य (गरीबों के लड़कों को पढ़ाना, बालिगों में साक्षरता फैलाना, हिन्दुस्तानी प्रचार, सांस्कृतिक कार्य, जैसे वाद-विवाद, नाटक, कलात्मक प्रदर्शन इत्यादि), स्वास्थ्य-सुधार, सर्वे का काम, मजदूर संघ या उस तरह के दूसरे कामों में सहायता पहुँचाना, भ्रमणार्थ टोलियों में निकल जाना, छुट्टियों में गावों में जाकर काम करना, विद्यार्थियों के सेवा-केंद्र स्थापित करना, इत्यादि।

जयप्रकाश की विचारधारा

ट्रेड यूनियन कांग्रेस राजनैतिक दृष्टि से इस मुल्क में पिछड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। महायुद्ध के जमाने में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की राजनैतिक हालत जितनी पिछड़ी हुई देखने में आई, उतनी पहले कभी नहीं आई थी। इस जमाने में वह हिन्दुस्तान के मजदूरों का कोई राजनैतिक नेतृत्व नहीं कर सकी। जब देश में क्रान्ति की ज्वाला फैली हुई थी और बहुत सारे मजदूर इस क्रान्तिमें शरीक भी हुए थे, उस समय भी ट्रेड यूनियन कांग्रेस किकर्तव्य विमूढ़ रही और यह नहीं तय कर सकी कि इस युद्ध में वह क्रान्ति के पक्ष में या साम्राज्यवादी ताकत के साथ है। मुख्यतः भारतवर्ष की कम्युनिस्ट पार्टी के विश्वासघात का यह परिणाम था। ट्रेड यूनियन कांग्रेस की इस राजनैतिक अकर्मण्यता को दूर करना आवश्यक है और ट्रेड यूनियन आन्दोलन को क्रान्तिकारी जंग के अनुरूप बनाना है जिससे मजदूर इस जंग में अपना उचित हिस्सा ले सकें।

किसान आन्दोलन भी आज छिन्न-भिन्न है, और इसका भी श्रेय ज्यादातर कम्युनिस्ट पार्टी की नीति को ही है। किसान आन्दोलन के उन टुकड़ों में, जो राष्ट्रीय लड़ाई के साथ रहे हैं, एकता स्थापित होनी चाहिए और तमाम आन्दोलन को एक नए सिरे से सगठित करना चाहिए।

उत्पादकों की को-अपरेटिव और सामूहिक खेती इन दोनों की तरफ में आपका ध्यान आकृष्ट करता हूँ। एकाध जगह इस ढंग के काम का प्रारम्भ शायद हुआ हो, लेकिन आम तौर पर यह काम हमारे लिए नया है। जहाँ कहीं ठीक कार्यकर्ता मिल जावें और वस्तुस्थिति भी अनुकूल हो, वहाँ इस दिशा में काम शुरू हो जाना चाहिए।

मैं पहले कह चुका हूँ कि राष्ट्रीय एकता के लिए जिस जनशक्ति का निर्माण करना है वह हमारे कार्यक्रम में बहुत ऊँचा स्थान रखता है। मैं फिर

आजादी के सैनिकों के नाम

उसको दुहराना चाहता हूँ और आपका ध्यान, जो कुछ मैं इसके विषय में कह चुका हूँ, उसकी ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ ।

मैंने यहाँ विशेष कार्यों की पूरी सूची नहीं दी है । उपरोक्त सूची तो मिसाल के तौर पर है । इनके अलावा औरतों के बीच काम करना विशेष प्रकार के कार्यों में से एक है । कोई ऐसा व्यक्ति जो इस ढंग के काम की ज्यादा जानकारी रखता हो, आपको इसके विषय में बाद में बतायेगा । दूसरे उदाहरणों को लोजिए, तो गान्धी जी के रचनात्मक कार्यक्रम के वे मद हैं जिन्हें हम शुरू कर सकते हैं, जैसे अस्पृश्यता निवारण, मद्य निषेध, गाँवों की सफाई, बुनियादी तालीम (Basic Education) इत्यादि । संक्षेप में, न तो काम की कमी है, और न कमी है जनता की सेवा करने, उन्हें संगठित एवं शिक्षित करने के साधनों की । यदि कमी है तो ऐसे कार्यकर्त्ताओं की जो इस काम को अच्छी तरह कर सकें ।

अब मैं आम ढंग के कामों के बारे में कुछ कहूँगा । इस तरह के काम में मैं सब से ऊँचा स्थान कांग्रेस के काम को देता हूँ, यानी, कांग्रेस को सुदृढ़ और लोकप्रिय बनाना । आज जो कांग्रेस का प्रभाव लोगों पर है, वैसा पहले कभी भी नहीं था । लेकिन आमतौर पर यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस की सस्था मृतप्राय हो गई है, और वैधानिक कार्यक्रम के चलते इसके अन्दर बहुत सी बुराइयाँ आ गई हैं । हमारा पहला काम यह होना चाहिए कि कांग्रेस कमीटियों को सजीव बनावें और उनके और जनता के बीच के सम्बन्ध को फिर से कायम करें । इसके अलावा हमें सदैव सतर्क रहना चाहिए, और कांग्रेस के भीतर की सब प्रकार की बुराइयों को दूर करने के लिए कटिबद्ध रहना चाहिए ।

कांग्रेस कमीटियों को सजीव बनाओ—यह वाक्य दुहराते दुहराते पुराना पड़ गया है । इसलिए मुझे शायद इसके अर्थ का खुलासा कर देना चाहिए ।

जयप्रकाश की विचारधारा

यह तो स्पष्ट ही है कि कांग्रेस कमीटियों में तभी जीवन का संचार हो सकता है जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमीटी तथा प्रान्तीय कांग्रेस कमिटियाँ रास्ता दिखायें। इन कमीटियों का यह काम होना चाहिए कि वे समय समय पर आदेश भेजें कि फला काम निश्चित समय के भीतर होना चाहिए जैसे किसी सर्वे (Survey) का काम, अस्पृश्यता निवारण या साम्प्रदायिक मेल, बालिंग साक्षरता, गल्ले का बंक, गाँवों में स्वयंसेवकों की भर्ती इत्यादि। इन ऊपर की कमीटियों को चाहिए कि कार्यकर्त्ताओं के लिए समय समय पर इस तरह का साहित्य तैयार करें जिससे उनको अपने रोजमर्रे के काम में और अपनी समस्याओं को समझने में मदद मिले। इन कमीटियों को अनुसंधान (Research) करना चाहिए और राजनैतिक योजना तैयार करनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि कांग्रेस को मेरे उपरोक्त कार्य क्रम को तथा उन कामों को, जिनका उल्लेख मैं नीचे कर रहा हूँ, पूर्ण रूप से अपनाने में कोई दिक्कत होगी। लेकिन, मैं नहीं कह सकता कि कब तक ये कमीटियाँ इस कार्यक्रम को अपनायेंगी, या कभी इसे अपनायेंगी भी या नहीं। इसलिए जहाँ कहीं भी कांग्रेस कमीटियों के जरिए हम काम कर सकते हैं वहाँ हमको चाहिए कि इस समूचे प्रोग्राम को उनके द्वारा कार्यान्वित करावें। लेकिन जहाँ यह सम्भव नहीं हो, वहाँ हमें अपनी पार्टियों की शाखाओं की मदद से इस कार्यक्रम को अमल में लाना पड़ेगा। पार्टियों की इन शाखाओं का यह भी कर्त्तव्य होना चाहिए कि उनके इस कार्यक्रम में और दूसरे गन्ने आजादी के सिपाहियों को शरीक करें।

आमतौर के कार्यक्रम के विषय में और ज्यादा कहने के पहले मैं चाहता हूँ कि इसका अर्थ समझा दूँ। हमारे विशेष प्रकार के कार्य का सम्बन्ध जनता की विभिन्न जमातों तथा वर्गों के साथ है। लेकिन जब हम समूचे समाज को लेते हैं, जैसे एक गाँव या शहर, शहर का एक महाल्ला और उसमें रहने

अजादी के सैनिकों के नाम

वाली तमाम जनता के बीच जो हमें काम करना है उसके बारे में सोचते हैं, तब हम आम कार्यक्रम के बारे में सोचते हैं। किसी गाँव में, उदाहरणार्थ, यदि हम किसान सभा कायम करें या किसी शहर में मजदूर सभ, तो यह विशेष प्रकार का कार्य होगा। लेकिन, यदि हम समूचे गाँव या शहर को एक मानकर उसके सुतल्लिक अपना कार्यक्रम बनाएँ, तो वह कार्यक्रम आम कार्यक्रम होगा।

पहले हम गाँव के काम को लें। हमारा अन्तिम ध्येय, मान लीजिए छः महीने काम करने के बाद, ग्राम-राज्य कायम करना है। ग्राम-राज्य एक खुदमुखतार गाँव है, वह एक प्रजातन्त्र है, न कि सिर्फ एक पंचायत। इस प्रकार के ग्राम-राज्य की रचना ग्रामवासियों को ही खुद अपनी शक्ति से, न कि सरकारी एजेंसियों द्वारा करना है। जिस तरहके ग्राम-राज्य की मैं कल्पना करता हूँ उसमें विदेशी राज्य अनावश्यक हो जायगा, और क्रान्ति के समय में ग्राम राज्य मुकाबिले और लड़ाई के केन्द्र हो जाएंगे, और भारतीय प्रजातन्त्र के निर्माण में ईंट का काम करेंगे।

ग्राम-राज्य कायम होने के पहले रचनात्मक कार्य की बहुत जरूरत होगी। मैं इसके लिए निम्नलिखित कार्यक्रम आपके सामने रखता हूँ।

- (१) कांग्रेस सदस्यों की भर्ती करना। प्रत्येक बालिंग ग्रामवासी को मेम्बर बनाने की कोशिश होनी चाहिए।
- (२) सांस्कृतिक केन्द्र खोलना चाहिए, जहाँ अखबार पढ़े जाय और दूसरे इस तरह के काम हो जैसे, बालिंग साक्षरता, नाटक, ग्रामगीत, अध्ययन के पुस्तकालय, पोस्टर, खेती सम्बन्धी सलाह इत्यादि।
- (३) सेवादल तथा आखाड़ा खोलना चाहिये।
- (४) व्यावहारिक टगो से कुआँ, तालाब, नहर बाँध इत्यादिके सबालों को हल करना।

जयप्रकाश की विचारधारा

- (५) स्वावलम्बन की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना ।
- (६) अस्पृश्यता निवारण ।
- (७) साम्प्रदायिक मेल ।
- (८) मद्यनिषेध ।
- (९) गाँवों की अवस्थाओं का अध्ययन और सर्वे (Survey) ।
- (१०) गल्ले के बंकों को खोलना ।
- (११) समीपवर्ती गाँवों में प्रचार कार्य के द्वारा जन जागरण पैदा करना ।
- (१२) को-अपरेटिभ (सहयोग पद्धति) से खरीद बिक्री का प्रबन्ध करना ।
- (१३) स्त्रियों और बच्चों के बीच काम करना ।

उस गाव में जहाँ ईमानदार और एकनिष्ठ कार्यकर्त्ता इस तरह के काम करके उस गाव के निवासियों का सहयोग प्राप्त करने में सफल हुए हैं, वहाँ छः महीने के अन्दर ही ग्राम राज्य का कायम होना सम्भव है । इस तरह गावों में सामूहिक खेती और सहयोगमूलक (Cooperative) उद्योग-धंधों का कायम होना सम्भव है ।

इस तरह के काम के लिए अच्छे से अच्छे कार्यकर्त्ता की आवश्यकता है, और यथेष्ट सख्या में । यह काम हिन्दुस्तान के आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक जीवन की जड़ों से सम्बन्ध है और इसमें रचनात्मक तथा क्रान्ति-कारी सम्भावनाएँ निहित हैं ।

शहर के बीच काम करने के लिए भी हमारे सामने इस तरह की तस्वीर है । शहरों में मुहल्ले मुहल्ले को लेकर हमें काम करना है । मुहल्लों में एक या अधिक केन्द्रों के जरिए हमको उसी प्रकार के रचनात्मक कार्य करना है, जैसा कि गावों में । शहर में वहाँ की आवश्यकता के अनुकूल ऊपर गावों के

श्रजादी के सैनिकों के नाम

लिए बताया गए कार्यक्रम में तन्दीलियां करनी पड़ेंगी। इस कार्य में हमारा ध्यान इस बात में होना चाहिए कि हमारा काम वहाँ के गरीब तबकों से ज्यादा सम्बन्ध रखे। विद्यार्थी कांग्रेस के कार्यशील मेम्बरों को इस काम में शरीक करना चाहिए।

इस कार्यक्रम को विस्तार पूर्वक बताया जा सकता है, लेकिन उदाहरण के तौरपर ऊपर बताया गए कार्यक्रम काफी हैं। स्थानीय जिम्मेदारी और वहाँ के अनुभवों के बलपर इस कार्यक्रम में छोट-काट किया जा सकता है। मैं अब इसे आपके सामने रखता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यह कार्यक्रम उपयोगी साबित होगा।

समाप्त करने के पहले मैं फिर एक बार आपका ध्यान हमारे केन्द्रीय क्रांतिकारी मकसद की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूँ। याद रहे, एक ही काम अलग-अलग ढंग पर और अलग-अलग नीयतों से किया जा सकता है। हमारे काम के पीछे हमारा जो मुख्य ध्येय है वह हमेशा हमारे सामने रहना चाहिए और उसे क्रांति के साधन में परिणत करना चाहिए।

आपका साथी

जयप्रकाश नारायण

अमेरिका के अफसरों और सिपाहियों के नाम--

[जिस समय जयप्रकाश हजारीबाग सेन्ट्रल जेल से भागकर बाहर आये और क्रान्ति का संचालन-सूत्र अपने हाथों में लिया, उस समय अमेरिका के फौजी दस्ते, हिन्दोस्तान को जापान से बचाने के लिए, देश के कोने-कोने में तानात कर दिये गये थे । कई जगहों पर अगरेजी साम्राज्यवाद ने उनसे अगस्त-क्रान्ति को कुचलने का काम भी लिया । अगरेजों के इस कुचक्र से अमेरिकन फौज को बचाने के लिए जयप्रकाश ने यह पत्र गुप्त रूप से प्रकाशित कराया और उनमें बँटवाया ।]

दोस्तो,

मैं यह पत्र आपको इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं अपने देश के बाद सबसे अधिक प्रेम अमेरिका से ही रखता हूँ । मैंने आपके महान देश में अपनी जवानी का सबसे सुनहला समय और जिन्दगी के सबसे सुखमय सात साल बिताये । आपके देश में मैं विद्यार्थी की हैसियत से गया था और वहाँ आपके विश्वविद्यालयों से ही नहीं, खेतों और कारखानों से भी बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त की जहाँ मैं अपनी पढाई के खर्चों का जुगाड़ करने के लिए मजदूरी की तरह काम किया करता था । कालिफोर्निया, इओवा और विस्कॉंसिन के विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करता हुआ, अन्ततः मैंने ओहियो में उपाधि प्राप्त की । आपलोगों में ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने इन विश्व विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की है । ऐसे लोगों के प्रति मैं भाईचारे का अभिवादन भेज रहा हूँ ।

आपकी सेवा में यह पत्र इसलिए भी भेज रहा हूँ कि मैं भी आपलोगों की तरह उनलोगों में से हूँ जो स्वाधीनता को प्यार करते हैं और उसके

अमेरिका के अफसरों और विपाहियों के नाम

लिए अपनी जान उत्सर्ग करने को उद्यत रहते हैं। एक समाजवादी की हैसियत से भी आपकी सेवा में यह पत्र प्रेषित कर रहा हूँ क्योंकि हमारा विश्वास है कि समाजवाद में ही लड़ाई का मूलोच्छेद हो सकता है और स्वाधीनता की सुरक्षा भी उसीके अन्दर सम्भव है।

एक और हैसियत से आपकी सेवा में यह पत्र भेजना आवश्यक जँचा। आप जानते ही हैं, मैं अंगरेजी साम्राज्यवाद द्वारा हजारीबाग जेल में कैद कर लिया गया था। किन्तु हर युद्धबन्दी को यह अविकार है कि वह दुश्मन के शिकजे से मौका पाते ही भाग निकले और मैं अभी-अभी उस अधिकार का उपयोग कर बाहर आया हूँ जिससे स्वाधीनता की लड़ाई में सक्रिय भाग ले सकूँ। हमारे देश के दुश्मन ने—मेरा मतलब अंगरेजी साम्राज्यवाद से है—यह घोषित किया है कि जो कोई मुझे पकड़ेगा या पकड़वा देगा उसे भारी इनाम दिया जायगा—मानों मैं काई घोर अपराधी हूँ और मैंने न्याय को चरका दिया है। यदि किसी कुयोग से आपसे कोई कभी दुश्मनो द्वारा युद्धबन्दी बना लिया जाय और मौका मिलते ही वह बाहर निकल आवे, तो निस्सन्देह ही आप उसे हीरो मानेंगे और उसकी अर्चना और अभ्यर्थना करेंगे। मैं अपने को हीरो कहलाने की धृष्टता नहीं कर सकता किन्तु मैं अपराधी भी नहीं हूँ। अपने देश की जनता की स्वाधीनता के लिए उद्योग करनेवाला एक तुच्छ सेवक ही अपने को मैं हमेशा मानता रहा हूँ।

आज ससार में बहुत से लोग स्वाधीनता के लिए लड़ और मर रहे हैं। किन्तु मेरे विचार से स्वाधीनता का शब्द बहुत कुछ धुँधला, अर्थहीन और श्रामक हो गया है। मेरे लिए यह शब्द कोई हवाई आदर्श नहीं है जिसपर सिर्फ रेडियो पर व्याख्यान दिये जायँ, बल्कि मेरे निकट वह एक ठोस पदार्थ के रूप में उपस्थित है। स्वाधीनता का सबसे पहला और प्रमुख अर्थ मेरे सामने

जयप्रकाश की विचारधारा

यह है कि मेरा यह देश स्वाधीन हो जाय—मेरे देश के करोड़ों लोगों के हाथ अँगरेजों द्वारा डाली गई जंजीरो से मुक्त हो जायँ ।

आपलोग स्वाधीनता के सैनिक हैं और संयोगवश हमारे देश के इतने निकट सम्पर्क में आये हैं , इसलिए मेरी समझ में आपके लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि आप हमारी इस स्वाधीनता को लड़ाई का महत्व समझें और हमारे उद्योगों की सराहना करें ।

नात्सियों के झूठे प्रचार से आपलोग अच्छी तरह अवगत हैं । डा० गोयबेल्स अपनी झुठाइयों के चलते असत्य का अवतार ही सिद्ध हो चुका है । किन्तु आपलोग एक झुठाई से अभी तक परिचित नहीं हो सके हैं जिसे साम्राज्यवादी झुठाई कहते हैं और जिसके आचार्य चर्चिल, हेलिफैक्स, एमरी और उनके अनेक अँगरेज साथी और शार्गिर्द हैं । यदि हिन्दोस्तान के बारे में जरा भी चिन्ता आपके मन में उदित हुई होगी, तो दो बड़ी झुठाइयाँ आपके सामने पेश की गई होंगी । उनमें पहली झुठाई यह है कि अँगरेज तो हिन्दोस्तान में हिन्दोस्तानियों को स्वराज्य की शिक्षा देने के लिए टिके हुए हैं और ज्योंही हम योग्य हुए कि वे यहाँ से बिना टिकट के ही रवाना हो जायँगे । दूसरी झुठाई यह है कि अँगरेज हिन्दोस्तान को आज ही आजाद कर देने को तैयार हैं बशर्ते कि हिन्दोस्तान के सभी लोगों में एका हो जाय ।

इनसे बड़ी झुठाइयाँ इतिहास में कभी नहीं कही गई थीं । किन्तु इन झुठाइयों का प्रचारित करनेवाला न तो गोयबेल्स है और न गुस्ताख नात्सी शासक । इसलिए इन झुठाइयों से आपके कान भन्ना नहीं उठते । इन पर युग और परम्परा की मर्यादा मँढो हुई है और अँगरेजी सस्कृति की कलई इनपर चढ़ी हुई है । बड़े-बड़े लाटों के मुँह से हम इन्हें सुनते हैं, बड़े-बड़े अभिजात्यों की जिह्वायें इन्हें बकती हैं । कविता और साहित्य, ज्ञान और

अमेरिका के अफसरो और सिपाहियों के नाम

विज्ञान ने इन झुठाइयों पर पवित्रता की मुहर लगा रखी है इस तरह कि हम उदार से उदार अँगरेजों के मस्तिष्क को भी इनसे मुक्त नहीं पाते हैं।

सिवा कुछ बदमाशों के, यह कहना भी मस्तिष्क का अपमान करना है कि साम्राज्यवाद की स्थापना पिछड़े हुए लोगों को स्वराज्य की शिक्षा देने के लिए की गई है। आप भी इसे अच्छी तरह जानते हैं कि साम्राज्यों को स्थापना लूटने और चूसने के लिए की जाती है। और अँगरेजों ने हमारे देश को जिस तरह लूटा और चूसा है, उसका ज्ञान आपको हो जाय, तो आप भी आश्चर्यचकित हो जायेंगे गन्ने आपके देश में आयव्यय का लेखाजोखा अरबों खरबों तक किया जाना साधारण-सी बात है।

अँगरेजों द्वारा गुलाम बनाये जाने के पहले हिन्दोस्तान एक आजाद देश था। स्वराज्य की शिक्षा उसे किसी देश से ग्रहण करने की जरूरत नहीं थी। इसमें शक नहीं कि हमारे देश में आपसी लड़ाइयाँ थीं किन्तु यदि इसीसे स्वराज्य की अयोग्यता सिद्ध की जाय, तो सारे यूरोप और उसके आस-पास के द्वीपों को स्वराज्य की शिक्षा पाने की सबसे अधिक जरूरत है जो कि हमेशा ही खूनी जग किया करते हैं—अच्छा हो कि उन्हें यह शिक्षा अमेरिका ही दे ! पहले तो किसी की आजादी छीन लेना और फिर यह कहना कि हम तुम्हें आजादी की शिक्षा दे रहे हैं—इतनी बड़ी झुठाई है कि कोई साम्राज्यवादी देश ही ऐसा दुस्ताहस कर सकता है।

और, अँगरेज हमें स्वराज्य की शिक्षा किस तरह दे रहे हैं। वे यहाँ पर १५० वर्षों से हैं। इससे कम ही समय में आपका देश ऐसी ही शिक्षा से अपने को मुक्त करके छोटे-मोटे असंगठित उपनिवेशों के झुंड से ससार का सबसे बड़ा और मजबूत राष्ट्र बन चुका है। आज तो आप हिन्दोस्तान में हैं, इसलिये आप खुद ही देख सकते हैं कि हमारे अँगरेज शिक्षकों ने हमारे लिए क्या किया है ? हमारे देश में पढ़े-लिखों की संख्या सैकड़ों दस से ज्यादा

जयप्रकाश की विचारधारा

नहीं हैं और देश के साधनों के विकास का अनुपात भी यही है। इस महायुद्ध के तीन सालों में हमारा देश युद्ध-सामग्रियों के उत्पादन में कितना आगे बढ़ सका है, यह भी आप देख ही रहे हैं। यह बात ऐसी शर्मनाक है कि अमेरिकन टेक्निकल मिशन ने, श्री ग्रैडी के नेतृत्व में, जो खोजगूँठ को है, उसकी रिपोर्ट तक हमारी सरकार प्रकाशित करने की हिम्मत नहीं कर पाती है। हमारी उन्नति और विकास के लिए हमारे अँगरेज प्रभुओं को इतनी विन्ता है कि हमारे देश में राजनीतिक, आर्थिक या शिक्षा-सम्बन्धी मामलों में जो भी तरक्की हुई है, वह उनके विरोध के बावजूद और कड़वे आन्दोलन एवं संघर्ष के बाद ही। उनमें से सबसे कड़वा और आखिरी संघर्ष इस समय जारी है और हम अँगरेजी गुलामी की फँसरी को अपने गले से हटा कर ही दम लेनेवाले।

क्रिप्स की यात्रा और उसके उपहार को बातें बहुत की जाती हैं। किन्तु क्रिप्स जो उपहार हमें देने आया था, वह क्या था? लड़ाई के बाद नाम की स्वाधीनता और उसके दरम्यान कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हिन्दोस्तान को अँगरेजों के बादो से कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है। हमें आजादी चाहिए और तुरत। इसका जवाब साम्राज्यवादी प्रचारक देते हैं—“ले लो आजादी, लेकिन उसके पहले एक तो हो जाओ।”

सबसे पहली बात तो यह है कि किसी देश में फूट हो, तो क्या दूसरे देश को हक हो जाता है कि उसे गुलाम बनाये रखे? यदि दो भाई लड़ते हों, तो क्या लुटेरों को यह हक हासिल हो जाता है कि उसके घर में घुस जायँ और लूट ले। अँगरेजों की स्थिति हिन्दोस्तान में लुटेरों की है। मान लीजिये कि हिन्दू और मुसलमान आपस में लड़ रहे थे, तो क्या यह उचित था कि अँगरेज हमारे देश पर चढ़ दौड़ें और उसपर कब्जा कर लें। यह दलील कि एक लुटेरा नहीं आता, तो दूसरा तो आता ही, क्योंकि घर में फूट थी,

अमेरिका के अफसरो और सिपाहियों के नाम

ऐसी दलील लुटेरों के दिमाग में हो पैदा हो सकती है। कोई भी भलामानस किसी अरक्षित घर में घुस कर चोरी नहीं करेगा और न यह दलील देगा कि मैं क्या कहूँ, मैं चोरी नहीं कहूँ तो दूसरा आदमी चोरी करेगा ही।

लेकिन इस दलील में भी कोई सच्चाई नहीं है। चाहे एका हो या फूट रहे—अंगरेज हमारे हाथों में यथार्थ शक्ति समर्पित करने को तैयार नहीं हैं। क्रिप्स-वार्ता के समय ही यह प्रगट हो चुका था कि यदि भारत में पूर्ण एका हो, तो भी वायसराय और उनकी कौंसिल का ही शासन रहेगा, भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी मंत्रिमंडल का संगठन नहीं हो सकता। सर स्ट्राफर्ड क्रिप्स ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वायसराय से मतभेद होने पर उनकी कौंसिल के सदस्यों को हट जाना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में इसका मानी-यह हुआ कि हमें जो आजादी क्रिप्स-मिशन दे रही थी वह आजादी थी उस दशा में इस्तीफा दे देने की आजादी जब कि मंत्रियों की सलाह में, जो भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करते, और वायसराय की राय में, जो साम्राज्यवाद का प्रतिनिधित्व करता, कोई मतभेद उठ खड़ा होता। आप ही कहिये, कितनी अच्छी और बड़ी आजादी हमें मिल रही थी।

भारतीय आजादी और हमारी एकता में कोई भी सम्पर्क नहीं है। यह नारा तो आँखों में धूल भोंकने के लिए अंगरेजों ने उठाया है। सही सवाल तो यह है कि अंगरेज अपने साम्राज्य को खत्म करने के लिए तैयार हैं या नहीं? क्रिप्स मिशन ने इसका सीधा जवाब दे दिया—नहीं, नहीं! इसी जवाब को चर्चिल ने हाल ही में दुहराया है जब कि उसने निर्लज्जता पूर्वक घोषित किया है कि मैं प्रधान मंत्री इसलिए नहीं बना कि वादनाह के साम्राज्य को ही खत्म कर दूँ।

हिन्दुस्तान को आजाद करने की अंगरेजी इच्छा को जाच इस बात से होनी चाहिये कि वह अभी तुरत क्या करने को तैयार है। उसके उदार वादों से

जयप्रकाश की विचारधारा

हमें कुछ लेनादेना नहीं है। वादा करना आसान काम है और लड़ाई के जमाने में शासकों की ओर से वादों की बाढ़ आ जाती है। पिछली लड़ाई में जो वादे किये गये, उनका क्या हथ्र हुआ, आप सभी जानते हैं। यदि लड़ाई के बाद एक अच्छी दुनिया बन सकी, तो शासकों के वादों के कारण नहीं होगी, बल्कि हमारे और आपके—ससार के साधारण आदमियों के—प्रयत्न से ही ऐसी दुनिया कायम हो पायगी।

अंगरेजी झुठाइयों के दो नमूने मैं आपके सामने और भी पेश करना चाहता हूँ। इसके लिए भारतीय सरकार की तरफ से आँख हटा कर हमें प्रान्तीय सरकारों की ओर जाना पड़ेगा। अंगरेजों ने हल्ला मचा रखा है कि आज भी कितने प्रान्तों पर भारतीयों द्वारा ही शासन किया जा रहा है। किन्तु इन स्व शासनो का क्या मूल्य है, आप जानते हैं? अभी अभी सिध के प्रधान मंत्री श्री अल्लावरूख को गवर्नर ने डिसमिस कर दिया है। उनका क्या कसूर था? उन्होंने 'खानबहादुर' की उपाधि अंगरेजों को वापस कर दी और हिन्दोस्तान में आजकल जो नीति बरती जा रही है, उससे अपनी असहमति प्रगट की। सिर्फ इसी अपराध पर एक गवर्नर की इतनी जुर्रत होती है कि जनता और असेम्बली का पूरा विश्वास जिसने प्राप्त कर रखा है, उसे प्रधान मंत्री को डिसमिस कर देता है। इसके अतिरिक्त बंगाल के बड़े सूबे में उसके एक मंत्री, डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी, को इसीलिए इस्तीफा देना पड़ा कि वहाँ का गवर्नर दिन-ब दिन के काम में हस्तक्षेप किया करता है। अपने एक बयान में उन्होंने बताया है कि किस तरह यह प्रान्तीय स्वतन्त्रता विल्कुल ढोंग और तमाशा है।

अंगरेजों का कहना है कि ज्यों ही एकता हुई कि हम हिन्दोस्तान को आजादी दे देंगे। बंगाल और सिध में तो यह एकता थी—क्योंकि वहाँ के मंत्रिमण्डल में सभी समूह के लोग शामिल थे और जो विरोधो पार्टी थी,

अमेरिका के अफसरो और सिपाहियों के नाम

उसका रहना तो प्रजातंत्र के सफल संचालन के लिए आवश्यक है ही। फिर इन प्रान्तों में ही स्व शासन का उपभोग क्यों नहीं करने दिया गया ? मुझे उम्मीद है कि अब अधिक उदाहरणों की जरूरत नहीं होगी इसे सिद्ध करने के लिए कि अंगरेज अपनी इच्छा से हिन्दोस्तान छोड़ने को तैयार नहीं हैं।

ऐसी हालत में हम क्या करें ? समूचा हिन्दोस्तान नात्सियों और फासिस्टों के खिलाफ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने और हमारी सोशलिस्ट पार्टी ने बार-बार यह घोषणा की है कि हम इस पाशविक और अनैतिक पद्धति के सर्वथा विरोधी हैं। इस महायुद्ध के शुरू होने के बहुत पहले से ही, जब तक कि बहुत से प्रजातंत्र अपने लिए पथ चुन नहीं सके थे, राष्ट्रीय और समाजवादी भारत ने प्रजातंत्री स्पेन और च्यांग काईशेक के प्रजातंत्री चीन के पक्ष में अपने को घोषित किया था और जर्मनी, इटली एवं जापान के खिलाफ जेहाद बोल दिया था। यदि हिन्दोस्तान आज़ाद होता तो इस अन्तर्राष्ट्रीय संकट में उसका शानदार हिस्सा हुआ होता और उसके हस्तक्षेप से यदि यह महायुद्ध टल नहीं गया होता, तो एशिया में फैल तो नहीं ही पाता। स्वतंत्र भारत और चीन किसी भी आक्रमणकारी देश के लिए बहुत बड़ी डरावनी शक्ति बन सकते हैं और यदि इन दोनों देशों को मिलकर काम करने का मौका मिला होता तो आधुनिक काल का इतिहास कुछ दूसरे ही ढंग से लिखा जाता।

किन्तु जिस तरह हम फासिज्म और नात्सिज्म के घोर विरोधी हैं, उसी तरह साम्राज्यवाद के भी हम कट्टर दुश्मन हैं। हम इसके अन्दर रह नहीं सकते, हम इसे जड़मूल से उखाड़ फेंकने का निश्चय कर लिया है और उसमें ढट गये हैं। जब ससार में जनता की स्वाधीनता के नाम पर एक महायुद्ध लड़ा जा रहा है, तब हम अपनी स्वाधीनता के लिए लड़े बिना रह नहीं सकते।

हम इसके लिए किसीसे कैफियत देने या क्षमा माँगने को तैयार नहीं हैं कि हम क्यों आजादी चाह रहे हैं और क्यों उसके लिए लड़ रहे हैं ।

आपको इस बात की चिन्ता हो सकती है कि अंगरेजों से हम जो लड़ाई छेड़े हुए हैं उसके कारण संयुक्त राष्ट्रों को धुरी राष्ट्रों से लड़ने में बाधा पहुँच सकती है । यदि ऐसी बात हो, तो इस प्रश्न पर विचार करने की जिम्मेवारी सिर्फ हमारी ही नहीं है । संयुक्त राष्ट्रों को भी इसपर क्रियात्मक विचार करना चाहिये । हम किसी भी तरह संयुक्त राष्ट्रों को उलम्बन में रखना या उनके कामों में बाधा पहुँचाना नहीं चाहते । किन्तु हमारी आजादी की लड़ाई से ऐसा होता हो, तो इसमें हमारा चारा क्या है ? यदि संयुक्त राष्ट्र उन्हीं आदर्शों के लिए लड़ रहे हैं, जिनकी उन्होंने घोषणा कर रखी है, तो हमारी आजादी की लड़ाई उन्हें मदद ही पहुँचायगी । यदि इससे उन्हें बाधा पहुँचती है, तो यह साबित होता है कि उनके युद्ध का आधार गलत है, उनके गवर्नों और कामों में अन्तर है, उनके आदर्शों और व्यवहारों में भेद है । हमारी आजादी की लड़ाई ऐसी हालत में भी संयुक्त राष्ट्रों को मदद ही पहुँचायगी; क्योंकि वह उन्हे शब्दों और कार्यों में सामंजस्य लाने को बाध्य करेगी और यों एक न्यायपूर्ण शान्ति की ओर उन्हें ले जायगी ।

इसलिए मैं आपसे, जो आजादी के ही सैनिक हैं, अपील करता हूँ कि आप हमारी आजादी की लड़ाई में मदद दें । यह मदद आप तीन तरह से दे सकते हैं । पहली बात—अंगरेजों ने हमारे खिलाफ जो फासिस्ट लड़ाई छेड़ रखी है, आप उसके काले धब्बे से अपने दामन को बचाये रखें । सुना है कि आपकी सरकार ने भी आपको ऐसी सूचना दी है कि आप दमन के काम में अंगरेजों की मदद नहीं करें । आप दूसरी मदद हमारी यह कर सकते हैं कि आप अपने देशवासियों, अपने नेताओं और अपनी सरकार को हिन्दोस्तान के सम्बन्ध में सच्ची खबर और राय दीजिये । आप हमारे बीच हैं, इसलिए

अमेरिका के अफसरों और सिपाहियों के नाम

आज हमारे सम्बन्ध में सच्ची खबरें साधिकार दे सकते हैं। अपने देश की सहानुभूति और सहयोग हमें प्राप्त कराकर आप उस आदर्श को सहायता पहुँचायेंगे, जिसके लिए आप जान तक कुर्बान करने को तैयार हैं। हमारी तीसरी मदद आपसे यह होगी कि आप अँगरेज सिपाहियों और अफसरों को भी हिन्दोस्तान की यथार्थ स्थिति के बारे में ज्ञान दें। अँगरेज सैनिक बड़े बहादुर होते हैं और यदि सत्य बातें उनके सामने रखी जायँ, तो वे हमारे उद्देश्य को न्यायपरता समझने में चूक नहीं करेंगे। आज तो उनके दिमाग और दिल में गलत धारणा, जातिगत घृणा और हिन्दोस्तान के प्रति घोर अज्ञान भरा पड़ा है। इसलिए वे हमारी हानि पहुँचा कर अपनी और अपने आदर्श की ही हानि कर रहे हैं। ज्यादातर अँगरेज सैनिक श्रमजीवी वर्ग से आते हैं और वे स्वयं भी साम्राज्यवादी शोषकों के शिकार हैं। उनके लिए यह आवश्यक है कि वे समझ जायँ कि हमारा उद्देश्य और उनका उद्देश्य भिन्न नहीं है, क्योंकि जब तक साम्राज्य टटता और नाश नहीं होता तब तक अँगरेज जनता भी शोषण और गरीबी से मुक्त नहीं हो सकती। इंग्लैंड में इसकी बड़ी चर्चा है कि महायुद्ध के बाद एक नया सामाजिक ढाँचा खड़ा करना चाहिये। अँगरेज सैनिकों का उस भविष्य पर अगाध विश्वास है, किन्तु सोचना यह है कि साम्राज्यवाद की पुरानी नींव पर नये समाज की भव्य इमारत क्या खड़ी की जा सकती है ?

इसलिए आप अँगरेजों से कहिये कि यदि वे एक नया और अच्छा ससार बनाने के लिए लड़ रहे हैं, जहाँ धन और अवसर, शक्ति और मर्यादा, शिक्षा और सस्कृति एवं जिन्दगी के उत्तमोत्तम साधन सबके बीच में न्यायपूर्वक बँट सकें, तो वे सबसे बड़ा गलत काम यह कर रहे हैं कि वे एशिया महादेश को सबसे अधिक वेग से झुकमोरने वाली आजादी की इस अनुपम लड़ाई को फासिस्ट ढग से कुचल डालने के लिए निरीह बच्चों और

जयप्रकाश की विचारधारा

अबला नारियों पर गोळियाँ बरसाते और देशभक्तों के घरों को लूटते और उनमें आग लगाते फिरते हैं। आप उनसे कहिये कि हमारी लड़ाई उनसे नहीं है, हम उनकी कोई हानि नहीं पहुँचाना चाहते, न हम अँगरेज जनता की ही कोई बुराई सोचते हैं। हमारी लड़ाई सिर्फ अँगरेजी साम्राज्य से है और हम उसे ही नष्ट करने में लगे हुए हैं; क्योंकि यह हमारी आज़ादी, खुशी और तरक्की का दुश्मन है। आप उनसे यह भी कहिये कि जब हम आज़ाद हो जायेंगे, तो उनके कंधे से कंधा भिड़ा कर ससार से सभी तरह के शोषणों और पाशविकताओं को हटाने के लिए लड़ेंगे—चाहे उसका नाम नात्सिज्म हो, साम्राज्यवाद हो या पूँजीवाद हो। तभी हम सब मिल कर एक नये ससार का एक नया ढाँचा बना सकेंगे। उनसे यह भी कहिये कि वे अपने दिमाग को खोलकर रखें और खुद सोचें। यदि वे अपने शासकों द्वारा प्रचारित प्रोपेगंडा के यों ही शिकार होते रहेंगे, तो उनकी लड़ाई और शहादत व्यर्थ जायगी; क्योंकि उनकी सतानों को यही विषैली, दुनिया मित्रगी, जहाँ अत्याचार है, वैषम्य है, निर्धनता है, कष्ट है, युद्ध है और शस्त्रीकरण करी दानवी प्रतिस्पर्धा है।

दोस्तो, संक्षेप में यही मेरी अपील आपसे है। मुझे पूरी उमीद है, यह आपके दिल में जगह पायगी।

आजादी की जय !

भारतीय इन्कलाब की जय !

हिन्दुस्तान के कोने से

जयप्रकाश नारायण

अपने विद्यार्थियों से

प्यारे दोस्तों,

मैं, बयान नहीं कर सकता कि आजादी की इस आखिरी लड़ाई में फिर से आपकी, बगल में आ खड़े होने में मैं कितनी खुशी महसूस कर रहा हूँ।

सबसे पहले मैं अपनी श्रद्धाजलि उन नौजवान देशभक्तों की स्मृति में पेश करना चाहता हूँ, जिनकी असीम वीरता और अनुपम शहादत ने हमारी राष्ट्रीय क्रान्ति के जीवत इतिहास में सुनहले पृष्ठ जोड़े हैं। उनका उदाहरण हमारे लिए एक अमर प्रेरणा बना रहेगा और उनके लिए एक फिटकार, जो विचलित हो रहे या पीछे हट रहे हैं।

उसके बाद आपने महान स्वाधीनता युद्ध में जो शानदार हिस्सा लिया है, उसके लिए मैं अपना हार्दिक अभिनन्दन आपके प्रति प्रेषित कर रहा हूँ। मैं शर्म से यह स्वीकार करता हूँ कि मैंने यह कल्पना नहीं की थी कि देश का विद्यार्थी-समूह इतना कर गुजरेगा। १९२१ में जो परम्परा विद्यार्थियों ने बनाई, वह ऊसर हो चुकी है, यह कल्पना भी अविश्वसनीय जँचती थी; किन्तु मेरा कुछ ऐसा ही विश्वास हो चला था। इसलिए जब आप बहादुराना

जयप्रकाश की वचारधारा

कार्रवाईयों से इतिहास की रचना कर रहे थे, मैं जेल की ठंडी दीवारों के अन्दर बड़े हर्ष और गर्व से दिन-ब-दिन की घटनाओं का अनुगमन कर रहा था। आपने इस खुली बगावत में जैसा हिस्सा लिया और जैसी कुर्बानियाँ कीं, उनके सामने १९२१ की घटनायें फीकी-फीकी जँचती हैं।

किन्तु दोस्तो, यह समय अपनी पतवार सम्हाल कर विश्राम करने या अपने कारनामों पर गौर करने का नहीं है। आज की समस्या यह नहीं है कि हमने कितना कर लिया; बल्कि देखना यह है कि हम अभी क्या कर रहे हैं और आगे क्या करने जा रहे हैं। इन्हीं प्रश्नों पर आपके सामने मुझे कुछ निवेदन करना है।

कुछ हफ्ते हुए, कालेज खुल गये हैं और आप अब अध्ययन की ओर प्रवृत्त हुए दिखाई पड़ते हैं। यदि मैं कहूँ कि यह समय पढ़ने या परीक्षा देने का नहीं, तो आप समझेंगे कि मैं चर्चित चर्चण कर रहा हूँ। किन्तु क्या रूस या चीन, ऑक्सफोर्ड या हावाई विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी ऐसी सलाहों पर इसी तरह सोचेंगे? आपके अभिभावकों या आपके विश्वविद्यालयों के कुलपतियों एवं दीक्षांत-भाषणकर्त्ताओं के लिए यह कहना साधारण बात है कि विद्यार्थियों का प्रमुख कार्य अध्ययन करना और उपाधि लेना है और उसके बाद ही उन्हें अधिक योग्य होकर राजनीति में प्रवेश करना है, जिसमें वे देश की अच्छी तरह सेवा कर सकें।

लेकिन, मैं कहता हूँ, इस तरह का सोचना या सलाह देना मढ़े दिमाग की निशानी है। साधारण समयों में विद्यार्थियों के लिए एक ही धर्म है कि वे पढ़ें और अपने व्यक्तित्व का विकास करें, जिससे वे योग्य नागरिक बन सकें और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से देश की सेवा कर सकें। किन्तु राष्ट्रों की जिन्दगी में ऐसे समय भी आते हैं, जब व्यक्ति के विकास को इसलिए रोक देना पड़ता है कि सारा राष्ट्र जीवित रह सके और विकसित हो सके—जब

समाज की उन्नति की वेदी पर व्यक्ति का निर्भय और निष्पक्ष बलिदान कर देना होता है। सोचिये तो कि रूस और चीन के विद्यार्थी इस समय अपने विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने में लगे हुए हैं या अपने देश के अस्तित्व और कीर्ति की रक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी हँसते-हँसते चढ़ा रहे हैं। सोचिये तो कि उन देशों में क्या शिक्षकों और अभिभावकों को इस तरह की बातें कहने की हिम्मत भी हो सकती है और क्या उनकी ऐसी बातें बर्दाश्त भी की जा सकती हैं? क्या कैम्ब्रिज या कोलम्बिया के विद्यार्थियों को युद्धक्षेत्र में जाने से इसलिए रोका जा सकता है कि उन्हें पहले उपाधि प्राप्त कर लेनी चाहिए?

नहीं दोस्तों, नहीं। ऐसे वक्त आते हैं, जब व्यक्ति को जान देकर अपने देश को जीवित रखना और अपनी सभ्यता को विकसित करना पड़ता है। आज का वक्त ऐसा हा है। हमें भी आज अपनी जान देकर, तकलीफें सहकर, अपने को मिटाकर अपने देश को आजाद करना है, अपनी सभ्यता को फूलने-फलने का मौका देना है। इसलिए आप डेगट्रोहियों और कायरों की बातों में न आये।

तब आप करें क्या?

अपने क्रान्तिकारी करतबों से आपने स्कूलों और कालेजों को बद होने को लाचार कर दिया। वे खुल रहे हैं यही आपको हार है, हमारी हार है, हम सबकी हार है। आप क्यों लौट रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आपने आजादी की वर्तमान लड़ाई का स्वरूप समझने में गलती की, ऐसा मैं किस तरह कहूँ? हमारी यह आखिरी लड़ाई सिर्फ प्रदर्शन या क्षणिक जोश की चीज नहीं। यह काफी गम्भीर और भयावही चीज ठहरी और विजय छोड़ कर दूसरा इसका अन्त नहीं। इस बारे में आप भ्रम में नहीं रहें!

जयप्रकाश की विचारधारा

कह नहीं सकता, आपका दिमाग किस तरह काम करता है; किन्तु यदि मैं आपकी जगह पर होता, तो अगस्त की घटनाओं के बाद स्कूल या कालेज में जाने का सपना भी नहीं देख सकता था। मैं अपने अनुभव से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि एक या दो साल कालेज से बाहर रहा जाय, तो उससे शिक्षा में कोई त्रुटि नहीं होती। १९२१ के असहयोग-आन्दोलन में एक साल मैं बाहर-बाहर रहा; किन्तु अमेरिका में पढ़ते समय भी कभी कभी महीनों, तो कभी साल-साल भर तक मैं कालेज से बाहर रहकर अपनी पढ़ाई का खर्च जुगाता रहा। और, मैं आपसे यह कहते हुए आनन्द अनुभव कर रहा हूँ कि विश्वविद्यालयों में जितना मैंने सीखा, बाहर उससे कम नहीं सीखा। फिर हमारे देश की शिक्षा पद्धति इतनी अस्वाभाविक, इतनी भूलभुलैया भरी और जीवन की यथार्थता से इतनी दूर है कि यदि आप एक-दो साल के लिए उसे सलाम कर लीजिये और राष्ट्रीय जीवन के तूफान में अपने को डाल दीजिये, तो आपको लाभ ही लाभ हो।

मालूम होता है, कालेजों से निकलने के बाद सूनापन अनुभव कर रहे थे, कोई काम हाथ में नहीं होने से आपका मन ऊब रहा था। किन्तु, मैं तो देखता हूँ कि आज काम ही काम है—इतने काम कि हर आदमी के लिए ढेर का ढेर अनुभव हो। मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि यदि आप घर पर रहकर खेतीवारी में मन लगाये होते या कुछ बच्चों को पढाये होते या गाँव की सफाई में लग कर लोगोंको स्वस्थ और सुन्दर जीवन की ओर प्रेरित किये होते, तो देश की बड़ी सेवा आपसे हो गई होती। ऐसा करके आप स्कूलों और कालेजों को खुलने से रोक सके होते और यों आप दुश्मन की मदद करने से बच गये होते—क्योंकि इनका खुलना तो दुश्मन की विजय की सूचना है।

किन्तु आज का तथ्य यह है कि स्कूल और कालेज खुल गये हैं। मैं

अपने में वह विश्वास नहीं अनुभव करता कि आपसे कहूँ कि अब भी आप उन्हें खाली कर दीजिये, यदि उन्हें बंद करा दीजिये। मेरे शब्दों का आपके लिए क्या वजन होगा, मैं नहीं जानता। लेकिन आपने जो किया है, उसके बारे में मैं आपको भ्रम में नहीं रखना चाहता। शिक्षणालयों में लौट कर आपने अपने को अपने प्रति और अपने नेताओं के प्रति बहुत छोटा और, मैं कहूँ, झूठा साबित किया है, तो आन बुन न मानें। प्रारम्भ में आपके जिस लक्ष्य की इतनी सेवा की, इतना लाभ पहुँचाया, उसे ही आपने इस कार्रवाई द्वारा धायल कर दिया, नुस्खान पहुँचाया। आपका रास्ता साफ है और खुला है—उसपर आप चलें या नहीं, आपको मर्जी।

लेकिन जो लोग रकूँ और कालेजों में रहना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत-से काम हैं। अपनी कमजोरियों के क्षणों में या बगावत कुचल दी गई, यह मानकर, आप इन शिक्षालयों में लौटें हैं। किन्तु अब भी समय है कि आप सोच विचार करें। सबसे बड़ी भूल होगी ऐसा सोचना कि क्रान्ति दबा दी गई या उसकी धारा में पानी न रहा। “आजादी के सैनिकों के नाम”—अपने पत्र में मैंने अगस्त क्रान्ति के भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में विश्लेषण किया है। उन बातों को दुहराना यहाँ फिजूल है, लेकिन दो बातों की ओर इशारा करना जरूरी है। क्रान्ति का पहला दौर सफल रहा; क्योंकि हिन्दोस्तान के बहुत-से हिस्सों से इसने अंगरेजी राज्य को उखाड़ फेंका। इसका विकास इसलिए नहीं रुका कि दुश्मन की बड़ी ताकत उसका रास्ता रोक सकी। बल्कि इसलिए कि उसके पीछे जबरदस्त सगठन नहीं था और न उसके सामने आगे का कोई चेतनापूर्ण कार्यक्रम ही था। इससे यही नतीजा निकलता है कि हमारा तुरत का काम यह होना चाहिये कि चढ़ाई के लिए हम अभी से सगठन, अनुशासन और कार्यक्रम पर ध्यान दें। हमारे पास खोने के लिए एक क्षण भी नहीं है—इसलिए इसमें जल्दी करना चाहिये।

जयप्रकाश की विचारधारा

तैयारी के हर क्षेत्र में आपको सहायता की हमें आवश्यकता है। हमें गांवों में और औद्योगिक केन्द्रों में, रेलवे में और खानों में, सेना में और सरकारी मुलाजिमों में काम करना है। हमें साहित्य का प्रकाशन एवं प्रचार करना है, सम्पर्क और यातायात का प्रवर्धन करना है, सैनिक दस्तों की शिक्षा दीक्षा के बारे में सतक रहना है, कारीगरों को विध्वंस के कार्यों के लिए एकत्र करना है, और इन कामों के साथ शत्रु से कदम-कदम पर मुठभेड़ और छेड़खानी करते जाना है। केन्द्रीय कमांड के अधीन संगठन का एक जाल बनाने की कोशिश हो रही है। वर्तमान सम्पर्कों के आधार पर हम आपसे मिलेंगे और आपको योग्य कार्यों में लगावेंगे।

इन कामों में बहुत-से काम हैं, जिन्हें आप पढते हुए भी कर सकते हैं, जैसा कि कुछ लोग कर रहे हैं। मुझे आशा है कि दूसरी चढ़ाई के वक्त भी आप अगस्त की ही तरह क्रान्तिकारी सेना की अगली पांत में रहेंगे। किन्तु इस चढ़ाई में दुश्मन के पैर तुरत और सदा के लिए ठखड़ जायँ, इसके लिए जरूरी है कि आप गम्भीरतापूर्वक इन कामों में लग जायँ और संगठन को तुरत ही पुख्ता बना लें।

आपको बहुत काम करने हैं। इसलिए मैं आपका ज्यादा समय लेना नहीं चाहता। आपने हमें बड़ी बड़ी आशाएँ दिलाई हैं। इन आशाओं को पूरा करना आप ही का काम है। याद रखिये, संसार भर में आज नौजवान अपना हृदयरक्त अच्छे या बुरे उद्देश्यों के लिए प्रचुरता से उड़ेल रहे हैं। चालीस करोड़ मनुष्यों की आजादी से बढ़कर राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय, नैतिक या भौतिक दृष्टि से कोई दूसरा महान और पवित्र उद्देश्य नहीं हो सकता। मान-वता के पंचमाश की स्वाधीनता का योद्धा बनकर आप आजादी, शान्ति और उन्नति की अन्तर्राष्ट्रीय सेना के अग्रसेनानी सिद्ध करेंगे। संसार के कल्याण की कुंजी एशिया है और एशिया की कुंजी हिन्दोस्तान !

अपने विद्यार्थियों से

इसलिए, साथियो, बढ़ते चलो । खून, आसू और मेहनत—हमारी तकदीर में यही लिखे हैं, किन्तु इन्हींसे हमारी मातृभूमि और हमारी जनता की आजादी प्रस्फुटित होगी । हम स्वतंत्र हिन्दोस्तान की सृष्टि करेंगे, और एक नये ससार की !

इन्कलाव जिन्दावाद

हिन्दुस्तान के कोने से

जयप्रकाश नारायण

— — —

जगप्रकाश की विचारधारा

तीसरा खंड

सीखचों के अन्दर से

देवली के वे मशहूर खत

[जयप्रकाश जब देवली कैम्प जेल में थे, अपनी धर्म-पत्नी श्रीमती प्रभावती से मुलाकात करते समय कुछ खत बाहर भेजना चाहता था। खत पकड़ लिए गये थे और उन्हें भारत-सरकार ने बड़े धूम-धाम से प्रकाशित कराकर जयप्रकाश को हिन्दोस्तान का षड्यन्त्रकारी नंबर १ करार देने की कोशिश की थी। इन पत्रों को सरकार ने हिन्दोस्तान के प्रायः सभी पत्रों में छपवाया था और रेडियो द्वारा हिन्दोस्तान और ससार की विभिन्न भाषाओं में ब्रॉडकास्ट भी कराया था।]

मैंने तुम्हारे पास कल रात में दो खत भेजे थे और उसमें बताया था कि यदि तुम्हे ये दोनों खत मिल जायें, तो तुम मुझे यह लिखना, बबुनी के घर में सब लोग आनन्द से हैं, मुरार में भी और डाल्टेनगज में भी। किन्तु जब खड्वा से तुम्हारा खत पहुँचा और यह इशारा नहीं था तो मुझे कुछ चिन्ता हुई। पता लगाने से मालूम हुआ कि जो आदमी तुम्हे खत देनेवाला था, वह डर गया और उसे तुम्हें न देकर अपने पास ही रख लिया। जब मैंने उसे धमकाया, तो उसने वह खत मुझे वापस कर दिया है, और इसीलिए तुम्हे मैंने फिर बुल-

चाया है। तुम्हें इस खत को लेकर बंबई जाना है। तुम पुरुषोत्तम से कहना कि वह मुझे उन हिदायतों के मुताबिक खत लिखा करें, जिनका निर्देश मैंने अपने खतों में किया है। तुम भी इस तरीके को समझ लो। कोई पुरानी मोटी किताब ले लो, जिसकी जिल्द मोटी हो। जिल्द को उखाड़ डालो, उसके भीतर खत को रख दो, फिर किताब पर वह जिल्द चढ़ा दो और भेज दो।

बसावनजी और दूसरे साथियों को भी ऐसा ही करना चाहिए, यदि वे मेरे पास कोई खास खबर भेजना चाहते हों।

दो या तीन दूसरे किताबों में प्रेमचंदजी का एक उपन्यास भेजना चाहिए। इसी किताब में खत भेजना चाहिए। यदि दूसरी किताबों में चिट्ठी भेजी जाय तो उसके १०० वें पृष्ठ पर पेन्सिल से X का निशान बना देना चाहिए। मैं उस किताब की जिल्द फाड़कर चिट्ठी ले लूँगा, जिसपर वह निशान होगा।

बसावन को खबर करो; अब वो रूपोश हो जायँ। रूपोश होकर वह गुप्त पार्टी के लिए नौजवानों को भर्ती करें। इसके लिए पुराने तरीके से अर्थ संग्रह करना चाहिए। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई चारा नहीं है। शुक्लजी भी इस राय को पसंद करते हैं।

गुप्त पार्टी काँग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से अलग नहीं होगी; किन्तु उसका नाम अलग रखा जा सकता है।

गंगा बाबू से कहना कि यदि देश से बाहर जाने का प्रोग्राम सम्भव न हो सके, तो अखिल भारतीय पार्टी के संयुक्त मंत्री की हैसियत से काम करें। उन्हें प्रान्तों में दौरा करना चाहिए और ऑफिस को अच्छी तरह चलाना चाहिए।

हमलोगों ने इधर चार दिनों की भूख-हड़ताल की थी, जिसकी चर्चा मैंने अपने खत में की है। बंबई में इसको कॉपी कर लेना और अपने साथ

देवली के वे मशहूर खत

बापूजी के पास ले जाना । इस सम्बन्ध में इस खत में तीन कायजात हैं । इन तीनों की नकल तुम अपने साथ ले जाना ।

एन० एम० जोशी, एम० एल० ए० (केन्द्रीय) यहाँ आये थे । हमने उन्हें सब कुछ लिखकर दे दिया है । पुरुषोत्तम से कहना कि वह उनसे मिले और उसकी नकल भी बापूजी के पास ले आना । यदि वह पुरुषोत्तम को उसकी नकल न देना चाहें, तो बापूजी उन्हें इसके लिए लिख सकते हैं ।

मैं यह खत लेकर आया था कि तुमको ठे दूँ; लेकिन ऐसा नहीं कर सका ।- इसीलिए मैं इसे उसी आदमी के मार्फत भेज रहा हूँ । यदि यह खत तुम्हें मिल जाय, तो कल जब तुम मुलाकात करने के लिए आओ तो कहना कि रात मेरे सिर में दर्द रहा । इससे मैं समझ जाऊँगा कि तुम्हें मेरी चिट्ठी मिल गई ।

अगर तुम गफफार खाँ साहब से वर्धा में मिल सको, तो उनसे कह देना, हकीम अब्दुस्सलम साहब, जो हजार डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमीटी के सभापति हैं, यहीं पर दूसरे कैंप में रखे गये हैं । उनकी तन्दुरुस्ती अच्छी है, किन्तु उनके हाथ में दर्द होता है, जिससे गठिये का सदेह हो रहा है । खान साहब कृपा कर सलम साहब के घर पर खबर कर दें कि वह यहाँ अच्छी तरह से हैं । सलम साहब की एक शिकायत यह है कि उनकी चिट्ठियाँ उनके घर पर दो-तीन हफ्ते के बाद मिला करती हैं । उन चिट्ठियों का सेन्सर यहाँ तो होता ही है, सरहद की सी० आई० डो० भी सेन्सर करती और काफी वक्त लगा देती है । इसके खिलाफ सरहद के पत्रों में समाचार और टिप्पणी निकलनी चाहिए । उनकी एक दूसरी शिकायत भी है, उन्हें सरहद का कोई भी अखबार पढ़ने को नहीं मिलता । अगर खान साहब से तुम्हारी मुलाकात न हो, तो बापूजी से एक पुर्जा उनके पास भेजवा देना ।

पुरुषोत्तम के लिए

(क) यहाँ की स्थिति

यह डिटेन्शन कैम्प मुख्यतः कम्युनिस्टों के लिए सुरक्षित है। इसलिए यहाँ पर ज्यादातर कम्युनिस्ट ही हैं।

यहाँ दो कैम्प हैं—कैम्प नं० १ और कैम्प नं० २ हैं; कैम्प नं० १ में पहले दर्जे के नजरबंद हैं और कैम्प नं० २ में दूसरे दर्जे के।

कैम्प नं० १ में १०४ राजबंदी हैं, जो ज्यादातर यू० पी० से आये हैं। उनमें ६६ कम्युनिस्टों के गिरोह में हैं और बकिये ३८ में ८ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के, ११ आर० एस० पी० के, ५ एच० एस० आर० ए० और १४ फुटकर लोग हैं, जो रायवादी, टैगोराइट, लेबर पार्टी, फारवर्ड ब्लॉक आदि के हैं।

कम्युनिस्ट गिरोह के ६६ नजरबंदों में ३५ जेल के बाहर से ही कम्युनिस्ट पार्टी के मेम्बर हैं, बाकी लोग मेरे आने के पहले ही उनमें शामिल हो गये हैं। ऐसे लोगोमें प्रमुख हैं बी० पी० एल० वेदी, तिलकराज चड्ढा, कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह। पिछले दो नौजवान भगत सिंह के भाई हैं, और ये सब पहले कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य थे।

कम्युनिस्ट पार्टी के लीडरों में यहाँ भारद्वाज, अजय, मीरजकर, अहमद और डांगे कैम्प नं० १ में हैं।

कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं में यहाँ गौतम हैं, जेतली हैं और मैं हूँ। बिहार के सभी साथी मेरे अतिरिक्त कैम्प नं० २ में हैं।

आर० एस० पी० के नेताओं में योगेश बाबू और केशव शर्मा हैं।

एच० एस० आर० ए० एक छोटा-सा गिरोह है। उसमें अच्छे आदमी नहीं हैं और उनके बारे में कुछ विशेष कहना नहीं है।

कैम्प न० २ में ९० नजरबंद हैं, जिनमें ७२ कम्यूनिस्टों के गिरोंह में हैं। ६ या ७ राजनोति से कोई सरोकार नहीं रखते। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख लोगोंमें वहाँ यागेन्द्र शुक्ल, सूर्यनारायण, श्यामाचरण भर्तृहार आदि हैं। कुछ लोग स्वतंत्र विचार के हैं और कुछ लोग फारवर्ड ब्लॉक, अकाली, बम्बर अकाली और कांग्रेस आदि से सरोकार रखते हैं। जिस तरह कैम्प न० १ में ज्यादातर यू० पी० के लोग हैं, उसी तरह कैम्प न० २ में ज्यादातर पंजाबी लोग हैं।

अब हम कम्यूनिस्ट पार्टी के गिरोंह को देखें। इस सम्बन्ध में दो प्रमुख बातें हैं। पहली बात तो यह है कि कीर्त्ति किसान पार्टी ने अपने को कम्यूनिस्टों में विलीन कर दिया है। इसके पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि कैम्प से निकलने पर भी यह एकता कायम रहेगी। किन्तु आज तो वे घुले-मिले दीखते ही हैं। उनकी संख्या १२ है।

दूसरी बात यह है कि पंजाब के साथी कम्यूनिस्टों से जा मिले हैं। सागर, मंगोराम वत्स, रिछपाल सिंह, ठाकुर गोविन्द सिंह और तीन दूसरे, जिन्हें आप जानते हैं, कैम्प न० २ में हैं। इसमें सागर का बहुत जबरदस्त हाथ रहा है और हमारे दोस्त क्रिश्नोरी ने भी उनका हाथ बँटाया है। क्योंकि यहाँ आकर उन्होंने लोगोंसे कहा कि हजारीबाग में मेरी भी कुछ ऐसी ही राय थी। पीछे चलकर किशोरी भी उनके गिरोंह में चले गये। उनके बारे में विशेष पीछे।

यह अफसोस की बात है कि मैं देवली में दो महीने पहले नहीं आ सका। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि घबराया जाय या उदास हुआ जाय। जबसे मैं यहाँ आया हूँ पंजाब के साथियों से मेरी बात चल रही है। उनमें सिर्फ ठाकुर गोविन्द सिंह को हमने सदा के लिए खो दिया है। बाकी

जयप्रकाश की विचारधारा

सब लोगोंने बताया है कि उनका यह निर्णय अंतिम नहीं है और जेल से छूटने के बाद हिन्दोस्तान और पंजाब के दोस्तों से मिलकर अंतिम निर्णय करेंगे। तिलकराज, रिछपाल, वत्स, ये बड़े प्रमुख सदस्य हैं और ये सब कम्यूनिस्ट पार्टी से ऊब उठे हैं और उनलोगों ने तो तय कर रखा है कि जेल से बाहर जाते ही कम्यूनिस्ट पार्टी से अलग हो जाने की बात वे जोरो से उठावेंगे और उन सभी साथियों का विरोध करेंगे, जो कम्यूनिस्टों के साथ रहना चाहते हैं। कुलदीप, कुलतार और कैम्प नं० २ के और साथी भी इसी विचार के हैं। वेदी की स्थिति क्या है, मैं लिखना भूल गया। वह डाँगे और रणदिवे से बहुत प्रभावित हुए हैं। कम्यूनिस्टों के साथ गहरी दोस्ती कर ली है। राजनीतिक दृष्टि से उनकी स्थिति सागर ऐसी है। किन्तु जहाँ सागर गहरा है, वहाँ वेदी छिछले हैं और उनमें विचारों की स्थिरता भी नहीं है। सागर कोई नया रुख लेने को तैयार नहीं तो जो कुछ उसने किया है उसका ज्यादा महत्व भी नहीं देते। इसमें सन्देह नहीं कि पंजाब के साथियों का बहुमत जेल से अलग होने पर कम्यूनिस्टों का साथ छोड़ देने के पक्ष में है। मैंने सलाह दी है कि यहाँ उन्हें छोड़ दो। किन्तु जब तक मुंशीजी नहीं आते, तब तक कोई निर्णय नहीं हो सकता। हम मुंशीजी के इन्तजार में हैं। मेरे साथ पंजाब के जो साथी हैं वे नहीं चाहते कि यहाँ उनके गिरोह में फूट पड़े। ऐसा होने से बाहर जाने पर काम में कठिनाई होगी, ऐसी उनकी धारणा है। अब जो कुछ होना है, मुंशीजी के आने पर ही।

मैं नहीं चाहता कि ये खबरें पंजाब या दूसरी जगहों के पार्टी मेम्बरों में फैलें। मैंने ये खबरें इसलिए दे दी हैं कि तुम होशियारी से जरूरत होने पर इस्तेमाल कर सको। तुम किस तरह करोगे, मैं नहीं जानता; किन्तु इसमें पूरी सावधानी रखनी चाहिए, इसकी ताकीद कर देता हूँ।

अब कुछ शब्द किशोरी के बारे में। उन्होंने यह अच्छी तरह साबित

कर दिया है कि उनमें आत्मविश्वास की पूरी कमी है ! पंजाब के साथियों से पहले ही वह कम्यूनिस्टों के साथ हो गये । मुझे उन्होंने एक ही कैफियत दी कि वे अपने को अलग अलग रखना पसंद नहीं करते थे । उन्होंने यह भी विश्वास दिलाया है कि उनका निर्णय अंतिम नहीं है । किन्तु, मैं उनपर विश्वास नहीं करता । वह मुझसे एक बात कहते हैं और दूसरों से दूसरी । वह लोगोंमें यह भी प्रचार करते फिरते हैं कि जयप्रकाश कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को इसलिए पकड़े हुए हैं कि उनकी नेतागिरी बनी रहे । उन्होंने शुक्लजी पर भी बहुत दबाव डाला कि वे कम्यूनिस्टों से आ मिलें । किन्तु शुक्लजी चट्टान की तरह अटल रहे । शुक्लजी की राजनीतिक सूझ और दृढ़ता देखकर मेरी तो उनपर अन्यतम श्रद्धा हो चली है । बिशोरी ने जो धोखा दिया है, उसकी खबर बिहार के साथियों को हो जानी चाहिए; किन्तु ऐसा न हो कि लाभ के बदले हानि ही पहुँचे ।

कम्यूनिस्टों की चर्चा खतम करने के पहले यह कह देना जरूरी है कि उनका व्यवहार बिल्कुल शत्रुओं के ऐसा और बचपना लिये होता है । जब मैं यहाँ आया, तो उन्होंने मेरा स्वागत दिल खोलकर किया और अजयघोष आकर मुझे कम्यूनिस्ट पार्टी में शामिल होने के लिए दावत भी दे गये । तुम कल्पना कर सकते हो कि उनमें और मुझमें क्या बातें हुईं । सबसे मजेदार बात तो यह रही कि अजय ने कहा कि लड़ाई शुरू होने के बाद हमने यह निर्णय किया है कि इस देश में कम्यूनिस्टों को छोड़कर कोई भी वामपक्षी या समाजवादी नहीं है । इसलिए समाजवादी एकता या वामपक्षियों की एकता का कोई मानी ही नहीं रद्द गया । उन्होंने बताया कि अब हमारा नारा है— जनता की कम्यूनिस्ट पार्टी । एक चीज मैं भूल रहा था । कम्यूनिस्ट पार्टी के जो लोग मेरे कैम्प में हैं, सबके सब बच्चे हैं और बाहर उनका कोई महत्त्व नहीं है । कैम्प न० २ में कीर्ति के पुराने सिक्खे लगे हैं ।

जयप्रकाश की विचारधारा

अब हम आर० एस० पी० पर आवें। मेरे यहाँ आने के पहले उनका रुख सतोषजनक नहीं था। वे लोग अपनी पार्टी में लोगोंको भर्ती करना चाहते थे, इसलिए वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की निन्दा किया करते थे। सिर्फ डाक्टर जेतली अपनी जगह पर मजबूती से खड़े रहे। किन्तु, जब से मैं आया हूँ, उनका रुख बदल गया है। मैंने उनसे कहा कि हमलोगों में एकता होनी चाहिये; यहाँ और बाहर भी। तुम्हें याद होगा कि जब मैं बाहर था, प्रतुल बाबू से भी मैंने ऐसा ही कहा था। इस सम्बन्ध में मैं तुमपर यह स्पष्ट प्रकट कर देना चाहता हूँ कि मेरे विचार से आर० एस० पी० को हमें अपने में मिला लेना ही है और इसकी पूरी संभावना है। बंगाल में उनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। यह बात मैं बंगाल के साथियों के बावजूद कह रहा हूँ। आर० एस० पी० के मिलने का मेरा मतलब यह है कि ये लोग कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो जायें। पार्टी का कानूनी नाम सी० एस० पी० ही रहे। किन्तु उसकी एक गैरकानूनी शाखा भी हो, जो दूसरे नाम से काम करे। अब यह मेरा विश्वास हो चला है कि कम्यूनिस्टों के खिलाफ सफलतापूर्वक खड़े होने के लिए हमें एक गैरकानूनी संगठन करने और कुछ गैरकानूनी कार्रवाईयाँ करते रहने की बड़ी जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि बंगाल की आर० एस० पी० से सम्पर्क बढ़ाया जाय और उनसे हार्दिक मित्रता का भाव रखा जाय।

एच० एस० आर० ए० के जो अच्छे लोग हैं, उनसे मैं सम्पर्क बढ़ा रहा हूँ और उनमें से दो तो हमारे साथ हो गये हैं।

जहाँ तक कैम्प की जिन्दगी और वर्गीकरण का सवाल है, कैम्प के सभी लोग, सिवा कम्यूनिस्टों के, हमारे साथ हैं।

कैम्प न० २ में कुछ स्वतंत्र विचारवाले लोग हममें शामिल हो गये हैं। मैं खेल के मैदान में उनके लिए और अपने साथियों के लिए प्रातःकाल एक

देवली के वे मशहूर खत

क्लास किया करता हूँ। यहाँ आपको यह बताना जरूरी है कि दोनों कैम्पों के लोगोंको पहले मिलने का हुक्म नहीं था। किन्तु, एक महीने से यह को आज्ञा मिली है कि हम खेल के मैदान में भोर को ७ से ८ तक और शाम ६ से ९॥ तक मिल सकते हैं।

पंडित धनराज शर्मा कम्यूनिस्टों से बहुत बिगड़े रहते हैं और मेरे क्लास में आते हैं। वह हम लोगोंके साथ मित्रता का व्यवहार रखते हैं, किन्तु अवधेश्वर आदि कुछ लोगोंके प्रति उनकी शिकायतें भी हैं। बिहार किसान सभा में जो कुछ हो रहा है, उससे वे दुःखित हैं और इस बात पर हमसे सहमत हैं कि बाहर जाकर हमें एकता कायम करनी चाहिए।

(ख) कैम्प का जीवन

साधारणतः यहाँ के सम्बन्ध में शिकायत की कोई बात नहीं है। हम-लोग बैरिकों में रहते हैं, जिनमें ४ या ५ बड़े-बड़े कमरे हैं। हर कमरे में आठ-दस आदमियों के लिए जगह है। कुछ छोटे-छोटे कमरे भी हैं, जिनमें दो या चार आदमी रहते हैं। मैं जिस कमरे में हूँ, उसमें १० आदमी रहते हैं।

जब मैं यहाँ आया, यहाँ की स्थिति गंभीर हो रही थी। भूख-हडताल करने की तैयारियाँ जारी थीं। हमारे लोग और आर० एस० पी० वालों की भी यह राय थी कि कम्यूनिस्ट पार्टी वाले इस भूख-हडताल का इस्तेमाल प्रचार के लिए करना चाहते हैं। उनका कहना था कि वे इस भूख-हडताल में तभी शामिल हो सकते हैं, जब कम्यूनिस्ट लोग यह विश्वास दिलावें कि यह भूख-हडताल तब तक नहीं तोड़ी जायगी, जब तक हमारी कम से कम माँगें पूरी नहीं की जाती। किन्तु कम्यूनिस्ट माँगों के बारे में गंभीर नहीं थे, वे तो सिर्फ प्रदर्शन करना चाहते थे। इसलिए वे लोग अपनेको किसी माँग से

बांधना नहीं चाहते थे और न लड़ाई के बारे में वे गंभीर थे। जब मैं आया, तो मैंने सलाह दी कि भूख हड़ताल का अल्टीमेटम देने के पहले कैम्प के अधिकारियों से समझौता शुरू करना चाहिए। समझौते के लिए कैम्प नं० २ के रोजाना ॥—) भत्ते को बढ़ाकर ॥—) कर दिया गया, दोनों कैम्पों में मिलने की सहूलियत दी गई, गर्मी के लिए खास कपड़े, पखे आदि के प्रबंध का बचन मिला। इन मांगों की स्वीकृति से तैयारी में कमजोरी आ गई; उधर बाहर से कम्यूनिस्टों की खबर आई कि तब तक भूख हड़ताल मत करो, जब तक स्कूल-कॉलेज खुल नहीं जाते और केन्द्रीय असेम्बली की बैठक नहीं शुरू हो जाती। इसका मतलब यह था कि वे तब तक रुके रहे, जब तक स्टूडेंट फेडरेशन और श्री एन० एम० जोशी उनके इस 'महान संघर्ष' के लिए प्रचार करने को तैयार न हो जायें। शीघ्र ही भूख-हड़ताल का जोश-खरोश खतम हो गया।

किन्तु कुछ घटनाओं ने हमें भूख हड़ताल करने को बाध्य हो कर दिया, जिसमें कम्यूनिस्टों ने हमारा साथ नहीं दिया। हाँ, जब एक दिन तक हमारी भूख हड़ताल चल चुकी थी, तब उन्होंने अधिकारियों को सूचित कर दिया कि अब वे भी भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। उनकी मांगें भी मामूली थीं और हमारी भूख-हड़ताल चल ही रही थी कि उन्होंने अपना अल्टीमेटम वापस कर लिया। इस तरह उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया और जान-बूझकर हमें कमजोर करने की कोशिश की। किन्तु, अधिकारियों की हमारे सामने झुकना पड़ा, हमारी मांगें मंजूर की गईं और पाँचवें दिन हमने भूख-हड़ताल तोड़ दी।

(ग) पार्टी का केन्द्रीय संगठन

ऐसा मालूम होता है, जबसे तुम पटना से लौटे, फिर न वहाँ गये और न रुक्ये ही भेजे। जब बिहार के साथ यह हालत है, जहाँ कि सबसे ज्यादा

काम होता है, तो दूसरे प्रान्त की और भी बुरी गत होगी। यह बहुत बुरी बात है। केन्द्र को चाहिए कि वह खुद अच्छी तरह काम करे और दूसरो से करावे। मेरी राय है कि गंगा वावू को सयुक्त मंत्री बना दो और उन्हें बर्बई में ला रखो। मेरा ख्याल है, बदली हुई हालत में उनके सम्बन्ध को दूसरी योजनायें त्याग दी गई होंगी।

प्रान्तीय शाखाओं को नियमित आर्थिक सहायता देना सबसे ज़रूरी है। तुम्हें यह इन्तजाम करना ही है।

(घ) पार्टी का प्रचार

अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति और कम्यूनिस्टों की स्थिति से फायदा उठाना चाहिए और अपने प्रचार-कार्य को जोरों से बढ़ाना चाहिये। यह सुनहला मौका है, इसे खोना नहीं चाहिये। बाहर के सभी साथियों को ज्यादा से ज्यादा इस ओर ध्यान देना चाहिये।

(ङ) हमारी राजनीतिक नीति

मैंने अखबारों में पढ़ा है कि तुमने सत्याग्रहियों की सूची से नाम कटा लिया है। मैंने इसे पसंद किया है। लेकिन तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिये कि पार्टी के राजनीतिक पथ को लोग समझे और चले और यह अनुभव करे कि सत्याग्रह के खेलवाड़ से मेरा यह पथ अधिक प्रशस्त है। मैं जोरदार ढंग से यह सोचने लगा हूँ कि इस मौके पर हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिये कि लोगोका ध्यान हमारी ओर आकृष्ट हो। हम कोई काम ऐसा न कर सकें सही, लेकिन हमें कुछ राजनीतिक महाजनी तो करनी ही चाहिये। यदि ऐसा करते हुये तुम में से ज्यादा लोग जेलों में चले जायें, तो भी कोई परवाह की बात न होगी। इस सम्बन्ध में मुझे बिहार की याद बार बार आती है।

जयप्रकाश की विचारधारा

किसान-सम्मेलन करने के बजाय कुछ चुने हुये क्षेत्रों में किसान-सर्घर्ष शुरू करना चाहिये या कुछ ऐसे काम, जो सिर्फ आन्दोलन न हो ।

बिहार के अतिरिक्त अखिल भारतीय आधार पर कुछ काम होने चाहिये, जिनपर देश का ध्यान आकृष्ट हो और जिनसे नौजवानों में जोश आये । कुछ ऐसी चीज सोचो ।

पार्टी की एक गुप्त शाखा जरूर संगठित की जाय और दूसरा नाम रखा जाय । क्रान्तिकारी श्रमजीवी पार्टी या इसी तरह का कोई नाम चुना जाय । पंजाब की पार्टी कम्युनिस्ट लीग के नाम से गैरकानूनी काम कर रही है और बोल्शेविक नाम से एक गुप्त अखबार भी निकाल रही है । एक अखिल भारतीय गुप्त अखबार का निकालना, कुछ नहीं तो युवकों को आकृष्ट करने के लिए जरूरी ही है ।

(च) टेक्नीकल बातें

यह दुःख की बात है कि तुमलोगों ने हमसे सम्पर्क कायम करने की कोई कोशिश नहीं की है । यह कोई मुश्किल बात नहीं है । गंगा बाबू यहाँ कुछ दिन रह चुके हैं, उनको फिर यहाँ भेजो कि इसके लिए इन्तजाम करे । वह अजमेर जा सकते हैं और वहाँ के दोस्तों से मिलकर देवली के लोगों से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं । कुछ रुपयों की जरूरत होगी और थोड़े संगठन की । देवली गाँव के कोई आदमी बीच-बिचाव का काम करने को तैयार हो जायँ, तो यह काम और आसान हो जाय । गाँव से हर हफ्ते दजी, धोबी, मोची, कैम्प में आते हैं । कैम्प के होस्टल में भी कुछ बच्चे काम करते हैं । वे बहुत गरीब हैं और इनमें कुछ की सहायुभृति हमारा ओर हो सकती है । थोड़ा समझाने-बुझाने और कुछ रुक्या खर्च करने से यह काम आसानी से हो सकता है । कम्युनिस्टों ने नियमित सपर्क कायम कर लिये

हैं। जब तक नियमित सपर्क विकसित नहीं होता, तब तक के लिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ। इस चिट्ठी का जवाब मुझे चाहिए। कोई उपन्यास ले लो, उसकी जिल्द को उघाड़ डालो, फिर उसके अंदर चिट्ठी रखकर किताब पर मढ़वा दो। इस किताब के साथ दो-तीन किताबें और भेजो, लेकिन अन्य पुस्तकें उपन्यास की न हों, जिससे मुझे पता चल जाय कि किस किताब की जिल्द मुझे खोलनी है। यदि संभव हुआ, तो मैं भी इस तरीके से तुम्हारे पास लिखूँगा।

मुझे कुछ गंभीर सलाह भी देनी है; लेकिन यह तभी संभव है, जब सपर्क पक्का हो जाय। तब तक मैं उपन्यास की प्रतीक्षा में हूँ।

क्या युद्ध अविभाज्य है ?

[जयप्रकाश ने यह लेख गुप्त रूप से हजारीबाग जेल से भेजा था और 'एक कांग्रेस समाजवादी' के नाम पर यह प्रमुख पत्रों में छपा था ।]

स्टालिनवादियों के, जो कि इस लड़ाई में ब्रिटिश सरकार की बिना शर्त मदद करने की नीति का समर्थन कर रहे हैं, दो मुख्य तर्क हैं—पहला यह कि यह 'जनता का युद्ध' है, और दूसरा यह कि यह युद्ध अविभाज्य (indivisible) है ।

जनता के युद्ध के प्रश्न पर लिखते हुए आचार्य नरेन्द्रदेव ने यह दिखा-लाया है कि जहाँ तक ब्रिटेन और अमेरिका का सम्बन्ध है, इस युद्ध के लिये 'जनता का युद्ध' बनना अभी बहुत दूर की बात है और इन देशों के लिये अभी यह ऐसा ही युद्ध बना हुआ है, जो कि उनके विशाल साम्राज्यों—राज-नीतिक तथा आर्थिक—तथा विश्वप्रभुत्व की उनकी स्थिति को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये लड़ा जा रहा है । •

अब हम यहाँ युद्ध की अविभाज्यता के प्रश्न की विवेचना करें । पहली बात यह है कि इस शब्दावली का अर्थ क्या है ? जब स्टालिनवादो यह कहते हैं कि यह युद्ध अविभाज्य है, तब उनके कहने का अर्थ यह होता है कि प्रत्येक मोर्चे के परिणाम से सोवियत रूस के स्वार्थ सम्बद्ध हैं । बर्मा, लांबिया अथवा एटलाण्टिक के मोर्चों में मिली कोई विजय सोवियत रूस के लिये उतनी ही महत्वपूर्ण है, जितनी कि स्मोलेंस्क में हुई जीत ।

क्या युद्ध अविभाज्य

वे लोग कुछ इस तरह की दलील पेश करते हैं—कम्यूनिस्ट होने के नाते हमें अवश्य ही सोविएत रूस को मदद पहुँचाने में जल्दी करनी चाहिए। लेकिन चूँकि हिन्दोस्तान ब्रिटेन के अन्तर्गत एक पराधीन देश है, इसलिये प्रत्यक्ष रूप से रूस की सहायता करने के लिये हम स्वतन्त्र नहीं हैं। प्रत्यक्ष रूप से हम केवल ग्रेट ब्रिटेन की मदद कर सकते हैं। किन्तु चूँकि युद्ध अविभाज्य है इसलिये जो कुछ मदद ब्रिटेन को दी जायगी, वह रूस की मदद होगी और चूँकि रूस की सहायता करते हुए हम किसी शर्त को बात नहीं सोच सकते, इसलिये हम ब्रिटेन को जो कुछ मदद दें, वह निस्सकोच और बिना शर्त के दी जानी चाहिये। संक्षेप में स्टालिनवादियों की यही दलील है, यद्यपि इसका निरूपण करने में और अपनी इससे पूर्व की नीति की गलतियों को मालूम करने में रूस-जर्मन युद्ध छिड़ने के बाद ६ महीने से अधिक उन्हें लगे।

जहाँ तक राष्ट्रीय भारत का सम्बन्ध है, यह स्पष्ट है कि यह तर्क इतनी घृणोत्पादक है कि उसपर विचार भी नहीं किया जा सकता। इसपर किसी को भी तर्कवितर्क करने की आवश्यकता नहीं। यह एक ऐसी वास्तविकता है, जिसके तथ्य को कोई भी व्यक्ति, जो कि ज्ञान-बुद्धिमान अन्धा नहीं बनना चाहता, स्वयमेव देख सकता है। यहाँ तक कि पण्डित जवाहरलाल नेहरू जैसे राष्ट्रीयतावादी व्यक्ति को भी, जिनकी अन्तर्राष्ट्रीय सहानुभूति गहरी और स्पष्ट है, विवश होकर कम्यूनिस्ट नीति को देशद्रोही कहना पड़ा है।

अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण

अब इस तर्क पर समाजवादी तथा मार्क्सवादी दृष्टिकोण से विचार करना शेष रह जाता है। स्टालिनवादो कहते हैं कि हम यह स्मरण रखें कि हमें सभी भ्रमपूर्ण कल्पनाओं (illusions), राष्ट्रीय धारणाओं से मुक्त होना

जयप्रकाश की विचारधारा

चाहिये और अपने अन्तर्राष्ट्रीय कर्तव्य का पूर्णरूप से पालन करना चाहिये ।

हिन्दुस्तान जैसे मुल्क में एक समाजवादी के लिये राष्ट्रवादिता भ्रमपूर्ण कल्पनामात्र नहीं है । यह एक कठोर यथार्थता है, जिसको उपेक्षा भारतीय समाजवादी समाजवादो आन्दोलन को भीषण हानि पहुँचाकर हो कर सकते हैं । इसके अतिरिक्त भारत की राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रश्न है । दुनिया की जनसंख्या के पचमांश की स्वतंत्रता का ससार के इतिहास पर और विशेषकर विश्वव्यापी साम्राज्यशाही पर निर्णयकारी प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता ।

ग्रेट ब्रिटेन के साम्राज्यशाही भवन की हिन्दुस्तान ही प्रधान आधार-शिला है, जिसके हटते ही सारा महल चक्रनाचूर होकर धराशायी हो जायगा । और, ब्रिटिश साम्राज्य के चक्रनाचूर होने का अर्थ यह होगा कि दुनिया की एक सबसे बड़ी प्रतिक्रियावादी शक्ति नष्ट हो जायगी । इस प्रकार हिन्दोस्तान की आज़ादी दुनिया भर के किसान-मज़दूरों तथा उत्पीड़ित जनता को लक्ष्य-प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ानेवाला एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा और साम्राज्यशाही दासनों से प्रत्यक्ष रूप में लाखों, करोड़ों जनता जो मुक्त होगी वह अलग से ।

ऐसी स्थिति में हिन्दोस्तान में भ्रमपूर्ण राष्ट्रीय धारणाओं (nationalist illusions) की बात करना मार्क्सवाद को हास्यास्पद बनाना है । एक मार्क्सवादी को अनिवार्य रूप से सदैव यह स्मरण रखना चाहिये कि आत्याचारी देशों की जनता की राष्ट्रीयता और उत्पीड़ित देशों की जनता की राष्ट्रीयता में अन्तर है । हिन्दोस्तान की आज़ादी के लिये प्रयत्नशील भारतीय समाजवादी उसी प्रकार अपने अन्तर्राष्ट्रीय कर्तव्य की पूर्ति कर

क्या युद्ध अविभाज्य है ?

रहा है, जिस प्रकार वह बन्दूक ले और रूसी भोचों पर नाज़ियों से लड़ने के लिये जाय ।

आइये, अब हम स्टालिनवादियों के तर्क को लें । जहाँ तक रूस को मदद देने का सवाल है, उसपर मतभेद नहीं हो सकता । प्रत्येक समाजवादो का यह कर्तव्य है कि वह रूस की मदद करे । मेरा विश्वास है कि हिन्दो-स्तान के अनेक राष्ट्रवादी—क्योंकि हमारा राष्ट्रीयता मूलतः प्रगतिशील है—प्रसन्नतापूर्वक रूस की मदद करने के लिये जायेंगे । याद रखना चाहिये कि वह कांग्रेस ही थी, जिसने कि चीन और स्पेन को जो कुछ भी सहायता पहुँचाना सम्भव था, पहुँचाया था । कांग्रेस ने प्रसन्नतापूर्वक रूस को इस प्रकार की या इससे भी अधिक सहायता भेजी होती, परिस्थितियाँ यदि ऐसा करने की अनुमति देती ।

यहाँ स्टालिनवादियों को युद्ध को अविभाज्यता की दलील उन्हे आश्रय देती है । चूँकि युद्ध अविभाज्य है, इसलिये रूस के किसी युद्ध के साथी को दी गयी सहायता का अर्थ रूस की सहायता है ।

अविभाज्य शान्ति नहीं, क्रान्ति

इसलिये जिस प्रश्न की हमें समीक्षा करनी है वह यह है—क्या ब्रिटेन को दी गयी मदद का अर्थ है रूस को मदद करना ? अर्थात् क्या युद्ध वास्तव में अविभाज्य है ? दुर्भाग्यवश स्टालिन को सरकार अर्से से ऐसी चीजों में अविभाज्यता पाने के प्रयत्न में है, जो कि स्वयं समाज के वर्गमूलक स्वरूप के कारण विभाज्य है और जो कि उनके प्रयत्न के पश्चात् विभाज्य प्रमाणित हुई है । दूसरी तरफ उक्त सरकार ने उस एकमात्र वस्तु की अविभाज्यता की उपेक्षा की है, जो कि आज की दुनिया में वास्तव में अविभाज्य है । यह वस्तु विश्वक्रान्ति है । मजदूर-क्रान्ति (उत्पीडक देशों में) तथा राष्ट्रीय क्रान्ति

(उन देशों में जो कि उत्पन्न हैं) उसके दो पूरक (complimentary) अंग हैं। सोविएट सरकार ने जानबूझकर क्रान्तिकारी कार्यकर्ताओं में फूट डालने की कोशिश की है और उनमें भ्रम और हतोत्साहिता फैलायी है।

कुछ वर्षों तक स्टालिन सरकार का अलीशान नारा यह था कि “शान्ति अविभाज्य है”। जब ब्रिटिश साम्राज्यशाही ने, चेम्बरलेन और उनके साथियों के नेतृत्व में, ऊपर बतलाये गये कारण के आधार पर अर्थात् यह कि दुनिया की सामाजिक व्यवस्था वर्गमूलक है और पूँजीवाद और समाजवाद में तथा प्रतिद्वन्द्वी पूँजीप्रणालियों के आपस के स्वार्थों में विरोध है—यह निर्णयात्मक रूप से प्रमाणित कर दिया कि शान्ति अविभाज्य है तो बेचारे लिटविनाफ को हटाया गया और स्टालिन ने हिटलर के साथ समझौता करके सुरक्षा का प्रयत्न किया और मोलोटोव ने बिना किसी हिचक के घोषणा की कि यूरोप के सुख शान्ति के लिये एक शक्तिशाली जर्मनी को जरूरत है। फिर भी उस घंषणा के चन्द महीनों के भीतर मोलोटोव के ‘शक्तिशाली जर्मनी’ ने शीघ्रता के साथ फ्रांस के विरुद्ध अपनी शक्ति का प्रमाण देने के बाद रूस की ही शान्ति और सुरक्षा पर जबरदस्त धावा बोल दिया और सर्वतोमुखी युद्ध के महानाश में उसे रौंद डाला।

अविभाज्य शान्ति भग हो गयी और अविभाज्य समझौता छिन्न भिन्न हो गया। अब हम एक अविभाज्य युद्ध के मध्य में हैं और आज तक जो लोग किसान मजदूर क्रान्ति के सैनिक थे वह आज ब्रिटिश साम्राज्यशाही के फौज भर्ती मुहकमे के अफसर बनने को ललायित हैं।

अविभाज्यता का अर्थ

किसी हालत में कोई युद्ध अविभाज्य होता है? उस समय जब कि प्रत्येक युद्धलिप्त राष्ट्र में युद्ध देश के प्रश्न पर मतैक्य हो। मान लीजिये कि

क्या युद्ध अविभाज्य है ?

केवल एक राज्यशक्ति दूसरी राज्यशक्ति से लड़ रही है। इस हालत में यह युद्ध प्रत्येक पक्ष के लिये अविभाज्य है; लेकिन केवल उसी समय तक, जब तक प्रत्येक पक्ष के लोगोंका लक्ष्य समान है और जब तक कि युद्धोद्देश्यों के बारे में तथा लड़ाई करने की आवश्यकता के बारे में जनता तथा उनकी सरकार में मतैक्य है। वर्तमान युद्ध में तो दोनों पक्ष में एक से अधिक राज-शक्तियाँ हैं। धुरी राष्ट्रों के पक्ष को ओर दूसरे पक्ष को अपेक्षा कहीं अधिक मतैक्य है। किन्तु वह मतैक्य केवल धुरी राष्ट्रों के शासकों में है। फिर भी जिस हद तक जनता और शासकों में युद्धोद्देश्य के प्रश्न पर मतभेद है, उस हद तक धुरी राष्ट्रों के लिये युद्ध विभाज्य हो जाता है।

मित्र राष्ट्रों के पक्ष की ओर हम दो साम्राज्यशाही ताकतें पाते हैं, जो दोनों ही विश्वव्यापी पूँजीवाद के नायक हैं और उन्हींके साथ हम एक समाजवादी सरकार को भी पाते हैं। क्या इस प्रकार के परस्पर विरोधी सामा-जिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं के दम्यन कभी युद्धोद्देश्यों में समानता हो सकती है ?

वर्तमान युद्ध की अविभाज्यता की विवेचना करते हुए हमने कहा था कि युद्ध अविभाज्य उसी हालत में कहा जा सकता है, जबकि प्रमुख युद्धलिंग राष्ट्रों के उद्देश्य समान हों। अब हम देखेंगे कि मित्र राष्ट्रों के उद्देश्य क्या हैं।

अब आइये, हम मित्र राष्ट्रों के युद्धोद्देश्यों की विवेचना करें। जब ब्रिटेन ने जर्मनी पर आक्रमण किया, तब पौलैण्ड के लिये सहायुभूति की भावना से उत्प्रेरित होकर वह युद्ध में नहीं सम्मिलित हुआ और न तो उसने दुनिया को नाजीवाद से छुटकारा दिलाने के लिये ऐसा किया, बल्कि उसने ऐसा एक पूँजीवादी प्रतिद्वन्द्वी को बहुत आगे बढ़ जाने और अत्यधिक शक्तिशाली बन जाने से रोकने के लिये किया। दूसरे शब्दों में, ब्रिटेन ने अपने सुदूर

जयप्रकाश की विचारधारा

विस्तृत साम्राज्य पर आंच न आने देने, आक्रमणकारियों को उसका अपहरण करने से दूर रखने और युरोप के शक्ति-सन्तुलन को कायम रखने के लिये ऐसा किया ।

यहाँ यह बात ध्यान में रखना प्रासंगिक होगा कि जर्मनी में हमेशा साम्राज्यवादियों के दो दल रहे हैं । एक दल युरोप के बाहर उपनिवेश प्राप्त करने का पक्षपाती रहा है और दूसरा, उग्रदल, युरोप में ही, विशेषकर मध्य और पूर्व युरोप में, साम्राज्य-वृद्धि में विश्वास करता आया है । पिछले महायुद्ध में इस उग्रपक्ष का प्रतिनिधित्व करनेवाले ल्युडेनडार्फ और हाफमान थे । आज-कल उग्रपक्षवालों का नेता हिटलर है । हिटलर की सफलता युरोप के उस शक्ति-सन्तुलन के लिये घातक सिद्ध हुई, जिसे ब्रिटेन और फ्रांस दोनों मिलकर बनाये रखना चाहते थे ।

अमेरिका का उद्देश्य

अमेरिका जानते से युद्ध में जापान के हमले के बाद ही शामिल हुआ है । लेकिन अमेरिका पहले से ही पूरी तरह ब्रिटेन, जिसकी पूँजीवादी व्यवस्था के साथ अमेरिका की पूँजीवादी व्यवस्था घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है और जिसपर अमेरिका ने निश्चित रूप से आर्थिक प्रभुत्व स्थापित कर लिया है, के पक्ष में काम कर रहा है । अमेरिका का महत्त्व युद्ध में सम्मिलित होने से पहले और उसके बाद दोनों हालतों में, उसकी विस्तृत उत्पादन-शक्ति में है । युद्ध में अमेरिका के सम्मिलित होने के पहले भी ब्रिटेन को इस उत्पादन-शक्ति से लाभ उठाने की पूरी सुविधा दी गई थी । अतः अमेरिका के सम्बन्ध में यह कहना ठीक होगा कि वह इस युद्ध में इसलिये शामिल हुआ है कि ससार को पूँजीवादी व्यवस्था में उसका नेतृत्व (hegemony over world capitalism) कायम रहे, ब्रिटेन और फ्रांस की साम्राज्यवादी ल्ट में ने

क्या युद्ध अविभाज्य है ?

उसको भी हिस्सा मिलता रहे और कर्ज के बोझ से दबे हुए युरोप से वह खिराज वसूल करता रहे ।

रूस और चीन

जहाँ तक सोवियत यूनियन का सम्बन्ध है, उसने अपनी नीति को हर तरह से तोड़-मरोड़ कर अपने को युद्ध से अलग रखने की कोशिश की । युद्ध के स्वरूप के सम्बन्ध में रूस को कभी शका नहीं थी, लेकिन रूस के लिये युद्ध से अलग रहना किसी तरह सम्भव न था । जब कि हिटलर और स्टालिन जन्म दिवस सम्बन्धी शुभ कामनाएँ एक दूसरे को भेजने में लगे थे, रूस-जर्मनी युद्ध की घड़ी निकट आ रही थी । जर्मनी ने अपनी आदत के मुताबिक विधुत वेग से रूस पर झपट्टा मारा और रूस की मजबूरन अपनी आजादी की रक्षा और अपनी भौगोलिक सीमा को ज्यों-का-त्यों बनाये रखने के लिये लड़ाई में शामिल होना पड़ा । इसलिये, जहाँ तक रूस का सम्बन्ध है, इस युद्ध में उसका सम्बन्ध आत्मरक्षा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । रूस के लिये यह राष्ट्रीय रक्षा का युद्ध है ।

शायद हमें मित्र राष्ट्रों के एक दूसरे सहयोगी अर्थात् चीन की याद दिलाई जाय । जो लोग हाल की अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं से परिचित हैं, उनके लिये इस बात पर विश्वास करना हास्यास्पद ही होगा कि अगर उनका मतलब चीन को जापान की दया पर छोड़ देने से निकलता हो तो ब्रिटेन और अमेरिका इस बात की रत्ती भर भी परवाह करेंगे कि 'अभागे चीनी कुलियों' पर क्या बीतती है । चीन और जापान के वर्तमान युद्ध के आरम्भ से अभी कुछ ही पहले तक चीन और जापान को आपस में फेसला करने के लिये छोट भी दिया गया था । चीन अपनी आत्मरक्षा के लिये वीरतापूर्वक युद्ध कर रहा है । परिस्थितियों के कारण कई शक्तिशाली राष्ट्र उसका पक्ष ले रहे हैं । पर

जयप्रकाश की विचारधारा

उसके इन मित्रों को चीन की वास्तव में कोई चिन्ता नहीं है। यहाँ तक कि अगर वे मौका देखें, तो चीन के आक्रमणकारी के साथ मिल कर चीन का वँटवारा करने में भी नहीं हिचकेंगे। चीन के कारण युद्ध के उद्देश्यों में कोई अन्तर नहीं आता।

लड़ाई के बाद की दुनिया

मित्र राष्ट्रों के इन उद्देश्यों को देखते हुए क्या वर्तमान युद्ध को प्रजातन्त्र और स्वतन्त्रता का युद्ध—न सिर्फ युरोप के गुलाम देशों, बल्कि ससारे भर के गुलाम देशों की स्वतन्त्रता का युद्ध—बतलाना ईमानदारी है? स्तालिनवादियों और उनके एजेण्टों द्वारा दिन-रात हमारे कान में यह बात टूँसी जा रही है कि यह युद्ध दासता, उत्पीड़न और अत्याचार के विरुद्ध है और मित्र राष्ट्रों के युद्धोद्देश्यों के साथ मानव-प्रगति और सुख का भविष्य बँधा हुआ है। इस अतिरंजित चित्र में क्या सत्य का भी कोई अंश है? अगर मित्र राष्ट्रों के युद्धोद्देश्य पूरे हुए तो हमारे सामने दुनिया की कौन-सी तस्वीर होगी? यही न कि दुनिया में चारों ओर एंग्लो-अमेरिकन साम्राज्यवाद का बोलबाला होगा, आज से कहीं अधिक क्षीण अवस्था में रूस अपनी आत्मरक्षा के प्रयत्न में व्याकुल होकर लगा होगा और चीन यद्यपि राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र होगा; किन्तु-एंग्लो अमेरिकन राजनीतिक रथ के पहियों के साथ वह बड़ी मजबूती के साथ बँधा हुआ रहेगा।

शायद हमें यह याद दिलाया जाय कि लड़ाई के नतीजे अमेरिका और ब्रिटेन के मौजूदा शासकों के युद्ध सम्बन्धी उद्देश्यों पर निर्भर हैं। वास्तव में इसी बात पर हम भी जोर देना चाहते हैं। अगर हम मित्र राष्ट्रों के युद्ध सम्बन्धी उद्देश्यों के पीछे जाकर उन सामाजिक शक्तियों पर दृष्टि डालें, जो कि युद्ध के कारण मुक्त होंगी, तो हमें युद्ध की अविभाज्यता का नारा एक-दम अर्थशून्य और प्रतिक्रान्तिवादी जान पड़ेगा और उसके स्थान पर क्रान्ति

क्या युद्ध अविभाज्य है ?

की अविभाज्यता का नारा उठता हुआ दिखाई देगा । और, अगर युद्ध के अन्त में क्रान्ति के भडक उठने की तत्वीर हमारे दिमाग में है, तो क्या यह उचित है कि लड़ाई के जमाने में उस क्रान्ति को दबाने की हर तरह से तैयारी की जाय । उदाहरण के लिये साम्राज्यशाही की बिना शर्त मदद की जाय और यह आशा की जाय कि युद्ध के अन्त में क्रान्ति पके फल की तरह आकाश से आ टपकेगी ? अगर ससार की क्रान्तिकारी शक्तियाँ ही अन्त-तोगत्वा रूस की सहायता कर सकती हैं, तो उनका दमन करने के स्थान पर अभी से उनका विकास करने में ही अपनी शक्ति क्यों न लगाई जाय ।

यहाँ पर हम एक महत्वपूर्ण घटना पर विचार कर लें, जिसके कारण युद्ध के बाद के ससार का ढाँचा निर्णयात्मक रूप से बदल सकता है । हाल के कई लेखकों ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि ब्रिटेन और अमेरिका, दोनों ही जगहों में पैदावार, व्यापार, मुद्रा और मजदूरी आदि के क्षेत्रों पर दिनोंदिन अधिकाधिक मात्रा में राज्य का स्वामित्व या नियन्त्रण स्थापित होता जाता है । इसी प्रकार दाम और मुनाफे का फैसला भी राज्य की ओर से हो रहा है । फ्रीडा यूटले ने हाल के एक लेख में कहा है, 'इस प्रकार मैं राज्य के स्वामित्व या नियन्त्रण के आधार पर एक नई व्यवस्था उत्पन्न होती हुई देख रही हूँ । युद्ध जितना ही अधिक लम्बा होगा, इस नई व्यवस्था के पूरी तरह स्वरूप ग्रहण करने और विकसित होने की उतनी ही अधिक सम्भावना है । प्रश्न उठता है कि एक बार राज्य मालिक का स्थान ग्रहण कर लेता है, तब क्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य का जनता पर नियन्त्रण रहेगा ? यह अनुभव किया जाता है कि अगर युद्ध के बाद भयंकर रूप से फैली हुई बेकारी और सभावित क्रान्ति की बदौलत आर्थिक प्रणाली को विश्रु खलित होने से बचाना है, तो युद्ध के बाद भी पूँजी और श्रम के इस नियन्त्रण को क्रायम रखना होगा ।'

जयप्रकाश की विचारधारा

आगे चलकर इंग्लैंड की चर्चा करती हुई वे लिखती हैं, 'अगर इंग्लैंड के लिये इस लड़ाई में अब भी जीतना मुमकिन है, तो इसके लिये उसे जो कीमत चुकानी पड़ेगी और जो कुर्बानियाँ करनी पड़ेगी, उसके सिलसिले में इंग्लैंड-का मध्यम वर्ग नष्ट ही हो जायगा, जैसा कि पिछली लड़ाई के बाद जर्मनी में हुआ ।'

और, इस सिलसिले में उठनेवाले उचित प्रश्नों का वे उल्लेख करती हैं, - 'क्या ऐसी हालत में प्रजातंत्रवादी तरीके को कायम रखा जा सकेगा ?' ब्रिटिश लिबरल पार्टी के नेता ने भी कहा है कि वे लड़ाई के खत्म होने के तीन साल बाद तक इंग्लैंड में नये चुनाव को टालने के लिये तैयार हैं ।

बहुत-से लोग राष्ट्र के आर्थिक जीवन में प्रजातंत्रवादी राज्यों के इस बढ़ते हुए नियंत्रण को आशाभरी दृष्टि से देखते हैं । उनका विश्वास है कि इस प्रकार के नियंत्रण के जरिये समाजवाद के लिये रास्ता साफ हो रहा है । पर यह भी समझ लेना चाहिये कि साथ ही साथ इस प्रकार का नियंत्रण फासिज्म के लिये भी रास्ता साफ करता है । राज्य का अधिकार या नियंत्रण केवल समाजवाद की ही नहीं, फासिज्म की भी विशेषता है । अन्तर सिर्फ इतना है कि फासिज्म के अन्तर्गत राज्य पूँजीवादी बना रहता है । दूसरे शब्दों में, सामाजिक दमन के अस्त्र पूँजीपतियों और उनके साथी अर्थात् गरीब और गुमराह मध्यमवर्ग के हाथ में बना रहता है ।

इस प्रकार युद्ध के बाद ब्रिटेन और अमेरिका में फासिज्म को स्थापना के लिये आवश्यक सभी कारण मौजूद होंगे—पूँजीवादी राज्य, आर्थिक जीवन पर राज्य का पर्याप्त नियंत्रण और दिवालिया मध्यमवर्ग । इसके अतिरिक्त क्रान्ति का वास्तविक भय भी मौजूद होगा । ऐसी हालत में क्या इस बात की सम्भावना नहीं है कि पूँजीवाद को क्रान्ति से बचाने का मार्ग न देखकर

क्या युद्ध अविभाज्य है ?

ये राष्ट्र फासिज्म को अपना लें । इस सम्भावना की दृष्टि में फासिज्म-विरोधी युद्ध का क्या परिणाम होगा ?

पिछला युद्ध युद्धों का सदा के लिये अन्त कर देने के लिये लड़ा गया था, किन्तु उसने अपने से भी भयानक युद्ध को जन्म दिया । वर्तमान युद्ध फासिज्म का अन्त करने के लिये लड़ा जा रहा है । कहीं इसके बाद फासिज्म का और विस्तार न हो ।

सोवियत रूस का प्रश्न

कुछ लोग यह प्रश्न करेंगे कि ब्रिटेन और अमेरिका में युद्ध के बाद फासिज्म के फैलने का खतरा रहते हुए भी क्या यह उचित न होगा कि हमलोग सोवियत रूस की रक्षा करें ? सोवियत यूनियन की रक्षा ही क्या इतने महत्त्व की नहीं है कि उसके लिये हम ब्रिटेन के दोस्त बनने में आनाकानी न करें ? क्या आज की अवस्था में हम ब्रिटेन की मदद करके रूस को सहायता नहीं पहुँचाते हैं ? निस्सन्देह, अगर रूस की रक्षा की जा सके, तो ससार की उन्नति के लिये यह सबसे महत्त्व की बात होगी । किन्तु इस सिलसिले में दो प्रश्न उठते हैं, पहला प्रश्न यह है कि रूस को फासिस्ट ताकतों से घेर कर क्या हम रूस की रक्षा करेंगे और दूसरा प्रश्न यह कि क्या ब्रिटेन को दी गयी मदद रूस को बचाने के काम में आयेगी ? क्या बर्मा या लीबिया के क्षेत्रों की कोई जीत उतना ही महत्त्व रखती है, जितना कि रूसी मोर्चे की कोई जीत ?

पहले प्रश्न के उत्तर में हमें यह याद रखना चाहिये कि लड़ाई के बाद रूस का किसी प्रकार बच रहना—जब कि वह काफी कमजोर हो चुका हो और फासिस्ट राष्ट्रों से घिरा हुआ हो—प्रजातंत्र, स्वतंत्रता और शान्ति के लिए कोई गारण्टी नहीं होगी, जिसका कि इतना ज्यादा शोर स्तालिनवादियों

जयप्रकाश की विचारधारा

के प्रचार में सुनायी पड़ता है। ऐसी हालत में सोवियत यूनियन की रक्षा और उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति केवल एक ही बात के जरिये हो सकती है और वह है, प्रत्येक देश में क्रान्ति की शक्तियों का विकास। हिन्दोस्तान का आज़ादी की ओर बढ़ना ही सोवियत यूनियन और संसार की शान्ति और उन्नति के लिए एकमात्र सेवा है।

अब आइये, हम दूसरे प्रश्न पर विचार करें। मित्र राष्ट्रों के युद्ध सम्बन्धी उद्देश्यों की विवेचना करते हुए हम यह देख चुके हैं कि किस हद तक उनके उद्देश्य विभिन्न तथा अनमेल हैं। ब्रिटेन और अमेरिका के मुख्य उद्देश्य तो वही हैं, जो जर्मनी के शासकों के। और, यह दोनों ही सोवियत यूनियन के खिलाफ हैं। इस बुनियादी बात को ध्यान में रखते हुए हम यह समझ सकते हैं कि ब्रिटेन और अमेरिका को सोवियत रूस की रक्षा की किस हद तक चिन्ता होगी। ब्रिटेन और अमेरिका के शासकवर्ग अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए जर्मनी के खिलाफ रूस को इस्तेमाल जरूर करेंगे; लेकिन मौका पडने पर रूस के हितों की उपेक्षा करके अपने प्रतिस्पर्धी से समझौता करने में उन्हें हिचकन होगी। ऐसी अवस्था में ब्रिटेन को दी गयी मदद रूस की मदद है, यह किस प्रकार समझा जा सकता है ?

युद्धसम्बन्धी उद्देश्यों में जो विभिन्नता है, उसके कारण युद्ध के संचालन और युद्ध के उपरान्त यूरोप और संसार के पुनर्निर्माण की योजनाओं में भी स्वभावतः विभिन्नता आ जाती है। इस बात के कितने ही प्रमाण हमें समय-समय पर मिलते रहते हैं। उदाहरण के लिए मन्त्रिमण्डल के सदस्य बन जाने के पहले सर स्टैफर्ड क्रिप्स की वक्तृताओं से ही हमारे कथन की पुष्टि होती है। उन्होंने अपनी वक्तृताओं में कहा था कि रूस का क्या हथ्र होनेवाला है। इस बारे में जैसा चाहिये, वैसा जोश ब्रिटेन में नहीं देखा जाता है। रूस और ब्रिटेन के विभिन्न राजनीतिक उद्देश्यों के कारण दोनों देशों के

क्या युद्ध अविभाज्य है ?

चीज बढ़ते हुए सन्देश के वातावरण का भी आपने उल्लेख किया था ।

स्तालिन, मोलोटोव, लिटविनाफ की यूरोप में हिटलर के खिलाफ दूसरा मोर्चा बनाने को अपोलो का क्या असर हुआ है, यह भी पाठक जानते हैं । जब स्तालिन ने बहुत स्पष्ट शब्दों में और जोरों के साथ दूसरे मोर्चे की माँग की थी, तब यह समझना अनुचित न होगा कि उन्होंने इस बात का विचार करके ही यह माँग की थी कि सैनिक दृष्टि से दूसरा मोर्चा बनाना व्यवहार्य है ।

हमारा विश्वास है कि दूसरा मोर्चा बनाने में अवतक जो आनाकानी दिखायी गयी है, उसका कारण सैनिक अव्यावहारिकता के अतिरिक्त और भी कुछ है । ब्रिटेन के साम्राज्यवादी शासक, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की शक्तिशाली सहायता प्राप्त हो गयी है, हिटलर को स्वयं हराना चाहते हैं; वे स्तालिन के द्वारा उसे हराया जाना देखना पसन्द नहीं करते । बर्लिन के प्रवेशद्वार पर स्तालिन का पहुँचना उन्हें उतना ही खतरनाक मालूम पड़ता है, जितना कि हिटलर का ब्रिटिश चैनल को पार करना ।

सच तो यह है कि जर्मनी में समाजवाद के फैलने की अपेक्षा ब्रिटेन के पूँजीपतियों को इंग्लैंड में फासिज्म का फैलना कम खतरे की चीज़ मालूम पड़ेगी । स्पेन के गृहयुद्ध के समय ब्रिटिश शासकों की नीति यही थी ।

हमारे इस कथन का यह तात्पर्य न समझा जाय कि ब्रिटेन और अमेरिका हिटलर के खिलाफ दूसरा मोर्चा न खोलेंगे । वे ऐसा अवश्य कर सकते हैं, पर अपनी सुविधा के अनुसार । ऐसे वक्त वे ऐसा मोर्चा खोलना न पसन्द करेंगे, जब कि उसका लाभ विरोध रूप से स्तालिन को मिले, न कि उनको । ब्रिटेन और अमेरिका की दृष्टि से आदर्श स्थिति यह होगी कि रूस और जर्मनी दोनों एक दूसरे से लड़ते-लड़ते थक जायें और ब्रिटेन तथा अमेरिका ऐसी सुविधाजनक स्थिति में हों कि वे फैसलाकुन चोट कर सकें और

जयप्रकाश की विचारधारा

इस प्रकार युद्ध में विजयी होने और शान्ति की स्थापना करने का यश उन्हें प्राप्त हो सके। ब्रिटेन और अमेरिका के शासकों की यह नीति युद्ध के आरम्भ के समय स्टालिन द्वारा अपनायी गयी नीति से मिलती-जुलती है। उस समय स्टालिन सोचते थे कि फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनो लड़कर अपना ताकत खत्म कर दें, तब वे आगे बढ़कर युरोप के भाग्य का फैसला कर सकें।

अमेरिका और ब्रिटेन पूर्वी मोर्चे पर लड़ाई को लम्बा चलाने की कोशिश करेंगे, इस बात का ख्याल रखते हुए कि दो में से कोई भी पक्ष जीतने न पाये। रूस की जो मदद की जायगी, उसमें इस बुनियादी बात का हमेशा ध्यान रखा जायगा। अगर ऐसा हुआ कि रूस को जो मदद दी गयी, उसके बावजूद भी हिटलर को रपतार जारी रही और उसको कामयाबी मिलती हुई दिखाई दी, तो रूस के हनन को सहन करके भी जर्मनी के साथ रूस के इन 'प्रजातन्त्रवादी' मित्रों को समझौता कर लेने में देर न लगेगी। यह आशा वे लोग अवश्य रखेंगे कि आगे चलकर अपनी तैयारी पूरी होने पर फिर वे जर्मनी को नीचा दिखा सकें। सम्भवतः वे ऐसा तब करें, जब कि अमेरिका की पैदावार अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाय। इससे उनकी ताकत बढ़ गयी रहेगी।

लेकिन अगर हिटलर के बढ़ने के बजाय लाल सेना ही बर्लिन के दरवाजे पर पहुँच गयी, तो भी ब्रिटेन और अमेरिका के शासक हिटलर से समझौता कर लेंगे। इस उद्देश्य से, कि युरोप को बोल्शेविज्म की बाढ से बचाने के लिए जर्मनी बांध का काम दे सके, जो आज रूस के दोस्त हैं, वे कल उसके दुश्मन भी बन सकते हैं।

भारी भ्रम

एक बड़ा भ्रम, जिसके शिकार स्टालिनवादी हो रहे हैं, वह यह है कि ब्रिटेन और अमेरिका के शासक प्रगतिशील शक्तियों के बन्दी होकर इस युद्ध

क्या युद्ध अविभाज्य है ?

में लड़ रहे हैं। लेकिन इस तरह की कोई मजबूरी वास्तव में नहीं है। युद्ध का संचालन आज भी उनकी इच्छा के अनुसार हो रहा है। रूस की सहायता के प्रश्न को भी वे लोग अपने ही ढंग से सुलझा रहे हैं। रूस को छोड़कर सभी क्षेत्रों में ब्रिटेन और अमेरिका के संचालन में ही लड़ाई चल रही है।

अटलाण्टिक की जिस घोषणा में मित्र राष्ट्रों के युद्धोद्देश्य की घोषणा और ससार की जनता की आंखों में धूल भोंकने की कोशिश की गयी थी, वह ब्रिटेन और अमेरिका के शासकों के दिमाग की ही उपज थी और समूचे ससार में उसका एलान हो जाने के बाद रूस से उसपर हस्ताक्षर करा लिये गये थे। रूस और उसके मित्रों के बीच सन्देह का वातावरण बढ रहा है, यह भी देखा जा सकता है। इस युद्ध में शासकगण जनता के बन्दी होकर नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि जनता ही अपने शासकों की पूँजीवादी व्यवस्था के लिए रचे गये षड्यन्त्र का शिकार होकर युद्ध में भाग ले रही है।

युद्ध नहीं, क्रान्ति अविभाज्य है

इस प्रकार हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि युद्ध अविभाज्य नहीं, बल्कि विभाज्य है। ब्रिटेन या अमेरिका को दी गयी मदद रूस को पहुँचेगी, ऐसा विश्वास नहीं किया जा सकता। ब्रिटेन और अमेरिका से रूस को उससे अधिक सहायता पहुँचने की आशा नहीं की जानी चाहिये, जितनी सहायता उन्हें अपने साम्राज्यवादी स्वार्थों की रक्षा के लिए आवश्यक प्रतीत होती हो। ऐसी अवस्था में अपनी आजादी के लिए लड़ना ही रूस और ससार की प्रगतिशील शक्तियों के लिए हमारी सबसे बड़ी सहायता है। यह न भूलिए कि क्रान्ति अविभाज्य है।

विदेशी आक्रमण के प्रति हमारा क्या कर्तव्य हो, यह युद्ध की अविभाज्यता से अलग प्रश्न है। हिन्दोस्तानी अपनी आजादी के लिए लड़

जयप्रकाश की विचारधारा

रहे हैं। वे ब्रिटेन, जर्मनी या जापान किसीकी गुलामी नहीं चाहते। स्वभावतः वे इसका स्वागत नहीं करेंगे कि एक प्रकार का विदेशी शासन हटकर दूसरा विदेशी शासन आ जाय। किन्तु इस देश के विदेशी शासन ने उन्हें निहत्था कर रखा है और सैनिक रक्षा का समूचा भार अकेले अपने ऊपर ले रखा है। संकट की इस घड़ी में भी वे जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में सेना का भार सिपुर्द करने के लिए तैयार नहीं; क्योंकि वे देश पर से प्रभुत्व खोना नहीं चाहते। ऐसी हालत में जनता के लिए सिर्फ यही चारा है कि वह जिस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्यशाही के खिलाफ लड़ती आई है, उसी तरह नये आक्रमणकारी के खिलाफ भी लड़े। 'राष्ट्रीय रक्षा' या 'जनता का युद्ध' के भ्रमात्मक नारों से बचते हुए हमे अपनी स्वतंत्रता के लिए अपना अथक प्रयत्न जारी रखना चाहिए।

लाहौर किले की यंत्रणायें

[लाहौर-किले में जयप्रकाश को जो यातनायें दी गईं, उनको लेकर देश भर में बड़ी सनसनी मची थी। श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी, प्रयाग ने हैबियस कार्पस की दरखास्त लाहौर हाईकोर्ट में दी और जयप्रकाश ने भी तीन दरखास्तें हाईकोर्ट में पेश कीं। नीचे उनकी आखिरी दरखास्त दी जा रही है, जिससे इस सम्बन्ध की पूरी जानकारी हासिल होती है।]

माननीय चीफ जस्टिस,

हाईकोर्ट, लाहौर।

महामान्यवर,

आपको कुछ खिजलाहट होगी, यह समझते हुए भी मैं फिर आपकी सेवा में यह अर्जी पेश कर रहा हूँ। जस्टिस मुनीर ने ४-१२-४४ को मेरी दरखास्त पर जो फैसला दिया है, उसीके सम्बन्ध में मुझे लिखने को मजबूर होना पड़ा है। सबसे पहले मैं आपको और जस्टिस मुनीर को धन्यवाद देता हूँ कि मेरी पहली दरखास्त रद्द किये जाने पर भी फिर से सुनवाई की।

(२५३)

(१) यह मेरा दुर्भाग्य रहा कि दूसरी बार की सुनवाई में भी, यद्यपि इस बार वकील भी मुझे मिले थे, मेरा मुकदमा आपके सामने सही सही नहीं रखा जा सका; क्योंकि पुलिस के सामने अपने वकील से बातें करना मैंने नामंजूर कर दिया था। मेरा ख्याल है, मैं कुछ भ्रम में था और मेरे वकील श्री कपूर भी। उन्होंने मुझे बताया था कि जिस समय मैं उनसे अपनी बातें कहूँ, उस समय पुलिस न रहे; कोर्ट मेरी इस अर्जी को नामंजूर भी कर दे, तो भी मुझे एक बार फिर से उनके सामने अपना मुकदमा रखने का मौका मिलेगा ही। मैंने सोचा था कि मैं इस दूसरे मौके से फायदा उठाऊँगा। मेरी समझ में नहीं आता कि श्री कपूर के माँगने पर भी यह दूसरा मौका मुझे क्यों नहीं दिया गया। मालूम होता है, जिन शब्दों में मैंने एफिडेविट की थी, उन्हींके चलते ऐसा हुआ। मुझे ताज्जुब होता है, साधारण आदमियों की भापा कानूनी तर्जेंबर्याँ से क्यों नहीं ज्यादा छफ होती है ! खैर, मुझे इस बात का दुःख है कि अपने वकील को मैं पूरी सलाह न दे सका, इसलिए मेरा मुकदमा न अच्छी तरह कोर्ट के सामने पेश किया जा सका और न मुझे कुछ फायदा हुआ। लेकिन, यह मैं आपके पास कुछ शिकायत को तरह से नहीं पेश कर रहा हूँ।

यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने क्यों पुलिस के सामने अपने वकील से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। पहली बात यह, कि मेरी ऐसी धारणा थी कि कैदी को यह कानूनी हक है कि वह अपने कानूनी पलाहकार से एकान्त में बातें करे या कम से कम इतनी दूरी पर बातें करे के कोई सरकारी अफसर न सुन सके। मैं इसी अधिकार का उपयोग करना चाहता था। दो और बातें भी थीं—विद्वान जज ने अपने फैसले में लिखा कि, 'कैदी का जो कुछ भी सलाह मिस्टर कपूर को देनी थी, उसे आखिर कोर्ट के ही सामने तो खुलेआम पेश करना था; फिर पुलिस सुन लेती, तो

क्या हो जाता ? जिसे कुछ दिन बाद पुलिस को सुनना ही था, वह बात पुलिस को नहीं सुनने देने के लिए कैदी के पास कौन-सी सच्ची दलील थी, यह मेरी समझ में नहीं आता ।' मेरा कहना है कि यहाँ जज ने सकुचित दृष्टि दिखाई है । मुलाकात के समय दो पुलिस ऑफिसर हाज़िर थे और तीसरा एक शौटहैण्ड जाननेवाला था, जो मेरी बगल में था । इससे साफ है कि जो कुछ मैं या मेरे वकील कहते या जिस बात को पुलिस से दिल चस्पी होती, उसे शब्दशः लिख लिया जाता । मुझे कुछ ऐसा लगता था कि मैं अपने वकील से बातें नहीं कर रहा हूँ, पुलिस के सामने अपना बयान दे रहा हूँ । जब कोई मुद्दई या मुद्दालह अपने वकील से बातें करता है, तो वह सिर्फ उन्हीं बातों की चर्चा नहीं करता, जिन्हें कोर्ट के सामने पेश करना होता है; बल्कि मुकदमे के सभी पहलुओं पर विचार-विनिमय करता है । कुछ पहलू कमजोर होते हैं, कुछ मज़बूत । फिर हर पहलू की अच्छी और बुरी सभावनायें होती हैं । उन्हें किस तरह पेश किया जाय, यह भी सवाल उठता है । इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि वह अपने वकील से खुलकर बातें कर सके । मैं भी यही चाहता था कि खुलकर मुकदमे के सभी पहलुओं पर राय दूँ और लूँ । लेकिन जब पुलिस सुन रही हो और शौटहैण्ड वाला नोट ले रहा हो, तब क्या ऐसा संभव था ? यह देश के किसी हिस्से में भी असंभव होता, किन्तु, खासकर इस प्रान्त में, जहाँ नागरिक आजादी का नाम भी नहीं है और पंजाब की सी०आई०डी० सर्व-शक्तिमान कही जाती है और नागरिकों के लिए भयानक हौवा बनी हुई है ।

एक तीसरी बात भी इस सम्बन्ध में मुझे कहनी है । मुझसे सलाह लेने के बाद मेरे वकील को कोर्ट के सामने मेरा मुकदमा रखना था और उरुख़ विरोध सरकारी वकील या एडवोकेट-जेनरल को करना था । अब श्री कपूर जब तक मेरी बातों को कोर्ट के सामने रखें, यदि उसके पहले ही सरकारी

जयप्रकाश की विचारधारा

वकील को सारी बातें मालूम हो जायँ, ता क्या मेरे और मेरे वकील के साथ यह इंसान की बात होती ? मेरी मुलाकात के समय लिये गये नोट की कापी पुलिस सरकारी वकील को नहीं दे सके, इसके लिए क्या कोई भी कार्रवाई सम्भव थी ? मुझे अफसोस है कि विद्वान जज ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया ।

(२) दूसरी बात मुझे फैसले में लिखी गई कुछ गलत बातों के सम्बन्ध में कहनी है । मैं नहीं जानता कि किसने कोर्ट को ये गलत बातें बताईं । अगर मेरे वकील ने बताई हो, तो उस बेचारे का क्या कसूर ! क्योंकि उनको सही बात जानने का मौका कहाँ दिया गया ! और, अगर सरकार की ओर से ये बातें रखी गई हैं, तो मेरी समझ में नहीं आता कि कोर्ट को गलत जगह ले जाने को ज़रूरत क्यों अनुभव की गई ?

मैंने यह कभी नहीं छिपाया कि बिहार के हजारीबाग सेण्ट्रल जेल से मैं भाग आया था; लेकिन मैं किसी एक आदमी के साथ नहीं, पाँच आदमियों के साथ भागा था । फिर यह घटना १९४३ में नहीं हुई थी, बल्कि नवम्बर १९४२ में । मैं अमृतसर स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था, जब मैं फ्रण्टियर मेल से दिल्ली से रावलपिण्डो जा रहा था और उसकी तारीख थी १८ सितम्बर १९४३ की भोर । किन्तु फैसले में लिखा गया है कि मैं लाहौर में १९ अगस्त १९४३ को, संभवतः भारत-रक्षा कानून की १९ वीं धारा के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया और २२ सितम्बर को उसकी दफा बदलकर २६ कर दी गई थी । गिरफ्तारी की तारीख तक मैं जब गलती है, तो नजरबंदी की दफाओं में भी गलती हो सकती है । मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि उस समय मुझपर कोई ऑर्डर तामील नहीं किया गया था । फिर, मैं कांग्रेस वकिंग कमीटी का सदस्य नहीं हूँ और न हजारीबाग से भागने के समय था । १९३६ में, थोड़ा समय छोड़कर, मैं कभी वकिंग कमीटी का मेम्बर

लाहौर किले की यंत्रणायें

नहीं रहा । मैं इस गलती को इसलिए सुधारना चाहता हूँ कि जेल से भागने या उसके बाद के मेरे काम से काँग्रेस का कोई सरोकार नहीं समझा जाय ।

मुम्बय सरकारों ऑर्डर, एक के बाद एक, तामोल होते रहे । पहला ऑर्डर पंजाब गवर्नमेण्ट के चीफ सेक्रेटरी का था, जिन्होंने पुलिस के आई० जी० को हुक्म दिया था कि १८५८ के बगाल रेगुलेशन के अनुसार मुझे लाहौर के किले में कैदी की हैसियत से रखा जाय । यह १९४३ के नवम्बर महीने के मध्य में हुआ, यानी जैसाकि अब मालूम होता है, श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी द्वारा हाईकोर्ट में दरखास्त देने के कुछ दिनों के बाद ही । इसके पहले भारत-रक्षा-कानून की १२९ या २६ धाराओं के अनुसार जो ऑर्डर हुए थे, मुझे उनकी कोई खबर भी नहीं । दूसरा ऑर्डर, जो मुम्बय तामील किया गया, वह मिस्टर वूर्न का था, जिसमें कहा गया था कि मुझे नजरबंद की तरह से उसी किले में रखा जाय । यह ऑर्डर १ ली जुलाई १९४४ का था, जिसकी चर्चा फैसले में की गई है । भारत सरकार के होम डिपार्टमेंट के सयुक्त मंत्री, मिस्टर सहाय, के ऑर्डर की मुझे कोई खबर नहीं । कुछ दिन के बाद सेण्ट्रल गवर्नमेण्ट ने २३ अगस्त, १९४४ को श्री टॉटिन्हम के दस्तखत से मुम्बय एक ऑर्डर तामील कराया, जिसमें कहा गया था कि मुझे १९४४ के तीसरे आर्डिनेन्स के मुताबिक उम किले में रखा गया । आखिरी ऑर्डर ३० नवम्बर को मुम्बय तामोल हुआ है कि पहला ऑर्डर मुम्बय जारी रखा जाय ।

यहाँ मैं आपके सामने पहले ऑर्डर के बारे में एक विचित्र बात का उल्लेख करूँगा । जैसाकि मैंने आपको कहा, यह पहला ऑर्डर नवम्बर के मध्य में मुम्बय तामील किया गया । तारीख की याद मुझे नहीं रही; लेकिन वह तीसरे सप्ताह के शुरू में जरूर था । कुछ दिनों के बाद, पंजाब गवर्नमेण्ट के द्वारा या केन्द्रीय सरकार के द्वारा यह तय किया गया कि मुझे

जयप्रकाश की विचारधारा

उस ऑर्डर के अनुसार स्टेट प्रिजनर की सारी सहुलियतें दी जायें । १ ली फर-वरी १९४४ को पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट ने आकर सरकार के निर्णय की सूचना मुझे दी । उन्होंने मुझे सूचित किया कि अन्य सहुलियतों के अतिरिक्त मुझे ५०) पचास रुपये माहवारी मिलेंगे और शुरु के खर्च के लिए ५०) इसके अलावा । उन्होंने कहा कि मेरा बकिऔता कुल मिलाकर १२५) हुआ, जो मेरे हिसाब में दर्ज कर दिया जायगा । उस समय मैंने हिसाब नहीं किया, लेकिन पीछे हिसाब किया तो मेरे १३५) २० होते थे—पचास रुपये शुरु के, पचीस रुपये आधे नवम्बर के और पचास पचास रुपये नवम्बर-दिसम्बर के । मैंने जब इस ओर स्थानीय अफसर का ध्यान आकृष्ट किया तो उसने कहा, मेरा हिसाब आधे दिसम्बर से किया गया है । मैंने कहा, आधे नवम्बर से क्यों नहीं ? तो उसने मजूर किया कि गलती हो गई है; किन्तु मुझसे आरजू की कि मैं इस सवाल को आगे न बढ़ाऊँ । पचास रुपये से कुछ होना-जाना न था, इसलिए मैं भी चुप्पी लगा गया ।

लेकिन अब, जब मैं उसपर विचार करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यह गलती जान-बूझकर की गई थी, जिसमें ऐसा मालूम हो कि लाहौर हाईकोर्ट में श्रीमती बनर्जी की दरखास्त पढ़ने पर मैं स्टेट प्रिजनर बनाया गया । कोई दूसरा कारण भी हो सकता है; क्योंकि बिना किसी कारण के पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट पचास रुपये की तुच्छ रकम क्यों हड़पता !

यहाँ मैं आपका ध्यान एक बात की ओर और खींचना चाहता हूँ । जहाँ मुझपर तामील किये गये या बेतामील किये गये ऑर्डरों की सभी तारीखें कोर्ट के सामने रखी गई हैं, जिनका फंसले में उल्लेख है, वहाँ बगाल रेगुलेशन वाले ऑर्डर की तारीख कहीं नहीं दी गई है, क्योंकि फंसले में कहीं भी इसकी चर्चा नहीं है ।

मैं कह नहीं सकता, इस विचित्र तथ्य का कोई महत्त्व है । तो भी मैंने

इसे आपके सामने रख दिया है और मैं यह भी कह देना चाहता हूँ कि इस पचास रुपये से मेरी कोई ढिलचस्पी नहीं है ।

मैं कह नहीं सकता कि जस्टिस मुनीर के फैसले पर इस तथ्य का कोई प्रभाव पड़ सकता है । यह आपके ओर विद्वान जज के विचार पर निर्भर करता है और मेरे वकील का काम है कि वह इससे कोई नई दलील शायद आपके सामने पेश कर सकें ।

(३) अब मैं अपनी दरखास्त के मुख्य हिस्से पर आता हूँ यानी इस बात पर कि मेरी नजरबंदी कानूनी है कि नहीं । मैं शुरू में ही कह दूँ कि कानूनी बातें आपके सामने रखने का उपयुक्त पात्र मैं अपने को महसूस नहीं करता । लेकिन मैं इस सम्बन्ध की बातों को आपके सामने संक्षेप में रख देना चाहता हूँ । सबसे पहले मैं कोर्ट के इस निर्णय पर संतोष प्रकट करता हूँ कि उसने सरकारी वकील की इस दलील को रद्द कर दिया है कि १९४४ के तीसरे आर्डिनेंस के आर्डरो पर हस्तक्षेप करने का कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है ।

मेरे वकील ने मेरी सलाह न मिलने पर भी मेरी दरखास्तों में उल्लेख की गई खबरों के आधार पर मेरा मुकदमा आपके सामने अच्छी तरह रखने की कोशिश की है । उन्होंने नजरबंदी की आज्ञा का दो कारणों से विरोध किया । पहला यह कि अधिकारियों को ऐसा आर्डर देने का अधिकार नहीं था और दूसरा यह कि उनका उद्देश्य विशुद्ध नहीं था । पहले कारण को इस धारणा पर अस्वीकार किया गया कि भारत-सरकार के ज्वायण्ट सेक्रेटरी को जरूर ही ऐसी आज्ञा देने का अधिकार दिया गया था । यह धारणा सच हो सकती है । लेकिन इसका कोई भी सबूत नहीं पेश किया गया और दूसरे कारण को इसलिए अस्वीकार किया गया कि मेरी नजरबंदी सिर्फ जिस किसी भी तरह से मुझसे कुछ बातें निकालने के लिए ही नहीं की गई होगी । और,

फिर यह कि १० दिसम्बर १९४३ के वाद कोई पूछताछ मुझसे नहीं की गई ।

इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन संक्षेप में यह है—मैं खुलेआम यह स्वीकार करता हूँ कि जो कानून हमारे देश पर जबरदस्ती लादा गया है, उसके अनुसार, जेल से भागने के पहले या उसके वाद को मेरी कार्यवाहियों से हो सकता है कि जनता की शान्ति में बाधा पड़ी हो और युद्ध के सफल संचालन में बिघ्न हुआ हो । किन्तु मैं समझता हूँ कि मेरी इन कार्यवाहियों से मेरे देश को अधिक से अधिक लाभ ही हुआ होगा । यह एक राजनीतिक विचार है और कानून और कोर्ट का इससे कोई भी ताल्लुक नहीं होना चाहिये और मैंने इसका उल्लेख यहाँ यों ही चलते-चलाते कर दिया है ।

इस विचार से, जिस समय मैं गिरफ्तार किया गया, मेरे मन में इस बारे में जरा भी सदेह नहीं था कि मेरी गिरफ्तारी और मजरबंदी तथाकथित जनता को शान्ति को रक्षा और युद्ध के सफल संचालन के लिए ही हुई है । मैं यह कहकर अपनी रिहाई नहीं चाहता था और न चाहता हूँ कि मुझपर ये आरोप गलत लगाये गये थे । तो भी मैं आपको बार-बार असुविधा दे रहा हूँ—दो मर्तबे दरखास्त दे चुका और यही तीसरी बार दे रहा हूँ, क्यों ?

इसका कारण वही है, जिसका उल्लेख मैंने पहली दरखास्त में किया था । जिस समय श्रीमती बनर्जी ने हाईकोर्ट में दरखास्त दी थी, उस समय उसकी खबर मुझे नहीं थी और न मुझे यह मालूम था कि मुझे स्वयं भी यह कानूनी हक हासिल है कि मैं ४९१ दफा के अनुसार दरखास्त देकर अपने ऊपर होने-वाले असहनीय वर्ताव को रोक सकता हूँ । तो भी मैंने उस तथाकथित पूछताछ के जमाने में कई बार यह चर्चा की थी कि मैं सरकार को इस सम्बन्ध में लिखना चाहता हूँ, किन्तु मुझे इसकी इजाजत नहीं दी गई । अब मैं सोचता हूँ कि यदि मैंने हैबियस कार्पस को दरखास्त देने का हुक्म माँगा होता, तो

उसे भी अस्वीकार कर दिया गया होता। मेरे खयाल से पारडीवाला के मुकदमे के बाद ही इस प्रान्त में यह सम्भव हो सका है कि मुसीबत में पड़ा हुआ राजवदी हैबियस कार्पोस की दरखास्त देकर कानूनी रक्षा की मांग कर सके।

जब श्रीमती बनर्जी की दरखास्त नामजूर की जा चुकी, तब मुझे उसकी धुंधली खबर मिली थी। उसका पूर्ण उद्देश्य का पता तो मुझे जस्टिस मुनीर के फैसले से लगा है। किन्तु मुझे यह खबर मालूम हुई थी कि चूँकि मैं बंगाल रेगुलेशन का स्टेट प्रिजनर हूँ, इसलिए मुझपर दफा ४९१ लागू नहीं हो सकती। किन्तु जब जुलाई में मुझे फिर बंगाल रेगुलेशन से हटाकर भारत-रक्षा-कानून के अनुसार नजरबंद बनाया गया, तो मुझे यह समझने में देर न लगी कि मेरी गिरफ्तारी के बारे में हुई कुछ गैरकानूनी कार्रवाई को ढकने के लिए ही यह चाल चली गई थी। मैंने पहली दरखास्त इसीलिए दी कि मैं कोर्ट को सही बात तक पहुँचने में मदद कर सकूँ। दूसरी दरखास्त में मैंने साफ लिखा कि अब तक गैरकानूनी कार्रवाइयों को दुस्त कर लिया गया होगा, तो भी कोई पता लगावे कि शुरू में गैरकानूनी कार्रवाई हुई थी या नहीं। गैरकानूनी कार्रवाई से मेरा मतलब वही था, जिसे मेरे वकील ने कोई सामने रखा था यानी यह ऑर्डर न तो योग्य अधिकारी द्वारा जारी किया गया था और न कानून के अनुसार मुझपर तामील किया गया था। यह सवाल अभी हल नहीं हो पाया है, क्योंकि मेरे वकील का ध्यान केन्द्रीय सरकार के २७ जून, १९४४ वाले ऑर्डर पर था।

जस्टिस मुनीर ने अपने फैसले में लिखा है—‘जब यह दरखास्त मेरे सामने १७ दिसम्बर, १९४३ को पेश की गई, सरकारी वकील ने बताया, चूँकि अभियुक्त बंगाल स्टेट प्रिजनर रेगुलेशन के अनुसार नजरबंद किया गया है, इसलिए उसपर ताजीरात हिन्द की ४९१ दफा लागू नहीं है और इसी

जयप्रकाश की विचारधारा

आधार पर यह दरखास्त रह कर दी जाय । सरकारी वकील की बात रह गई और २३ दिसम्बर को श्रीमती बनर्जी की दरखास्त डिसमिस की गई ।' इन शब्दों से ही मालूम होता है कि बगाल रेगुलेशन की आड़ इसीलिए ली गई थी कि श्रीमती बनर्जी को दरखास्त पर सुनवाई न हो । इस बात से मैं इस नतीजे पर आया हूँ कि मेरी गिरफ्तारी में जहर ही गैरकानूनी कार्रवाई को गई थी और मेरे साथ गैरकानूनी व्यवहार किया गया था, जिस तथ्य को हाईकोर्ट में प्रगट होने से सरकार डर गई थी । इसलिए बगाल रेगुलेशन का प्रयोग निस्सन्देह ही एक गैरकानूनी कार्रवाई को छिपाने के लिए किया गया था और मैं इस गलती को दुरुस्त कराने के लिए हर सम्भव उपाय को काम में लाना चाहता हूँ । यह गलती एक साल पहले हुई थी, इसलिए आज उसे सही नहीं मान लिया जा सकता, न कोर्ट को ही मुनासिब है कि उस ओर ध्यान न दे ।

अब मेरी गिरफ्तारी के सम्बन्ध की बुरी नीयत के प्रश्न पर आइये । मैं कोर्ट के फैसले से सहमत हूँ कि मेरी नजरबंदी सिर्फ मुझसे गुप्त गुप्त बातें निकालने के लिए ही नहीं हुई थी; लेकिन मेरा यह दृढ विचार है कि लाहौर किले में तो मुझे इसी उद्देश्य से रखा गया था । जज ने मेरी गिरफ्तारी और इस पूछताछ के बीच के लम्बे अर्से पर जोर दिया है । मेरा कहना है कि यह अर्सा लम्बा नहीं है; क्योंकि मैं १८ सितम्बर को गिरफ्तार हुआ था, न कि १९ अगस्त को । इसलिए पूछताछ तो एक महीने के बाद ही शुरू हो गई थी और इतनी देर करना जरूरी था; क्योंकि मेरे सम्बन्ध के कागजात केन्द्रीय सरकार के पास से ही नहीं, प्रान्तीय सरकारों के पास से भी मँगाने थे । सच बात तो यह है कि जिस समय पूछताछ शुरू हुई, पंजाब सी० आई० डी० के अतिरिक्त बगाल और बिहार की सी० आई० डी० भी वहाँ हाजिर थी । फिर, यह पूछताछ १० दिसम्बर को बंद हो गई, तो इसलिए कि मुझसे कुछ निकालना

असम्भव था और उधर पूर्णिमा वनजी की हाईकोर्ट की दरखास्त ने सरकारी अफसरों को भड़ाफोड़ से भयभीत कर दिया। पूछताछ को फिर-से जारी क्यों नहीं किया गया, इसका कारण भी वही है कि पुलिस समझ गई कि मुझसे वह कुछ पा नहीं सकती और बगाल रेगुलेशन का स्टेट प्रिजनर होते ही मुझसे मिलने को आये हुए पंजाब के होम सेक्रेटरी और गैर-सरकारी दर्शक नवाब मुजफ्फर अलो खाँ से मैंने इसकी शिकायत कर दी थी और पंजाब सरकार के पास एक दरखास्त भी भेजी थी। इसलिए, मेरा यह निवेदन, आपकी सेवा में, फिर से है कि मुझे लाहौर किले में रखने में सरकार की नीयत साफ नहीं थी, वह मुझसे अगस्त-क्रांति के सम्बन्ध की खबरें मुझपर जुल्म ढाकर प्राप्त करना चाहती थी। इस निवेदन के साथ अब मैं चौथे सवाल पर आता हूँ।

(-४) इस किले में रखा जाना मुझसे खबरें लेने की बुरी नीयत से हुआ था, यह निवेदन मैं कर चुका हूँ। अब मेरा यह निवेदन है कि इस किले में रखकर मुझे जान-बुझकर और बदले की भावना से अतिरिक्त सजा देने की कोशिश की गई। एक तो इस किले में किसीको रखना ही, दूसरे जेलों को दृष्टि में रखते हुए, जान-बुझकर अतिरिक्त कड़ी सजा देना है। मैंने सरकार को लिखा कि मुझे किसी जेल में भेज दीजिये, किन्तु उसने यह कहकर उस दरखास्त को रद्द कर दिया कि कोई जेल मेरे लिए सुरक्षित नहीं है। यह दलील लँगड़ी है और इसीसे उसकी बुरी नीयत साफ प्रगट हो जाती है। मैं मानता हूँ कि सरकार को यह हक है कि वह अपनी सुविधानुसार जेल का चुनाव करे, किन्तु इस हक के प्रयोग की सीमा होनी चाहिये। जिसपर कोई मुकद्दमा न चला, जो अपराधो सिद्ध न हुआ, -जिसे शान्ति-रक्षा के नाम पर ही नज़रबंद रखा गया है, उसके आराम और सुविधा का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। पन्द्रह महीनों तक एक छोटी-सी कोठरी में दिनरात बन्द रखना, शाम-सुबह सिर्फ एक घंटे के लिए बाहर निकालना, किसीसे मिलने-जुलने न देना—ये

जयप्रकाश की विचारधारा

तकलीफें तो सजायापता कैदियों को भी विशेष जुर्म पर ही दी जाती हैं। किसी भी तरह ये बातें नजरबंद पर लागू नहीं की जा सकती।

(५) अब मैं अपनी अन्तिम बात पर आता हूँ। मैंने अपनी पिछली दरखास्तों में चर्चा की है कि २० अक्टूबर १९४३ से १० दिसम्बर तक मुझे कष्ट और यंत्रणायें दी गईं। ये यंत्रणायें क्या थीं ? इस सम्बन्ध में मैंने पंजाब सरकार के होम सेक्रेटरी को जो खत लिखा था, उससे ही उद्धृत कर देना काफी समझता हूँ—

‘मैं पिछले साल १८ सितम्बर को अमृतसर में गिरफ्तार किया गया और उसी दिन मुझे इस किले में लाया गया। गिरफ्तारी के करीब एक महीने बाद मुझे आफिस में ले जाया गया, जहाँ पंजाब, बंगाल और बिहार के सी० आई० डी० आफिसर हाजिर थे। मुझे सूचित किया गया कि मुझे कुछ सवालों का जवाब और अपनी हाल की कार्रवाइयों पर बयान देना है। मैंने अफसरों से कहा कि हाल की गुप्त कार्रवाइयों को छोड़कर आप जो कुछ पूछेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा और जहाँ तक बयान देने की बात है, मुझे सिर्फ यही कहना है कि मैं भारत में स्थापित अँगरेजी साम्राज्य का शत्रु हूँ (इंग्लैंड या कामन-वेल्थ का नहीं) ; मैं अपने देश को आजाद करने का काम करता रहा हूँ और तब तक करूँगा, जब तक उद्देश्य में मुझे सफलता मिले या मेरी मौत आ जाय ! पूछताछ करनेवाले अफसरों ने कहा कि वे मुझे तब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक वे उन खबरों को, जिन्हें वह हासिल करना चाहते हैं, न पा लें।

इस तरह मुझसे वह तथाकथित पूछताछ शुरू की गई। इसके बाद मुझे रोज आफिस में बुलाया जाता और भिन्न-भिन्न समयों तक वहाँ बैठाया जाता। शुरू के दिनों में तो कुछ ही घंटों तक बैठाया जाता, तो भी मैंने उनसे कहा कि इस तरह मुझे जबरदस्ती बैठाना और उन सवालों को दुहराते जाना, जिनका

जवाब मैं देना नहीं चाहता, मेरे प्रति जुल्म और ज्यादाती है। उन्होंने जवाब दिया कि आप पजाब की सी० आई० डी० के हाथों में हैं, जहाँ इस तरह की बात उठाना भी फिजूल है। धीरे-धीरे पूछताछ का समय लम्बा होता गया—आठ बजे भोर से पाँच बजे शाम, फिर दस बजे रात और आधीरात तक। मुझे तरह-तरह से धमकाया जाता—कभी मुलायम से, कभी सभ्यतापूर्वक, कभी तयौरी बदलकर गुस्सा दिलाते हुए। मैंने इसका बहुत विरोध किया और कहा कि मुझे सुपरिण्टेण्डेण्ट से मिलाओ या सरकार के पास लिखने दो। यह बात मुझे विचित्र लगी कि कैदी को उस सरकार के पास लिखने या शिकायत करने का मौका भी नहीं दिया जाय, जिसने उसे कैद किया है। मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करता हूँ; क्योंकि इस बात के चालू रखने से बहुत-सी बुराइयाँ और बेइन्साफी हो सकती हैं। मेरे विचार से कैदी को दरखास्त देने का हक तो हर हालत में होना चाहिये। मैंने उस समय शेखी बघारने की नीयत से नहीं, बल्कि पूरी गम्भीरता के साथ, उनसे कह दिया कि आपलोग मेरी जान भले ही निकाल लें, किन्तु दबाव डालकर मुझसे बातें नहीं निकाल सकते। अपना अवरोधी शक्ति का अन्दाजा किसीको नहीं रहता; किन्तु यह मेरा ईमानदार निर्णय था और आफिसरों को मैंने उसकी गम्भीरता अनुभव कराने की पूरी कोशिश की।

‘मुझे जो कष्ट दिये जाते थे, वे यंत्रणा में तब बदल गये, जब मुझे रात या दिन में सोने नहीं दिया जाता था। भोर से बारह बजे तक मुझे आफिस में रखा जाता था। तब एक घंटे के लिए मुझे सेल में ले जाया जाता था; फिर वहाँ से एक या दो घंटे के लिए आफिस में लाते, फिर सेल में ले जाते—यों इस सिलसिले को रात भर भोर तक जारी रखते। बीच-बीच में जो थोड़ा वक्त सेल में मिलता, उसमें क्या खाक मैं सो पाता—ज्यों ही झपकी आती कि मुझे जगा देते और आफिस में ले जाते। कागज पर लिखने में यह क्रिया

जयप्रकाश की विचारधारा

उतनी भीषण न मालूम पड़े, किन्तु मैं ईमानदारी से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कई दिनों तक लगातार इस क्रिया को दुहराने पर ऐसा मालूम पड़ता था कि दिमाग फट गया, नसें चूर हो गईं, उफ, कैसी यंत्रणा ! हाँ, यंत्रणा छोड़कर इसका दूसरा नाम दिया नहीं जा सकता है !

‘दिसम्बर के दूसरे हफ्ते में इस यंत्रणा का अन्त हुआ और “पूछताछ” भी खत्म की गई। कुछ दिनों के बाद मुझे खबर दी गई कि अब मुझसे पूछताछ नहीं की जायगी।’

श्रीमान्, ये तथ्य हैं और सरकार को भी इसे अस्वीकार करने या इसकी सच्चाई पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं हुई है। अपने उस खत से ही मैं कुछ और भाग उद्धृत करना चाहता हूँ, क्योंकि वे इस मौके के लिए भी बेमौजू नहीं हैं—

‘मेरी शिकायत यह है कि मुझे जो यंत्रणायें दी गई हैं, या मेरे साथ जो ऐसा व्यवहार किया गया है, उसके लिये कोई भी औचित्य नहीं है। इसके लिये सरकार के पास कोई कानूनी या नैतिक भित्ति नहीं है। आर्डिनेन्सों में अधिक से अधिक अस्त्रियार दिये गये हैं, किन्तु ऐसी कार्रवाइयों के लिए उसमें भी जगह नहीं है। कैदी बेचारा सबसे निरीह प्राणी होता है; वह जो भी जुर्म करे, सभ्यता उसे बुरे व्यवहार से रक्षो करती है। अपने जुर्म के कारण, कानूनी ढग से, उसे फाँसी दी जा सकती है। वैदी की हैसियत से कैद के कानून तोड़ने पर, उसे सजाये भी दी जा सकती हैं; किन्तु पुलिस को यदि वह बातें न बताये, तो उसे कष्ट या यंत्रणा नहीं दी जा सकती; फिर राजनीतिक कैदों के साथ ऐसा व्यवहार हो, यह तो और भी भयानक बात है। यहाँ मैं सरकार का ध्यान दूसरी बात की ओर आकृष्ट करता हूँ। मैं अभिमान या शेखी नहीं दिखाता; लेकिन, अपनी बात को महत्व देने के लिए मुझे कहना पड़ता है कि यदि सो० आई० डी० मेरे

लाहौर किले की यंत्रणायें

साथ ऐसा व्यवहार कर सकती है, तो उनलोगों के साथ कहाँ तक वह जाती होगी, जो मुझसे भी अधिक देशभक्त होंगे, किन्तु जो जनता के समक्ष या सार्वजनिक जीवन में मेरे ऐसा स्थान या पद नहीं प्राप्त कर पाते। ऐसे लोगों को सी० आई० डी० की मर्जी पर छोड़ देना मुनासिब नहीं ; ऐसी स्थिति का अन्त तो होना ही चाहिये ।’

‘राजनैतिक विपक्षियों का दमन और नाश तो नाजियों और फासिस्टों का तरीका है और कष्ट एव यंत्रणायें उनके शासन के मुख्य चिह्न । यह तर्क पेश किया जाता है कि जो लोग मेरी तरह हिंसा में विश्वास रखते हैं, उनका दमन हिंसात्मक उपाय से करना अनुचित नहीं । मैं इस दलील को मान लेता हूँ, किन्तु उनके दमन के लिए भी कानूनी ढंग को ही बरतना होगा । एक राजनीतिक क्रान्तिकारी को फाँसी भी दे दीजिये, यदि कानून उसे अग्राधी समझता है तो ; लेकिन कोई सूचना या खबर उससे लेने के लिए उसे यंत्रणा नहीं दी जा सकती । राजनीतिक सचषों में युद्ध बहुत ही भयानक, पाशविक और सहारक है । किन्तु युद्ध के बदियों के लिए कुछ नियम हैं, जिनका पालन सुसभ्य समाज ईमानदारी से करता है । युद्ध क्षेत्र में जिसे फिरचों से भोक कर निर्ममता से मार दिया जा सकता है, उसे ही जब कैद कर लिया जाता है, तो उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाता और उससे उसके देश के जीवन के मापदंड और सेना में प्राप्त पद के अनुसार बर्ताव किया जाता है ।’

मैंने उस समय यह लिखा था और आज भी इन्हे इसलिए दुहरा रहा हूँ कि श्रीमान् इसपर विचार करें ।

इसका एक दूसरा पहलू भी है । पूछताछ के सिलसिले में कहा गया था कि पुलिस को अपना काम करना ही है और ऐसे कामों में मानवी मूल्यों और सभ्य आचार पर जोर नहीं दिया जा सकता । ऐसा कहना किसी भी

जयप्रकाश की विचारधारा

सभ्य सरकार और उसकी पुलिस के लिए लज्जास्पद है। मान लीजिये, पुलिस मानवो मूल्य और सभ्य आचार पर ध्यान न दे, तो उसे कानून पर तो ध्यान देना ही है। मेरा दावा है कि मेरे साथ जो व्यवहार हुआ, वह कानून-सगत नहीं था।

समाप्त करने के पहले श्रीमान् से एक बात और कहना चाहता हूँ कि भारत-रक्षा-कानून और आर्डिनेन्सों ने इस नारकीय किले को पुलिस के लिए स्वर्ग बना रखा है। इस किले में किसी कैदी को लाकर पुलिस उसे बाहर के ससार से बिल्कुल पृथक् कर देती है, उसे किसी कचहरी या मजिस्ट्रेट के पास पेन नहीं करती और जब तक चाहे, यहाँ सड़ाती रहती है। ऐसे तीन उदाहरण मेरे सामने हैं—इन्द्रप्रकाश आनन्द, जयचन्द्र विद्यालकार और डाक्टर राममनोहर लोहिया के साथ भी मेरे ही ऐसा या उससे भी बदतर व्यवहार किया गया है। मेरा ख्याल है, ऐसे सैकड़ों मामले होंगे। मुझे ताज्जुब होगा, इस प्रान्त का सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश होने की हैसियत से यदि श्रीमान् पुलिस के जुल्मों के शिकार ऐसे निरीह बन्दियों की रक्षा करने का भार अपने ऊपर नहीं लेंगे।

अब मैं अपने कथन का सारांश दे रहा हूँ—

(क) फैसले में जो कई तथ्य बताये गये हैं, वे गलत हैं और मैंने जो तथ्य पेश किये हैं, उनका फैसले पर प्रभाव पड़ना चाहिये।

(ख) मैं जो कुछ दिनों के लिए जल्द जल्द स्टेट प्रिजनर बना दिया गया था, वह या तो इसलिए कि मेरी नजरबंदी में की गई गैरकानूनी कार्रवाई को ढँक दिया जाय या मेरे साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, उसको ओर हाईकोर्ट का ध्यान नहीं जाने पावे।

(ग) लाहौर किले में मुझे रखना बुरी नीयत का नजोजा था और है।

लाहौर किले की यंत्रणायें

(घ) मेरे साथ २० अक्टूबर से १० दिसम्बर, १९४३ तक गैरकानूनी व्यवहार किया गया, यानी, मुझे कष्ट और यंत्रणायें दी गईं ।

इसलिए मेरा निवेदन है कि ४९१ दफा के अनुसार या किसी दूसरी दफा के अनुसार मुझे यह अधिकार दिया जाय कि मैं अपने वकील के मारफत इस बात को कोर्ट के सामने पेश करूँ और इस सम्बन्ध में फ़ैसला पाऊँ । अन्तिम बात के सम्बन्ध में आपसे यह प्रार्थना है कि आप उनलोगों के खिलाफ़ मामला चलायें, जो गैरकानूनी व्यवहार करने के मुजरिम हैं और मुझे आज्ञा दी जाय कि मैं सरकार पर मुकदमा चलाऊँ, जिसके नौकरों ने मेरे साथ ऐसे बुरे सलक किये हैं ।

इस सम्बन्ध में अपने वकील श्री जीवनलाल कपूर से सलाह ले सकूँ और उन्हें अपनी बातें बतला सकूँ, इसके लिए श्रीमान् से निवेदन है कि उन्हें मुझसे मिलने की आज्ञा उन शर्तों के साथ दी जाय, जिन्हें आप उचित समझे । यह भी निवेदन है कि इसकी एक कापी उनको दे दी जाय, जिसमें वह इस बारे में योग्य कार्रवाई कर सके ।

इतना समय लेने के लिए क्षमा चाहता हुआ,

श्रीमान का अत्यन्त विश्वस्त

जयप्रकाशनारायण

कुछ फुटकर चीजे

१. हमारे मेहतर

कम-से-कम उत्तर भारत में अछूतो की जितनी श्रेणियाँ है और उनके जितने प्रकार के कर्म हैं, उनमें मेहतरों या भगियों की श्रेणी और उनका कर्म मुझे सबसे पतित मालूम होता है। जो काम हम अपने भगियों से छेते हैं, वह ऐसा काम है कि उसकी वर्तमान दशा में किसी मनुष्य को अधिकार नहीं होना चाहिये कि दूसरे, मनुष्य से वह कर्म कराये। जब जब मैंने मेहतरानियों या भगिनों को सर पर मैले का टोकड़ा या बालटी रखकर शहरों की सड़कों पर से गुजरते देखा है, तो मेरी आत्मा कांप उठी है और मैंने अक्सर अपने से पूछा है कि क्या यह काम मैं स्वयं करने को राजी हो सकता हूँ ? अमेरिका में जब पढ़ता था, तो अनेक प्रकार के काम पढाई का खर्च जुटाने के लिए किये थे। खेतों में, होटलों में, कारखानों में काम किये और अन्त में विश्व-विद्यालय में अध्यापन भी किया। इसी सिलसिले में एक बार शिकागो के एक होटल में दो सप्ताह तक एक नौगरो छात्र के साथ पाखाने भी सफ करने का काम करना पड़ा। लेकिन जिस प्रकार के वहाँ के पाखाने थे और जिस प्रकार के यन्त्रों तथा वस्तुओं से सफाई की जाती थी, वे ऐसे थे कि हाथों से ग्लोज़ का स्पर्श होता ही नहीं था और दुर्गन्ध भी नहीं के बराबर होती थी। जीवन भर यदि वही काम मुझे करना पड़े, तब तो मेरा मन अवश्य

विद्रोह कर उठे; लेकिन कुछ समय के लिए आज भी उस प्रकार का काम करने के लिए तैयार हूँ। दूसरों से भी वह काम कराने में मुझे कोई उज्र नहीं है, हालाँकि मेरी कोशिश यह अवश्य रहेगी कि अप-टु डेट ट्रायलेटो के साफ करनेवाले भी उमर भर वही धन्धा न करते रहे। लेकिन जो कर्म हमारे मेहतारों को आज करना पड़ता है, उसको ध्यान में लाने पर भी जी मितला उठता है।

पटने में एक बार मेहतारों का युनियन बनाने का ख्याल हुआ। उस सिलसिले में उनके घरों में जाना पड़ा। म्युनिसिपैलिटी की तरफ से उनके रहने की जगहें बनी हुई हैं या मुकर्रर हैं। वह जगहें इन्सान के रहने की जगहें नहीं हैं—वह नरक हैं, भीषण नरक। कम-से-कम कोई अमेरिकन किसान अपने सूअरों को भी वैसी जगहों में न रखेगा। लेकिन यह एक ऐसा रोग है, जिसकी दवा थोड़ी-सी चेष्टा करने पर मिल सकती है।

असली और जटिल प्रश्न तो यह है कि जो काम हम अपने मेहतारों से लेते हैं, उसका क्या इलाज है? एक जवाब और बहुत हद तक सही जवाब तो यह है कि हम अपने शहरों में 'पलश' तरीके के पाखाने और अन्तर-वाहिनी नालियाँ बनायें। लेकिन क्या हम अभी बहुत वर्षों तक ऐसा कर सकते हैं? मेरा अनुमान है कि बहुत मुदत तक हमारी आर्थिक दशा इस सुधार की इजाजत न देगी। तब फिर क्या इलाज है? गांधीजी के आश्रमवासी स्वयं पाखाने की सफाई करते हैं। लेकिन हमारे नगरों के बसनेवाले क्या ऐसा करेंगे? उत्तर स्पष्ट है। तो फिर क्या किया जा सकता है?

मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है। अछूतोंद्वारा या हरिजन सेवा का जो लोग काम कर रहे हैं, उनके सामने मैं यह प्रश्न रखना चाहता हूँ। सम्भव है, वह इसका कई हल निकाले। मैं यहाँ पर इतना ही और लिख सकता हूँ कि कुछ अनुभवी सैनीटरी इंजीनियरों की एक कमिटी बना ली

जयप्रकाश की विचारधारा

जाय और उसके सामने यह समस्या रखी जाय कि हमारे मेहतरों का काम किस प्रकार थोड़ा मानुषीय बनाया जा सकता है। यदि कोई उपाय नहीं निकाला जा सके, तो मेहतरों का उद्धार हम एक ही प्रकार से कर सकते हैं— यानी उनको सघटित करके उनसे पाखाने साफ करने का काम छोड़वा दें और किसी दूसरे व्यवसाय में उन्हें लगा देने का यत्न कर दें। ऐसी अवस्था में शहर के बाबू लोग या तो खुद पाखाने साफ करेंगे या नर्क में रहने का हठ और उत्तम निश्चय कर लेंगे। जिन लोगोंने (मैं भी अपने को उनमें गिनता हूँ) दूसरों को नर्क में डाल रखा है, वह यदि स्वयं नर्क का आनन्द उठायें, तो शायद समाज का कुछ कल्याण हो और हम भारतवासी कम से कम सफाई के मामूली नियम तो सीख जायें।

—लाहौर फोर्ट में

२. स्वर्गीय सत्यवती देवी

प्रिय बलभद्र जी,

किन शब्दों में अपने भाव व्यक्त करूँ ? आपने अपना जीवन-साथी खोया। मैंने तथा बहनजी के सहस्र साथियों और अनुगामियों ने भी अपना साथी खो दिया। आपका दुःख हमारा दुःख भी है, सारे देश का दुःख भी। इससे भी अविक सान्त्वना और क्या हो सकती है ? आपका तथा वन्दनाय माताजी का दुःखभार इससे हलका तो होना चाहिए।

बहनजी की दशा बिगड़ती जा रही थी, यह समाचारपत्रों से मालूम हुआ करता था; लेकिन अन्त इतना समीप था, इसको तनिक भी शक नहीं थी। खैर, बहन ने अपने घोर पार्थिव कष्ट से मुक्ति पाई और अब जहाँ

भी वह होंगी, उन्हे शान्ति ही मिली होगी। हमलोगो के लिए तो वह एक ज्योति जगा गई; प्रकाश की एक ऐसी रेखा छोड़ गई, जिसका अवलम्बन कर हम कल्याण-पथ पर नये साहस से अग्रसर हो सकेंगे। उसका वलिदान अमर रहेगा और उस अमरत्व की दो-दो वूँद पीकर हम जंसे भीरु भी वलिदान-पथ पर निर्भय हो बढ़ते जायेंगे।

इन शब्दों को उस दुःखद समाचार के मिलने के कई दिन बाद इसलिए लिख रहा हूँ कि उस समय महीने के सब खत लिख चुका था। आज १ ली तारीख को इस महीने के पत्र लिखने को मिले, तब यही पहला खत लिख रहा हूँ।

३ हमारा प्राचीन वाङ्मय

साधारणतः भारतीय हिन्दू अपने प्राचीन वाङ्मय से सर्वथा अपरिचित होता है। जो अपढ हैं, उनका तो कहना ही क्या। अधिक-से-अधिक उनके लिए इतना ही सम्भव है कि गाँवों के कथावाचकों से वे उस वाङ्मय का थोड़ा परिचय प्राप्त करें। लेकिन कथावाचक प्रायः रामायण, श्रीमद्भागवत तथा अन्य पुराणों से आगे नहीं जाते। जो पढ़े-लिखे हिन्दू हैं वे अधिकतर अंग्रेजी वाङ्मय से परिचित होते हैं। इसमें भारतीय शिक्षापद्धति का दोष तो है ही, साथ साथ संस्कृत में प्रवेश होने की कठिनाई के कारण जो अपने दर्शनादि, वेदादि को देखना भी चाहते हैं, वे उन्हे देखने के सौभाग्य से वंचित रह जाते हैं। अंग्रेजी के द्वारा इनका वे मनन कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी की इतनी योग्यता बहुत कम लोगोंमें होती है। इस परिस्थिति का नतीजा यह होता है कि हममें से अधिकांश अपने प्राचीन वाङ्मय को एक अपूर्व अग्राह्य, अगम्य वस्तु समझ लेते हैं, जिससे हमारा मानसिक स्वातन्त्र्य और हमारा स्वाभाविक विकास दब जाता है। हमारे वेद, हमारे दर्शन

जयप्रकाश को विचारधारा

हिमालय-शृंखला बन जाते हैं, जिसकी चोटी पर हमारा पहुँचना असाध्य मान लिया जाता है। इस मानसिक और बौद्धिक संकोच को मिटाये बिना हममें न विचार-स्वातन्त्र्य पैदा हो सकता है और न मानसिक साहस। यदि प्राचीन भित्तियों के आधार पर हमें सभ्यता की नई मंजिलें खड़ी करनी हैं, तो उन भित्तियों को हट कराना और उनका महत्त्व समझना आवश्यक होगा।

यह ठीक है कि हममें से जो लोग संस्कृत के आचार्य हैं, उनके लिए यह वाङ्मय गम्य और सुलभ है। लेकिन जनसाधारण की भाषा आज संस्कृत नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि हमारे समस्त प्राचीन वाङ्मय का जनसाधारण की भाषाओं में रूपान्तर किया जाय—इन भाषाओं में उर्दू भी एक है, इसे न भूलना चाहिए। आज परिस्थिति यह है कि हिन्दी या अन्य वर्तमान भारतीय भाषाओं की अपेक्षा अंग्रेजी और जर्मन भाषाओं में हमारे वेद, दर्शनादि अधिक सुलभ हैं। यदि हिन्दी को ले लें, तो इस भाषा में प्राचीन भारतीय वाङ्मय का अनुवाद करने का कार्य छोटे-मोटे प्रकाशकों का नहीं है। यह काम तो बड़ी बड़ी सार्वजनिक संस्थाओं का ही हो सकता है। क्या यह खेद का विषय नहीं है कि अमेरिका का एक विश्व विद्यालय—उदाहरण के लिए 'हरवर्ड' (Harvard)—एक प्राच्य ग्रन्थ माला (Oriental Series) का प्रकाशन करे और हमारा हिन्दू विश्व-विद्यालय कौटिल्य के 'अर्थ-शास्त्र'-जैसी पुस्तक को भी अंग्रेजी में ही पढाये। यह आशा की जा सकती थी कि यह विश्वविद्यालय पुराने वाङ्मय का हिन्दी में प्राप्य बनाने की चेष्टा करेगा, लेकिन वहाँ भी अंग्रेजी भाषा का ही साम्राज्य है। वह साम्राज्य इतना विस्तृत है कि यदि कोई वक्ता वहाँ विद्यार्थियों की सभा में हिन्दी बोलना शुरू करता है, तो चारों तरफ से 'इंगलिश-इंगलिश' का शोर मच जाता है। कम-से-कम मेरा तो दो बार का यही अनुभव है। इसका कारण यह बताया जाता है कि वहाँ देश के हर

भाग से विद्यार्थी आते हैं और विशेषकर दक्षिण के विद्यार्थी हिन्दी समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। यह भी विचित्र बात है। यदि ये दक्षिणी विद्यार्थी बर्लिन या पेरिस पढ़ने के लिए जाते हैं, तो ये चेष्टा करते हैं कि कम-से-कम समय में जर्मन या फ्रेंच समझने और बोलने की क्षमता प्राप्त कर ले। लेकिन काशी में रहते हुए भी इस बात की प्रेरणा इनको नहीं होती कि थोड़ी हिन्दी सीख लें। परंतु उनको ही क्यों दोष दिया जाय, जब स्वयं महामना पंडित मालवीयजी ने ही अपने पवित्र 'हिन्दू विद्यालय' में अंग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम बनाना उचित समझा। यह कौन कह सकता है कि लालों रुपये के खर्च से एक मंदिर बनाने का जो आयोजन वहाँ हो रहा है, वह मंदिर ही भारतीय सस्कृति को जोवित रखने का कारण बनेगा अथवा वह प्राचीन वाङ्मय के प्रकाशन का आयोजन, जिसके अभाव पर ऊपर खेद प्रकट किया गया है? उस सांस्कृतिक वाङ्मय की अपेक्षा, जिसका पुनरुद्धार तबतक असंभव है जबतक वह जनता के लिए सुलभ और सुगम नहीं बनाया जाता, महामना पंडितजी को सुखी-चूने में ही हिन्दू-सस्कृति की आत्मा उयादा सफाई से नजर आई।

मेरा ऐसा विचार है कि एक ऐसी संस्था स्थापित की जाय, जिसका केवल यही कार्य हो कि भारत के पुराने (वैदिक, अवैदिक, बौद्ध, जैन, ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक) वाङ्मय का हिन्दी में अनुवाद करे, कराये और प्रकाशित करे। व्यापारिक लाभ इस संस्था का हेतु न हो, केवल सांस्कृतिक हेतु हो। इसमें सुलझे विचार के विद्वान् हों और इसका उपयोग नत-विशेष के प्रचार के लिए न हो। विद्वानों में अंग्रेजी, जर्मन, चीनी, अरबी इत्यादि विदेशी भाषाओं के भी पंडित हों, लेकिन जहाँ तक संभव हो, सब भारतीय हों। विदेशी विद्वानों को—जिनसे सहायता लेना आवश्यक हो—एक परामर्श-दात्री समिति बना ली जा सकती है। अनुवाद

जयप्रकाश की विचारधारा

की भाषा—जैसे हिन्दी—सरल हो और (हिन्दी में), उर्दू के प्रचलित और सुबोध शब्दों का बहिष्कार न हो । आद्योपान्त कार्य-संपादन के लिए एक योजना बना ली जाय और एक निश्चित समय में कार्य को समाप्त कर देने की चेष्टा हो । इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि यह सारी योजना हमारे व्यापारी दानवीरों के विद्विलास का हेतु न बन जाय । धन के बिना यह कार्य नहीं हो सकता, फिर भी धनियों के द्वारा इस कार्य का संपादन कल्पना से परे है । यह कार्य निःस्वार्थ, निर्वोप, महामना विद्वानों का है । स्पर्धा और द्वेष से आवद्ध पंडितों को भी इससे दूर रखना आवश्यक होगा ।

लाहौर-किला, २० अगस्त १९४४

४. महादेवीजी

आज महादेवीजी के “अतीत के चलचित्र” और “स्मृति की रेखाये” समाप्त की । दूसरी पुस्तक में पहली से अधिक प्रौढ़ता है—शैली और कला की । लेकिन दोनों पुस्तकें सुन्दर हैं । अबतक हिन्दी में ऐसी चीज देखने की नहीं आई थी ।

इन पुस्तकों में उनलोगों की कथाएँ हैं, जिनके सम्पर्क में महादेवीजी किसी न किसी समय में आई हैं । बचपन के रामा से लेकर हाल के जुगिया तक का वर्णन आता है । लेखिका के सभी पात्र गरीब, दुःखी, उत्पीड़ित साधारण प्राणी हैं, जिनमें अधिकतर स्त्रियाँ हैं । लेकिन इन कथाओं से महादेवी के व्यक्तित्व का ज्ञान भी हमें हो जाता है—और कितना सुन्दर है यह व्यक्तित्व ! वह तो सहृदयता, सुशीलता और दयालुता की प्रतिमा-सी मालूम होती है । और, कठोरव्रती और कर्तव्यपरायण । मैं तो समझता था कि कवि होने के कारण उनका जीवन लिखने-पढ़ने और काव्यचर्चा में

कुछ फुटकर चीजे

ही बीतता होगा । लेकिन वह तो एक कुशल और दृढ़व्रती सामाजिक कार्य-कर्त्ता भी हैं । जितना कार्य इस दिशा में उन्होंने अबतक किया है, उसके बल पर तो साधारण तरह से लोगोंको नेतागिरी प्राप्त हो जाती है । पर इनका सब काम एकान्त और बिना विज्ञापन के हुआ है ।

सहृदयता

शोल

दुखी नारी

शुद्ध और शिव की ओर

५. विश्व-साहित्य-सार

दुनिया को उन्नत भाषाओं में—जैसे अँगरेजी, जर्मन, इत्यादि—प्रति-दिन नई नई पुस्तकें छपती रहती हैं । ये पुस्तकें साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक-विज्ञान, दर्शन इत्यादि सभी विषयों पर लिखी होती हैं । हमें इस बात की आवश्यकता प्रतीत होती है कि एक ऐसे मासिक पत्र का प्रकाशन किया जाय, जिसमें इन विदेशीय ग्रन्थों में से कुछ चुनो हुई पुस्तकों का सार दिया जाय । यह काम कोई योग्य और प्रगतिशील प्रकाशक कर सकता है, लेकिन अधिक योग्यता से इसे हिन्दी साहित्य सम्मेलन जैसी कोई संस्था हो कर सकती है । पुस्तकों का चुनाव और उनके सारांश का तैयार करना, यह कार्य एक योग्य सम्पादक-समिति के सुपुर्द होना चाहिये, जिसके सदस्य विदेशों की बौद्धिक उन्नति के सम्पर्क में हों । पंडित जवाहरलालजी इस सम्पादक-मण्डल के प्रधान यदि हों, तो मण्डल का कार्य योग्यता से सम्पादन हो सके ।

१८-९-४४

६. मुलाकात

नरेन—२० वर्ष—एम० ए० का विद्यार्थी, क्रान्तिकारी, जिला अफसर का हत्या ।

गौरी—१८ वर्ष—नरेन से देखादेखी । एक ही जाति । ब्राह्मण । नरेन व्याह नहीं करना चाहता था । गौरी को देखने के बाद राजो । व्याह के बाद हत्या । फरार । इसी अवस्था में गौरी से उसके घर जाकर मिलना । गिरफ्तार । फाँसी को सजा । गौरी का कचहरी और जेल में मिलना । नरेन की जेलर से प्रार्थना । जेलर की शर्तें । फाँसी के बाद गौरी का क्रान्तिकारी हो जाना । दादा । दूसरा हत्या । गौरी फरार । गिरफ्तारी । एक का मुख़ाबिर होना । पुरुष-वेष । पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट । फाँसी ।

७. गाँधीजी की एक चिट्ठी

प्रिय बापूजी,

चरणों में सादर सप्रेम प्रणाम ।

प्रभा के हाथों आपका जो कृपा-पत्र आया था, वह उसी समय मिल चुका था । खेद है कि अब तक उत्तर नहीं दे पाया था, क्षमाप्रार्थी हूँ ।

मैंने प्रभा से सिर्फ इतना ही कहा था कि आपसे पूछ ले कि जो पत्र लाहौर से सेवा में भेजा था, वह मिला था या नहीं । मुझे दुःख है कि उसने आपको पत्र लिखने का कष्ट दिया । फिर भी कृपापत्र पाकर धन्य हुआ हूँ ।

यह सही है कि कुछ विचार-क्षेत्रों में मैं लिचकर आपके बहुत निकट आ गया हूँ, जिससे मुझे प्रसन्नता ही मिली है । परन्तु साथ ही इस बात का दुःख बना हुआ है कि मौलिक सिद्धान्तों के क्षेत्र में आज भी अपने को आप-

से उतनी ही दूर पाता हूँ, जितना कभी भी था और कार्य क्षेत्र से तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा क्षेत्र दूर ही नहीं, बल्कि नितान्त पृथक् भी हो जायगा। इधर प्रायः जितनी घटनायें हुई हैं, उनके कारण तो मैं इस धारा में अपने को अधिकाधिक वेगवान हो हुआ पाता हूँ। अस्तु, जैसा आपने लिखा है, जेल की और बाह्य जगत की भावनाओं में अक्सर अन्तर पाया जाता है।

यों तो जेल मनुष्य के रहने का स्थान नहीं है, फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं न अपनी रिहाई के दिन ही गिन रहा हूँ, न यही सोचता हूँ कि कोई महायज्ञ कर रहा हूँ।

क्रान्तियों में कुछ का मरना, कुछ का वरबाद हो जाना, कुछ का कारागारों में सड़ते रहना अनिवार्य है। इसमें किसी प्रकार के सोच-विचार का स्थान ही कहाँ है! अभी हजारों जेल में पड़े हैं—आगे भी हजारों पड़े रहेंगे।

अब हमारे बाग के बरसाती फूलों के म्लान मुख पर बुढ़ापे की झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं। उनकी जगह लेने के लिए शीत ऋतु के फूलों के अक्षुर मिट्टी के अचल में झाँक रहे हैं। और, आजकल मेरा अधिक समय उन्हींके भविष्य के निर्माण में बीत रहा है और इस कल्पना में कि मेरी इस छोटी दुनिया के किस कोने को कौन-सा फूल आलोकित करेगा और किस क्यारी को अपने मुस्कान से ढँक लेगा।

परिस्थिति इस बात का विश्वास दिला रही है कि अपनी कल्पनाओं का मूर्त रूप अवश्य देखने को मिलेगा।

और, इसमें प्रसन्नता का ही अनुभव करता हूँ, क्योंकि अपने परिश्रम का निष्फल जाना साधारणतः मनुष्य को सख्त नहीं होता।

जयप्रकाश की विचारधारा

आशा है, इस बकवास से कुछ मनोरंजन ही हुआ होगा। फिर भी पत्र की लम्बाई के लिए क्षमा चाहता हूँ। पत्रोत्तर देने का कष्ट न करें, तो ही मुझे सतोष होगा।

बम्बई में ज्वर हो आने का समाचार पढ़कर दुःखी हुआ था। आशा है, अब स्वास्थ्य ठीक होगा। सरदार साहब के चरणों में मेरा प्रणाम। समाचार-पत्रों से यह जानकर खुशी हुई है कि उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। आशा है, शीघ्र ही पूर्ण स्वास्थ्य लाभ कर सकेंगे।

प्रभा पिछले मास के १५, १६ को आई थी। फिर इस महीने के अन्त में उसके आने की आशा है।

आपका—

जयप्रकाश

जयप्रकाश की विचारधारा
चतुर्थ खंड
आजादी के बाद

जनराज्य या हिन्दूराज्य

एक लम्बे असें के बाद आपके सामने आने का मौका मिला है। इस असें में देश में बड़ी-बड़ी घटनायें घटी हैं। उन घटनाओं का क्या महत्त्व है, मैं नहीं जानता कि आपमें से कितने भाई उसे समझते होंगे। उन घटनाओं ने देश के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है। १५ अगस्त को देश आजाद हुआ। बड़ी कशमकश के बाद हमने आजादी हासिल की। आपस में जो भी झगड़े हों, प्रवृत्तियाँ हों, रास्ते हों, लेकिन, यह आजादी बराबर कायम रहेगी, यह आम लोगों का ख्याल है। किन्तु, पिछले हफ्तों की घटनाओं ने सवाल पेश किया है कि यह आजाद हिन्दोस्तान कें दिन जिन्दा रह सकेगा ? या यह जिन्दा रहेगा भी कि नहीं ? मैं मानता हूँ, सबको इस खतरे का अनुभव नहीं हो सकता। आजाद भारत के जीने पर भी सगंय हो, इतनी दूर तक अभी बहुतों ने नहीं सोचा हो। लेकिन, यदि आप हालत को समझेंगे और सोचेंगे, तो आप भी उसी नतीजे पर आयेगे।

कुछ दिन पहले मैं दिल्ली गया था—रेल और खान के मजदूरों का सवाल लेकर। उन्होंने दिनों दिल्ली में दंगा चल रहा था। मैंने जो हालत देखी, जो तस्वीर देखी, उससे मैं बहुत चिन्तित हुआ, परीशान हुआ। सिर्फ दुःखी ही नहीं हुआ, देश के अधिकारमय भविष्य की कल्पना कर स्तब्ध रह गया। अखबारों में आपने सिर्फ यह पढ़ा होगा कि पंजाब और दिल्ली में दंगे हो रहे

जयप्रकाश की विचारधारा

दंगों में जिन लोगोंने भाग लिया था उनके सामने एक तस्वीर थी, बड़ी लुभावनी तस्वीर। वह तस्वीर थी हिन्दू राज्य कायम करने की। यह सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन, सोचिये तो रहस्य खुले। हिन्दू राज क्या है? उसमें सिक्ख क्यों रहेंगे, हरिजन क्यों रहेंगे, पारसी और ईसाई क्यों रहेंगे? हिन्दुओं में भी किसका राज—मराठों का या राजपूतों का? हिन्दू राज एक धोखा है, यह सर्वनाश का रास्ता है। जो हिन्दू राज की बात करते हैं, वे हमें आपस के झगड़े में फँसाना चाहते हैं। आज हिन्दोस्तान का एक छोटा-सा टुकड़ा निकल गया है, हम-आप सभी चिन्तित हैं। लेकिन, तो भी एक बहुत बड़ा हिस्सा एक साथ है। अगर वह हिस्सा भी टुकड़े-टुकड़े हो गया, तो याद रखिये, हमारे सारे वलिदान निष्फल हो जायेंगे। हमारे जहीद आत्मान से आँखों में आँसू भरकर हथानी और देखेंगे और हमें वागिजार देंगे—हमने, ओ कपूतो, क्या इसीके लिए अपनी जान की कुर्बानी की? तिरंगे झंडे की छाया में हमने गोली खाई, डंडे खाये, हम मिट गये; लेकिन, उसकी शान नहीं मिटने दी कि समूचे देश में इस तिरंगे के नीचे एक राज्य कायम हो, पूर्ण स्वराज्य कायम हो। और, तुम ऐसे नालायक निकले कि हमारे देश को टुकड़ों में बँटवा दिया। अब भगवा झंडा ले के क्या दंग बड़े टुकड़े को तार तार कर देना चाहते हो? बताइये, अपने शहीदों की इस उक्ति का हम क्या जवाब देंगे?

याद रखिये, हिन्दू साम्प्रदायिकता एक धरें का छत्ता है, ज़हर का गेंता है, उसे खोदकर मत उकसाइये, नहीं तो, आप हम कहीं के नहीं रह जायेंगे। आज कांग्रेस की हुकूमत है, राष्ट्रीय सरकार है, तो भी हमारे ग्रान्त में क्या हो रहा है? राजपूत, भूमिदार, कायस्थ, यादव, फुरमी आदि जातों की पाटियाँ बन रही हैं। आपस की फूट है, तू-तू में-में है, लाग तबाह हैं। फिर जब हिन्दुत्व के नाम पर आप राज्य कायम करेंगे, तो उसमें कितने भेद-

भाव होंगे, कितनी परीशानियाँ होंगी—आप सोच सकते हैं ।

मुझे सुनने में आया है, हमारे बहुत से नौजवान भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक सच में भर्ती हो रहे हैं । मैं साफ कहूँ, यह आप गलत कर रहे हैं, आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं । आज मुसलमान समझने लगे हैं कि जिना का रास्ता नाश का रास्ता है । किन्तु, कितना बड़ा अफसोस कि हमारे भोले भाले उत्साही नौजवानों को उसी नाश के रास्ते पर ले जाया जा रहा है । मैं अपने उन नौजवान साथियों से कहता हूँ—कि मैं आपका साथी हूँ, आपका सेवक हूँ । आपसे मैं पूछता हूँ कि वह कौन-सी तस्वीर थी हमारे सामने, जिसने हमें घर की माया-ममता से खींचकर बलिदान के रास्ते पर ला खड़ा किया था ? हमारा क्या उद्देश्य था हजारों तरह की मुसीबतें झेलकर आगे बढ़ने में ? क्या आपलोगों ने उन दिनों यह सुना था कि आजादी की लड़ाई हिन्दू राज्य कायम करने के लिए लड़ी जा रही है ? क्या हमारे शहीदों के सामने यह हिन्दू या सिक्ख राज्य था ? १९४२ की क्रान्ति में जो नौजवान जगल जगल घूमते रहे, जो नौजवान देश के बाहर नेताजो की फौज में शामिल हुए, क्या उनके दिमाग में हिन्दू राज था, मुस्लिम राज की तस्वीर थी ? आजादी की लड़ाई इसलिए लड़ी गई थी कि हमारे गरीब देश के लोगोंको भरपेट भोजन मिले, कपड़े मिले । हमारे लाखों भाई आज सड़कों के किनारे बाल-बच्चों को लेकर जिन्दगी गुजार रहे हैं । हम आजादी इसलिए चाहते थे कि सबके पास अच्छा घर हो और घर के अन्दर अच्छो गृहस्ता । एक अकाल आता है और लाखों आदमी मर जाते हैं । बंगाल के अकाल में ३५ लाख आदमी मर गये । हम आजादी इसलिए चाहते थे कि एक ऐसा हिन्दोस्तान बनायें, जिसमें अकाल न हो, बीमारी न हो, गरीबी न हो । अस्पताल बने, स्कूल बने । हम अपने लोगोंको सभ्य बनायें, सुसंस्कृत बनायें । समाज में घोर अन्याय है, जो मेहनत करते हैं, एँड़ी-चोटी का

जयप्रकाश की विचारधारा।

पसीना एक करते हैं, वे भूखों मरते हैं और जो कोई काम नहीं करते, ऐसा करते हैं। हम आजादी इसलिए चाहते थे कि उस अन्याय को दूर करें, उस प्रथा को दृष्टाये, जिसके चलते ऐसे अन्याय होते हैं, न कि हिन्दू राज, खालिस्तान या द्राविडिस्तान कायम करने के लिए।

हिन्दू राज की बातें करके जो लोग हमारे नौजवानों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक सघ में भर्ती करते हैं, उनसे पूछिये—क्या हिन्दू राज पहले नहीं था और आज भी नहीं है? नेपाल में तो हिन्दू ही राजा है, वहाँ का क्या हाल है, आप जानते हैं? मैं वहाँ जेल में कैद था, वहाँ के बारे में कुछ जानकारी रखता हूँ। हमारे देश में जब विदेशी राजा था, तो भी हम उस राज्य की आलोचना कर सकते थे—अखबार निकालते थे, सभा करते थे, उससे लड़ने के लिए संगठन करते थे। लेकिन नेपाल के आपके हिन्दू राज में वहाँ के गासकों के खिलाफ आप जवान भी नहीं दिला सकते। यदि ऐसी गुस्ताखी आप करे, आप को जवान खींच ली जाय, आपका सिर उतार लिया जाय। सिक्ख भाई जरा पटियाला जाकर देखे, सिक्ख राज कैसा होता है? मैसूर में हिन्दू राज्य है, जो हिन्दू प्रजा पर गोलियाँ चलवाने में नहीं हिचकता। त्रावनकोर का हिन्दू दीवान पाकिस्तान से दोस्ती गाँठने चला था। इन हिन्दू राज्यों में एक राजा है, उसके आसपास मैकड़ों जागीरदार हैं, वे जनता को लटते हैं, बीस-रानियाँ रखाते हैं, तरह-तरह के दुराचार करते हैं। ऐसे राज्यों और राजाओं के दिन लड़ गये। आज जनता का ज़माना है। हम एक ऐसी दुनिया देखना चाहते हैं, जिनमें कोई राजमुकुट पहननेवाला न रहे। जो लोग हिन्दू राज की बात करते हैं, वे प्रतिक्रियावादी हैं, वे देश को संकड़ों वर्ष पीछे ले जाना चाहते हैं।

दिल्ली में एक सज्जन मेरे पास आगे और बोले कि हमारा हिन्दू राज से मतलब है, रामराज्य ने। मैंने उनसे कहा—रामराज्य की अजल ने जो

राज्य कायम करना चाहेगा, वह पड़ोसियों के घर में आग नहीं लगावेगा, लूटमार नहीं करेगा, परायी औरतों की इज्जत नहीं छूटेगा, बच्चों को कत्ल नहीं करेगा। आग लगाकर, बलात्कार करके, कत्लेआम करके रामराज्य नहीं कायम किया जा सकता। वह तो जानवरों का राज होगा, डकैतों का राज होगा, लठैतों का राज होगा। आप रामराज्य कायम करना चाहते हैं, तो हिन्दोस्तान में एक ही व्यक्ति है, जिसके चरणों के नीचे आपको बैठना होगा, जिसके चरण-चिह्नों पर चलना होगा। वही एक व्यक्ति है, जो देश को रामराज्य की ओर ले जाना चाहता है, उसीकी तपस्या ने हमें आज्ञा दी दलाई है, उसीके तपोबल से हमारा बूढ़ा देश ससार के देशों के सामने खिर ऊँचा करके खड़ा हुआ है। उसीके उपदेशों और आदेशों पर चलकर हम रामराज्य कायम कर सकते हैं, बाकी लोग तो हमें धोखा देना चाहते हैं।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अन्दर गरीब नौजवान, स्कूल-कालेज के विद्यार्थी और छोटे-छोटे रोजगारियों और व्यापारियों के बच्चे शामिल हो रहे हैं। उन बेचारों को यह पता भी नहीं है कि इस संघ के पीछे कौन-सी ताकत काम कर रही है। देश की आज्ञा दी के लिए किसी एक भी राजा ने काम नहीं किया—वे अंगरेजों के जूते चाटते रहे। जमींदार और सेठ-साहूकार भी अंगरेजों के ही खीमे में रहे। उनमें से सिर्फ चन्द इने-गिने लोगों ने देश का साथ दिया। बाकी लोग जिस समय देश जीवन-मरण के बीच में था, चोर-बाजारी और मुनाफाखोरी से जेब गर्म कर रहे थे। गांधीजी ने पिछली लड़ाई में अंगरेजों को कोई मदद न करने को कहा। न एक पाई, न एक भाई—यह था राष्ट्र का नारा। लेकिन, ये जमींदार और साहूकार राष्ट्र की पुकार सुन सके? जेल से निकलकर मैंने भी इनसे बार-बार अपील की, लेकिन, कौन सुनता है। वे तो लड़ाई में लखपती से करोड़पति बनते रहे। हिन्दू सभा या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग भी उन दिनों

जयप्रकाश की विचारधारा

कहाँ थे ? जब फाँसी और गोली के मौके थे, तो ये विलों में घुसे रहे। लेकिन आज आज़ादी मिलते ही बाहर आये हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पीछे करोड़पति हैं, राजे-महाराजे हैं, उनका रुपया है, उनका हाथ है। उनके छिपे हुए मतलब को समझना कोई मुश्किल नहीं है। इन राजों-महाराजों, जमींदारों-साहूकारों को हिन्दोस्तान की जनता से खतरा है। आज़ादी के बाद खतरा बढ़ गया है। वे देख रहे हैं—एक तूफान, एक आंधी आ रही है। यह तूफान राजमुकुटों को सरो से गिराकर सात समुद्र पार फेंक देगा। यह आंधी तिजोरियों से नोटों के पुलिन्दों को उड़ाकर भुखमरों और भिखमरों में बांट देगी। वे इस आंधी-तूफान को रोकना चाहते हैं, किन्तु, रोकें तो कैसे ? जब अँगरेजों की तोपें कोई काम कर न सकें, तो फिर इनकी क्या विज्ञात ? तब उन्होंने एक नई चाल चली है। इनकी नई चाल यह है कि जनता को ही पथभ्रष्ट कर दें, देश की प्रगतिशील शक्तियों को दूसरे स्तर पर मोड़ दें। ऐसा सर्मा पैदा कर दें कि मजदूर राज, किसान राज की बात हवा में उड़ जाय और हिन्दू राज्य के भूल-भुलैया में सब लोग पड़ जायें; तिरंगे को लोग भूल जायें और भगवे झण्डे के नीचे सारी प्रगतिशील शक्तियाँ एकत्र होकर प्रतिक्रिया के पथ की ओर मुड़ जायें। यह भगवा झण्डा देश के लिए खतरा है, गरीबों के लिए खतरा है, आपके लिए खतरा है। हम इस खतरे का सामना करें। हम साफ बातें अपने नौजवानों से कहें। हमारे नौजवानों का हृदय साफ है। क्रान्ति और प्रगतिशीलता उनकी नसों में है, वे बहुकाव में नहीं आ सकते और जो फँस गये हैं, वे भी इस माया-जाल को छोड़कर निकल जायेंगे।

साम्प्रदायिकता आज़ादी पाने के पहले भी हमारा दुश्मन थी। अँगरेजों ने इसकी पाला-पोसा, इसकी मदद ली। फिरकापरस्ती के चलते ही देश दो टुकड़ों में बँटा। हमने अँगरेजों पर विजय प्राप्त की; पर, पूरी नहीं।

कितने दुःख की बात है, आज भी साम्प्रदायिकता हमारा दुश्मन बनी हुई है। कल उसके शिकार मुसलमान थे, आज हिन्दू होने जा रहे हैं। यह फिर हममें भगड़े पैदा कर रही है। एक बार हम आपस में लड़े, तो डेढ़ सौ वर्षों तक गुलाम रहे। यदि हमने फिर वही गलती की, तो हमारे देश पर क्या आफत आयगी, इसकी कल्पना से ही मैं घबरा जाता हूँ।

देश पर सकट है। मैं बार-बार कहता हूँ कि विश्वास रखे, यह हिन्दू-मुसलमान का भगड़ा नहीं है। इन भगड़ों की आड़ में दूसरी ताकतें काम कर रही हैं। दिल्ली में ऐसे हिन्दू नौजवान मिले, जो कहते हैं—एक दिन जवाहरलाल की लाश सड़को पर पाई जायगी। वे बेचारे नहीं जानते कि जिस दिन जवाहरलाल की लाश सड़को पर होगी, उस दिन हिन्दोस्तान की लाश ससार के सामने लावारिश पड़ी होगी।

आप पूछ सकते हैं, हिन्दुओं पर इतने आत्याचार हुए, उनका क्या जवाब? क्या हम बैठे रहे? इसका जवाब सोधा है। यदि आप समझते हैं कि आप जुल्म को जुल्म से बद कर सकेंगे, तो यह नादानी है। क्या आप दस करोड़ मुसलमानों को मिटा सकते हैं? जो 'हां' कहते हैं, वे पागल हैं। इनको मिटाने के लिए आपको भी मिट जाना पड़ेगा। जिन बातों के लिए हम जिना साहब को गाली दें, वे ही काम हम खुद करें। किन्तु, उसका नतीजा? जब बिहार में दंगा हुआ, तो लोग कहते थे—शाबास बिहारियो, अच्छा जवाब दिया, अब दंगे रुक जायेंगे। क्या दंगे रुक गये? हमने उस समय जो किया, उससे पाकिस्तान को जड़ मजबूत हुई। दुनिया ने भी मान लिया कि जब बिहार ऐसे काग्रेसी सूबा में ऐसा हो सकता है, तो दूसरी जगह क्या नहीं हो सकता? पाकिस्तान बनकर रहा।

आज तो आपको अपनी सरकार है। यदि आपपर कोई जुल्म करता है, तो उसका जवाब आपकी सरकार दे सकती है, चाहे वह जुल्म पाकिस्तान

जयप्रकाश की विचारधारा

करे या अफ्रीका—जिना करे या स्मट्स। लेकिन यह जवाब तभी मिल सकता है, जब आपकी सरकार मजबूत हो। आज तो जिना देखता है कि जवाहरलाल की हुकूमत में जवाहरलाल की बात नहीं चलती। उसका हुक्म उसके मुलाजिम नहीं सुनते। फिर उस सरकार की ताकत ही क्या है? आप दिल-दिमाग को दुस्त कर अपने राज्य को मजबूत तो बनाइये। हमारे देश में किस चीज की कमी है? कमी है तो मेहनत की, ईमानदारी की। हमारे पास कोयला है, लोहा है, अन्न है, कपास है। हमारे पास बिजली पैदा करने के सामान हैं। ३० करोड़ से ज्यादा की हमारी तायादा है। अगर हम एक राज कायम करें और मेहनत करें, तो फिर हम क्या नहीं कर सकते? १९१७ की क्रान्ति के समय उस एक हारा, थका, उजड़ा हुआ देश था। तीस साल के अन्दर उसने ऐसा सगठन किया है कि अब सिर्फ अमेरिका ही उसका मुकाबला कर सकता है। हमने भी यदि योजनाएँ बनाकर ईमानदारी से काम शुरू किया, तो हमारा देश भी उतना ही बड़ा हो सकता है। फिर पाकिस्तान की क्या हस्ती, जिना साहब की क्या ताकत जो हमारे लोगोंपर आत्याचार कर सकें? यदि आप पाकिस्तान से बदला चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि जो हिन्दू या सिक्ख पश्चिमी पंजाब से भाग आये हैं, उनकी ज़मीन और रुपये वापस हों, तो उसका एक ही तरीका है कि आप अपनी हुकूमत को मजबूत बनाइये, देश को मजबूत बनाइये। मुसलमानों को कत्ल करके आप उसका बदला नहीं चुका सकते।

मुसलमानों को यहाँ से हटा दिया जाय; ज़रा इसके बारे में भी सोचें। मैंने हमेशा लीग की मुखालफत की, जिना को मीरजाफर कहा। पंजाब में जहाँ मुसलमानों की आबादी ७०-८० सैकड़े तक है, उन जगहों में भी मैंने जिना को मीरजाफर कहा। किन्तु, मैंने जिना या लीग को सभी मुसलमानों का प्रतिनिधि नहीं माना। कांग्रेस के अन्दर भी मुसलमान हैं और बड़े बड़े

मुसलमान हैं। क्रांतिकारी आन्दोलन में रामप्रसाद फाँसी पर चढ़े, तो अशफाक भी फाँसी पर चढ़ा। आज्ञाद हिन्द फौज में सहगल थे, तो, शाहनवाज़ भी थे। हमारी पार्टी में ऐसे मुसलमान हैं, जिनपर हमें नाज़ है। फिर हम मुस्लिम लीग और मुसलमान को एक कैसे समझते हैं? हाँ, मुसलमान जनता को भड़काया गया, उसे गुमराह किया गया। हमसे भी चलती हुई कि हम मुसलमान जनता तक नहीं पहुँच सके। नतीजा यह हुआ कि लीग ने उन्हें मनमाना नचाया। किन्तु, हम उन्हें आज भी समझा सकते हैं, उनको अपनी तरफ कर ले सकते हैं। मुझे मुस्लिम जनता पर विश्वास है। किन्तु, मैं साफ कह दूँ, मुस्लिम लीग के जो लीडर आज हमारे नेताओं के साथ घूमा करते हैं और हिन्दोस्तान के प्रति राजभक्ति की कसमें खाते हैं, उनपर मेरा विश्वास नहीं है। खलिकुज्जमा साहब को आपने देखा न, उन्होंने राष्ट्रीय झंडे को सलाम किया, राजभक्ति की कसमें खाई; किन्तु, करीबी पहुँचते ही उनको राजभक्ति हवा में उड़ गई। आप ऐसे लीगी लीडरों को हिन्दोस्तान से निकाल दीजिये, मुझे कोई उज़्र नहीं है। किन्तु, आप साढ़े चार करोड़ मुसलमानों को किस तरह हटायेगे, इसपर सोचिये। आज दस बीस लाख शरणार्थियों को हटाने में आपकी सरकार को दो करोड़ रोजाना खर्च पड़ रहा है। यदि साढ़े चार करोड़ को हटाया, तो कितना खर्च होगा, यह सोचिये। और, वह पैसे आर्येंगे कहाँ से? आपकी ही जेब से तो। फिर इनके ढोने ढुलाने में जो परेशानी होगी, सारा इतजाम तखड़-पखड़ हो जायगा, उसकी कल्पना भी आप कीजिये और अत में एक बात और ख्याल कीजिये—अमना घर सबको प्यारा होता है। जिन साढ़े चार करोड़ को सगीन की नोकों से आप निकालेंगे, वे आपके जानी दुश्मन बन जायेंगे और पाकिस्तान के साढ़े चार करोड़ मुसलमानों से मिलकर हिन्दोस्तान के खिलाफ इतना बड़ा जबर्दस्त मोर्चा बनायेंगे कि हमारा सारा ध्यान लड़ने-लड़ाने में

जयप्रकाश की विचारधारा

ही लगा रहेगा; क्योंकि वे लोग अपने घरों पर फिर से कब्जा करने को छुटपटाते रहेगे। याद रखिये, प्रतिशोव की भावना सभी भावनाओं से प्रबल होती है। हमें ठंडे दिमाग से सोचना है और एक ऐसी परिस्थिति पैदा करना है, जिसमें टूटा हुआ हिन्दोस्तान फिर एक हो सके। यह तभी हो सकता है जब कि हम हिन्दोस्तान के मुसलमानों के दिल को जीतें और दिल्ली के तख्त पर एक ऐसा राज्य कायम करें, जो जनता का राज्य हो, सही मानी में किसान-मजदूर का राज्य हो। जब दिल्ली में किसान मजदूर-राज्य कायम होगा और हिन्दोस्तान के मुसलमान खुशहाल होंगे, तब पाकिस्तान के मुसलमान सोचने लगेंगे कि यह क्या? हमसे कहा गया था, दिल्ली पर हिन्दुओं का राज्य है, किन्तु वहाँ तो हिन्दुओं का नहीं, गरीबों का राज्य है। हमारे ही जैसे खेतिहरों और मेहनतकशों का राज्य है, तो वे फिर अपने यहाँ नवाबों और सरमायेदारों का राज्य वर्दास्त नहीं करेंगे। वे इस्फहानी और ममदोत के यथार्थ रूप को समझ जायेंगे और उन्हें तख्त से उतार डालेंगे। वहाँ भी गरीबों का राज्य होगा। फिर पाकिस्तान और हिन्दोस्तान के गरीब हाथ मिलायेंगे, उनका दिल एक होगा, उनका राज्य एक होगा। अपने देश से मुसलमानों को हटाकर आप यह तस्वीर नहीं खींच सकते।

ठंडे दिल से सोचिये कांग्रेस ने क्या कहा था—सभी हिन्दोस्तानी एक हैं, भाई-भाई हैं, हिन्दू-मुसलमान, सिक्ख-पारसी सभी भारत माता की संतान हैं। गांधीजी ने ४० करोड़ को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की। यह तो जिना ने कहा था कि हम अलग अलग हैं और इसलिए कहा था कि वह अंगरेजों के इशारे पर नाचते रहे। लेकिन आज अजीब हालत है। हिन्दू लोग मुस्लिम लीगी बनते जाते हैं और मुसलमान कांग्रेस की ओर आ रहे हैं। हजारों साल से लोग हमारे देश में आते रहे। आर्य, द्रूण, शक, मुगल-पठान सब आये और एक हो गये। किन्तु, यदि हमने उन्हें अलग माना, तो

निश्चय ही लोग का झुका अपने हाथ में ले लिया, हम जिना की फौज में शामिल हो गये। जिना की फौज आज टूट रही है, क्योंकि मुसलमान अब समझते लगे हैं कि उनको धोखा हुआ। वे भक्ति की शपथ लेकर काँग्रेस की फौज में शामिल होने को आतुर हैं। जिना का रास्ता पकड़कर हम सर्वनाश की ही ओर जायेंगे, यह याद रखिये।

देश के सामने नाजुक हालत है। हम अपने नौजवान साथियों से खास-कर अपील कर रहे हैं—नौजवानों, आपने इन्कलाब जिन्दावाद का नारा लगाया, वह सफल हुआ, किन्तु, सफलता आधी ही मिली है। राजनीतिक इन्कलाब में हम सफल हुए, हम आज आजाद हैं। लेकिन, दूसरा इन्कलाब बाकी है। हमें सामाजिक क्रांति करनी है। गरीबी, सामन्तशाही, पूँजीवाद और जाति भेद आदि को दूर करना है। जाति-भेद को दूर किये बिना हम उन्नति की ओर नहीं बढ़ सकते। आजादी के बाद अब समाजवाद ही एक रास्ता रह गया है। सारी दुनिया में समाजवाद की लहर है। पूँजीवाद बूढ़ा हो चला है। यूरोप में इसका जन्म हुआ, वहाँ इसके दफन की तैयारियाँ हो रही हैं। हिन्दोस्तान में समाजवाद कायम करना है, तो ऊँच नीच, जाति-पाँत का भेद हटाना होगा। साम्प्रदायिकता और फिरकापरस्ती को लात मारनी होगी। आप ही नौजवानों पर आसरा है। अफसोस, आप धोखे में आकर भगवा झंडे के पीछे दौड़ रहे हैं। आपका झंडा तिरंगा है, जिसे आपने खून से रंगा है। इस झंडे को हटाकर, काँग्रेस को मिटाकर, आप हिन्दू राज्य भी कायम नहीं कर सकते। सारा देश टुकड़े-टुकड़े में बँट जायगा। दिल्ली का गौरव नष्ट हो जायगा, राजे-महाराजों और पूँजीपतियों की चाँदी होगी, गरीब पिस जायेंगे। आप चलत जगह पर खड़े न हों। जो लोग तिरंगे के सामने सर नहीं झुकाते, वे गद्दर हैं, देशद्रोही हैं। आइये, हम देशद्रोहियों को दूर भगायें। आज भारत माता कीचड़ में पड़ी है। उसे हिमालय के शिखर पर रखें और उसके

जयप्रकाश की विचारधारा

वरदहस्त की छाया तले एक ऐसा राज्य बनायें, जो जनता का राज्य हो, किसानों और मजदूरों का राज्य हो ; जिस राज्य में सब सुखी रहें, सब धानन्द रहें ।

बापू की हत्या : जिम्मेवार कौन ?

पिछले महीनों में हमारे देश में जो दुर्घटनाएँ हुई हैं, वैसी दुर्घटनाएँ हमारे देश के इतिहास में क्या—दुनिया के किसी देश के इतिहास में नहीं हुई थीं। हाल ही में देश ने आजादी हासिल की थी कि उसके सर पर सकट के पहाड़ टूट पड़े। बड़े-बड़े सकट आये, ऋगड़े-फसाद, खून-गारत क्या-क्या न देखने पड़े हैं हमको एक बाजाप्ता लड़ाई भी कई महीनों से चल रही है। इन मुसीबतों से सारा मुल्क दबा जा रहा था कि अचानक एक ऐसी बड़ी मुसीबत आ गई, जिससे देश को कमर टूट-सी गई है। अभी हम उठकर खड़े हुए थे, कदम बढ़ा रहे थे कि गाज गिरी और हमें सर पर हाथ रखकर बैठ जाना पड़ा। अब हम किस तरह फिर खड़े होंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे किस रास्ते से जायेंगे—सारे देश के हृदय में यही प्रश्न उठ रहा है। किन्तु, इसका जवाब आसान नहीं। जो कुछ देश ने किया, उसपर पानी फिर जायगा। साठ बरस की तपस्या, त्याग, कुर्बानी व्यर्थ जायगी, यदि हमने आगे का रास्ता नहीं ढूँढ़ निकाला। चोट खाकर भी हमें सम्हलना है, कर्त्तव्य को निभाना है, सही रास्ते पर जाना है। देश पर जो मुसीबतें आईं, वे क्यों आईं, कैसे आईं—इसे समझना सबके लिए जरूरी है। जो हुआ, सो हुआ। आगे हमारी मुसीबतें आपसे आप बढ़ हो जायेंगी, यदि हम ऐसा समझें तो यह भूल होगी।

जयप्रकाश की विचारधारा

दुश्मन घर में है और उसने अपनी जड़ बहुत नीचे तक जमा रखी है। उस दुश्मन को पहचानना है और उसे जड़ से उखाड़ कर खत्म करना है।

कोई अमर होकर नहीं आया। महात्माजी कहते थे कि वह १२५ साल तक जीना चाहते हैं। वह जीना चाहते थे दुनिया के मजे लटने के लिए नहीं। और नेताओं के घर जमींदारियाँ हैं - रुपये-पैसे हैं। उनके लिए अच्छे अच्छे पद हैं, वजारात है, किन्तु गांधीजी ने तो घर को भी छोड़ रखा था, बाल-बच्चों को छोड़ रखा था। पद का सपना भी वह देख नहीं सकते थे। वह जीना चाहते थे तो देश के लिए, देश की सेवा के लिए; किन्तु ऐसे वक्त पर वह चले गये, जबकि उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। यों तो ऐसे भी बहुत-से लोग हैं, जिन्होंने उनके चरणों में बैठकर सीखा था, वे भी कहते थे—‘अब महात्माजी सन्यास ले लें, राजनीति में दखल न दें’, ‘राजनीति के सिद्धान्त कुछ जुटे होते हैं; वह महात्मा हैं, राजनीति के दांव-पेंच वे क्या जानें’—किन्तु, आप लोगों का ध्यान तो गांधीजी पर लगा था। आजाद हिन्दोस्तान की सरकार किसकी हो, गांव कैसे हों, शहर कैसे बसाये जायें, उद्योग-धन्धों की उन्नति किस तरह हो, किस तरह की शिक्षा हो, हमारा आपस का बर्ताव कैसा हो—इन सारी बातों में जनता गांधीजी ही की तरफ देखती थी। इस मौके पर वही देश को राह बता सकते थे। देश को ही नहीं—दुनिया को राह दिखाना था उन्हें। इस दुनिया में जहाँ पशुता का ही बड़ा बल समझा जाता है, जहाँ हथियार और फौज ही सबसे बड़ी शक्ति समझी जाती हैं, आज उनकी जरूरत सब दिनों से ज्यादा थी, तभी वह चले गये। जिस तरह लोग जाते हैं, वह भी चले गये होते, उनकी प्राकृतिक मृत्यु हुई होती, तो भी हिन्दोस्तान को दुख होता, तब भी यह कमी पूरी नहीं हो सकती थी। किन्तु, वह जिस तरह गये, उसने हमारे शोक को और बढ़ा दिया है, हमारी क्षति को अपूरणीय कर दिया है; किन्तु हमें सिर्फ रोना नहीं

बापू की हत्या : जिम्मेवार कौन ?

है। जिन व्यक्तियों के हथ उनका बलिदान हुआ, हमें उन्हें पहचानना है और उन्हें किस तरह पछाड़ें, शिकस्त दें—यह सोचना है। हम अंगरेजों से लड़े, उन्हें हराया, गुलामी से छुटकारा पाया, किन्तु शत्रु नये ढग का है। इन नये शत्रुओं का मुकाबला कैसे किया जाय—यही सवाल है। अंगरेजों को भी हिम्मत नहीं हुई थी कि उनकी शान के खिलाफ कुछ करें। उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, तो कभी उनके हाथ में हथकड़ियाँ नहीं डाली गईं, जेल में भी ले गये, तो इज्जत से ले गये—उसी महात्मा की हत्या एक हिन्दोस्तानी के हाथ से हो जाय, क्या यह आश्चर्य की बात नहीं मालूम पड़ती ?

याद रखिये—यह किसी पागल का काम नहीं था। किसी एक व्यक्ति ने उनकी हत्या नहीं की। देश में एक जमात थी—एक खास ढग के लोग थे, जिनका हाथ इस हत्या में था। गाँधीजी ने हमें बहुत-सी बातें सिखाई थीं। कुछ पर हमने ध्यान दिया, कुछ को अनसुनी कर दिया। दिल्ली से प्रतिदिन प्रार्थना में कितनी बातें बताते थे वे हमें। किन्तु कितने लोग उनपर ध्यान देते थे ? तो भी वह हमें बताते जाते थे। किन्तु, वह हमें यह नहीं बता सके कि जो लोग हमारी आजादी को बर्बाद कर देना चाहते हैं, उनसे हम किस तरह से बचे। जो उनकी जिन्दगी से नहीं सीख सके, अब हम उनको कुर्बानी से तो सीखें। तीन महीने पहले मैंने अपने एक भाषण में कहा था कि देश में एक अजीब ताकत पैदा हो गई है। उस ताकत ने दिल्ली में दस दिनों तक गजब मचा रखा था। वह मुसलमानों की ताकत नहीं थी। वे तो पनाह माँग रहे थे—भागते जा रहे थे। खतरा था उन हिन्दुओं से, उन सिक्खों से, जिन्होंने लूटमार मचा रखी थी, जिन्होंने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि इस हुकूमत को जनता के हाथों से, जनता के प्रतिनिधियों के हाथों से छीन लेंगे। वे सरेआम कहते थे कि हम बर्मा की हालत यहाँ भी करेंगे;

जयप्रकाश की विचारधारा

गांधी और जवाहर की लक्ष्मी दिल्ली की सड़कों पर तड़पती होंगी। मैंने आपको उन दिनों आगाह किया था और आपको बताया था कि आजादी की लड़ाई क्यों लड़ी गई। गरीबों को तकलीफ दूर हो, जनता का राज हो, भूखों को भन्न मिले, फटेहालों को कपड़े मिलें, बीमारों को दवा मिले, स्कूल कालेज खुलें, कृषि और उद्योगों की तरक्की हो—आजादी की लड़ाई इसलिये लड़ी गई थी। हमारे देश में उलटी गंगा बह रही है; मेहनत करनेवाले तो भूखों मरते हैं और बैठे-ठाले लोग मौज करते हैं, सेवा कराते हैं। ऐसा राजतन्त्र, ऐसा आर्थिक-तन्त्र देश में हो, जिसमें मेहनत का बँटवारा न्याय के अनुसार हो। आजादी की लड़ाई अलवर ने, खालियर ने या पूंजीपतियों और करोड़पतियों ने नहीं लड़ी। वे तो अँगरेजों के जूते झाड़ते रहे। लड़े गरीब। तो राज भी गरीब का होना चाहिये। यही समस्या है—सबसे बड़ी समस्या। एक इन्कलाब हो चुका है—दूसरा इन्कलाब होना चाहिये। राज में क्रांति हो चुकी है, अब समाज में क्रांति होनी चाहिये। एक ऐसा समाज बनाना चाहिये, जिसमें नीच-ऊँच का भेद न रहे; कोई राजा और कोई रक्त न हो। यह काम अँगरेजी राज के हटाने से भी बड़ा काम है; किन्तु, यह होकर रहेगा। दूसरा इन्कलाब भी जल्द आनेवाला है। कांग्रेस तो कोई सोशलिस्ट संस्था नहीं। उसकी भी आर्थिक समिति की रिपोर्ट से जो सूत निकली है, आपने देखी होगी। उसमें भी समाजवाद है, जिससे कलकत्ता और बम्बई के पूंजीपतियों के मुँह में तहलका मच गया है और वे तार-पर-तार दिल्ली भेज रहे हैं।

यह जो शक्तियाँ इन्कलाब से घबराती हैं, उनके पास अँगरेजों की तरह के कोई साधन नहीं कि जनता का मुकाबला कर सकें। वे राजे, वे नवाब, वे सेठ, वे साहूकार क्या खाकर जनता का सामना कर सकेंगे? उनके पास न फौज है, न कोई जासन-यन्त्र है, इसलिए इन्होंने कुछ ऐसे दपाय

बापू का हत्या : जन्मवार कौन ?

सोच निकाले हैं कि जिनसे इनकी रक्षा हो सके। इन्कलाब से हमी सबक नहीं लेते हैं, जनता के दुश्मन भी सबक लेते हैं। वे देखते हैं कि बहुमत गरीबों का है। गरीबों का स्वार्थ एक है, उनकी तकलीफें एक हैं और उन तकलीफों को दूर करने का तरीका भी एक है। वह तरीका है, जनता का जबर्दस्त संगठन। जब सब गरीब एकत्र हो जायेंगे, हमारी सत्ता छीन लेंगे, हमारे राज-पाट, बैंक, कारखाने सबपर कब्जा कर लेंगे। इसलिये कोई ऐसा रास्ता निकालो कि गरीब एक न हो सकें। अंगरेजों से उन्होंने सबक लिया है। हम आपस में झगड़ रहे थे कि अंगरेज भा गये और इस झगड़े को हमेशा बढ़ाते रहे, और वे तबतक बने रहे, जबतक हम एक न हो गए। कांग्रेस ने सबको एक किया। अब ये सरमायेदार जागीरदार यह चाह रहे हैं कि उस एकता को तोड़ दें—जनता को आपस में लड़ा दें। ऐसी हालत पैदा कर दें कि हिन्दू किसान मुसलमान किसान का गला काटें, पठान मजदूर सिक्ख मजदूर के पेट में छुरा भोक दें—यही नहीं, बंगाल-बिहार का झगड़ा हो, गुजरात-महाराष्ट्र का झगड़ा हो, यों तरह-तरह के झगड़े हों कि सारी जनता, जो उनकी ओर बढ़ी आ रही है, वह पथ-भ्रष्ट हो जाय—उद्देश्य को भूलकर बीच में उलझ जाय। मैंने आपको कहा था कि यह जहर इटाइए। मुसलिम लीग के नेतृत्व और अंगरेजों के षड्यन्त्र से देश के तीन टुकड़े हो गए हैं। यदि हमने इन्हे नहीं रोका, तो जनता के राज की बात तो दूर, देश ३०० टुकड़ों में बंट जायगा। एक हिन्दू राष्ट्र नहीं हो सकता। जब हिन्दू राज्य होगा, तो सिक्ख राज्य क्यों नहीं? बौद्ध, जैन, पारसी, आदिवासी इनके भी अलग-अलग राज्य क्यों न बनेंगे? फिर हिन्दुओं में भी किनका राज्य? राजपूतों का राज्य, जाटों का राज्य, ब्राह्मणों का राज्य—किनका-किनका राज्य? भरतपुर के जाट दिल्ली पर आख गड़ाए हुए हैं। राजपूताने में राजपूतों का राज—किन्तु वहाँ भी उदयपुर का राज्य या जयपुर का

जयप्रकाश को विचारधारा

राज्य ? और, मराठों का राज्य हो, तो शिवाजी के देश-घर कोल्हापुरवालों का राज्य या बड़ौदा अथवा ग्वालियर का राज्य ? याद रखिये, इन राजाओं में देश की भक्ति नहीं है। इनका अपना-अपना स्वार्थ है। होई लगेगा और फैसले के लिए कोई गोलमेज कान्फ्रेंस नहीं बैठेगी, तलवार से फैसले होंगे—खून की नदी बहेगी, देश सैकड़ों टुकड़ों में बँट जायगा और हमारी वही हालत होगी, जो मुगल सल्तनत के बिगड़ने पर हुई। फिर ? गुलामी को आने से भी हम नहीं रोक सकेगे; हम गुलाम होकर रहेंगे।

जिस समय मैंने ये बातें कहीं, उस समय अखबारों ने मेरी खिल्ली उड़ाई, नेताओं ने मुझपर फबितियाँ कसीं; किन्तु, जिनके दिमाग के दरवाजे बन्द थे, अब खुल जाने चाहिए। यदि साम्प्रदायिकता रही, तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। भिन्नताओं की हममें कमी नहीं। भिन्नताओं को अलग करके ही हमने आजादी हासिल की। इन भिन्नताओं को दबा कर ही हम उसे क्रायम रख सकते हैं। लोहार लोहे को गरम करके, पीट करके, तब तलवार या हल बनाता है। यदि हमने यह नहीं किया, तो महात्माजी का बलिदान निष्फल जायगा। सबसे पहले हम हिन्दोस्तानी हैं, उसके बाद हिन्दू या मुसलमान, बिहारी या बंगाली। जब तक हम ऐसा नहीं सोचते, तब तक देश बच नहीं सकता। तब तक हमारा कोई भविष्य नहीं। यही महात्माजी बार बार कहते रहे और अपना शानदार शहादत द्वारा चलते चलते फिर अन्त में उन्होंने हमें यही बताया है। १५ अगस्त के बाद हम कई कदम पछे ही गये हैं, आर्थिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से भी। दुनिया में जो हमारी इज्जत थी, उसे भी हमने धूल में मिलाया है। यह रुशो की बात है कि हुकूमत की भो आँखें खुली हैं और उसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनकी तरह की दूसरी फिरकापरस्त जमातों को गैरकानूनी करार दिया है। हम पहले से ही आगाह कर रहे थे, किन्तु देश के नेताओं ने ध्यान नहीं

बापू की हत्या : जिम्मेवार कौन ?

दिया। यहाँ बिहार राष्ट्रीय स्वयंसेवक सघ की रैली हुई और उसमें कई वजीर तक गये। ऊपर से देखने पर तो कवायद अच्छी लगती ही है। किन्तु, असल चीज थी उनकी अदरुनी सर्किल। उस सर्किल में लेकर तब वे भेद बताते थे। हमने ये बातें जनता के सामने रखी, कांग्रेस के सामने रखीं? किन्तु दुश्मन हूकूमत के साथे में पलता रहा, बढ़ता रहा। हूकूमत बदलने को सबको हक है, किन्तु उसका तरीका क्या हो? सावरकर या गोडसे जनता से कहे कि यह खराब राज है। जब चुनाव हो, तो जनता से कहें कि वह उन्हें ही वोट दे और जनता यदि हत्यारों का ही राज चाहे, उन्हें ही वोट दे, तो यही सही। आखिर लोग आत्म-हत्या भी तो करते ही हैं। यदि जनता आत्म-हत्या ही करना चाहे, तो उसे कौन रोक सकता है? किन्तु जब सैकड़ें निनानवे लोग नेहरू का राज चाहते हैं, तब सैकड़ें एक बम-पिस्तौल से इस राज को उलटाना चाहें—यह तो देश के साथ, जनता के साथ गद्दारी है। अँगरेजों के खिलाफ हममें से कुछ ने पिस्तौल चलाये, बम फेंके; क्योंकि वह राज जनता की इच्छा के खिलाफ देश पर लादा गया था। इसलिये हमें यह हक था कि उसे उलट दें। किन्तु, जो राज प्रजा की इच्छा से कायम हुआ, उसके साथ यह सलूक करना तो प्रजाविद्रोह है, प्रजा के साथ गद्दारी है। ऐसा राज प्रजा-राज नहीं कहा जा सकता, वह तो कातिलों का राज होगा, लुटेरों का राज होगा, चाहे ऐसे लोग राजा हों या नवाब, पूँजीपति हों या करोड़पति।

दिन दिन यह खतरा बढ़ता जा रहा था। हम गला फाड़-फाड़कर चिल्ला रहे थे। आखिर कांग्रेस का ध्यान इस ओर गया और दिल्ली में जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी की बैठक हुई, तो उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक सघ के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ। उस प्रस्ताव को खुद गाँधीजी ने अपने हाथों से लिखा था और बताया था कि यह सघ देश के लिए मिनेस है, खतरा है—

जयप्रकाश की विचारधारा

किन्तु, तीन महीने हो गये केन्द्रीय सरकार ने या सूबाई हुक्मर्तों ने उसे दबाने के लिए क्या किया ? कांग्रेस की संस्था सर्वव्यापी है, गाँव-गाँव तक उसकी पैठ है । प्रान्तीय सरकारों और कांग्रेस संस्थाओं ने उस तरह काम किया होता, जैसा हमने किया, तो शायद हमने महात्माजी को नहीं गँवाया होता । मैंने पूना में, जहाँ इस सघ का गढ़ है और जहाँ इसके गुप्तजी का घर है, हेडगवार साहब, जो ट्रिटर से सीखकर आए थे, उनके घर में भी खुलेआम सघ की भर्त्सना को । मेरे पास संघवालों ने धमकी के खत भेजे, लेकिन मैं सब जगह गया और बोलता रहा; किन्तु कांग्रेस के कुछ नेताओं ने, कुछ वजोरोँ तक ने कहा कि यह तो देशप्रेमियों की संस्था है । मुझे इससे चोट लगी । यह गैरजिम्मेवारी क्यों ? गाँधीजी की इस हत्या की जिम्मेवारी उन सब लोगोंपर है, जिन्होंने साम्प्रदायिकता से समझौता किया । सिर्फ महात्माजी की हत्या ही उनका उद्देश्य नहीं था । उनके बाद बड़े पैमाने पर हत्याएँ करने का षड्यन्त्र था । इन हत्याओं से-वे दिल्ली की हुक्मत उलट देना चाहते थे । उनके आदमी हुक्मत में थे, पुलिस में थे, सिविल सर्विस में थे, सेक्रेटेरियेट में थे । उनका आयोजन था कि जब दिल्ली पर ये हमला करेंगे, तो उनके ये सब-के सब लोग उनकी मदद करेंगे । यह खतरा अभी टला नहीं है । चन्द गिरफ्तारियों से कुछ होने-जाने का नहीं । मजबूत हाथों से इनका सर कुचलना होगा, साथ ही जनता में पूरा प्रचार करना होगा । ये नौजवान क्यों सघ में गये ? उनमें शक्ति थी, उमर था । हम कहते रहे कि उनके लिए कोई रास्ता बनाइये । एक ऐसी सिविल-गार्ड, नैशनल-गार्ड बने, जिसमें हम नौजवानों को भर्ती करें, उन्हें कयायद सिपायों, हथियार चलाना सिखायें, उन्हें बौद्धिक शिक्षा दें । किन्तु ऐसा किया गया ? नैशनल गार्ड की बात में भी बड़ी नौकरशाही तरीका—जैसे हजार वर्ष में नया हिन्दोस्तान बनेगा ।

बापू की हत्या - जिम्मेवार कौन ?

जैसा मैंने कहा, सकट उला नहीं है और हमें उसका सामना करना है। उसी उद्देश्य से हमने दिल्ली में एक बयान दिया। उस बयान को लेकर तरह-तरह की गलतफहमियाँ फैलायी जा रही हैं। यहाँ भी कहा गया है कि मैं उन गलतफहमियों को दूर करूँ। आप मेरे अपने हैं। मैं आपके घर का हूँ। आपको भी मेरे बारे में गलतफहमी हो, ऐसी उम्मीद मुझे नहीं थी। किन्तु, दुर्भाग्य से, ऐसे अवसर हैं, जिनकी नकल करोड़पतियों और महाराजाओं के हाथ में है। वे जिस तरह प्रचार कर रहे हैं, उनके चलते आपके दिल में गलतफहमी हो जाय, तो आश्चर्य की बात नहीं। किन्तु, आप मेरी नीयत पर शक करें, तब मुझे दुःख होगा। मैं गलती कर सकता हूँ, मतभेद भी हो सकता है; किन्तु, यह कहना कि मैं महात्माजी की हत्या से फायदा उठाना चाहता हूँ, मेरे साथ अन्याय करना है। १९३० से ही बिहार में सोशलिस्ट पार्टी कायम है। दूसरों की गलती से हमने कभी नहीं फायदा उठाया। फिर महात्माजी की हत्या से फायदा उठाना चाहूँ, तो मुझे सार्वजनिक जीवन में रहने का कोई हक नहीं। व्यक्तिगत रूप से मैं उनके कितना निकट था, आप जानते हैं। मेरी पत्नी और मुझे उनके निकटसम्पर्क का सौभाग्य प्राप्त था। आर्थिक प्रश्नों पर भी इधर उनसे मेरा बहुत-कुछ मत साम्य हो-चला था। किन्तु, ऐसे भी अवसर आये हैं कि मैंने उनसे मतभेद प्रगट किया। किन्तु, इस मतभेद में बदतमीजी नहीं, अश्रद्धा नहीं आने दी। फिर उनके सठ जाने के बाद मैं फायदा उठाना चाहूँ, तो मेरे लिए राजनीतिक जीवन में रहने का स्थान नहीं। मेरा यह पक्का विश्वास है कि गांधीजी की हत्या इसलिये हुई कि हमसे गलतियाँ हुईं, हमारे नेताओं से गलतियाँ हुईं। मैं भाग्य नहीं मानता कि मान बैठूँ, यही होना था। यदि हमने जनता को सघ के खतरों से आगाह किया होता, हमारे वजीर सघ के जलजों में शामिल नहीं हुए होते और उसकी तारीफें नहीं किये होते, यदि हमने नौजवानों

जयप्रकाश की विचारधारा

को समझाया होता, उससे दटाया होता, तो मेरा विश्वास है, हमने गांधीजी को नहीं खोया होता। गांधीजी की रक्षा का जो इन्तजाम था, उसमें भी त्रुटियाँ थीं। हमसे गलती हुई है, तो हमें साफ स्वीकार करना चाहिए। किन्तु, हम तो बातों पर हमेशा लीपा-पोती करते हैं। बिहार में इस छोटे की बात लीजिये। इतना हल्ला मचा, फिर वही लीपा-पोती हुई। मैंने समझा था कि सत्य कहने से हम गाली सुनेंगे। तो भी उसे जनता के सामने रखना ही चाहिये। यही हमारी मशा थी। किन्तु, हमें गालियाँ ही गालियाँ मिलीं। कहा जाता है, गांधीजी गये, तो जयप्रकाश को पद की उत्सुकता हुई है। मैं पद चाहता, तो पहले मिल गया होता। ऐसे पद, जिनके लिए खुशामदें होती हैं, सिफारिशें होती हैं। मंत्री का पद भी मेरे लिए दूर नहीं था। खुद महात्माजी ने कई बार चर्चा की थी। मैं ज्यादा अक्लमन्द नहीं; किन्तु, इतनी अक्ल तो मुझमें थी ही कि यदि मैं पद चाहता, तो खुशामद करता, न कि इस तरह की निर्भीक बातें कहता। यह निर्भीकता अपने माला-पिता से सीखी, आपसे सीखी और गांधीजी से सीखी। खैर, इस वयान से किसीका नुकसान नहीं हुआ; नुकसान हुआ, तो मेरा ही। एक सभा में मैंने पटेल और नेहरू के मतभेदों की चर्चा की, तब भी फन्तियाँ कसी गईं कि शोक-सभा में यह चर्चा ठीक नहीं। दिल्ली में जितनी शोक-सभायें मैंने कीं, उतनी दूसरे किसी ने नहीं की। इन बीसों सभाओं में से सिर्फ एक में मैंने इसकी चर्चा की और वह भी खास उद्देश्य से। दिल्ली में यह आम चर्चा थी कि पटेल और नेहरू में हर मामले में मतभेद है। बड़े-बड़े लोगों के हलके में भी यही चर्चा। विदेशी अखबारों तक में भी यही चर्चा। मैं चाहता था कि उसे सामने रख दूँ कि हमारे वं दोनों नेता इस भ्रम को दूर कर दें और जनता को विश्वास दिलावें कि दोनों मिलकर आगे का रास्ता बतावेंगे। मुझे खुशी है कि इस काम में भी मुझे कामयाबी मिली और दोनों नेताओं के जो वयान छपे हैं।

बापू की हत्या : जिम्मेवार कौन ?

उनसे बात साफ हो गई है ।

दिल्ली की वर्तमान हुकूमत से बहुत लोग सतुष्ट नहीं हैं । जब साम्प्रदायिकता से लड़ना है, तो फिर उसमें हिन्दू-सभा या अकाली दल के लोग क्यों रहें । मन्त्रिमण्डल कोई दुर्घटना होने पर ही बदलता है । लड़ाई के जमाने में चर्चिल और रूजवेल्ट ने कई बार अपने मन्त्रिमण्डलों में परिवर्तन किये । अंगरेजों पर आज आर्थिक सकट है । इस सकट के मुकाबिले में एटली ने अपने मन्त्रिमण्डल में कितने ही क्रान्तिकारी परिवर्तन किये हैं । मैंने कहा—हमारे लिए यह भी तो महान सकट आन पड़ा है, यही मौका है कि मन्त्रिमण्डल में परिवर्तन किये जायें । साम्प्रदायिक लोगोंको वहाँ से हटाया जाय और उन्हें भी, जो हमेशा दुश्मन की कतार में रहे हैं । यह जनता की हुकूमत है; यह पूँजीपतियों की हुकूमत नहीं । तो भी अभी हाल में एक नेता ने पूँजीपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि घबराते क्यों हो, एक वजीर को हमने इसी-लिये रखा है कि वह तुम्हारे प्रतिनिधि हैं । आप ही बताइये, क्या इस तरह का आश्वासन जनता के हित के लिए है ? मन्त्रिमण्डल में परिवर्तन करने की बात कहकर मैंने कोई बेमौके बात नहीं कही है, यह मेरा आज भी विश्वास है ।

किन्तु यह तो कैफियत है, जो आप लोगों को ठे देना जरूरी था, क्योंकि आप मेरे अपने हैं । लेकिन असल बात तो वह है, जो कि मैंने आपसे पहले कही । यह जो कुछ गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, उनका होना जरूरी था । किन्तु इन गिरफ्तारियों से साम्प्रदायिकता दूर होने को नहीं । फिर सघ या मुस्लिम लीग के नेशनल गार्ड को गैर-कानूनी करार दिया गया, किन्तु मैं पूछता हूँ कि महासभा या मुस्लिमलीग को भी गैर-कानूनी करार क्यों नहीं दिया जाता । यह कहना कि इन सस्याओं को दबाना प्रजातंत्र को दबाना होगा, बिल्कुल गलत बात है । यदि हमें एक संयुक्त राष्ट्र बनाना है, तो राष्ट्रीय एकता को

कायम रखना होगा । धर्म के नाम पर वोट मांगने का हक देना उस राष्ट्रीय एकता को तोड़ना है । आर्थिक कार्यक्रम के बदले धर्म के नाम पर वोट मांगने की इजाजत अगर हम देंगे, तो हमारे राजनीतिक जीवन में एक ऐसी बाधा पड़ेगी कि हमारे लिए कहीं ठिकाना न रहेगा । जिस समय पाकिस्तान बना, सोशलिस्ट पार्टी ने उसी समय कहा था कि देश में किसी साम्प्रदायिक संस्था के लिए इजाजत नहीं होनी चाहिए । हम आज भी कहते हैं कि तुरत कानून बनाना चाहिये कि कोई भी संस्था एक जात, फिरका या धर्म के नाम पर राजनीतिक क्षेत्र में काम नहीं कर सकती । पहले हमारी आवाज नहीं सुनी गई । महात्माजी के इस महान वलिदान के बाद भी तो हमारे इस कथन की सचाई को समझने की कोशिश की जाय ।

सबसे बड़ा खतरा तो उन लोगों से है, जो हुकूमत के अन्दर रहते हुए भी संघ के हृदय हैं । बिहार के कुछ बड़े पुलिस अफसरों पर भी यह इलजाम है; उसका एक सबूत भी हमारे पास है । बिहार में संघ का सचालक कोई जोशी नाम का आदमी था । भारत सरकार ने संघ को गैर-कानूनी घोषित किया, उसके तीन दिनों के बाद जोशी के घर की तलाशी हुई । अंगरेजों के जमाने में कांग्रेस जब गैर-कानूनी होती थी, उसी आधी रात को सारे देश में तलाशियाँ हो जाया करती थीं, गिरफ्तारियाँ हो जाया करती थीं । आज तो अपना राज है । और भी मुस्तैदी से काम होना चाहिये । फिर यह कैसी बेवकूफी की बात कि तीन दिनों के बाद हमारे पुलिस अफसरों की नाँद टूटे । मैं उन लोगों में से हूँ, जो यह मानते हैं कि सरकारी मुलाजिमों को भी अधिकार है कि वे राजनीतिक ख्याल रखें और अपनी पसन्द के राजनीतिक दलों के लोगों को ही वोट दें । सरकारी अफसर भी तो नागरिक हैं । उन्हें नागरिकता का हक क्यों न मिले ? लेकिन हुकूमत के अन्दर एक आतंकवादी जमात के मेम्बर हों, यह बहुत बड़े खतरे की बात है । अफसोस की बात है कि ऐसे

बापू की हत्या : जिम्मेवार कौन ?

लोगोंपर दिल्ली या यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई है । जिसका नमक खाते हैं, उसीके साथ गहारी । ऐसे लोगोंको मुहकमे से हटा देना चाहिये । मेरा बस चले, तो उन्हें न सिर्फ़ डिसमिस किया जाय, बल्कि उन्हें जेल में डाल देना चाहिये ।

साम्प्रदायिकता का अन्त सिर्फ़ सरकार को ही नहीं करना है । आपलोगों का भी इसमें कोई कर्त्तव्य है । यथार्थ बात तो यह है कि साम्प्रदायिकता आप ही मिटा सकते हैं । आपमे से एक एक का यह धर्म होना चाहिये कि जहाँ भी साम्प्रदायिकता देखिये, उसका सर कुचल दीजिये । जो भूले हुए लोग हैं, उन्हें समझाइये, अपने में लाइये, किंतु जो राष्ट्रवाद के खिलाफ़ करते या कहते हैं, उनका स्थान अपने समाज में कोढियों का-सा कर दीजिये । वे हर जगह से अपने को निकाले हुए समझें । नौजवानों से मेरी खास अपील है । आप अपनी जिम्मेवारी समझे और फिरकापरस्ती से लड़ें । हमारे सर पर जो कलक का टीका लग गया है, उसे नौजवान ही धो सकते हैं । हमारा कितना बड़ा पतन हो गया है । हमारे देश में ऐसा दुष्कर्म कभी नहीं हुआ था । बहुत से देश मिट गये, किंतु हमारा देश इसीलिए बचा रहा कि हममें उच्च कोटि की नैतिकता थी । दूसरे देशों की तरह हमने सेनापतियों या सम्राटों की पूजा नहीं की । हमने हमेशा महात्माओं और अर्म गुरुओं की पूजा की, किंतु आज हमारा इतना पतन हो गया है कि हमने सबसे बड़े महात्मा की हत्या कर डाली है । हम पशु हो गये हैं । हमें पशुता से मानवता की ओर बढ़ना है । महात्माजी ने हमें बताया था कि अत्याचार का बदला हमें अत्याचार से नहीं लेना है । अगर पाकिस्तान में लूट होती है, तो हम भी लूट-मार करें बच्चों की हत्या करें, औरतों की इज्जत लूटें । यह धर्म नहीं, न्याय नहीं, इसमें देश का कल्याण नहीं । नोआखाली का बदला हमने बिहार में लिया, लेकिन उसके बाद क्या आया ? पाकिस्तान बनकर रहा लूट-हत्या बढ़ती

जयप्रकाश की विचारधारा

गई और अन्त में हमें महात्माजी से हाथ धोना पड़ा। महात्माजी ने पाकिस्तान नहीं मंजूर किया था, न हमने किया था। पाकिस्तान तो मंजूर किया था पटेल साहब ने, नेहरू साहब ने। अब मुसलमानों की भी आँखें खुल रही हैं। जिन लोगों ने पाकिस्तान के नाम पर उन लोगों से वोट लिए, वे उन्हें छोड़ कर चले गये। यदि इसपर भी वे गद्दारी करें, तो उन्हें गोली से उड़ा दो। किंतु याद रखो, गद्दारों की कमी हिंदुओं में नहीं है। जिन्होंने गांधी या नेहरू की गिरफ्तारी की, क्या वे मुल्क के गद्दार नहीं थे? जो आज भी सरकारी मुहकमों में घूसखोरी करते हैं; आजाद हिंदोस्तान में घूस—क्या यह गद्दारी नहीं है? जिन व्यापारियों ने चोरबाजारी की, क्या वे गद्दार नहीं? जो लोग त्रिवेणी सघ, भूमिहार सभा आदि बनाकर जाति के नाम पर वोट मांगते हैं, क्या उनसे भी बढ़कर कोई दूसरा गद्दार है? इन गद्दारों को पहले खतम करो, तब मुसलमानों की ओर नजर डालना। हमारे देश में हमेशा से तरह-तरह के धर्म रहे हैं, तो भी हममें एकता रही है। यही भारत की मिट्टी की खूबी है। महात्माजी की इस शिक्षा को जिदगी में उतारो और अपने देश के नये निर्माण में लग जाओ। हमें नये गाँव बसाने हैं, नये शहर बसाने हैं, एक नई जिदगी, सस्कृति का निर्माण करना है। एक ऐसा हिंदोस्तान बनाना है, जिसमें शोषण न हो, दोहन न हो, भुखमरी और फटे हाली न हो। ऐसे नये भारत की रचना करने से ही दुनिया में हमारी शान होगी—यही कल्याण का मार्ग है। महात्माजी ने अपने जीवन भर हमें यही शिक्षा दी। हम उनकी मृत्यु से यही शिक्षा लें।

काँग्रेस मर गई

हिन्दोस्तान में राजनीति जो नई करवट ले रही है, उसमें किसान-मजदूरों का ज्यादा हिस्सा होगा। इसलिए, यह जरूरी है कि किसान-मजदूर इस नई राजनीति के लायक बनें और उसमें उनका क्या जिम्मेवारी हो, इसपर हम गौर करें।

सोशलिस्ट पार्टी काँग्रेस से अलग हो चुकी है। यह क्यों अलग है, इसपर तरह-तरह की बातें पूछी और कही जाती हैं। इधर काँग्रेसी मंत्रिमंडलों के काम से जनता बहुत असंतुष्ट हो गई है। लेकिन काँग्रेस के प्रति जो पुरानी श्रद्धा है, वह बहुत अशों में बनी हुई है। इसलिए, जनता भी यह ठीक नहीं समझ पा रही है कि आखिर हम काँग्रेस से क्यों अलग हुए। आखिर काँग्रेस के भंडे के नीचे ही लड़कर तो हम देश को आजाद कर सके हैं, काँग्रेस में पं० जवाहरलाल नेहरू और डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ऐसे नेता हैं, जिन्होंने जनता की अनुपम सेवा की और कर रहे हैं। फिर काँग्रेस में रहकर उनकी मदद करना चाहिए या उनका साथ छोड़ देना चाहिए। और, फिर जो लोग निकल चुके हैं, उनकी हस्ती ही क्या है? अभी तो ये लोग नवयुवक हैं, न इन्हें उतना अनुभव है और न इतनी प्रसिद्धि। अगर चुनाव ही करना है, तो हम पुराने नेताओं का साथ क्यों छोड़ें और क्यों नये लोगो-

जयप्रकाश की विचारधारा

का साथ दें—ऐसी बात बार-बार उठाई जा रही है और उठाई जायगी। इसलिए सबसे पहले हमें कांग्रेस के बारे में ही समझ लेना है।

कांग्रेस क्या थी और आज कांग्रेस क्या हो चली है—क्या आप लोगों ने इसपर गौर किया है ? कांग्रेस एक संयुक्त मोर्चा थी, अंगरेजी साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए। इस दृष्टि से कांग्रेस एक सेना थी, एक फौज थी। देश को आजाद करने के लिए शान्तिमय तरीके से लड़ना उसका उद्देश्य था। देश को आजादी मिल चुकी, अंगरेजी फौज की आखिरी टुकड़ी भी हिन्दोस्तान से जा चुकी। देश में इस समय देशवासियों का राज्य है—जो दो चार अंगरेज रह गये हैं, उन्हें हम नौकर की तरह रखे हुए हैं। इस तरह हमने पूर्ण स्वराज्य कायम कर लिया, जो कांग्रेस का लिखित उपदेश था। जब वह उद्देश्य पूरा हो गया, तो फिर कांग्रेस की जरूरत ही क्या रह गई। साफ बात यह है कि १५ अगस्त के बाद कांग्रेस वह कांग्रेस नहीं रही। अब वह एक विलकुल नये ढंग की सस्था हो गई है। यह नये ढंग की कांग्रेस का काम रह गया है, अंगरेजों के हाथ से छीने गये राज्य का संचालन करना। यों जहाँ कांग्रेस पहले राज्य से लड़नेवाली सस्था थी, वहाँ अब वह गुद राज करनेवाली सस्था बन गई है। जब वह विदेशियों से लड़ती थी, तब उसका विरोध करना देशद्रोह था। किन्तु, जब उसका रूप बदल गया, तो फिर उससे जुदा होने या उसका विरोध करने में वह पुरानी बात नहीं रह गई। फिर जब तक विदेशी शासन के खिलाफ लड़ाई होती रही, तब तक कांग्रेस सस्की सस्था थी, उसमें जमींदार, पूँजीपति, किसान, मजदूर सभी शामिल थे। किन्तु, सत्ता को हाथ में लेकर अब कांग्रेस नहीं कह सकती कि वह सबकी सस्था है। उसका वह गुण और लक्षण मिट गया। अब तो उसे यह तथ्य करना होगा कि वह किसके साथ रहेगी—धनियों के साथ या गरीबों के साथ। क्योंकि धनियों और गरीबों के स्वार्थ जुदा जुदा हैं और जो एक का

समर्थक होगा, वह दूसरे का हित नहीं हो सकता, यह निश्चित है ।

कई महीने पहले मैंने कहा था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस को तोड़ देना चाहिए । बंबई, दिल्ली या वर्धा में एक जलसा हो और वह वहाँ सर्वसम्मति से कांग्रेस की अत्येष्टि किया कर दे । जो सबकी सस्था रही हो, उसका उपयोग एक मुट्ठी लोग अपने स्वार्थ को पूरा करने में अव्यय करें, यह कहाँका न्याय है ?

मैंने इस आशय का वयान ही नहीं दिया, देश के नेताओं से भी चर्चा की । वे भी राजी मालूम होते थे, किन्तु, अब वे बदल गये हैं । हाँ, महात्माजी ने अपने वसीयतनामे में वैसा ही प्रस्ताव रखा—जैसा हमने कहा था । कांग्रेस का नाम मिट रहा है, उसकी इज्जत नष्ट हो रही है । इससे त्याग तपस्या करनेवाले सभी सच्चे आदमी दुःखी हैं । गांधीजी भी दुःखी थे, इसलिये उन्होंने कहा कि कांग्रेस को राजनीति से अलग करो, उसका दुरुपयोग चुनाव में मत करो । गांधीजी ने मरते समय यह नारा हमें दिया और इसके बाद मुझसे भी एक कदम आगे बढ़ गये । कांग्रेस के भग कर देने से देश में जो एक शून्यता फैलती, उससे हानि होने को सभावना थी । इसलिये गांधीजी ने एक और नई वार्ता जोड़ दी कि कांग्रेस का विकास लोक सेवक सघ' के रूप में किया जाय । किन्तु, गांधीजी को यह अंतिम बात भी नहीं मानी गई ।

अब यह साफ हो चला है कि आज जो कांग्रेस है, वह पुरानी कांग्रेस नहीं है । यह तो एक झिलझिल नई कांग्रेस है । इस नई कांग्रेस में रहने और न रहने का निर्णय करने का हक, नये सिरे से सबको है । हमारे सामने दो ही रास्ते थे । या तो हम इस नई कांग्रेस के साथ रहते, जिसके हाथ में आज हुकूमत है, फलतः ज़िदमें तरह-तरह की गदगी फैल रही है और जो हुकूमत की ताकत के लिये लड़ने का आखाड़ा बन गई है । यह नई कांग्रेस

जयप्रकाश की विचारधारा

और उसके मातहत की कांग्रेसी सरकार किस तरह काम कर रही है—आप-हम सभी जानते हैं। हमारे बहुत जोर लगाने पर वे जमींदारी उठाने को तैयार हुए, तो अब इतना मुआवजा दे रहे हैं कि बेचारे किसान पिस जायेंगे। सदियों तक जमींदारों ने लूटा, फिर उन्हें मुआवजा देना तो एक बेतुकी-सी बात है। दरभंगा के राजा के लिए मुआवजे की क्या ज़रूरत है? हाँ, छोटे जमींदारों की परवरिश के लिए जितना दीजिए। किन्तु, सिर्फ जमींदारी उठाने से ही तो किसानों का कल्याण नहीं हो जाता है। जमींदारी उठाने के बाद क्या नक्शा होगा—यह भी सवाल है। जमींदारी उठाना तो पहला कदम है, हमें आगे बढ़ना होगा, तभी किसानों का फायदा है। एक नई कृषि-योजना तैयार कर उसपर मुस्तैदी से काम लेना है। किन्तु, कांग्रेस की हुकूमत यह सब नहीं करना चाहती। ऐसे बड़े-बड़े किसान हैं, जिनके पास हजारों बीघे जमीन है। और दूसरी ओर, ऐसे लोग हैं, जिनके पास एक धूर भी जमीन नहीं है। यह भेदभाव भी तो दूर करना ही होगा।

हमारे सामने दो ही सवाल थे—या तो कांग्रेस में रहकर हम भी खायें-पकायें या उससे अलग होकर हम आन्दोलन करें कि कांग्रेस और उसकी सरकारों में जो गद्गरी आ गई है, वह दूर हो और सही मानी में जनता का राज्य कायम हो।

हमने इसी दूसरे रास्ते को पसंद किया है।

एक बात और भी है। कांग्रेस का जो स्वरूप बदल गया है, उसका पता आपको एक बात से चलेगा। जब कांग्रेस के सदस्य का मानी जेल जाना, लाठी खाना, धन जब्त कराना था, तब जो लोग उससे दूर-दूर रहते थे, वे ही अब कांग्रेस की ओर दृष्ट पड़े हैं। जिन्होंने कभी खहर का सपना नहीं देखा, वे खहर पहनकर अपने महलों और मोटरों पर तिरंगे झंडे उड़ाये जा रहे हैं। दिल्ली की सरकार में वैसे वजोर हैं, जो कांग्रेस के द्रोही थे

काँग्रेस मर गई

षष्ठमुख चेट्टी को लीजिए। उनका इतिहास क्या है ? जिन्दगी भर अँगरेजों के पिट्टू रहे और आज पूँजीपतियों के पिट्टू बनकर नेहरू-सरकार में वजीर बनकर अब तो पूरे काँग्रेसी बन गये हैं। जिस काँग्रेस में षष्ठमुख चेट्टी और श्यामाप्रसाद मुखर्जी ऐसे लोग हों, क्या उस काँग्रेस को पुरानी काँग्रेस ही कहा जायगा ?

लोग पूछते हैं, मान लिया कि अब वह काँग्रेस नहीं रही ; पर वहाँ राजेन्द्र बाबू और नेहरू तो हैं ? हमारा यह दावा नहीं कि हमलोग हटे, तो कोई अच्छे लोग नहीं रहे। वहाँ भी ऐसे लोग हैं, जो जनता की सेवा करना चाहते हैं और उसकी इज्जत करते हैं। किन्तु, उस काँग्रेस में ऐसे लोगोंका बोलबाला हो रहा है, जो इस ताक में हैं कि प० नेहरू को भी हटा दें। इस-पर आप आश्चर्य मत कीजिये। बिहार को ही ले लीजिये। बिहार के एक-मात्र नेता हैं, डा० राजेन्द्र प्रसाद। जबसे मिनिस्ट्री बनी, कितनी गन्दगी फैली, कितनी बदनामी हुई। छोये को बात ने सारे बिहार को बदनाम किया। क्या राजेन्द्र बाबू इस गन्दगी को दूर कर सके ? क्या छोये की जाँच भी करा सके ? इसके क्या मानी ? बड़े-बड़े नेता जनता के सेवक हैं ; किन्तु काँग्रेस एक मशीन है, जो नेता से भी बड़ी है। सभी नेताओं के नेता महात्माजी अन्तिम दिनों में काँग्रेस की गन्दगी से किस तरह बैचैन थे ? वह बार-बार कहते थे, मैं क्या कहूँ, मेरी तो चलती नहीं। उनकी आवाज में कितना दर्द रहता था—रेडियो सुननेवाले जानते हैं। जब उनकी नहीं चली, तो फिर नेहरू, आजाद या राजेन्द्र बाबू की क्या चलेगी ? नेहरू साहब प्रधान मन्त्री हैं; किन्तु, उनकी छाप क्या उनकी हुकूमत पर हम पाते हैं ? उनकी चलती, तो देश की कायापलट हो जाती। नेहरू साहब एक वक्तव्य देते हैं कि दूसरी ओर से दूसरा निकल जाता है और ऐसा चक्र चलता है कि उनका कहा-सुना ठप्प तो जाता है। तो वे भी काँग्रेस से या इस पद पर

जयप्रकाश को विचारधारा

से क्यों नहीं हट जाते ? शायद इसलिए कि थोड़ा-बहुत जो कर पाते हैं, वह भी न हो और ऐसे लोगोंके हाथों में हुकूमत जाय, जिससे देश का बुरा होगा। किन्तु, नेहरू साहब की सारी परेशानियों के बाद भी देश उसी ओर जा रहा है। चीन में भी ऐसा ही हुआ और यदि यही रबैया रहा, तो हमारे देश की भी दुर्दशा चीन की ही तरह होगी।

हमारे नेता कांग्रेस को अच्छी राह पर ले जाना चाहते हैं; किन्तु वे कर नहीं सकते। हमने भी ऐसा करके देखा है। किन्तु, कांग्रेस में दिन-दिन अमीरों को बोल-बाला होता जा रहा है। गांधी-नेहरू सब असमर्थ सिद्ध हुए। फिर हमारी क्या बिसात ! तब हमने सोचा कि कांग्रेस के अन्दर हम जब तक हैं, तब तक देश का कल्याण नहीं। अलग होकर हम कांग्रेस और उसकी सरकार की बुराइयों को जनता के सामने रखें और देश में एक नये ढंग का समाज बनाने के लिए अन्दोलन करें।

तब हमारा देश स्वर्ग होगा

आज हम सोशलिस्ट पार्टी के झंडे के नीचे 'मजदूर-दिवस' मनाने जा रहे हैं। मजदूर-दिवस के महत्त्व के बारे में मुझे कुछ विशेष नहीं कहना है; इस दिवस के महत्त्व को बढ़ाने के लिए सोशलिस्ट पार्टी ने अपनी सरकार से अनुरोध किया था कि पहली मई को आम छुट्टी का दिन घोषित किया जाय, जिससे सारे देश के मजदूर अच्छी तरह इस दिवस को त्योहार के रूप में मनावें। उस दिन हिन्द के सारे दफ्तर, खान, इंडस्ट्रिज और छोटे-छोटे उद्योग धंधे बन्द रहें। किन्तु बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि भारत सरकार ने अभी तक इसका कुछ फैसला नहीं किया; इसके महत्त्व को नहीं समझा। फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल इस काम में बहुत ज्यादा प्रगति होगी, जिससे इसको हम एक बड़ी शानदार चीज बना सकें।

सोशलिस्ट पार्टी ने इसपर अपना ज्यादा जोर क्यों दिया, इसके कई कारण थे ? एक कारण तो यही था कि इसके जरिए अन्तर्राष्ट्रीयता का प्रचार बैठेगा—उसे एक बहुत बड़ा बल मिलेगा। दूसरा कारण था हिन्दोस्तान में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है; क्योंकि यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर गरीब मजदूर और किसान बसते हैं, जिन्हें इसका महत्त्व समझना है। इसके अलावा

जयप्रकाश की विचारधारा

जो परिश्रम करके पैट भरते हैं, ऐसे बुद्धिजीवी लोगोंके दिमाग से वावूगिरी का खाल निकालना है और उन्हें समझाना है कि आपका वर्ग भी वही है, जो शारीरिक परिश्रम करके अपनी रोजी चलाते हैं। और, इस तरह धीरे-धीरे उन सबको इस भंडे के नीचे लाना है। इन सबका अन्तिम उद्देश्य है, एकमात्र लक्ष्य है—समाजवाद का प्रचार तथा समाजवादी व्यवस्था को कायम करना।

मैं इस सम्बन्ध में आपके सामने कुछ खास बातों का जिक्र कर देना चाहता हूँ।

१५, अगस्त को देश आजाद हुआ। आजादी के बाद देश ने सोचा—अब हम लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, अपना मार्ग तय करेंगे और किसान मजदूर राज कायम करेंगे। मगर वैसा होते कुछ नजर नहीं आ रहा है। आप कहेंगे कि आप जो कहते हैं, वही बात तो वे भी कह रहे हैं, फिर अन्तर किस बात का? आप धीरज धरें, कुछ समय उन्हें दें। अभी जल्दीबाजी क्या है?

जहाँ तक समाजवादियों का सवाल है, उनके पास समाजवाद का—राज्य-व्यवस्था का—निश्चित स्वप्न है। हम जल्दबाजी कहाँ कर रहे हैं? फिर भी यदि हमें एक घर बनाना है, तो पहले उसका नक्शा तैयार कर लेना जरूरी है। बगैर नक्शे के हम घर का रूप क्या देंगे—उसमें किधर क्या और कितनी एव कंसी कोठरियाँ रख सकेंगे? आज कांग्रेस नेताओं के पास इस व्यवस्था के लिए कोई नक्शा नहीं है। यदि ऐसा होता, तो उनका कोई मंत्री कुछ और कोई कुछ नहीं बोलता। सब-के-सब पथभ्रष्ट की तरह अंधेरे में इधर-उधर भटकते नजर आ रहे हैं। हमारी इन बातों से आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए। अभी पंडित जवाहरलालजी ने बम्बई की ए०आई०सी०सी० की मीटिंग में भारतीय औद्योगिक नीति के बारे में जो कुछ कहा है, उससे भारतीय सरकार की नीति से कोई समानता नहीं। भला जिस सरकार का

तब हमारा देश स्वर्ग होगा

प्रधान मंत्री जी बात कहे और उससे सरकार की नीति में समानता नहीं, तो वह कैसी शासन-व्यवस्था है ? भारत सरकार के औद्योगिक मंत्री डाक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने पूँजीपतियों को पूरा आश्वासन दिया है और कहा है कि हमारी नीति साफ है, इसमें जरा भी संदेह नहीं। पंडित नेहरू जैसा क्रान्तिकारी नेता चाहते हैं कि सड़ी-गली इमारत की मरम्मत करके सुखी रहें, यह नामुमकिन है। जब इमारत जीर्ण हो गई है, तो हमें चाहिए—देश के नौजवानों को चाहिए कि उसे बिल्कुल ध्वस्त कर नए सिरे से नई इमारत बनाएँ, जो खूब पोखता हो। आपने यह भी पढ़ा कि कलकत्ते में सरदार पटेल ने पूँजीपतियों की एक सभा में उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि अब तुम क्या चाहते हो ? तुम्हारे तो दो दो प्रतिनिधियों को मंत्रिमंडल में रख लिया गया है, व्यर्थ घबराते हो। मगर एक दूसरे मंत्री ने कहा कि चन्द वर्षों में हम पूँजीवाद को खत्म कर देंगे। इस तरह कुछ भी पता नहीं चलता कि सरकार की क्या नीति है, उसकी कौन-सी दिशा है। उसका निश्चित कोई कार्यक्रम नहीं है। मगर नहीं, समाजवादियों के दिम ग में व्यवस्था का पूरा चित्र है और एक निश्चित दिशा है।

आज देश के सामने भोषण गरीबी और अभाव की समस्या है। आज इस सवाल को हल करने की एक निश्चित दिशा चाहिए। देश में ९८ फी सदी गरीब मजदूर और किसान बसते हैं। इनके कपड़े, भोजन, घर, शादी-व्याह हर तरह के अभाव को दूर करने की समस्या है। हमारे पिछड़े भाई हरिजन लोगोंके, घरों को देखिये, जानवर से भी बदतर इनकी हालत है। जिन घरों में ये रहते हैं—वह भी इनका अपना नहीं। जब मालिक चाहे, उन्हें उसमें से निकाल बाहर कर देता है। बीमारी की समस्या विकराल है। पथ, दवा के बिना ये चूहों की तरह सड़-सड़कर मर रहे हैं। डाक्टर के लिए उनके पास पैसे कहाँ ? कहीं-कहीं तो लाश को फेंकनेवाला भी कोई

समस्या का विचारधारा

मिलनी चाहिए—चाहे वह देश सेवक हो, मंत्री हो, वैज्ञानिक हो, गवर्नर हो या गवर्नर-जनरल हो। आज धन के वटवारे की विषमता को, लूट को, अन्नाय को, शोषण को, तमाम अत्याचारों को बदलना है, इसके विरुद्ध सारे देश को लड़ना है।

हमारे नेता इस बात के लिए बहुत कुछ उलटी सीधी बातें रखते हैं और रखेंगे। मगर इसपर तो आप को खुद सोचना है। आज आपको एक आनेवाले भारी ग़ातरे से आगाह कर देना चाहता हूँ। आज असेम्बली में, ब्रिस्टल में, दिल्ली में यह भयकर राजिश चल रही है कि हिन्दु तान को डोमिनियन स्टेट्स बनाकर रखा जाए। इस राजिश में बड़े-बड़े नेता फसते जा रहे हैं। पता नहीं आप क्या चाहते हैं? जनता को तो हमारे नेता सर्प की तरह वीणा बजाकर मुग्ध कर लेते हैं—वे जो चाहते हैं जनता को समझा देते हैं, विचारी जनता उनपर विश्वास कर उनके पीछे हो लेती है। वे कहेंगे डोमिनियन स्टेट्स ही अच्छी चीज है, अभी हिन्द पर खतरा है। इस मुकामिल आजादी के लायक नहीं हुए हैं। बस विचारी जनता उनपर विश्वास कर ही लेगी। मगर मैं कहता हूँ कि हम तो पूर्ण आजादी चाहते हैं। अब आप सोचिये कि आप क्या चाहते हैं? मगर खतरा बहुत नज़दीक है, इससे आपको अगाह कर देता हूँ।

मैंने पहले कहा है कि चन्द लोगों के पास जो धन एकत्र है, उसको लेकर सबसे बड़ा टेने से सब सुखी नहीं हो जायेंगे। सुखी तो लोग तब होंगे, जब पैदा हुए धन का न्यायपूर्ण उचित वटवारा हो और यह काम कानून के जरिए तथा सामाजिक व्यवस्था के जरिए होगा। यदि हिन्दुस्तान में आज कई गुना ज्यादा धन पैदा हो भी तो उससे गरीब हिन्द को कोई फायदा नहीं। इससे तो और भी गरीब गरीब होते जायेंगे और अमीर अमीर। पूँजीपतियों की सख्या में वृद्धि अवश्य हो जायगी। आपने देखा या सुना

तब हमारा देश स्वर्ग होगा।

होगा कि अमेरिका में बहुत धन पैदा होता है, जिससे सारे ससार का बाज़ार भरा जा सकता है। मगर इससे क्या, वहाँ के मजदूर थोड़े सुखी हैं ? मैं खुद वहाँ मजदूरी कर चुका हूँ। १४ रु० रोजाना आमदनी थी, मगर फिर भी कठिन जिन्दगी बितानी पड़ी थी—यद्यपि वह समय अमेरिका के लिए सब तरह से अच्छा था। ज्यादा धन पैदा होने से वहाँ ससार के सबसे बड़े पूँजीपति भी हैं। और सबसे ज्यादा उन्हें मुनाफा होता रहा है। वहाँ भी यही बात है कि धन का उचित बँटवारा नहीं है ! मजदूरी ज्यादा मिलने से क्या होगा जब कि चीजों का दाम ही ज्यादा होगा जैसा कि अमेरिका में है। इसलिए जबतक हम समाज-व्यवस्था और कानून नहीं बदलते, तबतक यह संभव नहीं। और यह काम एक मात्र समाजवाद के जरिए ही हो सकता है। समाजवाद पार्टी यही चाहती है कि मिहनत करनेवाले जो लोग हैं—वे जहाँ भी हों, उन्हीं में धन का उचित बँटवारा हो। पहला कानून यही बनना चाहिए कि बूढ़, रोगी, बच्चा और गर्भिणी को छोड़कर जो व्यक्ति मिहनत नहीं करेगा, वह भूखा मरेगा और जो मिहनत करके धन पैदा करेगा, उसीमें उस धन का उचित बँटवारा होगा।

इसके अलावा पैदा किये हुए धन के बँटवारे करने का अख्तियार भी उन्हीं लोगों को होगा जो उस धन को पैदा करते हैं। अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वे ही सोचेंगे कि कौन-सा धन ज्यादा पैदा करने से हम सम्पूर्ण देशवासी सुखी और स्वस्थ रह सकेंगे। सारे कारोबार का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए।

आज राष्ट्रीयकरण में जितनी ज्यादा देर हो रही है, सब पूँजीपतियों के चलते। आज देश के तमाम उद्योग-धंधों और सरकार पर भी इनका सिक्का जमा है। हमारे पटेल साहब कहते हैं—‘दस वर्ष निश्चित रहो।’ उद्योग-

जयप्रकाश की विचारधारा

बन्धों में पूँजी लगाने चलो । तुम्हारे दो प्रतिनिधियों को इसीलिए सरकार में रवाना दे रखा है ।' मगर दस वर्ष में ये पूँजीपति क्या बमजोर पड़ जायेंगे ? ऐसा सोचना पागलपन होगा । दस वर्ष में तो ये और भी मजबूत हो जायेंगे—देग को नस-नस पर कब्जा कर लेंगे, तब-इनको हटाना और भी कठिन होगा । ये पूँजीपति किसी तरह में कुछ जोखिम उठाना नहीं चाहते । देश में कुछ ऐसे कारखाने चलनेवाले हैं जिसमें सरकार और पूँजीपति दोनों के पैसे लगेंगे । उसमें पब्लिक के पैसे ५१ सै० और ४९ सै० पूँजीपति के होंगे । पूँजीपतियों की यह साजिश है कि अपने निज के कारखाने में अच्छे माल पदा करके और साझे-वाले कारखाने में अड़गे की नीति लगा कर इसकी पैदावार को ठप्प कर देंगे । जब पूँजीपतियों के कारखाने में मजदूरों को कुछ मुबधा मिलेगी और साझे-वाले कारखाने के मजदूरों को उसे उत्पन्न धन से कोई ज्यादा मुनाफा नहीं मिलेगा; तब स्वभावतः ऐसे कारखाने में उत्पादन की वृद्धि कम होगी और वर्षों घाटे में कारखाने चलते रहेंगे । आपने देखा होगा कि रूस में वगैरह पूँजीपतियों के पाँच वर्ष के अन्दर मजदूरों ने भूखों रहकर इतना ज्यादा काम किया जितना ३० साल में भी हिन्दोस्तान में नहीं हो सकता । आज चीन में वर्षों से आजादी मिली है, मगर व्यवस्था और कानून के ऐसे दोष रहे जिससे सारा चीन बर्बाद होता जा रहा है । वही हाल १८८५-१८९० का भी होनेवाला है । इसका एक मात्र सुधार समाजवादी व्यवस्था से ही हो सकता है । दूसरा कोई रास्ता कामयाब नहीं हो सकता ।

हमारे देश में छोटे-छोटे किसानों की सख्या सबसे ज्यादा है । यदि यही वर्तमान व्यवस्था और कानून रहे, तो खेती के मामले में भी विशेष कोई तरकी नहीं होने को । यह काम भी समाजवादी सरकार के जरिये ही हो सकता है । सरकार के हाथों में बहुत बड़ा अधिकार होता है । एक अधिकार

तब हमारा देश स्वर्ग होगा

यह है कि वह कानून बनाती है और दूसरा उस कानून को काम में लाने के लिए सेना, पुलिस आदि का उपयोग करती है। इसलिए जैसी सरकार होगी, देश का भला बुरा वैसा होगा।

आज जो एटम बम का उपयोग ससार के विध्वंस में लगाया जा रहा है, यदि उसका उपयोग सरकार देश के उत्पादन शक्ति में लगाये तो आप जरा सोचिए, देश कैसा होगा ? जब देश के प्रत्येक श्रमजीवी को १०००) मासिक मिलने लगेगा, तब हमारा देश स्वर्ग होगा—नन्दन बन होगा। मेरे इस चित्र को मूर्त्त रूप देना होगा। मगर इसे अकेले सोशलिस्ट पार्टी नहीं कर सकती। आप हमारी सहायता करें। यह देश के करोड़ों व्यक्तियों की सहायता से होगा। आज राष्ट्र की उन्नति खतरे में है। आज शोषण से लड़ना है, वर्ग-विहीन समाज बनाना है, आर्थिक क्रान्ति करनी है, समाज में ऊच-नीच का भेद मिटाना है। यह काम भी समाजवाद के जरिये ही हो सकता है।

आज मैं एक बात की और चेतावनी देना चाहता हूँ कि आज हमारे पिछड़ी जाति के भाई लोग देश में वही खतरा उत्पन्न कर रहे हैं जो पहले उच्च जातिवालों ने किया है। इनका सगठन भी वैसा ही हो रहा है जिससे एक जाति दूसरी जाति को मिटाने में सलग्न रहती है। हम मानते हैं कि इन सगठनों के जरिये पिछड़ी जातियों के कुछ लोग उच्च ओहदे पर पहुँचेंगे, मगर इससे क्या होगा। यदि समाज की यही व्यवस्था रही, तो देश में वही वर्ग विद्वेष और गरीबी का साम्राज्य छाया रहेगा। इससे आम जनता को क्या मिलेगा ? पहले जो उच्च जाति वाले देश पर—समाज पर शासन करते रहे हैं, उससे क्या तमाम उच्च जाति के लोगों की गरीबी दूर हो गई थी ? इससे तो कुछ थोड़े ही व्यक्तियों का बोलवाला रहेगा—उसका शोषण जारी

जयप्रकाश की विचारधारा

हो रहेगा। यहाँ तो प्रगति का समाल है—व्यवस्था का दोष है। इसलिए आज देश में आधिक क्रान्ति के साथ वर्ग-विहीन समाज का निर्माण करना सबसे ज्यादा जरूरी है। समाजवादियों ने इस दिशा में भी आन्दोलन करना शुरू कर दिया है। इस ओर भी आपकी सहायता अत्यन्त आवश्यक है। मैं आज आप के सामने स्पष्ट कह रहा हूँ कि आप देश और समाज की भलाई के नाते रोजगारिणी पार्टी के मांडे के नीचे आये और समाजवाद को सहायता करें। मैं किसी तरह आपको बरगला नहीं रहा हूँ और न चिकनी-चुपड़ी बातें ही करता हूँ। यही सत्य और क्रान्तिजनक मार्ग है।

